

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DATE	SIGNATURE

जापान का संविधान

तथा

अपराध-दण्ड कानून

(THE CONSTITUTION OF JAPAN AND CRIMINAL LAWS)

अनुवाद

डॉ० रामाप्रसाद पाठक, एम० ए० पी एच० डी०



सत्यमेव जयते

पंजाबिया तथा तकनीकी शस्त्रावली आयोग, शिक्षा मन्त्रालय,

भारत सरकार के तत्त्वानुष्ठान में

हिन्दी प्रकाशन समिति

वासी हिन्दू विश्वविद्यालय, वागणसी—७

द्वारा प्रकाशित

जापान का संविधान तथा अपराध-दण्ड कानून

(THE CONSTITUTION OF JAPAN AND CRIMINAL LAWS)

अनुवादक

डॉ० रामाधर पाठक, एम्. ए., पी एच्. सी.



सत्यमेव जयते

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मन्त्रालय,
भारत सरकार के तत्वावधान में हिन्दी प्रकाशन समिति,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-5
द्वारा प्रकाशित

1965

प्रथम संस्करण—1965

© वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
भारत सरकार

प्रकाशन सहायक—भगवतीप्रसाद राय

ज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के सत्त्वावधान में
प्रकाशित 'जापान का संविधान तथा अपराध-दण्ड कानून'
अंग्रेजी पुस्तक 'The Constitution of
Japan and Criminal
Laws' का हिन्दी
रूपान्तर है ।

प्रकाशक
हिन्दी प्रकाशन समिति,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

मुद्रक
लक्ष्मीदास
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी प्रेस, वाराणसी-5

प्रकाशकीय

8 अगस्त सन् 1963 ई० को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की ओर से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी प्रकाशन समिति की स्थापना हुई। समिति के तत्त्वावधान में मानक ग्रन्थों का अनुवाद और कुछ विषया पर मौलिक ग्रन्थों का प्रणयन निश्चित किया गया। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की ओर से अन्य मानक ग्रन्थों सहित घाना, जापान, स्विटजरलैण्ड, पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया, ब्रिटिश नार्थ अमेरिका एण्ड समुक्त राज्य अमेरिका रूस आदि के सविधान अनुवाद के लिए सौंपे गए। समिति ने इनका अनुवाद विश्वविद्यालय के अनुभवी अध्यापकों से कराया है। जापान का सविधान इस योजना की दूसरी पुस्तक है। अनुवाद करते समय भारत सरकार की ओर से प्रकाशित पारिभाषिक शब्दावली का पूर्ण उपयोग किया गया है। भाषा सरल तथा औपचारिक रखी गई है। सविधान की अधिकांश शब्दावली पारिभाषिक होती है, उसके प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, इसलिए विषय सुस्पष्ट बनाने के लिए भाषा में यथासम्भव पर्यायों के प्रयोग से बचने का प्रयास किया गया है। यथा-अवसर सविधान के मिथ या समुक्त वाक्य हिन्दी की प्रवृत्ति के अनुकूल छोटे वाक्यों में रखे गए हैं।

अन्य भाषा में देने सविधान का हिन्दी भाषा में अनुवाद करते समय यह ध्यान रखा गया है कि उस देश के शिष्टाचार तथा सत्कृति मूलक प्रयोग विशेष परिवर्तित न हो। सम्भव है इससे कहीं-नहीं भाषा अनेकल प्रनीत हो, जैसे Koso Appeal (कोसो अपील), Kokoku Appeal (कोकोकु अपील), Jokoku Appeal (जोकोकु अपील) आदि।

इस कार्य के लिए पूरी आर्थिक सहायता भारत सरकार से मिली है। इस अनुदान तथा प्रोत्साहन के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की हिन्दी प्रकाशन समिति भारत सरकार के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ है। अनुवादकों ने बड़े परिश्रम से इसका अनुवाद किया है। उनका कार्य प्रशंसनीय है और वे समिति

की ओर से बघाई के पात्र है। प्रकाशन-कार्य में मैनेजर, वी० एच्० य० प्रेस, का सहयोग पूर्णरूप से प्राप्त हुआ है। मैं उन्हें अपनी ओर से तथा समिति की ओर से धन्यवाद देता हूँ।

वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय

वाराणसी 5

नन्दलाल सिंह

निदेशक, हिन्दी प्रकाशन समिति

विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ
जापान का संविधान	1
1 सभ्राट	4
2 युद्ध का परित्याग	5
3 नागरिका के अधिकार एवं कर्तव्य	5
4 राज्यसभा	10
5 मन्त्रि-परिषद्	14
6 न्यायपालिका	16
7 वित्त	18
8 स्थानाय स्वायत्त शासन	19
9 सशस्त्र	20
10 सर्वोच्च विधि	20
11 अनुपूर्व उपबन्ध	21
दण्ड संहिता	22
पहला खण्ड सामान्य उपबन्ध	22
1 विधिया के विनियोग	22
2 दण्ड	24
3 अवधि का परिवर्तन	27
4 दण्ड के निष्पादन का विलम्बन	28
5 कारागार से सामयिक निमुक्ति (वाग्विद्रोह)	29
करिगुत्तुगाकु	
6 दण्ड का भोगाधिकार एवं उसकी समाप्ति	30
जिका	
7 अपराध का वियोजन एवं दण्ड का घटाव एवं क्षमा प्रदान	31
हन्जाद ना कुसइरित्तु ओयावि वेइ नो मेमेन	
8 आपराधिक प्रयत्न	33
मिसुइजाई	

अध्याय			पृष्ठ
9. अनेकापराध	33
	"हेरगोजाइ"		
10 पुनरावृत्त अपराध		...	35
	"रदहन"		
11. सहापराधिता		.	36
	"बयोहन्"		
12. दण्ड घटाव वाली परिस्थितियों के कारण दण्ड का घटाव...			37
	"भकुचो गेट्केइ"		
13. दण्ड के बढ़ाव या घटाव के सामान्य नियम			37
	"बगेन् रेइ"		
दूसरा खण्ड अपराध		...	39
1 निषाल दिया गया		.	39
2 गृह-मुद्द से संबद्ध अपराध		..	39
	"गइगन नि बन्-मुर लूमि"		
3. (बाह्य) मुद्द संबन्धी अपराध	40
4. अन्तर्राष्ट्रीय सन्ध्या से संबद्ध अपराध		..	40
	"बाक्का नि बन्-मुर लूमि"		
5. कार्यालयीय कार्यों में बाधा डालने के अपराध		...	41
	"कामु नो भिक्को वो बीगैमुर लूमि"		
6. निकल भागने (पलायन) के अपराध	42
	"तोमा नो लूमि"		
7. अपराधियों को मन्थन देने एवं साक्ष्य के अविवक्ष्यन के अपराध	43
	"हनिग जोतोडु जायोवि शोको इमेत्तु नो लूमि"		
8. धलत्रे के अपराध	43
	"मोजा नो लूमि"		
9. जाग लगाने एवं उपेक्षावश जलाने के अपराध		...	44
	"हक्का जोयोवि शिक्का नो लूमि"		
10. बाध्यावन एवं जल के उपयोग से संबद्ध अपराध		..	46
	"इम्मृइ ओयोवि मुदरो नि बन्-मुर लूमि"		

अध्याय	पृष्ठ
11 यातायात में अवरोध पहुँचाने से सबद्ध अपराध ‘आराइ वो वागाइ-मुह त्मुमि	48
12 अतिचार के अपराध जुक्था वा आरमु त्मुमि	49
13 ग्रापनीयता उल्लंघन के अपराध हिमि-मु वा आरमु त्मुमि	49
14 अशोभ-तन्त्राकू से सबद्ध अपराध अहन-वेवना नि वन्-मुह त्मुमि	50
15 पय जग्ग से सबद्ध अपराध इनरियागुद नि वन् मुह त्मुमि	51
16 जागी सिक्क धनान के अपराध त्तुर गिजा ना त्मुमि	52
17 गृह्य की जागसाजी के अपराध वुगा गिजा नो त्मुमि	53
18 मूल्यवान वणपत्रा (जमानता) की जागसाजी के अपराध युक्कावन् गिजा ना त्मुमि	55
19 मुद्राभा (मुहरा) की जागसाजी के अपराध ‘इत्ता गिजा ना त्मुमि	56
20 मिथ्या गण्य का अपराध गिगा ना मुमि	57
21 मिथ्या अभियाग का अपराध पुरोत्तु ना त्मुमि	58
22 अज्ञोन्ता बलात्कार तथा द्विपत्नीत्व के अपराध वैसामु वनिन ओयोवि जुवान नो त्मुमि	58
23 जुआ गग्ग तथा लाटरो से सबद्ध अपराध तोत्रु ओयोवि तामिबुजि नि वन्-मुह त्मुमि	59
24 पूजास्थानों एवं ममाधिया से सबद्ध अपराध रइहैगा ओयोवि पुन्वा नि वन्-मुह त्मुमि	60
25 वायाग्यीय अष्टाचार के अपराध ताहु गोत्तु नो त्मुमि	61

अध्याय	पृष्ठ
26 मानववध व अपराध संभोजन ना मुमि	63
27 धायर वरन व अपराध नागा ना मुमि	64
28 अनवधानता स धायर वरन व अपराध रांगु नागाद ना मुमि	65
29 गभपति व अपराध दताद ना मुमि	65
30 अभिधाग व अपराध नरि ना मुमि	66
31 (अवध) बदाररण एव परिचाय व अपराध तहो जायावि वन तिन ना मुमि	67
32 अभिधारा व अपराध वयाहट ना मुमि	67
33 हरण एव अपहरण व अपराध गियटु आयावि मुवाइ ना मुमि	68
34 रयाति व बिरद अपराध मर्या नि तदमुग मुमि	69
35 राग एव व्यवसाय व प्रति अपराध गिया जायावि ग्यामु नि तदमुग मुमि	71
36 चारा जोर गूट व अपराध राता आयावि गाता ना मुमि	71
37 धायरवाजा जार नयादाहन व अपराध गगि जायावि वयावगु ना मुमि	73
38 छापूण विनिषादन व अपराध जायो ना मुमि	74
39 चारा व माग न मवद अपराध जावगु नि तदमुग मुमि	74
40 विनाग एव छिपान व अपराध विमि आयावि गताड ना मुमि	75

अध्याय	५८
दण्ड प्रक्रिया संहिता	७७
पहला खण्ड—सामान्य उपबंध	७७
1 जायाग्या का अधिकार-क्षेत्र	७७
2 जायाग्य व वधचारिया व अपवजन एवं आपत्ति	८१
3 वाचवरण सामर्थ्य	८४
4 परामर्शाता द्वारा प्रतिष्ठा तथा सुवर्धिया द्वारा सहायता	८७
5 निषय	८८
6 प्रत्य तया विवरण	८९
7 अयधिया	९१
8 अभियुक्त व आह्वान प्रस्तुति और निराप	९१
9 अभियुक्त और तत्परा	१०३
10 निरीक्षण द्वारा साक्ष्य	११०
11 साक्षा की परीक्षा	११२
12 विषय साक्ष्य	११८
13 अयनिवचन एवं अनुवाद	१२०
14 साक्ष्य का परिष्करण	१२०
15 विचारण व परिष्करण	१२१
दूसरा खण्ड—आवधिक व्यवहार	१२३
1 परिष्करण एवं अनुसंधान	१२३
2 आह्वानवाही	१३०
3 आवधिकारण	१४५
अनुभाग 1 आवधिकारण की तैयारी तथा उपरी प्रक्रिया	१४५
अनुभाग 2 साक्ष्य	१५५
अनुभाग 3 आवधिकारण का विनिर्णय	१६०
तीसरा खण्ड—अपील	१६६
1 सामान्य उपबंध	१६६
2 कासा अपील	१६९
3 अपील अपील	१७०
4 कासी अपील	१७०

अध्याय		पृष्ठ
चौथा खण्ड कार्यवाही का पुनर्विचार	...	184
पांचवां खण्ड — असाधारण अपील	..	191
छठा खण्ड — क्षिप्र प्रक्रिया	...	193
सातवां खण्ड — विनिश्चय का निष्पादन	..	195
अनुपूरक उपबन्ध	...	204
पारिभाषिक शब्दावली	.	205

— — —

जापान का संविधान

मुने हर्षे है कि जापान की जनता की इच्छा के अनुसार नव जापान के निर्माण के लिए निरग्न्याग किया गया है जोर में प्रिन्सी कोमिट के परामर्श एवं उच्च मन्त्रिपरिषद् के अनुच्छेद 73 के अनुसार मण्डित राज्य सभा के निर्णय के अनुसार जापान के राष्ट्रीय मन्त्रिपरिषद् गुणरा का अधिनियमितर अनु मादिन एवं प्रयत्नित करता है।

इम्पाथर हिरोहितो मन्त्राट की मुद्रा

दिनांक ११ मार्च १९४६ को जारी किया गया था
(3 मई 1946)

प्रति ११११११

प्रधान मंत्री एवं परमाणु मन्त्री

योशिदा शिगेरु

राज्य मन्त्री

बेन्ग शिवेहरा किजुरा

वाय मन्त्री

किमुरा ताकुत्सा

गृह-मन्त्री

ओमुरा मभादनी

शिक्षा मन्त्री

तनका वातरा

वृषि एवं वन मन्त्री

वादा हिराभा

राज्य मन्त्री

साइतो कराओ

मवाद-मन्त्री

हितोत्सुमत्सु मदयोशि

वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री

होशिजिमा जिरो

सन्त्याण मन्त्री	कनाई यासिनरी
राज्य मन्त्री	उएहरा एत्सुजिरा
पञ्चवहन मन्त्री	हिरत्सुकु त्मुनेजिरा
मित्र मन्त्रा	इशीवशी तजान
राज्य-मन्त्री	कानामोरी तातुजिरा
राज्य मन्त्री	जेन काइनामुने

अध्याय 1

सम्राट्

अनुच्छेद 1 जनता की इच्छा से ही जिसमें सर्वोच्च प्रभुत्व निहित है, अपनी प्रतिष्ठा पाता हुआ सम्राट् राज्य एवं जनता की एकता का प्रतीति होगा।

अनु० 2—राज्य महामन्त्र राजवर्गीय हागा और राज्य सभा (Diet) द्वारा पारित राज्य-मदन-विधि (Imperial House Law) के अनुसार ही इसका उपभाग होगा।

अनु० 3—सम्राट् के राज्य-मन्त्री सभी कार्यों में मन्त्रिपरिषद् का परामर्श एवं अनुमोदन आवश्यक होगा और इससे लिए मन्त्रिपरिषद् उत्तरदायी होगी।

अनु० 4—सम्राट् राज्य के केवल उन्हीं विषयों में अपना कार्य कर सकगा जो इस मविधान में विहित हैं और उसमें सगरार या सामन्त-विषयक शक्ति नहीं रहेगी।

सम्राट् राज्य के विषयों में अपने कार्य-संपादन का प्रतिनिधान, विधान के निर्देशों के अनुसार, कर सकता है।

अनु० 5 जब राज्य-मदन-विधि के अनुसार, वार्ड राज-प्रतिनिधिमंडल (Regency) नियुक्त होगा, तो वह राज-प्रतिनिधि (Regent) राज्य के रिषय में सम्राट् के नाम पर कार्य करेगा। ऐसी दशा में, पिछले अनुच्छेद का पढ़ा पच्छेद ही लागू होगा।

अनु० 6—सम्राट्, प्रधान मन्त्री को, जैसा कि राज्यसभा (Diet) ने यह नाम दिया है, नियुक्त करेगा।

सम्राट्, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की, जैसा कि मन्त्रिपरिषद् ने यह नाम दिया है, नियुक्ति करेगा।

अनु० 7—सम्राट् मन्त्रिपरिषद् के परामर्श एवं अनुमोदन के अनुसार, जनता की ओर से राज्य-विषयक निम्नलिखित कार्य करेगा

मविधान, विधियों, मन्त्रिपरिषद् के आदेशों एवं मधि-मंत्रों के मशौयनों का प्रवर्तन करना,

राज्य-सभा का समारोह,

प्रतिनिधि-मदन भंग करना,

अनु० 11—मानव के किसी मौखिक अधिकार के उपयोग से नागरिक वंचित नहीं रखा जायेगा। यह संविधान द्वारा संप्रदत्त (प्रयाभूत) मौखिक अधिकार में से कौनसा एक जागामा पाटो के नागरिकों का नागरिक एवं अन्य अधिकारों के रूप में नहीं जायेगा।

अनु० 12 संविधान द्वारा जनता का दस वर्षे स्वनयता तथा अधिकारों की सुरक्षा जनता के शतक प्रयागों द्वारा का जायेगा जो उक्त स्वनयता एवं अधिकारों का दृष्टिकोण न करेगा तथा मन्त्रों उनका उपयोग जनवल्याण के हाथों वगैरे का उत्तरदायी होगा।

अनु० 13 समस्त जनता का व्यक्तिगत रूप में वरता जायेगा। 'नव' जावन स्वतंत्रता एवं सुख के प्रयोजन के लिए तक विधान तथा अन्य सम्मेलनों में समस्त जनता समस्त जायेगा जब तक कि ये जनता के विरोध में नहीं जायेगा।

अनु० 14 विधान के समक्ष समस्त जनता समान है। जाति धर्म या सामाजिक स्तर के कारण (1) (2) (3) (4) के कारण - पतन का कारण राजनयिक जाति के अथवा सामाजिक व्यवस्था में बाध नहीं होगा।

पुत्रों के अथवा पुत्रों की जाति नहीं होगी।

किसी सम्मान अथवा धन या किसी वैशिष्ट्य प्रदान के साथ बाध विनापि धनार न रहेगा और न तो इस प्रकार का बाध प्रदान उस व्यक्ति का जाति के पञ्चान विहित समस्त जायेगा जो उस अवस्था में पाया है या भविष्य में पान वाला है।

अनु० 15—जनता का अपने सरकारों वमचारियों का चुनाव एवं पदव्युत्तर वगैरे का अधिकार है।

गंगा यह वमचारों समस्त जनता के सचक के किसी वय विनापि नहीं।

यह वमचारियों के चुनाव के संबंध में गांवजनि के वयम मन्त्राधिकारों का कारणों का जाता है।

गंगा चुनावों में मतदान गुण रखा जायेगा। विना या मतदान के द्वारा विना या चुनाव के मतदान में व्यक्तिगत या गांवजनि के रूप में बाध नहीं किया जायेगा।

नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य

अनु० 16—प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान के निराकरण, और सम्वाग्धिता के ज्ञाने, विविधा, अध्यादेना एवं अधिनियमों के अधिनियमन निरुपित एवं समायोजन, एवं अन्य विषयों के लिए शान्तिपूर्ण वाचिका का अधिकार होगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति का उस प्रकार की वाचिका का प्रयोग करने पर किसी प्रकार का अग्रगण्य नहीं समझा जायगा।

अनु० 17—उस दशा में जब किसी व्यक्ति का किसी एकर-व्यवस्थापक द्वारा अपने राज्य में ज्ञान पहुँचाई गई हो वह राज्य या प्रजा की किसी गणितन इकाई में जैसा कि विधि द्वारा विहित हो धर्म-धर्म के लिए बाध प्रस्तुत कर सकता है।

अनु० 18—किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का सम्पत्ति में नहीं रखा जायगा। कबल किम सा अग्रगण्य के दण्ड के रूप में अतिव्यक्ति के अनिवार्य अन्य अनिवार्य अतिव्यक्ति निषिद्ध है।

अनु० 19—किसी एक अतिव्यक्ति का सम्पत्ति का अतिव्यक्ति नहीं किया जायगा।

अनु० 20—धर्म के मध्य में समा की सम्पत्ति दी जाती है। किसी भी धार्मिक गणितन का राज्य का आरंभ नहीं किया जायगा, न ही उस किसी प्रकार का गणितनिक प्रभुत्व जमान का हो अधिकार होगा।

कई भी व्यक्ति किसी धार्मिक उद्यम समाराह, वम या प्रिया में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जायगा।

राज्य एक दुर्गम अथवा सम-अग्रगण्य शिक्षा अथवा अन्य किसी धार्मिक उद्यम से दूर रहेंगे।

अनु० 21—किसी एक मध्य तथा भाषण प्रेम (यन्त्राग्य) एवं अन्य प्रमाणों के प्रकारों की सम्पत्ति दी जाती है।

किसी तरह की मध्य व्यवस्था विहित न होगी और न ही मध्य के किसी प्रकार के मध्य का ही उद्घाटन किया जायगा।

अनु० 22—हर व्यक्ति का अपना निवास चुनने एवं बदलने तथा अपने व्यवसाय चुनने की उस जय पर सम्पत्ति होगी जिस अथ वह वह जन हित के विचार में नहीं जानो।

हर व्यक्ति को विदेश जाने एवं अपनी गृह्णीयता बदलने की स्वतंत्रता होगी ।

अनु० 23—मनो का धार्मिक स्वतंत्रता को गारंटी दी जाती है ।

अनु० 24—विवाह दाना दो लिंगों के पारम्परिक अभिमत पर आधारित होगा और इसका निर्वाह पारम्परिक मह्याग एवं पति-पत्नी के समान अधिकार का आधार मानने हुए किया जायगा ।

अपने जाड़े चुनने मरणा के अधिकार उत्तराधिकार, आवास चुनने, विवाह-विच्छेद तथा विवाह एवं परिवार के अन्य विषयों के मरणा में, विधियों का अनिवार्यता, व्यक्तिगत समान एवं लिङ्ग के अनिवार्य गुणों की दृष्टि से किया जायगा ।

अनु० 25—जनता का अनुसृत सुग्री एवं सम्प-समृद्ध जीवन स्तर पर जीवित प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

जीवन र हरेर क्षेत्र में राज्य के प्रयास सर्वथा सामाजिक हित, सुरक्षा एवं जनस्वाम्य के वृद्धि एवं प्रसार के लिए होंगे ।

अनु० 26—जनता का अपनी योग्यता के अनुसार, जैसा कि विधान द्वारा विहित होगा, समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

जनता को, जैसा कि विहित है, अपने लड़के-लड़कियों का संरक्षण में रखने हुए मापारण शिक्षा दिलाना अनिवार्य होगा । ऐसी अनिवार्य शिक्षा निशुल्क होगी ।

अनु० 27—जनता को काम करने का अधिकार एवं दायित्व होगा ।

बेदन, (काम करने के) घट्टी, एवं विश्राम तथा अन्य काम करने की शर्तों के मानदण्ड विधान द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

बच्चों का शोषण नहीं किया जायगा ।

अनु० 28—काम करने वालों को संगठित होने, सौदागरी एवं सामूहिक रूप से काम करने के अधिकार की गारंटी दी जाती है ।

अनु० 29 मरणा करने या उसके सम्बन्ध का जटिल अधिकार होगा ।

मरणा के अधिकारों का निर्माण, विधान द्वारा, जन-हित के अनुसार किया जायगा ।

व्यक्तिगत मरति का, जनता के उपयोग के लिए न्यायाचिन प्रतिकर देकर, लिया जा सकता है ।

अनु० 30—जनता का जैसा कि विधि द्वारा विहित होगा, कर देना पड़ेगा ।

अनु० 31—किसी भी व्यक्ति का जीवन अथवा स्वतन्त्रता या वचन नहीं लिया जायगा और न ता विधान द्वारा निर्णय प्रक्रिया के दृष्ट के अतिरिक्त अन्य ढाढ़ दृष्ट ही दिया जायगा ।

अनु० 32—किसी भी व्यक्ति का न्यायाग्या से न्याय पाने के अधिकार में वचन नहीं दिया जायगा ।

अनु० 33—किसी भी व्यक्ति पर राई मदद तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि किसी समर्थ न्यायाधिकारी द्वारा जा कि आरापिन अथवा का गविरोप निश्चित करणा राई अधिपत्र (चार्ज) न जारी किया गया हो और जयतर कि वह गविरोप न निरुद्ध हो और अपराध दिया न गया हो ।

अनु० 34—किसी भी व्यक्ति का उसके विरुद्ध लगाए गए आराप का तत्काल सूचन लिए दिना अथवा परामर्श-दाता के सरकारी विन्याधिकार के दिना न ता बन्दी दिया जा सकता है और न ता निरुद्ध दिया जा सकता है, और न ता उसे समुचित कारण के दिना ही निरुद्ध दिया जा सकता है, और किसी व्यक्ति के साथ रहने पर उक्त कारण गुने न्यायालय में तत्काल उमरी पर उसके परामर्शदाता की उपस्थिति में, अवश्य प्रकट दिया जायगा ।

अनु० 35— सभी व्यक्तियों का अपने निवास, गोपनीय वागजात एवं संपत्ति के पड़ताल, तलाशी एवं अभिग्रहण के विरुद्ध पाय का अधिकार तब तक रद्द नहीं समझा जायगा जब तक समुचित कारण पर बाई अधिपत्र न जारी हो और जिसमें विशेष रूप से उन स्थान का निर्देश न हो जिसकी तलाशी लेनी हो तथा उन वस्तुओं का भी जिनको बरामद करना हो, अथवा अनु० 33 में विहित दशाओं के अतिरिक्त हो ।

प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण किसी समर्थ न्यायाधिकारी द्वारा जारी किए गए जलग-अलग अधिपत्रों पर ही की जायेगी ।

अनु० 36—किसी भी लाश-अधिकारी द्वारा किसी तरह की पीडा या रोई दूर दृष्ट विगुल निषिद्ध है ।

अनु० 37—सभी आपराधिक अभियोगों में अभियुक्त का किसी निम्न न्यायालय में अविद्वन् न्याय पाने का अधिकार होगा।

अभियुक्त का सभी साक्षिजनों के निर्वाचन (जिग्हु) करने का अवसर दिया जायगा और उस अपने लिए राजकीय मंच पर साक्षिजनों के पाने के लिए अनिराध कायदाद्वारा का अधिकार होगा।

इस समय अभियुक्त का समर्थ परामर्शदाता की महायत्ना मिलेगी जा कि, यदि अभियुक्त अपने प्रयासों से न बच सकना तो उसमें उपयोग के लिए राज्य के द्वारा दी जायगी।

अनु० 38 किसी भी व्यक्ति का अपने विरुद्ध प्रमाण देने का बाध्य नहीं किया जायगा।

किसी भी प्रकार का बाध्यता यन्त्रणा या घमकी या लम्बे धर्दी-वरण या निर्वासन के परम्परों की सभी सम्बन्धित प्रमाण रूप में नहीं मानी जायगी।

किसी भी व्यक्ति का बँकरा उसकी सम्बन्धित के ही प्रमाण पर न ता अनिराध समझा जायगा और न कोई दण्ड ही दिया जायगा।

अनु० 39—किसी भी व्यक्ति का उस कार्य के लिए अपराधी नहीं ठहराया जा सकेगा जा कि वह जाने के समय बँध रहा है या जिसके लिए उसे दंड रही है और न ता उस दाह्य मन्त्र अवका मदह (jeopardy) में ही रखा जायगा।

अनु० 40—प्रत्येक व्यक्ति, उस दशा में जबकि वह धर्दी-वरण या निराध में मुक्त कर दिया गया है, विधान के अनुसार, निवारण के लिये मुद्रमा कर सकता है।

अध्याय 4

राज्य सभा (Diet)

अनु० 41—राज्य-सभा राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग होगा और राज्य का ऐसमात्र विधायक अंग भी।

अनु० 42—राज्य-सभा में दो मदन होंगे जिनके नाम प्रतिनिधि-मदन एवं मन्त्रिमदन होंगे।

अनु० 43 दाना सदना में सम्स्त जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य एक प्रतिनिधि रहेंगे।

प्रत्येक सदस्य के सदस्या की भाषा या निराग्रण विधान द्वारा किया जायगा।

अनु० 44 दोना सदना के सदस्या एवं उनका निर्वाचन की अहताशा या निराग्रण विधान द्वारा किया जायगा। दस सम्प्रदाय में जानि सम्प्रदाय हिन्दू, सामाजिक स्थिति बौद्धिक मूल शिक्षा वर्गनि अथवा आय व आधार पर कोई भेद नहीं किया जायगा।

अनु० 45 प्रतिनिधि-सदन के सदस्या का कार्यकाल चार वर्ष होगा पर यदि प्रतिनिधि-सदन भंग कर दिया जायगा तो वह कार्यकाल पूरा अवधि के पूरा भी रहने सम्भवा जायगा।

अनु० 46—समान-सदन के सदस्या का कार्यकाल छ वर्ष होगा और दस वर्ष अवधि सदस्या का चुनाव हर तीसरे वर्ष होगा।

अनु० 47 निराग्रण छत्र मनदान पद्धति एवं दोना सदना के चुनाव का पद्धति में सम्प्रदाय अन्य विषया का निश्चय विधान द्वारा किया जायगा।

अनु० 48—हिन्दी भी व्यक्ति का एक साथ दाना सदना का सदस्य हान की अनुमति नहीं दी जायगी।

अनु० 49 दाना सदना के सदस्या का विधानानुसार राष्ट्रीय बाप से सम्बन्धित यापित निधि दी जायगी।

अनु० 50 विधान द्वारा बिहिता दाना के अतिरिक्त दाना सदना के सदस्य राज्य-सभा के अधिवेशन की अवधि में गिरफ्तारी से मुक्त हाने और किसी भी सदस्य पर अधिवेशन के आरम्भ से की गई गिरफ्तारी से वह अधिवेशन की अवधि तक के लिए सदस्य का मौख पर मुक्त किया जायगा।

अनु० 51 दाना सदना के सदस्य सदन के भीतर शपथ पत्र पत्र लेना या पढ़ना के समय में सदन के बाहर उत्तरदायी नहीं ठहराए जायेंगे।

अनु० 52—राज्य-सभा का सामान्य अधिवेशन प्रतिवर्ष एक बार होगा।

अनु० 53—राज्य-सभा के असाधारण अधिवेशन का निर्धारण मंत्र परिषद् करगी। दाना सदनों के सदस्या की संख्या के एक चौथाई या अधिक सदस्या की मौख पर मंत्रिपरिषद् ऐसा अधिवेशन बुलाएगी।

अनु० 54—प्रतिनिधि-सदन के भंग हो जाने पर भंग होने का तिथि स चात्तम (40) दिन के अन्दर प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का एक सामान्य निर्वाचन होगा और निर्वाचन के तीस (30) दिन के अन्दर राज्य-सभा का अधिवेशन अवश्य बुलाया जायगा।

प्रतिनिधि-सदन के भंग होने पर उसका भाग्य सभासद-सदन भी दन्द कर दिया जायगा। तथापि मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रीय मन्त्रि के समस्त सभासद सदन का सक्त्वांगीन अधिवेशन बुला सकती है।

विद्युत् परिच्छेद के उपबन्ध में उल्लिखित अविवर्तन में प्रयुक्त उपाय अस्थायी होंगे और राज्य-सभा के दूसरे अधिवेशन के दस (10) दिन के अन्दर प्रतिनिधि-सदन द्वारा अनुमादित न होने पर व्यर्थ हो जायगा।

अनु० 55—प्रत्येक सदन अपने सदस्यों का अहता से सबद्ध विवादा का निणय करेगा। तथापि किसी सदस्य का उसका स्थान से बर्चित करने के लिए उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई या उससे अधिक मत द्वारा पारित प्रस्ताव आवश्यक होगा।

अनु० 56—दाना सदन में कार्यवाही तब तक नहीं प्रारम्भ की जायगी जब तक कि कुछ सदस्यों के एक तिहाई अथवा उससे अधिक सदस्य उपस्थित न हों।

प्रत्येक सदन में विषयों का निणय संविधान में अन्यत्र विहित दशांशों का छाड़ कर उपस्थित सदस्यों के बहुमत में होगा, एक-तिहाई (1/3) का छाड़कर जिनका निणय अधिष्ठाना करेगा।

अनु० 57—प्रत्येक सदन में विचारविमर्श सावजनिक रूप में होगा। तथापि गुप्त बैठक भी की जा सकेगी यदि उसमें लिए उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई या उससे अधिक सदस्य प्रस्ताव पारित करें।

प्रत्येक सदन अपना कार्यवाहिया का रंग रखा। इन रंगों का, बकर गुप्त बैठक का कार्यवाहिया के उन अंगों का छाड़कर जिनका निणय रचना आवश्यक समझा जायगा प्रमाणित एवं जन सामान्य तक प्रमाणित किया जायगा।

उपस्थित सदस्यों के 1/3 अथवा उससे अधिक सदस्यों का भाग पर किसी भी विषय पर सदस्यों के मतों का कार्यवाही के रंग में ज्विन किया जायगा।

अनु० 68—राज्य के मन्त्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा तथापि उसकी कुछ मर्यादा का अधिपान राज्य-सभा के सदस्यों में से चुना जायगा।

प्रधान मंत्री राज्य के मन्त्रियों का तैय्य चुन सकता है वेम ही उन्हें नियोजन भी कर सकता है।

अनु० 69—यदि प्रतिलिपि-मदन राष्ट्र अधिवेशन का प्रस्ताव पारित करता है अथवा किसी विधायक व प्रस्ताव का रद्द करना है तो मन्त्रिपरिषद् मामूली रूप से ग्राह्यता दे देगी। यदि हम (10) दिन के अन्दर प्रतिलिपि-मदन विपक्षित न है। जाय।

अनु० 70—प्रधान मंत्री का पद रिक्त होने पर अथवा प्रतिलिपि-मदन के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के बाद राज्य सभा व प्रथम सभापति पर मन्त्रिपरिषद् मामूली रूप से जायता दे देगी।

अनु० 71 रिक्त दा अनुच्छेदों में उल्लिखित दशांशों में मन्त्रिपरिषद् उस समय तक अपना कार्य करना शुरू करेगा कि नया प्रधान मंत्री नियुक्त नहीं हो जाता।

अनु० 72 मन्त्रिपरिषद् के प्रतिलिपि के रूप में प्रधान मंत्री विदेश प्रस्तुत करेगा, सामान्य राष्ट्रीय विषयों पर राज्य सभा व बाह्य मन्त्रियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा तथा अन्य प्रशासनिक विभागों का नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण करेगा।

अनु० 73 अन्य सामान्य प्रशासनिक कार्यों के साथ ही मन्त्रिपरिषद् का निम्नलिखित कार्य करने हाने

अध्यापक विधानों का निष्पादन करना राज्य के कार्यों का मन्त्रित्व करना।

विदेशी विषयों का प्रत्यक्ष करना।

मन्त्रियों का नियुक्त करना, विन्तु इन विषयों में राज्य-सभा (1)(1) का पद है, अथवा परिस्थितियों व अनुसार बाद में अनुमति आवश्यक है।

विधि द्वारा निर्धारित मानदण्डों व अनुसार पर (1)(1) मन्त्रियों का नियोजन करना।

राज्य-सभा के कार्य करना एवं उन राज्य-सभा के मन्त्रों प्रस्तुत करना।

अनु० 62—प्रत्येक मदन सरकार के संबंध में जाच-भडताल कर सकता है और साक्षियों की उपस्थिति एवं प्रमाण की मांग कर सकता है तथा लिखित प्रमाणों का प्रस्तुत करने की भी मांग कर सकता है ।

अनु० 63—प्रधान मंत्री एवं राज्य के अन्य मंत्री, चाहे वे सदन के सदस्य हों या न हों किसी भी समय किसी भी सदन में विधेयका पर बोलने के लिए जा सकते हैं । उत्तर अथवा स्पष्टीकरण देने के लिए जब उनकी उपस्थिति अपेक्षित हो तो उन्हें अवश्य उपस्थित होना पड़ेगा ।

अनु० 64—राज्य-सभा उन न्यायाधीशों के अभियोगों के निर्णय के लिए जिनके विरुद्ध पदच्युत करने की कार्यवाही की जा चुकी हो दाना सदन के सदस्यों में से एक महाभियोग-न्यायालय का गठन करेगी ।

इस प्रकार के महाभियोगों से संबंध विषयों की व्यवस्था विधि द्वारा की जायेगी ।

अध्याय 5

मन्त्रि-परिषद्

अनु० 65—कार्यकारी शक्ति मन्त्रिपरिषद् में निहित होगी ।

अनु० 66 मन्त्रिपरिषद् में राज्य के अन्य मंत्री एवं उनके अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री रहेंगे जैसा कि विधि द्वारा विहित होगा ।

प्रधान मंत्री एवं राज्य के अन्य मंत्री मिलिलियन (फौजी में भित) रहेंगे ।

कार्यकारी शक्ति के संचालन (प्रयोग) में मन्त्रिपरिषद् राज्य सभा के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी होगी ।

अनु० 67 राज्य-सभा के एक प्रस्ताव द्वारा राज्य-सभा के सदस्यों में से प्रधानमंत्री का पदनामित किया जायेगा । यह पदनाम अन्य सभी कार्यों में पद रहेंगे ।

यदि प्रतिनिधि-एवं सभामुद्-मदन एवमत्र नहीं हों और यहाँ तक कि दाना सदन की समिति बैठक में भी कोई निर्णय नहीं हो पाता, जैसा कि विहित है, अथवा सभामुद्-मदन, प्रतिनिधि-मदन के पदनाम देने के दस (10) दिनों के अन्दर अवकाश का छाटकर, यदि पदनाम देने में असमर्थ रहे तो प्रतिनिधि-मदन का निर्णय राज्य-सभा का निर्णय माना जायेगा ।

अनु० 68—राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा तथापि उनकी कुल मर्यादा का अधिपति राज्य-सभा के सदस्यों में से चुना जायगा ।

प्रधान मंत्री राज्य के मंत्रियों का जैसे चुन सकता है वैसे ही उन्हें तिराज भी करता है ।

अनु० 69 यदि प्रतिनिधि-मदन कोई अविद्यास का प्रस्ताव पेश करता है अथवा किसी विद्यास के प्रस्ताव का खूद करता है तो मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देगी यदि दण (10) दिन के अन्दर प्रतिनिधि मदन विपक्षित न हो जाय ।

अनु० 70 प्रधान मंत्री का पद रिक्त होने पर अथवा प्रतिनिधि-मदन के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के बाद राज्य सभा के प्रथम सम्मेलन पर मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देगी ।

अनु० 71 पिछले दस अर्धशताब्दी में उत्पन्न दशाब्दा में मन्त्रिपरिषद् उस समय तक अपना काम करती रहेगी जरायु कि नया प्रधान मंत्री नियुक्त नहीं हो जाना ।

अनु० 72 मन्त्रिपरिषद् के प्रतिनिधि के रूप में प्रधान मंत्री विशेषतः प्रस्तुत होगा, सामान्य राष्ट्रीय विषयों एवं राज्य सभा के बाह्य मंत्रियों का प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करेगा तथा अन्य प्रधानमन्त्री विभागों का नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण करेगा ।

अनु० 73 अन्य सामान्य प्रधानमन्त्री कार्यों के साथ ही मन्त्रिपरिषद् का निम्नलिखित कार्य करने हाने

श्रद्धापूर्वक विद्या का नियोजन करना राज्य के कार्यों का संचालन करना ।

विदेशी विषयों का प्रत्यक्ष करना ।

मधिया का निश्चय करना किन्तु इन विषयों में राज्य-सभा (House) का पद है ही, अथवा परिस्थितियों के अनुसार बाद में अनुमति आवश्यक है ।

विधि द्वारा निर्धारित मादकता के अनुसार छात्र (1911) संस्था का नियोजन करना ।

आयव्यय तैयार करना एवं उस राज्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करना ।

प्रस्तुत संविधान एक विधि की व्यवस्थाओं के निष्पादन के लिए मंत्रिमण्डल के आदेशों के अधिनियमित करना। तथापि मंत्रिमण्डल के ऐसे आदेशों में बिना दायित्व व्यवस्थाओं का तब तक समावेश नहीं होगा जब तक कि वे उक्त प्रकार के विधि द्वारा प्राविष्ट न हों।

सामान्य राज्य-क्षमा दण्ड का उद्धारण अधिकारों का प्रतिगमन एक प्रयावतन आदि का निषेध करना।

अनु० 74—जबो विधिया एक मंत्रिमण्डल के आदेशों पर राज्य के समक्ष मंत्रियों के हस्ताक्षरों तथा एक प्रधान मंत्री का प्रतिहस्ताक्षर होगा।

अनु० 75—राज्य के मंत्रियों पर अपने कार्यक्षेत्र के बाह्य भाग वैधानिक कार्यवाही प्रिना प्रधान मंत्री का समक्ष के न्यायाधीशों के द्वारा उक्त कार्यवाही करने के अधिकार का आहरण नहीं होगा।

अध्याय 6

न्यायपालिका

अनु० 76—यदि विषय के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में तथा उन अन्तर न्यायालयों में निहित है जो विधि द्वारा सम्पादित हों।

न्यायाधीशों का असाधारण न्यायाधिकारण (Extraordinary tribunal) स्थापित नहीं किया जायेगा और न ही न्यायपालिका के निम्न अंग या अधिकारण का ही सर्वोच्च न्यायाधीश गति दी जायेगा।

जब न्यायाधीशों के अन्तर्निर्देश के साथ करने के स्वतन्त्र रूप और उन पर अन्य संविधान एक विधियों के अधिनियमित हों।

अनु० 77—विधायिका गति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है जिसमें वह प्रक्रिया एक व्यवहार के तथा न्यायपालिका के सम्बद्ध मामलों, न्यायालयों के आतन्त्रिक अनुगमन एवं न्यायिक विषयों के प्रशासन के सम्बद्ध नियमों का निराकरण होगा।

राज-समाजों सर्वोच्च न्यायालय की विधायिका गति के अधिनियमित हों।

सर्वोच्च न्यायालय जय न्यायालयों के अन्तर न्यायालयों के लिए नियम बनाने के अधिकार प्राप्त करने हैं।

अनु० 78 जनता द्वारा लगाए हुए महाभियोग की स्थिति का छाड़कर, न्यायाधीश तब तक नहीं हटाए जा सकते जब तक कि वे न्यायालय द्वारा मानविर अथवा शारीरिक रूप से अक्षम नहीं घोषित किए जायें। न्यायाधीशों के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही किसी भी कार्यपालिका के अंग अथवा अभिभरण द्वारा नहीं की जा सकती।

अनु० 79 सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश एक उत्तर और न्यायाधीश रहेंग जिनमें विधान द्वारा नियमित किए जाएंगे। प्रधान न्यायाधीश के अनिवार्य अन्य सभी न्यायाधीशों का सचिव-परिषद नियुक्त करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों के पक्ष सामान्य निर्वाचन के अवसर पर उत्तरा नियुक्ति के बाद, जनता द्वारा पुनर्निर्वाचन किया जायगा और प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों के प्रथम सामान्य निर्वाचन के अवसर पर दस (10) वर्ष बाद पुनः पुनर्निर्वाचन किया जायगा तथा दस वर्ष बाद से भी किया जायगा।

विच्छेद परिच्छेद में उल्लिखित दशा में यदि मतदानांश का बहुमत किसी न्यायाधीश की पदच्युति के पक्ष में है तो वह पदच्युत कर दिया जायगा।

पुनर्निर्वाचन से शरद्ध विषय विधान द्वारा विहित होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश विधान द्वारा निर्दिष्ट आयु तक पहुँच जाने पर निवृत्त कर दिए जाएंगे।

एक सभी न्यायाधीशों का नियमित अन्तर पर समुचित प्रतिहर मिलेगा जो कि उत्तर कार्यवाही से कम नहीं किया जायगा।

अनु० 80—अब न्यायाध्या के न्यायाधीशों की नियुक्ति सचिव परिषद द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित ध्वनिका की नियमावली के से किया जायगा। ऐसे सभी न्यायाधीशों दस (10) वर्ष की अवधि तक कार्यभार वहन करेंगे, के दस वर्ष बाद भी नियुक्त हो सकेंगे यदि वे विधान द्वारा नियत आयु पर निवृत्त कर दिये जायें।

अब न्यायाध्या के न्यायाधीश नियमित अन्तर पर समुचित प्रतिहर पार्लेमेंट और वह उनके कार्यभार के अन्तर घटाया नहीं जायगा।

अनु० 81—किसी विधि आदेश नियम या आधिकारिक कार्य की सावित्रानित्ता के निर्धारण में सर्वोच्च न्यायालय ही अन्तिम आशय का समर्थ न्यायालय है।

अनु० 82—विचारणो (trial) का संचालन एवं निर्णय की घोषणा मार्जनिन क्ल में की जायगी। जब कोई न्यायालय इनके प्रचार को एकमत से मार्जनिन व्यवस्था अथवा नैतिक आचार के लिए घातक घोषित करे, उस देश में सर्ट भी न्यायिक विचारण गुप्त रीति में किया जा सकता है, किन्तु राजनीतिक अपराधों के अथवा पन्थालय में भवद्व अपराधों के विचारण में अथवा उन अभियोगों में जिनमें हिंडम मविधान के अध्याय 3 में नमूद जन्तों व अतिराग का प्रश्न है विचारण मार्जनिन क्ल में किया जायगा।

अध्याय 7

वित्त

अनु० 83—राष्ट्रिय वित्त का प्रशासन करने की शक्ति का प्रयोग राज्य-सभा के निर्णयों व अनुसार होगा।

अनु० 84—निम्ना विधान के अनुसार नए कर लगाए जा सकते हैं और न पुनर्गठन के पश्चात् वित्त किया जा सकता है, अथवा ऐसी दशाओं में, जैसा विधान द्वारा निर्दिष्ट है, किया जायगा।

अनु० 85—राज्य-सभा द्वारा प्रातिष्ठित हुए बिना राज्य द्वारा न तो कोई धन शक्ति व्यय की जा सकती है और न तो राज्य अनिवार्य रूप से उसका उपयोग ही कर सकता है।

अनु० 86—मन्त्रिपरिषद् प्रत्येक राजवित्तीय वर्ष के लिए आयव्यय तैयार करेगी तथा उस पर विचार एवं निर्णय के लिए राज्य-सभा का प्रस्तुत करेगी।

अनु० 87—आयव्यय में अदृष्ट कमियाँ को पूरा करने के लिए राज्य-सभा द्वारा एक आगक्षित निधि की व्यवस्था की जायगी। वा मन्त्रिपरिषद् के दायित्व पर खर्च की जायगी।

आगक्षित निधि में न किये जाने वाले सभी भुगतानों के लिए मन्त्रिपरिषद् का सदन में राज्य-सभा से स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

अनु० 88—राज-परिषद् की समस्त संपत्ति राज्य की संपत्ति होगी।

राज-परिषद् के सभी व्ययों का नियोजन राज्य सभा द्वारा आयव्यय में किया जायगा।

अनु० 89 —किसी भी गावजनिब द्रव्य या अथ संपत्ति का विनिर्माण या ध्वज किसी धार्मिक संस्था या मठ के उपयोग लाभ या संचारण के लिए अथवा किसी धर्माथ गिना-मवधी अथवा परंपरापर विषयव उद्योग के लिए जा लाय प्राधिकरण के नियंत्रण में न हो नही किया जा सकता ।

अनु० 90 राज्य के व्यय एवं आय (राजस्व) के अंतिम एकाग्रता का कृपा गरी राज प्रतिवर्ष एक लेखा परीक्ष मण्डल द्वारा किया जायगा और मन्त्रि परिषद द्वारा राज्य विनाय वष के अन्तर्गत परीक्षण के विवरण के साथ उस समय के राज बाज जव तब का वह गरी का राज्य मन्त्रा को प्रस्तुत किया जायगा ।

राज परीक्षण-मण्डल के संगठन एवं सामयिक का निर्धारण विधान द्वारा किया जायगा ।

अनु० 91 कुछ नियम अन्तर्गत पर और कम-स-कम प्रतिवर्ष मन्त्रि परिषद गण्ट्राय मन्त्रस्व को स्थिति के विवरण में राज्य-सभा एवं जनता को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करेगा ।

अध्याय 8

स्थानीय स्वायत्त शासन

अनु० 92 —स्थानीय शासनका संरक्षण एवं कार्य करने के नियमों का निश्चय विधान द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन सिद्धांतों के अनुसार किया जायगा ।

अनु० 93 —स्थानीय शासनका विधानानुसार सभाओं को स्थापना अपने विचार विमर्श एवं बातें अथ के रूप में करेगा ।

सभा स्थानीय शासनकाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों उनकी सभाओं के मन्त्रियों तथा उन स्थानीय कमचारियों के जो विधान द्वारा नियमित किए जाय निर्वाचन उनके विभिन्न समुदायों में प्रयोग मतदान द्वारा होगा ।

अनु० 94 —स्थानीय लोक सभाओं का अपनी संपत्ति अपने विविध विषयों एवं प्रशासन के प्रवृत्ति करने तथा विधान के अंतर्गत अपने निजी नियमों का अतिनियमित करने का अधिकार होगा ।

अनु० 95—एक स्थानीय लोक-सभा में लागू होने वाले किसी भी विशेष विधान को जो विधि-मन्त्र पाया गया है उस स्थानीय लोक-सभा के मत-दाताओं के बहुमत द्वारा प्राप्त अनुमोदन के बिना राज्य-सभा द्वारा अधिनियमित नहीं किया जा सकता।

अध्याय 9

संशोधन

अनु० 96—इस संविधान में संशोधन का सूत्रपत्र राज्य-सभा द्वारा दोनों सदनों के कुल सदस्यों के द्वा-विहाइ या इसमें अधिक सदस्यों के सम्मिलित मतदान से किया जायगा और तब वह मर्यादित के लिए जनता का प्रस्तुत किया जायगा। इस मर्यादित के लिए एक विशेष जनमत-संग्रह का, अथवा निर्वाचन के अवसर पर जैसा कि राज्य-सभा निश्चय करे, कुल मत के बहुमत का सकारात्मक मत अपेक्षित है।

इस प्रकार से मर्यादित या अनुमोदित संशोधन तत्काल सम्राट् द्वारा जनता के नाम से संविधान का अभिन अंग घोषित कर दिया जायगा।

अध्याय 10

सर्वोच्च विधि

अनु० 97—जापान की जनता के लिए प्रत्याभूत (guaranteed) मानव के मूल अधिकार उसके उम्र स्वतन्त्रता-समर्प के प्रतिपद हैं जिसे वह युगान्तरों में करना पड़ा आ रहा था। ये अधिकार अनेक चिरम्यायिता की यथार्थ कमीष्टियाँ पर खरे उतरे हैं। अब इन्हें वर्तमान एवं भविष्य में होने वाली पीढ़ियों का इस विश्वास के साथ प्रदान किया जाता है कि जापान का मानव इन्हें सर्वदा अक्षुण्ण बनाए रखेगा।

अनु० 98—प्रस्तुत संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च विधान होगा जिसमें समस्त किसी भी विधि, अध्यादेश, सम्राट् की घोषणा या अन्य सरकारी अधिनियम या उसका अंग का, या इसकी व्यवस्थाओं के विरुद्ध होगा, विधि-युक्त या मान्यता नहीं प्राप्त होगी।

जापान द्वारा की गई अधिकांश एवं राष्ट्र के प्रतिष्ठापित विधानों का धृढ़-पूर्वक अनुशासन किया जायगा।

अनु० 99—सम्राट अथवा राजप तथा राज्य क सभा मंत्रिया राज्य सभा क मदस्या यापाधीन तथा अथ सभा लाक-कर्मचारिया का इस सविधान क प्रति समुदर ग्यन एव इसका मयादा बनाए रखन का वाध्यता होगी ।

अध्याय 11

अनुसूचक उपसन्ध

अनु० 100—प्रास्थापित करन का निधि स छ (6) मास का अवधि क बाद यह सविधान प्रवर्तित होगा ।

प्रमन सविधान क प्रवर्तन क गि आवश्यक विधिया क अधिनियमन सभासद मदन क मदस्या क निवाचन राज्य-सभा क समाराह का प्रशिया तथा इस सविधान क प्रवर्तन क लिए अथ प्रारम्भिक प्रशियाभा का विच्छ परिच्छेद में रिक्ति निधि क पूर निष्पन्न किया जायगा ।

अनु० 101—यदि इस सविधान क अनुसार समारम्भ निधि क पूर सभासद मदन का संगठन नहीं हो जाता तो प्रतिनिधि-मदन राज्य-सभा के रूप में तत्काल कार्य करना रहेगा जब तक कि सभासद मदन का संगठन नहीं हो जाता ।

अनु० 102—इस सविधान क अन्तगन पहला अवधि में कार्य करत हुए सभासद मदन क जाय मदस्या का कार्यकाल तान क्य होगा । इस कालि क अन्तगन शान का मदस्या का निराग्न विधि द्वारा किया जायगा ।

अनु० 103—इस सविधान का समारम्भ निधि पर अपना कार्य करत हुए राज्य क मंत्री-गण प्रतिनिधि-मदन क मन्स्य एव यापाधीन तथा अथ सभा लाक-कर्मचारी जा तस यदा के गवद यदा पर हो जा सविधान द्वारा मायना शान्त हो स्वन इस सविधान क प्रवर्तित होन पर अपन पद से च्युत नहा हगें जब तक कि विधान द्वारा उनका अथवा उत्सन्न न किया जाय किन्तु जब उनका उत्तराधिकारी इस सविधान की व्यवस्थाभा के अनुसार निवाचन या नियुक्त हो जायगें तब वस्तुन उन्हें अपना पद त्यागना पनेगा ।

दण्ड संहिता

(1921 के विधि क्र० 77 1941 के विधि क्र० 61 एवं 1947 के विधि क्र० 124 द्वारा संशोधित 1907 का विधि क्र० 45)

पहला खण्ड—सामान्य उपबन्ध

अध्याय 1

विधियों के विनियोग (प्रयुक्ति)

अनु० 1—यह विधि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगी जिन्होंने जापान राज्य की सीमा के अन्तर्गत कोई अपराध किया है।

यह उन सभी व्यक्तियों पर भी लागू होगी जिन्होंने जापान राज्य के बाहर भी किसी जापानी जहाज पर चढ़े हुए अपराध किया है।

अनु० 2—यह विधि उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जिन्होंने जापान की सीमा के बाहर निम्नांकित अपराधों में किसी का किया हो

- (1) निर्मित ,
- (2) 77 से 79 तक के अनुच्छेदों में उल्लिखित अपराध ,
- (3) अनु० 81, 82, 87 और 88 में उल्लिखित अपराध ,
- (4) अनु० 148 में उल्लिखित अपराध एवं उमका प्रयत्न ,
- (5) अनु० 154, 155, 157 और 158 में उल्लिखित अपराध ,
- (6) अनु० 162 एवं 163 में उल्लिखित अपराध ,
- (7) अनु० 164 से 166 में उल्लिखित अपराध एवं अनु० 164 के परिच्छेद 2, 165 के परि० 2 तथा 166 के परि० 2 में उल्लिखित अपराधों के प्रयत्न ।

अनु० 3—यह विधान उन सभी जापान राष्ट्र के निवासियों पर लागू होगा जिन्होंने जापान की सीमा के बाहर निम्नांकित में से कोई अपराध किया हो

- (1) अनु० 108 एवं अनु० 109 के परि० 1 में उल्लिखित अपराध , अनुच्छेद 108 एवं अनु० 109 परि० 1 के अनुसार व्यवहृत किए जाने वाले अपराध एवं उनके प्रयत्न ,

(2) अनु० 119 में उल्लिखित अपराध

(3) अनु० 159 से 161 तक के अनुच्छेदों में उल्लिखित अपराध

(4) अनु० 167 में उल्लिखित अपराध एवं उक्त अनुच्छेद व परि० 2 में उल्लिखित अपराध प्रत्येक

(5) अनु० 176 से 179 181 और 184 में उल्लिखित अपराध

(6) अनु० 199 एवं 203 में उल्लिखित अपराध एवं उनके प्रत्यक्ष,

(7) अनु० 204 एवं 205 में उल्लिखित अपराध

(8) अनु० 214 से 216 में उल्लिखित अपराध

(9) अनु० 218 में उल्लिखित अपराध तथा उक्त अपराध के करने में किसी व्यक्ति का मार डालने या घायल कर देने का अपराध

(10) अनु० 220 एवं 221 में उल्लिखित अपराध

(11) अनु० 224 से 228 में उल्लिखित अपराध

(12) अनु० 230 में उल्लिखित अपराध

(13) अनु० 235 236 238 से 241 और 243 में उल्लिखित अपराध,

(14) अनु० 246 से 250 में उल्लिखित अपराध

(15) अनु० 2-3 में उल्लिखित अपराध

(16) अनु० 256 परि० 2 में उल्लिखित अपराध ।

अनु० 4 यह विधान उन सभी जापानी लाक-अस्त्रधारियों पर लागू होगा जिन्होंने निम्नांकित में से किसी अपराध का जापान की सीमा के बाहर किया है।

(1) अनु० 101 में उल्लिखित अपराध एवं उसका प्रत्यक्ष

(2) अनु० 156 में उल्लिखित अपराध

(3) अनु० 193 अनु० 195 परि० 2 और अनु० 179 से 197—(3) में उल्लिखित अपराध एवं अनु० 195 परि० 2 में उल्लिखित अपराध के द्वारा किसी व्यक्ति का मार डालने अथवा घायल करने का अपराध ।

अनु० 5—चाहे किसी भी देश में कोई अटल निषेध भले हो दिया गया हो। उमम जापान में उसके लिए कोई दण्ड बाधित नहीं होगा। तथापि यदि अपराधी विदेश में घातित दण्ड का अथवा अथवा पूर्णतः निषादिन कर चुका हो तो

जापान में उम्र ६५ वर्ष का नए नए कर दिया जायगा या कम छुट दिया जायगा ।

अनु० 6—यदि त्रिमा अणुगत्र व उग्न व वाद मया दण् विधान द्वारा
वदन् त्रिमा गया ना ना जा ग्घु दण् हागा वदा गग हागा ।

अनु. 7—इमं त्रिषानं म गच्छ यमचारा पदं स मर्यादा यमचारिया
गच्छ-यमचार्या मभाजा एव समितिया क मदम्या तथा अय गंगा या ना
जा जन गाधारण क कार्या म विधिया एव अद्यादगा क अनुमात्र एव ह्ये हा
दात्र गंगा ।

गिर कीयाग्य पद ग ग्न म्याना वा ममला जायगा उहाँ गिर-बमचारा
 अपना शाय उरग ।

अनु ४—यस विधान र सामान्य व्यवस्था रन अभियोग (अपराध) र सत्य र नर ताम ताम जिनर ताम ताम अथ विधिया या आदना द्वारा रिस्ति र। ताम ताम ताम का उन्तर ताम ताम विधिया या आदना द्वारा वर ताम रिस्ति र।

अध्याय 2

दण्ड

अनु० १—प्रधान दण्डः—प्राण-दण्डः कटाक्षमरागयाम वागवाम
अथदण्डः शस्त्रि निग्राह तया ग्धु ए दण्डः गज्यगानरुण एव अनिग्नित
दण्डः ।

अनु० 10—प्रधान दण्ड का माप । शस्त्रा पिछा अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रम माप का पक्का आजायन वागवायन भासित कठारथमसागत्राम म तथा गामिन रागत्राम भा भासित कठारथमसागत्राम म गुह्यतर जाया यदि पक्का का चरम अर्थात् दूसरा का चरम अवधि म दण्डा अर्थात् १ ।

गमान प्रसार व शब्दों में ता जितना अधिक चरम अवधि या अधिक चरम गति आता है वृत्तवत् आता । यदि चरम अवधि एवं चरम गति प्रसार में ता जितना यत्नतम अवधि या यत्नतम गति अधिक आता वृत्तवत् माना जायगा ।

ऐसा व्यक्ति जो पूरे लघु अर्धदण्ड का देने में असमर्थ होगा उन्हें किसी कमशाला में कम से कम एक दिन और अधिक में अधिक तीन दिन तक रखा जायगा।

उम दशा में जबकि दो या उससे अधिक अर्धदण्ड सामूहिक रूप में लगाए गए हैं या बड़े अर्धदण्ड या छोटे अर्धदण्ड साथ लगाए गए हैं तो उक्त निरोध की अवधि तीन वर्षों में अधिक नहीं की जा सकती। उम दशा में जबकि दो या अधिक छोटे अर्धदण्ड साथ लगाए गए हों, निरोध की अवधि पाठ दिन से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती।

जब कोई बड़ा या छोटा अर्धदण्ड लगाया गया है तो तेज बड़े या छोटे अर्धदण्ड या पूर्णतः देने में असमर्थ होने की दशा में निरोध की अवधि भी साथ ही निर्धारित एवं धारित कर दी जायगी।

समस्त पक्ष की राय के बिना बड़े अर्धदण्ड के लिए निरोध निर्णय के अटल है जाने के तमाम दिन के अन्दर तथा छोटे अर्धदण्ड के लिए दस दिन के अन्दर प्रवर्तित नहीं किया जा सकता।

जब कोई व्यक्ति जिस पर बड़ा या छोटा अर्धदण्ड लगाया गया हो तथा उसने उसका कुछ भाग चुका दिया हो तो वह पूरी अवधि के उम दीर्घ अथवा निरोध में रखा जायगा जितना कि पूरी निरोध-अवधि में उसने दिए गए धन के अनुपात में दिना की सम्म्या घटाने में योग बनेगा।

निरोध-अवधि के अन्तर्गत की गई भूयतान में चाली दिनों में नौ दिनों की सम्म्या उमी अनुपात में घटाई जायगी जैसा कि विच्छेद परिच्छेद में उल्लिखित है।

ऐसी राशि जमा नहीं है मोगी जो एक भी दिन के निरोध के अनुपात में न हो (अर्थात् निरोध की पूरी अवधि के दिना में न एक दिन पर जो अर्धदण्ड आता है उममें भी कम अर्धदान स्वीकार नहीं किया जायगा)।

अनु० 19—निम्नांकित वस्तुओं का राज्यमातृगण किया जा सकता है :

- (1) वे वस्तुएँ जो आपराधिक कर्म की घटक रही हैं,
- (2) वे वस्तुएँ जिनका किसी आपराधिक कर्म में प्रयोग या प्रयोग करने का प्रत्यक्ष रहा है,

जापान का संविधान

अनु० 24—दण्ड भोगने का पहला दिन चाहे किसी घंटे में भोगना शुरू किया जाय पूरे एक दिन के रूप में परिगणित किया जायगा। यही नियम भोगाधिकार की अवधि के पहले दिन के मकसद में भी लागू होगा।

दण्ड की अवधि के पूरे होने बाद दिन के बाद वाले दिन निर्मुक्ति का निष्पादन किया जायगा।

अध्याय 1

दण्ड के निष्पादन का निलम्बन

अनु० 25—यदि निम्नलिखित व्यक्तिता में में किसी को कठोरश्रम-कारावास या कारावास का दण्ड मिल चुका हो जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक न हो या अपेक्षित जा 5,000 येन से अधिक न हो तो ऐसे दण्ड का निष्पादन, निर्णय के दिन से परिस्थितियों के अनुकूल, कम-से-कम एक वर्ष तथा अधिक-से-अधिक पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए निलम्बित किया जा सकता है।

- (1) ऐसे व्यक्ति जिन्हें पहले कारावास या कोई बठिन दण्ड न मिला हो,
- (2) ऐसे व्यक्ति जिन्हें यद्यपि पहले कारावास या कोई बठिन दण्ड मिल चुका हो किन्तु उस पूर्व दण्ड के निष्पादन के पूर्ण होने या क्षमा किये जाने की तिथि से मान वर्ष के अन्दर कोई कारावास या बठिन दण्ड फिर न मिला हो।

अनु० 26—अर्थात्लिखित दशाओं में दण्ड के निष्पादन का निलम्बन प्रतिमहूत किया जा सकता है।

- (1) जबकि निम्बन की अवधि के अन्तर्गत कोई अन्य अपराध किया गया हो और उसके लिए कारावास या कोई और बठिन दण्ड दिया गया हो,
- (2) जबकि दण्ड-निष्पादन के निम्बन की घोषणा के पूर्व किए गए अपराध के लिए कारावास या कोई और बठिन दण्ड दिया जा चुका हो,

- (3) पिछले अनुच्छेद के प्रभाग (2) में उल्लिखित व्यक्ति के अनिरित्त, जब यह पता चल जाय कि उस व्यक्ति का, दण्ड-निष्पादन के निम्बन्धन की घोषणा के पहले किसी अन्य अपराध के लिए वाग्विश्वास या कोई कठिन दण्ड मिला था।

जब निलम्बन की अवधि के अन्दर कार्ड और अपराध किया गया है और उसके लिए कार्ड अर्पण दिया गया है या दण्ड निष्पादन के निम्बन्धन की घोषणा प्रतिमहान की जा सकती है।

अनु० 27 -जब दण्ड निष्पादन के निम्बन्धन की अवधि निम्बन्धन की घोषणा के प्रतिमहान के बिना ही चल जाय या दण्ड की घोषणा प्रभावशून्य हो जायगी।

अध्याय 5

कारागार से सामयिक निर्मुक्ति (वाग्विश्वास)

“करिडुल्मुगोकु”

अनु० 28— यदि कार्ड कठान्त्रम-कारागार या वाग्विश्वास में दण्डित व्यक्ति सुधार के सर्वेक्षण प्रकट करे तो प्रशासनिक अधिकारियों की कारवाही द्वारा, दण्ड की अवधि मीमित होने पर उसका एक तिहाई एवं आश्रयन रहने पर दस वर्ष भोग लेने पर, कारागार से सामयिक (कुछ गतों पर) निर्मुक्ति दी जा सकती है।

अनु० 29—कारागार से सामयिक निर्मुक्ति की वाग्विश्वास अधिनियम दण्डों में प्रतिमहान कर दी जायगी।

- (1) जबकि सामयिक निर्मुक्ति की दशा में कार्ड और अपराध किया गया है और कार्ड अर्पण या कठिन दण्ड दिया गया है,
- (2) जबकि सामयिक निर्मुक्ति के पहले किए गए अन्य किसी अपराध के लिए कार्ड अर्पण या और कठिन दण्ड दिया गया है,
- (3) जबकि व्यक्ति का कार्ड जयदण्ड या कठिन दण्ड भुगवता है या कि उसे सामयिक निर्मुक्ति के पूर्व किसी अन्य अपराध के लिए दिया गया था,
- (4) जबकि सामयिक निर्मुक्ति के नियन्त्रण विषयक विनियम अनिलपित हो गए हों।

सामयिक निर्मुक्ति की कार्रवाई के प्रतिसहृत किये जाने की दशा में कारागार व बाहर बिताए गए दिना का दण्ड की अवधि में सम्मिलित नहीं किया जायगा ।

अनु० 30—दाण्डिक निराय स दण्डित व्यक्ति का परिस्थितिया के अनुसार किसी भी समय प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई द्वारा सामयिक रूप में निमुक्त किया जा सकता है ।

यही नियम उन व्यक्तियों के विषय में भी लागू होगा जो किसी बड़े या छोटे अथदण्ड का पूर्णतः देने में असमर्थ होने व फलस्वरूप निराय स रहे गए हों ।

अध्याय 6

दण्ड का भोगाधिकार एवं उमकी समाप्ति

“जिको”

अनु० 31—किसी दण्ड में दण्डित व्यक्तियों का उस दण्ड के निष्पादन में भागाधिकार द्वारा अवमुक्त किया जायगा ।

अनु० 32—यह भागाधिकार उस समय पूरा होगा जबकि दण्ड की अन्तिम नियम का विधि स निम्नांकित अवधि के अन्तर्गत दण्ड का निष्पादन न किया गया हो

- (1) मृत्युदण्ड के लिए, तीन वर्ष,
- (2) आजीवन कठोरश्रम-कारावास या आजीवन कारावास के लिए, दस वर्ष,
- (3) मौमित कठोरश्रम-कारावास या मौमित कारावास के लिए, पन्द्रह वर्ष यदि अवधि दस वर्ष या उससे अधिक हो, दस वर्ष, यदि अवधि तीन वर्ष या उससे अधिक हो, पाँच वर्ष, यदि अवधि तीन वर्ष से कम हो,
- (4) बड़े अथदण्ड के लिए, तीन वर्ष,
- (5) दाण्डिक निराय, छोटे अथदण्ड एवं राज्यमात्सर्य के लिए, एक वर्ष ।

अनु० 37—जीवन, शरीर, स्वतन्त्रता या अपनी अथवा दूसरों की संपत्ति के प्रति उपस्थित खतरा का हटाने के लिए किए गए अनिवार्य कार्य दण्डनीय नहीं होंगे यदि उन कार्यों द्वारा पहुँचाई गई क्षति, होने वाली क्षति से अधिक न हो। तथापि, परिस्थितियों के अनुसार, ऐसे कार्यों के दण्डों को, जिनमें होने वाली क्षति से उक्त कार्यों द्वारा की गई क्षति अधिक हो, हल्का अथवा क्षमा किया जा सकता है।

विच्छेद परिच्छेद की व्यवस्थाएँ (उपबन्ध) उन व्यक्तियों के संबंध में लागू नहीं होगी जो अपनी जीविका या व्यवसाय के कारण किसी विशेष दण्डन के अन्तर्गत हैं।

अनु० 38—बिना आशय के किए गए अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को दण्डित नहीं किया जायगा परन्तु यह उस दशा में लागू नहीं होगा जहाँ कि किसी विधि में कोई विशेष व्यवस्था उसके विरुद्ध है।

उस दशा में जब कि किसी व्यक्ति का, जिसने अपराध किया हो, अपराध करते समय यह ज्ञात न रहा है कि जो अपराध वह कर रहा है वह उमरे मोचे गए अपराध से गुन्नाह है ता उसे उमरे गुन्नाह अपराध के लिए दण्डित नहीं किया जायगा।

विधि की व्यवस्था की अनभिज्ञता के बल पर किसी व्यक्ति को अपराध करने के आशय से दण्ड नहीं माना जायगा। तथापि, इस दशा में परिस्थिति के अनुसार, दण्ड कम किया जा सकता है।

अनु० 39—अविवेकी व्यक्तियों के कार्य दण्डनीय नहीं होंगे। निर्बल मन वाले व्यक्तियों द्वारा किये गए अपराध-कृत्यों के दण्डों का हल्का कर दिया जायगा।

अनु० 40—मूक बधिरा के कार्य दण्डनीय नहीं होंगे अथवा दण्डित होने पर उनका दण्ड हल्का कर दिया जायगा।

अनु० 41—चौदह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों के अपराध दण्डनीय नहीं होंगे।

अनु० 42—उन व्यक्तियों का दण्ड हल्का किया जा सकता है जिन्होंने अपराध करने के बाद समय-अधिकारियों के समक्ष जाच होने पर अपना प्रत्याभ्यास कर दिया हो।

अथदण्ड छोटे अथदण्ड एवं राज्यसात्करण व अतिरिक्त और कोई दूसरा दण्ड नहीं दिया जायगा ।

अनु० 47—यदि हद्दगाजाइ में स दा या उससे अधिक अपराध सीमित कठोरश्रमसारावास जबवा कागवाम व दण्ड व याग्य हा ता दण्ड वा चरम अवधि गुन्तम अपराध वा चरम अवधि तथा इसकी आधी और (अथात् डेढ़ गुना) हागी किन्तु यह अवधि दूसरे अन्व किए गए अपराधा व लिए उल्लिखित चरम अवधिया में अधिक नहीं हागा ।

अनु० 48—यद्यपि अनु० 46 व परि० 1 की दंगा व अनिरिक्त कोई अन्य दण्ड या अन्य दण्ड भा याग्य-याग दिया जायगा ।

दा या अधिक अथदण्ड उतनी मात्रा तक दिए जायेंगे जहाँ तक कि उनकी राशि अनेक अपराधा पर लगाए गए अथदण्डों व याग से अधिक न हा ।

अनु० 49 यद्यपि हद्दगाजाइ व अन्तर्गत गुन्तम अपराध व लिये राज्य सात्करण वा उल्लेख नहीं किया गया है तथापि यह अतिरिक्त रूप में लगाया जा सकता है यदि अन्व में स रिमी अपराध पर राज्यसात्करण विहित हा ।

राज्यसात्करण व दा या अधिक दण्ड एवं साथ लगाए जा सकते हैं ।

अनु० 50—यद्यपि हद्दगाजाइ व अन्तर्गत एक या अधिक अपराध (अपराधा) पर न्याय निणय दिया गया हा और अन्य (अन्वा) पर नहीं ता अनिर्णीत अपराध (अपराधा) पर न्याय निणय दिया जायगा ।

अनु० 51—यदि हद्दगाजाइ पर दा या अधिक निणय दिए जा चुके हा, तो दण्ड मयुक्त श्रम निष्पादित किए जायेंगे, किन्तु यदि प्राण-दण्ड निष्पादित करना हा ता राज्यसात्करण के अतिरिक्त अन्य कोई भी दण्ड वायान्वित नहीं किया जायगा । यदि अजीवन कठोरश्रमसारावास या अजीवन कारावास वा दण्ड निष्पादित करना हा ता अथ-दण्ड एवं राज्य-सात्करण व अतिरिक्त अन्य कोई दण्ड वायान्वित नहीं किया जायगा । सीमित कठोरश्रमसारावास या सीमित कारावास के निष्पादन की अवधि, अनेक अपराधा में स गुन्तम व लिए उल्लिखित दण्ड की चरम अवधि एवं उगरी आधी (अथात् डेढ़ गुनी) से अधिक नहीं हागी ।

अनु० 52—यदि हद्दगाजाइ व लिए दण्डित रिमी व्यक्ति वा एक (या अधिक) अपराध (या अपराधा) व मन्व में सामान्य राज-शमा की दृष्टा प्रदान की गई हा ता ऐम शमा प्रदान में भिन्न अपराध (अपराधा) के लिए दण्ड वा निणय विशेष रूप में किया जायगा ।

अनु० 57—किसी पुनरावृत्त अपराध के दण्ड की अवधि, उस अपराध के लिए उल्लिखित नदोहरावकारावास की चरम अवधि के दुगुने से अधिक नहीं होगी।

अनु० 58—निवाले दिया गया।

अनु० 59—पुनरावृत्त अपराधों से संबंध व्यवस्थाएँ उसी तरह उन व्यक्तियों पर भी लागू होंगी जिन्होंने कोई अपराध तीन या अधिक बार किया हो।

अध्याय 11

सहापराधिता

“क्योहन्”

अनु० 60—किसी अपराध-कार्य में सहायता देने वाले को या अधिक व्यक्तियों को मुख्य अपराधी के रूप में व्यवहृत किया जायगा।

अनु० 61—वह व्यक्ति, जिसने दूसरे का अपराध करने के लिए उकसाया हो या उससे अपराध करवाया हो, मुख्य अपराधी समझा जायगा।

यही नियम उस व्यक्ति के संबंध में भी लागू होगा जिसने किसी उकसाने वाले को उकसाया हो।

अनु० 62—मुख्य अपराधी को सहायता देने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका उपसहायक है।

उपसहायक का उकसाने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपसहायक ही समझा जायगा।

अनु० 63—उपसहायक का दण्ड, मुख्य अपराधी के दण्ड का हल्का किया गया दण्ड होगा।

अनु० 64—अन्यथा विनियम प्रकार से विहित दण्ड को छोड़कर, उकसाने वाले एवं उपसहायकों का दण्डित निरोध अथवा छोटे अर्थ दण्ड द्वारा दण्डनीय अपराधों के लिए दण्डित नहीं किया जायगा।

अनु० 65—यदि कोई व्यक्ति निम्नी ऐसी कार्य में पकड़ा गया हो जो अपराध करने वाले की स्थिति के कारण अपराध हो तो उसे सहापराधी के रूप में व्यवहृत किया जायगा मले ही उसकी वैसी स्थिति न हो।

यदि दण्ड की गुफ्ता अपराधी की स्थिति पर निर्भर करती हो तो वैसी स्थिति न रखने वाले व्यक्तियों को मामान्य दण्ड दिया जायगा।

अध्याय 12

(दण्ड) घटाव वाली परिस्थितियों के कारण

दण्ड का घटाव

“शत्रुओं गेहकेड़”

अनु० 66—(दण्ड) हल्का करने वाला परिस्थितियाँ व रहल पर किया कारण का दण्ड हल्का किया जा सकता है।

अनु० 67—बिधि द्वारा प्रदत्त दण्ड बढ़ाया या घटाया जाना चाहिए। फिर भी (दण्ड) हल्का करने वाला परिस्थितियाँ व कारण (दण्ड) हल्का किया जा सकता है।

अध्याय 13

दण्ड के घटाव या घटाव के सामान्य नियम

“करोल रेड”

अनु० 68—यदि बिधि द्वारा दण्ड हल्का करने के एक (या अधिक) आधार है। (ह) ता वह अनाधिकार नियमों व अनुसार हल्का किया जाएगा

- (1) यदि प्राथमिक दण्ड का हल्का करना है तो इस कठोरमकारणों या कारणों के रूप में किया जाएगा जिसका अवधि आजीवन अवधि इस वर्ष से कम नहीं होगा
- (2) यदि आजीवन कठोरमकारणों या आजीवन कारावास दण्ड हल्का करना है तो इस मामिल कठोरमकारणों या मीमित कारणों के रूप में किया जाएगा जिसका अवधि मान वर्ष से कम नहीं होगा,
- (3) यदि मीमित कठोरमकारणों या मीमित कारणों हल्का करना है तो इस मामिल दण्ड की अवधि का आधा कर दिया जाएगा,
- (4) यदि कोई बड़ा अवधि हल्का करना है तो इस अवधि को कुछ राशि का आधा कर दिया जाएगा,
- (5) यदि दायित्व निराप हल्का करना है तो अवधि चरम अवधि का आधा कर दिया जाएगा,

(6) यदि कोई छोटा अथदण्ड हल्का करना हो तो उस उसकी पूरा राशि का आधा कर दिया जायगा।

अनु० 69—जब विधि द्वारा कोई दण्ड हल्का करना हो किन्तु उससे सबद अनुच्छेद दो या अधिक दण्डों का विधान करता हो, तो सबसे पहले लगाए जाने वाले दण्ड का निषेध एक सत्यद्वारा दण्ड का हल्काव किया जायगा।

अनु० 70—यदि बन्धनमन्त्रालयों के कारावास या दण्डिक निराश या हल्का करने में पूरा एक दिन से कुछ घंटे कम पड़े तो उनकी गणना नहीं की जायगी।

यही नियम उस दशा में लागू होगा जबकि किसी (बड़े) अथदण्ड या छोटे अथदण्ड का हल्का करने में एक सत्र का कोई भाग (मिन) बच रहे।

अनु० 71—(दण्ड) हल्का करने वाली परिस्थितियों के कारण दण्ड का हल्काव करने में अनुच्छेद 68 एवं पिछले अनुच्छेद के नियमों का भी अनुसरण किया जायगा।

अनु० 72—यदि दण्ड का उसी समय बढ़ाना और हल्का करना हो तो उसका अर्धालिखित प्रम होगा

- (1) पुनरावृत्त अपराध के लिए दण्ड में बढ़ाव,
- (2) विधि द्वारा दण्ड में घटाव,
- (3) अनेकपरदा (हड़गाजाइ) के लिए दण्ड में बढ़ाव,
- (4) (दण्ड) हल्का करने वाली परिस्थितियों के कारण दण्ड में घटाव।

दूसरा खण्ड—अपराध

अध्याय 1

अनु० 73 म 76 तक निराल दिया गया ।

अध्याय 2

गृहपुद्ग से मंद्य अपराध

“नश्वरान नि कन्सुसु त्सुमि”

अनु० 77—प्रत्येक व्यक्ति जिसने मन्वार (गज्यमत्ता) का उन्हाड़ फेंकने, राज्य के उपनिवेश के बलान् अभिग्रहण करने अथवा अन्य प्रकार से गण्ट्रीय मविधान के विरुद्ध करने की धांग्ना से कोई विद्रोह मन्धी या राजद्रोही कृत्य किया है। गृहपुद्ग करने का अपराधी ज्ञाता और अघालिखित विशेषताओं के अनुसार दण्डित किया जायगा।

(1) प्रधान राजद्रोहिया का प्राण दण्ड अथवा आजीवन कारावास

(2) जितने पद्मत्रा में भाग लिया है। अथवा किसी भीड़ में अपना आदेश बलाया है। उन्हें आजीवन अथवा कम से कम तीन वर्ष का कारावास, वे जो ऐसे अनेक अन्य कृत्या में लगे हैं, उन्हें एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कारावास,

(3) विप्लव-मन्धी या राजद्रोही कृत्य में अनुपायिया अथवा केवल समिलित होने वाला का अधिक से अधिक तीन वर्ष का कारावास ।

पिछले परिच्छेद के धमा० 3 में उल्लिखित व्यक्ति का जो छोड़कर पिछले परिच्छेद के अपराध का प्रयत्न भी दण्डनीय होगा ।

अनु० 78—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने गृहपुद्ग के लिए तैयारी की हो, या पद्मत्र किया हो, एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कारावास दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 79—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने अस्त्र-शस्त्र, धन, साधन-सामाग्री या ऐसे अन्य कार्य से सहायता द्वारा पिछले दो अनुच्छेदों का अपराध किया हो, अधिक से अधिक सात वर्ष तक का कारावास का दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 80—यदि कोई व्यक्ति जो पिछले दो अनुच्छेदों का अपराध कर चुका हो, किन्तु विप्लव के संपादन के पहले ही आत्मप्रत्याख्यान कर दे तो उसका दण्ड क्षमा कर दिया जायगा ।

अध्याय 3

(बाह्य) युद्ध संबंधी अपराध

अनु० 81—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने किसी विदेशी राज्य के साथ पड़्यत्र किया हो और उस दश से जापान राज्य के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग कराया हो प्राणदण्ड दिया जायगा।

अनु० 82—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने किसी विदेशी राज्य के जापान के विरुद्ध शक्ति के प्रयोग करने पर उक्त विदेशी राज्य की सहायता में सैनिक सेवा के लिए प्रवर्तन किया हो या उसे सैनिक सहायता दिया हो, प्राण दण्ड अथवा आजीवन या कम से कम दो वर्ष का कठोरश्रमवारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 83 से 86 तक निराल दिया गया।

अनु० 87—अनुच्छेद 81 एवं 82 के अपराधों के प्रवर्तन भी दणनीय हानि।

अनु० 88—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने अनुच्छेद 91 एवं 82 में उल्लिखित अपराधों के लिए उद्योग किया हो या पड़्यत्र किया हो एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक या कठोरश्रमवारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 89 निराल दिया गया।

अध्याय 4

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों से संबद्ध अपराध

“कोक्को नि कन्सुरु त्सुमि”

अनु०—90 और 91 निराल दिए गए।

अनु० 92 प्रत्येक व्यक्ति का जिसने किसी विदेशी शक्ति (देश) का अपमानित करने की धारणा से उसके राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्र के किसी अन्य प्रतीक का हानि पहुँचाया विनष्ट किया हटा दिया या घराशायी किया हो, दो वर्ष तक या कठोरश्रमवारावास का दण्ड या 200 येन तक का अथदण्ड दिया जायगा किन्तु उक्त दण्ड का अभिमात्रन उक्त सरकार की माँग पर ही किया जायगा।

अनु० 93—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने किसी विदेशी शक्ति के विरुद्ध निर्यो युद्ध करने का धारणा में तैयारियाँ की हो या उसके लिए पड़्यत्र किया

हो नाल मान से चर पाँच वष तक का कारावास का दण्ड दिया जायगा किन्तु आम प्रमाथ्यान करन पर दण्ड क्षमा कर दिया जायगा ।

अनु० १५—प्रत्येक व्यक्ति का जिसन दो विदेशी गतिनया के पुढकाठ में नम्पनया व अध्यादा का उत्पथन किया हो अधिक से अधिक तीन वष तक का कारावास या 1000 घन तक का अथदण्ड दिया जायगा ।

अध्याय 5

कार्यालयीय कार्यों में बाधा डालने के अपराध

"कोमु नो शिक्का वो धारोमु त्सुमि"

अनु० 9०—प्रत्येक व्यक्ति का जिसन अपना कतन्य करत हुए किसी लान कमचारी व बिस्ट हिमा या घमकी का प्रयाग किया हो तान वष तक का बठारथमकारावास या कारावास का दण्ड दिया जायगा ।

यहा उस प्रत्येक व्यक्ति के मद्रथ में लागू हाया जिसन किसी लान कमचारी क बिस्ट हिमा या घमकी का प्रयाग उसस काई बारवाई करतन या किसी कारवाद से विमुख करन या उस अपन पन से त्याग-पत्र दिलान के अभिप्राय से किया हो ।

अनु० 96—(1) प्रत्येक व्यक्ति का जिसन किसी लान कमचारी द्वारा अरिन मद्राआ या कुर्फी व चिह्ना का नुकसान पहुचाया हो या विनष्ट किया हो अथवा जिसन अन्य प्रकार से उन मद्राआ या चिह्ना को व्यय कर दिया हो दो वष तक का बठारथमकारावास अथवा 300 घन तक का अथदण्ड दिया जायगा ।

अनु० 96—(2) प्रत्येक व्यक्ति का जिसन मर्पति छिपा दिया हो नुकमान किया हो विनष्ट कर दिया हो अथवा अन्नरित कर देन का बहाना किया हो अथवा अनिवाय निष्पादन क परिहार के लिए किसी बाध्यतावा रवन का बहाना किया हो दो वष तक का बठारथमकारावास अथवा 1000 घन तक का अथदण्ड दिया जायगा ।

अनु० 96—(3) प्रत्येक व्यक्ति का जिसन किसी सावजनिक नीलामा या निविदा व मद्रथ में किसी कष्टपूर्ण उपाय या प्रभाव से औचित्य के प्रतिकूल काई काय किया हो दो वष तक का बठारथमकारावास या 5000 घन तक का अथदण्ड दिया जायगा ।

यही उस व्यक्ति के संवत्स में भी लागू होगा जिसने उचित मूल्यों को बचाने या अनुचित लाभ पाने के अभिप्राय से आपस में परामर्श किया हो।

अध्याय 6

निकल भागने (पलायन) के अपराध

“तोसो नो त्सुमि”

अनु० 97—प्रत्येक सिद्धदाय या असिद्धदाय बन्दी का, जो निकल भागे, एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 98—यदि कोई सिद्धदाय या असिद्धदाय बन्दी या व्यक्ति, जिसके विरुद्ध प्रभुति का अधिपत्र निष्पादित हो, निरोध-स्थान या बन्धन को भाङ्गकर या हिंसा या धमकी देकर, या दा या अधिन व्यक्तिगणों के साथ कामना उभेक्षा करके निकल भागा हो उसे तीन मास में लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 99—प्रत्येक व्यक्ति को, जो विधि या आदेश द्वारा निरोधित किसी अन्य व्यक्ति का छुड़ा लिया हो, तीन मास में लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 100—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने विधि या आदेश द्वारा निरोधित किसी अन्य व्यक्ति का निकल भागने के अभिप्राय से ऐसे यंत्र या साधन उपलब्ध किया हो, या उसके निकल भागने का सरल बनाने के अभिप्राय वाले अन्य प्रकार के कार्य किया हो, तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या दण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति को जिसने पिछले परिच्छेद के अभिप्राय से हिंसा का प्रयोग किया हो या धमकी दी हो, तीन मास में लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 101—प्रत्येक व्यक्ति को, जो विधि या आदेश द्वारा स्थानबद्ध व्यक्ति का देखभाल या वहन के लिए उत्तरदायी हो, और उगने, उन्हें निकल भागने दिया हो, एक वर्ष में लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 102—इस अध्याय के अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अध्याय 7

अपराधियों को मंत्रय देने एवं मन्त्रय के अधिलंघन के अपराध

“हमिन् जेतोसु ओयोनि शोका इमेत्सु नो त्सुमि”

अनु० 103—प्रथम व्यक्ति का जितन रिमा एम व्यक्ति का आश्रय दिया २१ या जितना नगना म इम्पन्स दिया २१ या जितन अथदण्ड या गुल्फर दण्ड द्वारा दण्डमाय अपराध दिया २१ अथवा जा निगाय या अवस्था म निरु भागा २१ दो वष तक का बढारथमसारावाय या 200 यन तक का अथदण्ड दिया जायगा ।

अनु० 104 प्रथम व्यक्ति का जितन रिमा अथ व्यक्ति व विद्रु रिमा अपराधित अभियोग में माय का नमन दिया २१ जाग्गादा दिया हा जयवा उस मिथ्या बनाया २१ अथवा जितन जाग या मिथ्या माय का प्रयाग दिया २१ दो वष तक का बढारथमसारावाय या 200 यन तक का अथदण्ड दिया जायगा ।

अनु० 105 जब इस अध्याय का बाद अपराध अपराध या परार व रिमा मवधा द्वारा अपराध या परार व गम व लिए दिया जाय तो दण्ड क्षमा किया जा सकता है ।

अध्याय 8

बलवे का अपराध

“सोतो नो त्सुमि”

अनु० 106 व व्यक्ति जा उदा मग्गा में एवत्र गजर हिमा विय हा अथवा घमका दिय २१ एवत्र व अपराध मान जायेंगे और उन्हें निम्नलिखित वर्गीकरण व अनुसार दण्ड दिया जायगा

- (1) गरमता वा एव वष म एवत्र दम वष तक का बढारथमसारावाय या बारावाय दण्ड
- (2) जितन दूमरा वा निर्देग दिया या ननुव दिया एव अशानि पैलाई २१ उन्हें छ मास म एवत्र मान वष तक का बढारथमसारावाय या बारावाय दण्ड
- (3) जितन वरु अनुमरण दिया हा उन्हें 50 यन तक का अथदण्ड ।

अनु० 107—उन व्यक्तियों में से जा हिमक प्रयोग करने या धमकी देने के अभिप्राय से बड़ी सख्या में एकत्र हुए हों। एक लोक-वर्मचारियों द्वारा तीन या अधिक बार तितर बितर होने के लिए आदेश दिए जाने पर भी नहीं हटे हों, मरगना का तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या कारावास एवं अन्य का 50 येन तक का अर्थ दण्ड दिया जायगा ।

अध्याय 9

आग लगाने एवं उपेक्षावश जलाने के अपराध

“होका ओयोयि शिक्का नो त्सुमि”

अनु० 108—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने मानव-निवास के रूप में प्रयुक्त अथवा जिसमें व्यक्ति हो ऐसे भवन, रेलगाड़ी, विजली की कार, जलयान, या कारावास खान का आग लगा कर जला दिया हो, प्राण-दण्ड या आजीवन-अथवा कम-से कम पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 109—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी भवन, रेलगाड़ी, जलयान या खान का जिसका प्रयोग, उम समय मानव-निवास के रूप में नहीं होता था, अथवा जिसमें आदमी नहीं थे आग लगा कर जला दिया हो, कम से कम दो वर्ष का सीमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

यदि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित वस्तुओं में से कोई अपराधी की निजी संपत्ति रही हो तो उसे छ मास से लेकर मातः वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास दण्ड दिया जायगा, किन्तु यदि कोई सार्वजनिक सड़क न हुआ हो तो कोई दण्ड नहीं दिया जायगा ।

अनु० 110—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने पिछले दो अनुच्छेदों में उल्लिखित वस्तुओं के अनिश्चित किसी वस्तु में आग लगाकर जला दिया हो और उससे सार्वजनिक सड़क उत्पन्न किया हो, एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

यदि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित वस्तु अपराधी की निजी संपत्ति हो, तो उसे एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड या 100 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा ।

अनु० 111—अनु० 109 परि० 2 या, पिछले अनुच्छेद के परि० 2 के अपराध-मपादन के फलस्वरूप यदि अनुच्छेद 108 या 109 परि० 1 में

उल्लिखित वस्तुओं तक आग फैल गई है और उन्हें जला दिया हो तो अपराधी को तीन मास में लेकर दस वर्ष तक का बढावरमकागकाम दण्ड दिया जायगा ।

यदि पिछले अनुच्छेद के परि० २ में उल्लिखित अपराध के संपादन के पन्ध्रवर्ष आग फैल गई हो और पिछले अनुच्छेद के परि० १ में उल्लिखित किसी वस्तु को जला दिया हो तो अपराधी का तीन वर्ष तक का बढावरमकागकाम दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 112—अनु० 104 एवम् 109 परि० १ के अपराधों के प्रपन्न भी दण्डनीय होंगे ।

अनु० 113—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने अनु० 105 या 109 परि० १ में उल्लिखित अपराध को करने के अभिप्राय में तैयारियाँ की हों, दो वर्ष तक का बढावरमकागकाम दण्ड दिया जायगा , किन्तु परिस्थितियों के अनुसार उसका दण्ड पूर्णतः क्षमा भी किया जा सकता है ।

अनु० 114—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने किसी अग्निकाण्ड के अवसर पर आग बुझाने वाले यंत्र का टिठा दिया हो नुकसान पहुँचाया हो, (बिगड़ कर दिया हो) अथवा अन्य किसी तरह में आग बुझाने में बाधा पहुँचाई हो, एक वर्ष में लेकर दस वर्ष तक का बढावरमकागकाम दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 115—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने अनु० 109 परि० १ एवं अनु० 110 परि० १ में उल्लिखित किसी वस्तु का जला दिया हो उस दूसरे व्यक्ति को वस्तु जलाने वाले व्यक्ति के रूप में व्यवहृत किया जायगा यदि उक्त वस्तु कुर्सी के अन्दर हो, जिसका वास्तविक अधिकार निर्माण न हो, किराए या पट्टे पर दी गई हो, या बौमाकृत हो चाहे उक्त वस्तु अपराधी की ही क्यों न हो ।

अनु० 116—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने अमावधानी के कारण अनु० 103 या अनु० 109 में उल्लिखित किसी वस्तु का जला दिया हो और जो अन्य व्यक्ति को मारति हो, 1,000 पैन तक का अर्थ दण्ड दिया जायगा ।

यहाँ नियम ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के मध्य में भी लागू होगा जिसने अनु० 109 में उल्लिखित किसी वस्तु का जो उसकी निजी संपत्ति हो, अथवा अनु० 110 में उल्लिखित किसी वस्तु का अमावधानी के कारण जला दिया हो और उसमें कोई सार्वजनिक सफ्ट उत्पन्न कर दिया हो ।

अनु० 117—(1) प्रत्येक व्यक्ति का, जिमने वास्टर (gunpowder), भाप वायलर (steam boiler) या अन्य किसी विस्फोटन वस्तु का विस्फोट किया हो और (उसमें) अनु० 108 में उल्लिखित किसी वस्तु या अनु० 109 में उल्लिखित किसी वस्तु का नुस्खाना पहुँचाया हो या बिनष्ट कर दिया हो, जो दूसरे व्यक्ति की संपत्ति रही हो, जाग लगाने वाल की तरह ही दण्ड दिया जायगा। यही नियम ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में लागू होगा जिमने अनु० 109 या 110 में उल्लिखित किसी वस्तु का हानि पहुँचाया हो या बिनष्ट किया हो जो उसकी निजी संपत्ति रही हो, और उससे कोई मार्बलजिनिक मकद उत्पन्न किया हो।

यदि पिछले परिच्छेद का बाड कृत्य अनावधानी के कारण हो गया हो तो उस अनावधानी के कारण रही हुई जाग के कृत्य की तरह व्यवहृत किया जायगा।

अनु० 117—(2)—ऐसी दशा में जबकि अनु० 116 या पिछले अनु० के परि० 1 में उल्लिखित बाट्टी बर, यावमायिन दृष्टि में जावदयन सावधानी की उपशब्द या घात उपशब्द में हो गया हो तो अपराधी का तीन वर्ष तक का कारावास या 3,000 येन तक का अर्थ दण्ड दिया जायगा।

अनु० 118—प्रत्येक व्यक्ति का, जिमने गैस, रिजली या भाप को किसी छेद से निकलने दिया हो या बाहर प्रवाहित किया हो, या बन्द कर दिया हो और उसमें दूसरा व जावन, शरीर या संपत्ति का मकद उत्पन्न कर दिया हो, तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 100 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति का, जिमने गैस, बिजली या भाप को किसी छेद से निकलने दिया हो, बाहर प्रवाहित किया हो या बन्द कर दिया हो और उसमें दूसरे का भार डाला हो या घायल किया हो, उपर्युक्त दण्ड एवं घायल करने के दण्ड की तुलना में जो गुनगुन दण्ड होगा दिया जायगा।

अध्याय 10

आप्लावन एवं जल के उपयोग से संबद्ध अपराध

“इस्मुट ओयोवि मुटगी नि कन्सुरू त्सुमि”

अनु० 119—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने कोई आप्लावन (बाढ़) किया हो और उसमें किसी भवन, रेग्गारी, रिजरी की वार या मान का जलमग्न कर

दिया है या क्षति पहुँचाई हो जिसका उपयोग जन-आवास के रूप में होता हो या जिसमें व्यक्ति रहा हो (रह रहा) प्राण नष्ट या आजीवन कारावास या कम से कम तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास नष्ट किया जायगा।

अनु० 120—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने आप्लावन किया है और उससे पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित सभी वस्तुओं का जन्तुमान किया हो या क्षति पहुँचाई हो और इस प्रकार कोई जन मरने पर उपस्थित कर दिया हो एवं वर्ष से दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास नष्ट किया जायगा।

यदि आप्लावन से क्षति वस्तु अपगन्धा की निजी संपत्ति हो तो पिछले अनुच्छेद का दण्ड बवल उन्ही दण्डों में लागू होगा जहाँकि उक्त वस्तु दुर्गम में हो वास्तविक अधिकार के विवाद में हो भाड़ पर दी गई हो पट्टे पर दी गई हो या बामोदित है।

अनु० 121—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने आप्लावन के समय उस दूर करने में उपयोगी किसी वस्तु का डिपा किया है क्षति पहुँचाई हो या नष्ट किया है या किसी दूसरी तरह से आप्लावन के लिए प्रयुक्त क्रिया का निराकरण किया है एवं वर्ष से दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 122—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने प्रयादवर्ग कोई आप्लावन कर लिया है और उससे अनु० 119 में लिखित किसी न किसी वस्तु का क्षति पहुँचाई है या जिनमें (उसी तरह) अनु० 120 में लिखित किसी वस्तु का क्षति पहुँचाई है एवं उससे कोई जन मरने पर उपस्थित किया हो 300 यन तक का अश्रम दिया जायगा।

अनु० 123—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने किसी भराव या बाँध का ताल किया है किसी प्रणाली (मारी) का नष्ट किया हो या पानी के उपयोग को रोकने अथवा बाँध या आप्लावन करने के आशय से कोई अन्य कार्य किया हो वा वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या कारावास अथवा 200 यन तक का अश्रम दिया जायगा।

अध्याय 11

यातायात में अवरोध पहुँचाने से संबद्ध अपराध

“ओराइ वो वोगाइ-सुरु सुमि”

अनु० 124—प्रत्येक व्यक्ति का, जो स्थल या जल से किसी सड़क का हानि पहुँचा कर, नष्ट करे या अवरोध करे या किसी पुल को तोड़ कर यातायात बाधित किया हो, दो वर्षों तक का कठोरश्रमकारावास या 200 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले परिच्छेद के अपराध का करने में किसी अन्य व्यक्ति को घायल किया हो या मार डाला हो, उक्त दण्ड एवं घायल करने के दण्ड की तुलना में गुरुतर दण्ड में दण्डित किया जायगा।

अनु० 125—प्रत्येक व्यक्ति का जिगने रेलवे या उमरे मिगनल (केतु, *ketu*) का क्षति पहुँचाई हो या नष्ट किया हो या अन्य प्रकार से ट्रेन या बिजली की कार के यातायात का गति रुकवा दिया हो, कम से कम दो वर्षों तक के मोमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दण्डित किया जायगा।

यही नियम उन व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होगा जिन्होंने किसी लाइट हाउस (*light house*) या बाया (*buoy*) का नुकसान पहुँचाया हो या नष्ट किया हो अथवा दूसरी तरह से नौपरिवहन यातायात का गति रुकवा दिया हो।

अनु० 126—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने किसी रेलगाड़ी या बिजली की कार का, जिसमें आदमी रहे हो, स्थूलन (*upset*) किया हो, या नष्ट किया हो, आजीवन या कम से कम तीन वर्षों तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यही नियम उन व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होगा जिसने किसी जलयान को, जिसमें आदमी रहे हो, डूबा दिया हो या विनष्ट किया हो।

प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने पिछले दो परिच्छेदों के अपराधों के करने में किसी अन्य व्यक्ति का प्राणान्त कर दिया हो, प्राण-दण्ड या आजीवन कठोरश्रमकारावास के दण्ड में दण्डित किया जायगा।

अनु० 127—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने अनु० 125 का अपराध किया हो और उसमें किसी रेलगाड़ी या बिजली की कार का स्थूलन कर दिया हो या

गोपनीयता-उल्लंघन के अपराध

किमी जग्गान का डूबा दिया हा या विनष्ट कर दिया हा पिछ्ठा अनुच्छेद में विहित व्यवस्था क अनुरोध करहेन किमा जागगा ।

अनु० 128—अनु० 124 परि० 1 अनु० 125 पर अनु० 126 परि० 1 और 2 में निर्दिष्ट अपराधा क प्रयत्न ना दण्डनीय हाग ।

अनु० 129—प्रत्येक व्यक्ति का ज़िम्मेदार जमावघाती क कारण किमी रेलगाडी या विजरा का कार या जग्गान-यानावान का गतरा पहुचाना हा या किमा रेलगाडी या विजरा का कार का स्थगन किया हा या उन्हे विनष्ट किया हा या किमा जग्गान का डूबा दिया हा या विनष्ट किया हा अधिक स अधिक 500 येन तक का अचदण्ड दिया जागगा ।

यदि पिछ्ठा परि० का बाड अंगार यानावान क उपयुक्त व्यापार में लगा हा ता उम तान क तक का कारावास दण या 1000 येन तक का अचदण्ड दिया जागगा ।

अध्याय 12

अतिचार (Irregularity) के अपराध

“जुम्हो वो ओफिसु लुमि”

अनु० 130 प्रत्येक व्यक्ति का ज़िम्मेदार बिना किमी कारण क किमी काम-गृह या आरम्भित स्थान नवन या दल्लान का अनिचार किया हा या माग करन पर तम स्थान का छात्र न लिया हा अधिक स अधिक तान बप का कठार-धमकारावास दण या 50 येन तक का अचदण्ड दिया जागगा ।

अनु० 131 निराश किया गया ।

अनु० 132—अनु० 130 क अपराधा क प्रयत्न ना दण्डनीय हाग ।

अध्याय 13

गोपनीयता उल्लंघन के अपराध

“हिमित्सु वो ओफिसु लुमि”

अनु० 133—प्रत्येक व्यक्ति का ज़िम्मेदार बिना किमी उचित कारण के किमी मुख्यदफ्तर का खाल दिया हा अधिक स अधिक एक बप का कठार-धमकारावास दण अथवा 200 येन तक का अचदण्ड दिया जागगा ।

अनु० 134—प्रत्येक व्यक्ति का जो कोई वाय-चिह्नितक औपचारिक जीपधिनिर्माता यात्री बक्की (विचित्र), परामर्शदाता या लेख्यप्रमाणक (notary) हो या रह चुका हो तथा जिमने बिना किसी कारण के किसी अन्य व्यक्ति का कोई सापनीय रहस्य गाल दिया हो जो कि उसकी जानकारी में अपने व्यवसाय के अनुमरण सबधी किसी तथ्य में आया हो, अधिक से अधिक छ मास तक का बठारश्रमकागवाम या 100 येन तक का अथ दण्ड दिया जाएगा।

यही नियम प्रत्येक उस व्यक्ति के संबंध में भी लागू होगा जो किसी ऐसे व्यवसाय में लगा हो या रह चुका हो जो धर्म या वाराधना में संबद्ध हो और जिमने किसी ऐसे व्यक्ति का रहस्य गाल दिया हो जो व्यक्ति उसकी जानकारी में अपने व्यवसाय के अनुमरण सबंधी किसी तथ्य में आया हो।

अनु० 135—इस अध्याय में निर्दिष्ट अपराध की कार्यवाही परिवार (complaint) पर ही की जाएगी।

अध्याय 11

अफीम-तम्बाकू से संबद्ध अपराध

“अहेन-तथको नि कन्सुद रसुमि”

अनु० 136—प्रत्येक व्यक्ति को, जिमने अफीम-तम्बाकू का आयात किया हो निर्माण या विनष्ट किया हो या विषय के अभिप्राय में अपने पास रखा हो, छ मास से मान वर्ष तक का बठारश्रमकागवाम का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 137 प्रत्येक व्यक्ति को, जिमने अफीम-तम्बाकू पीने के उपयोग में जाने वाले किसी उपकरण का आयात, निर्माण या विषय किया हो, या विषय के अभिप्राय में अपने पास रखा हो, तीन मास से तेकर पाँच वर्ष तक का बठारश्रमकागवाम का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 138—कोई भी नीमा गुल्क कर्मचारी जिमने अफीम-तम्बाकू अथवा अफीम-तम्बाकू पीने में उपयोगी किसी उपकरण का आयात किया हो या आयात की अनुज्ञा दी हो, उसे एक वर्ष से तेकर दस वर्ष तक का बठारश्रमकागवाम का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 139—अफीम-तम्बाकू पीने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का बठारश्रमकागवाम का दण्ड दिया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति का ज़िम्मेदार अपने लाभ व निमित्त अपना पान व ग्लि काई स्थान प्रदान किया है। ॥ माम स र्कर मान वष तक का कठारधम कारागार का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 140—प्रत्येक व्यक्ति को ज़िम्मेदार अपना लम्बा पान का काई उपकरण देना है। अतिरिक्त अधिक एक वष तक का कठारधमकारागार का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 141 इस अध्याय व अपराध व प्रयत्न भी स्पष्ट है।

अध्याय 15

पेय जल से सबद्ध अपराध

“इन्रियोसुइ नि कन्-सुह लुमि”

अनु० 142—प्रत्येक व्यक्ति का ज़िम्मेदार ज़नना व पान व गुद जल का दूषित किया है या उस जल व अनुपयोग्य कर दिया है। अतिरिक्त अधिक ॥ माम का कठारधमकारागार या 50 वष तक का अव दण्ड दिया जायगा।

अनु० 143—प्रत्येक व्यक्ति का ज़िम्मेदार ज़नना का पान व ग्लि जलघर या जल रिया सान व ममन (Supplid) गुद जल का दूषित किया है या उस अनुपयोग्य बना दिया है। छ माम स र्कर मान वष तक का कठार धमकारागार का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 144—प्रत्येक व्यक्ति का ज़िम्मेदार पीन के गाव पाना में विष या अन्य रक्त जन-स्वास्थ्य का हानि पहुँचाने वाला पदार्थ मिला दिया है। अधिक स अतिरिक्त मान वष तक का कठारधमकारागार दण्ड दिया जायगा।

अनु० 145—प्रत्येक व्यक्ति का ज़िम्मेदार पिछले तीन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट में न रिया अपराध का किया है और ज़मम किया ज़मम व्यक्ति का पाप किया है या मा-जल है। उक्त ज़मम पापल करने व दण्ड का तज़ना में ज़ी मुरतज़न दण्ड होगा दिया जायगा।

अनु० 146 प्रत्येक व्यक्ति का ज़िम्मेदार जलघर या अन्य सान स ज़नना का पीन व ग्लि पहुँचाने पान व गुद जल में विष या अन्य कोई हानिकारक पदार्थ मिला दिया है। ज़िम्मेदार जन-स्वास्थ्य का हानि पहुँचाने कम स कम दो वष का मामित कठारधमकारागार दण्ड दिया जायगा। यदि उमर ज़ममे किसी का प्राण र दिया है। तब उस प्राण-जल अवका आजीवन या कम स कम पाँच वष का कठारधमकारागार का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 147—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने जनता के पेय जल की साफ बल-नली (Water main) का नुकसान पहुँचाया हो, विनष्ट किया हो या अवश्रुत किया हो, एक वर्ष में लेकर दस वर्ष तक का बठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अध्याय 16

जाली मिक्के बनाने के अपराध

“त्सुक—गिजो नो त्सुमि”

अनु० 148—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी चालू सिक्के, बागजी मुद्रा या बैंकनोट के बदल जाला मिक्के जादि बनाने के आशय में जाली बनाए हो, आजीवन या कम में कम तीन वर्ष का बठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यही नियम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होगा जिसने जाही मिक्के चलाए हो या मिक्का बागजी मुद्रा या बैंकनोट में परिवर्तन कर दिया हो या इसे चलाने के अभिप्राय में वितरित किया हो या आयात किया हो।

अनु० 149—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी विदेशी सिक्के, बागजी मुद्रा या बैंकनोट को, जो इस देश में परिचालित हो, चलाने के अभिप्राय में उसमें बदले जाली तैयार किया हो या उसमें परिवर्तन किया हो, कम में कम दो वर्ष का भीमिन बठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यही (वण्ड) प्रत्येक उक्त व्यक्ति के सम्बन्ध में भी लागू होगा जिसने जाली या परिवर्तित मिक्के, बागजी मुद्रा या बैंकनोट जादि को बनाया हो या जिसने इसमें परिचालन के अभिप्राय से उसे वितरित किया हो या इसका आयात किया हो।

अनु० 150—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने परिचालन के अभिप्राय में जाली या परिवर्तित मिक्का, बागजी मुद्रा, या बैंकनोट किया हो, अधिक में अधिक तीन वर्ष तक का बठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 151— निम्नलिखित तीन अनुच्छेदों में विहित अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अनु० 152—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने जानबूझ कर जाही मिक्का, बागजी मुद्रा या बैंकनोट लेकर परिचालन के अभिप्राय में चलाया हो या वितरित किया हो, गुरु अर्थ-दण्ड या लघु अर्थ-दण्ड, जो 1 येन में लेकर उस मिक्के या बागजी मुद्रा या बैंकनोट के तीन गुने तक का होगा, दिया जायगा।

किसी लार-कार्यालय या लार-कर्मचारी द्वारा निर्मित होने चाहिए, अथवा किसी लार-कार्यालय या लार-कर्मचारी द्वारा निर्मित किसी लेख्य या मानचित्र में हेन्-फेर किया हो, अधिक में अधिक तीन वर्ष तक का कटोश्रम कारावास या 300 येन तक का अर्बंदण्ट दिया जायगा।

अनु० 156 प्रत्येक लार-कर्मचारी का, जिसने चाटू करने के अभिप्राय में तथा अपना दफ्तरी कारवाट के मकसद में चाटू जाली लेख्य या मानचित्र बनाया हो अथवा किसी लेख्य या मानचित्र में हेन्-फेर किया हो, उसी रूप में ध्वस्त किया जायगा तैसा कि पिछले दो अनुच्छेदों में निर्दिष्ट है, अन्तर केवल उस पर मुहर या हस्ताक्षर के करने या न करने के अनुसार किया जायगा।

अनु० 157 प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का, जिसने किसी लार-कर्मचारी के समान चाटू गलत विवरण दिया हो और उसने द्वारा किसी अधिकार या कर्तव्य के मयद प्रमाणित विलय (authenticated deed) के मौलिक पत्र में काँ गलत इन्दगात्र बना दिया हो अधिक में अधिक पाँच वर्ष तक का कटोश्रम कारावास या 1,000 येन तक का अर्बंदण्ट दिया जायगा।

प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का, जिसने किसी लार-कर्मचारी के समान गलत विवरण दिया हो और उसने किसी अनुमति या अनुज्ञापत्र अथवा पासपोर्ट (passport) में गलत इन्दगात्र बना दिया हो, अधिक में अधिक एक वर्ष तक का कटोश्रम कारावास अथवा 300 येन तक का अर्बंदण्ट दिया जायगा।

पिछले दो अनुच्छेदों में निर्दिष्ट अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अनु० 158—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने पिछले चार अनुच्छेदों में निर्दिष्ट किसी लेख्य या मानचित्र को चुराया हो, वही दण्ट दिया जायगा जो उस व्यक्ति को दिया जाता, जिसने उस लेख्य या मानचित्र की जाहगारजी की हो या उसने हेन्-फेर किया हो या काँट मिथ्या लेख्य या मानचित्र बनाया हो या काँट गलत इन्दगात्र बनाया हो।

पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट अपराध के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अनु० 159—प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का, जिसने चुराने के अभिप्राय में, किसी अधिकार, कर्तव्य या तथ्य के प्रमाणन में मयद किसी लेख्य या मानचित्र की जाहगारजी, किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर या मुहर के प्रयोग में किया हो अथवा जिसने अधिकार, कर्तव्य या तथ्य के प्रमाणन में मयद किसी लेख्य या मानचित्र की जाहगारजी, अन्य व्यक्ति के जाही हस्ताक्षर या जाही मुहर के प्रयोग में किया

21. तान मास स त्तर पाच वष तक का बटारधमकारावाम का दण्ड निया जायगा ।

यन् नियम प्रयत्न एस व्यक्ति पर भी लागू नगा जिसन किसी अन्य या चित्र (मानचित्र) स रेखर किया हा जा अधिकर कसव्य या किसी तथ्य क सत्यापन स संबद्ध न तया जिस पर किया अय व्यक्ति का सम्पत्ति पर हा ।

पिछ 21 परिच्छेद स आन बागे सम्पत्ति क अनिरिक्त प्रयत्न व्यक्ति का जिसन अधिकार कसव्य या किसी तथ्य क प्रमाणन स संबद्ध अन्य या चित्र (मानचित्र) की जात्माजा या उसम हेर कर किया हा अधिक स अधिक एक वष तक का बटारधमकारावाम अवदा 100 यन तक का अधण्ड निया जायगा ।

अनु० 160 प्रयत्न एस चिकित्सक का जिसन किसी एक वादाय स प्रस्तुत करने क लिए किसी चिकित्सा प्रमाणपत्र गव-गरीभा प्रमाणपत्र या मय प्रमाणपत्र स गन्त सम्पन्न किया न। अधिक स अधिक तान वष तक का कारावाम या 500 यन तक का अधण्ड निया जायगा ।

अनु० 161 प्रयत्न व्यक्ति का जिसन पिछ 21 द्वा अनच्छेद स निश्चित लक्ष्य या चित्र (मानचित्र) का चण्डा न। वन् अन्य निया जायगा जा अन्य या चित्र (मानचित्र) की जात्माजा या उसम हेर कर करने वा न या गन्त सम्पन्न करने वा का विधि ह ।

पिछ अनुच्छेद स निश्चित अपराधों के प्रयत्न भी सम्पन्न हो हाण ।

अध्याय 18

मूल्यवान् ऋणपत्रों (जमानता) (Valuable Securities)

की जालमाना क अपराध

‘युक्तायेन गिना ना लुमि

अनु० 162 प्रयत्न व्यक्ति का जिसन परिवारालन के अभिप्राय स किसी एन-बण्डर किसी ठाक-कार्यालय के ऋणपत्र किसी बम्पनी क अग्रप्रमाण पत्र (Share certificate) या अय किसी मयवान् ऋणपत्र की जात्माजा या उसम हेर कर किया हा तीन मास स त्तर दम वष तक का बटारधम कारावाम का दण्ड निया जायगा ।

यही नियम उस व्यक्ति पर भी लागू होगा, जिसने चलाने के अभिप्राय में किसी मूल्यवान् जमानत (Valuable Security) या ऋण-पत्र में कोई गलत इन्दराज किया हो।

अनु० 163 प्रत्येक व्यक्ति को जिसने किसी जागी या परिवर्तित मूल्यवान् ऋणपत्र (जमानत) या ऐसे ऋणपत्र का चलाया हो जिसमें कोई गलत इन्दराज हुआ हो, या चाटू करने के अभिप्राय में ऐसे ऋणपत्र की अन्य किसी की वितरित किया हो या उसका आयात किया हो तीन मास से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

पिछले परिच्छेद के अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अध्याय 19

मुद्राओं (मुहरों) की जालमाजी के अपराध

“इन्शो-गिजो नो त्सुमि”

अनु० 161—परिचालन के अभिप्राय में, जाली राज्य-मुद्रा, राज्य की महामुद्रा या इम्पीरियल साइन मैन्युएल का प्रयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कम से कम दस वर्ष का मोमिन कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यही दण्ड उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जिसने राज्य-मुद्रा, राज्य की महा-मुद्रा या इम्पीरियल साइन मैन्युएल का अनुचित प्रयोग किया हो, अथवा जिसने जागी राज्य मुद्रा, राज्य की महामुद्रा या इम्पीरियल साइन मैन्युएल का प्रयोग किया हो।

अनु० 165—परिचालन के अभिप्राय में, किसी लोक-न्यायालय की मुहर की जाटमाजी करने वाले या लोक-कर्मचारी के जागी हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

यही दण्ड उस व्यक्ति के सबन्ध में भी लागू होगा, जिसने किसी लोक-न्यायालय की मुहर या लोक-कर्मचारी के हस्ताक्षर का अनुचित प्रयोग किया हो अथवा जिसने लोक-न्यायालय की जागी मुहर या लोक कर्मचारी के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया हो।

अध्याय 21

मिथ्या अभियोग के अपराध

“फुकोकु नो त्सुमि”

अनु० 172—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने अन्य व्यक्ति पर आपराधिक या आनुशासनिक दण्ड आरापित करने के अभिप्राय से गलत सूचना दी हो, वही दण्ड दिया जायगा जो अनु० 169 में विहित है।

अनु० 173 पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट अपराध करने वाला व्यक्ति, यदि उस बाद के संबंध में जिममें उसने गलत सूचना दी हो, निर्णय के बदल जाने अथवा अनुशासनीय कारवाई किए जाने के पहले ही प्रत्याख्यान कर देता उसका दण्ड हल्का या समा किया जा जा सकता है।

अध्याय 22

अश्लीलता, घलात्कार तथा द्विपत्नीत्व के अपराध

“वैसेत्सु, फनिन ओयोवि जुकोन नो त्सुमि”

अनु० 174—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने सार्वजनिक रूप से कोई अश्लील कृत्य किया हो अधिक से अधिक छ मास तक का कठारश्रमकारावास, या 500 येन तक का अर्थदण्ड या दण्डित्व निरोध या लघु अर्थ दण्ड दिया जायगा।

अनु० 175—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने किसी अश्लील पुस्तक (लेख), चित्र या अन्य वस्तु का वितरण या विप्रेषण किया हो या सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन किया हो, अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठारश्रमकारावास या 5,000 येन तक का अर्थदण्ड या लघु अर्थदण्ड दिया जायगा। यही दण्ड उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जो विप्रेषण के अभिप्राय में उक्त वस्तुओं का अपने पास रखे हो।

अनु० 176—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने बालन् या घमकी देकर कम से कम तरह वर्ष के किसी नर या नारी के साथ कोई अभद्र कृत्य किया हो, छ मास से लेकर सात वर्ष तक का कठारश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा। यही नियम उस व्यक्ति के साथ भी लागू होगा जिमने तरह वर्ष से कम आयु के लड़के या लड़की के साथ अभद्र कृत्य (indecent act) किया हो।

अनु० 177—प्रत्येक व्यक्ति, जिमने बालन् या घमकी देकर कम से कम तरह वर्ष का किसी औरत के साथ भ्रमण किया हो, बलात्कार (rape) का

1 000 येन तक का अर्थदण्ड या लघु अर्थदण्ड दिया जायगा, किन्तु यह उस दशा में नहीं लागू होगा जब कि दाव क्षणिक मनोरजन के लिए अभिप्रेत है।

अनु० 186—प्रत्येक व्यक्ति का जो नियमित अभ्यास के रूप में जुआ खेलने या पण (दाव) लगाने में शामिल है अथवा से अधिक तीन वर्ष तक का कठारधमकारावास दण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति का जिसने कोई छूत-गृह खाल रखा हो या जुआरिया का एकत्र किया है और उसमें गंभीर उठाया है तीन मास से छतर पाँच वर्ष तक का कठारधम कारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 187—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने लाटरी टिकट बेचा है, अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठारधमकारावास या 3 000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति का जिसने लाटरी टिकट के विपणन में मध्यस्थ (अभिकर्ता, एजेंट) का काम किया है, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कठारधमकारावास या 2 000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने, पिछले दो परिच्छेदों में अन्तर्भूत दशाओं के अनिश्चित कोई लाटरी टिकट दिया है या लिया हो, अधिक से अधिक 3,000 येन तक का अर्थदण्ड या लघु अर्थदण्ड दिया जायगा।

अध्याय 24

पूजा-स्थानों एवं ममाधियों से संबद्ध अपराध

“रेइईशो ओयोवि कुन्गो नि कन्-सुरु त्सुमि”

अनु० 188—प्रत्येक व्यक्ति का, जो किसी शिन्तो चैत्य, बौद्ध-मन्दिर, शिन्मान या किसी अन्य पूजा-स्थल के प्रति गार्वजनिक रूप से कोई अपमानजनक कार्य किया है, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कारावास या कठारधमकारावास या 100 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 189—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने किसी ममाधि (कब्र) में गव-उत्पन्न किया है अधिक से अधिक दो वर्ष तक या कठारधम कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 190—प्रत्येक व्यक्ति का जिमान किया गया अवगण या मूल व्यक्ति के वेतन या अव-पटिका (coffin) में प्रदत्त किसी वस्तु का क्षति पहुँचाया है। नष्ट कर दिया है। परित्यक्त कर दिया है। या अधिनगर में कर लिया हो अधिक म अधिक नान वष तक का बढाग्रभमकारावाम दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 191—प्रत्येक व्यक्ति का जिमान अनु० 189 में निर्दिष्ट अपराध किया है। और किया गया अवगण मन व्यक्ति के वेतन या अव-पटिका में प्रदत्त किसी अव वस्तु का क्षति पहुँचाया है। नष्ट किया है। या परित्यक्त किया है। तान माग म उकर पांच वष तक का बढाग्रभमकारावाम दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 192—प्रत्येक व्यक्ति का जिमान किया अस्वामाविन रूप स मूल व्यक्ति की गध-नराणा कारण जिना है। दण्डना दिया है। अधिक म अधिक 50 येन तक का अवदण्ड या वाड उधु अवदण्ड दिया जायगा ।

अध्याय 25

कार्यालयीय भ्रष्टाचार के अपराध

"तोतुसोकु नो त्सुमि"

अनु० 193—प्रत्येक लान-नमचारा का जिमान अपने आधिकार का अनुचित प्रयोग किया है। और जिस व्यक्ति स वेगा बाप कराया है। जिस करने के लिए वह बाध्य न है। अथवा उस अपने समुचित अधिकार के प्रयोग करने में रका है। अधिक म अधिक दस वष तक का बढाग्रभमकारावाम या कारावाम का दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 194—न्यायिक आभियागिक या पुलिस के कार्य में सहायता पहुँचाते हुए अथवा समका कार्यान्वित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति का जिमान अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग करके जिस व्यक्ति का बढा कर लिया हो या निन्द कर लिया है। छ माग म उकर दस वष तक का बढाग्रभमकारावाम या कारावाम का दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 195—न्यायिक आभियागिक या पुलिस के कार्य में सहायता पहुँचाते हुए या उसे कार्यान्वित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति का जिमान अपने कनव्य के पालन में किसी आपराधिक अभियुक्त या अन्य व्यक्ति के प्रति कोई हिंसा या

क्रूरता का कार्य किया हो अधिक से अधिक सात वर्ष तक का कठोरश्रम कारावास या कारावास का दण्ड दिया जायगा।

यही दण्ड उस व्यक्ति के संबंध में भी लागू होगा जिसने विधि या अध्यादेश द्वारा परिचरित किसी व्यक्ति के प्रति जिसकी वह रखवाजी कर रहा हो या न्यायाधीन जा रहा हो हिंसा या क्रूरतापूर्ण कार्य किया हो।

अनु० 196—प्रत्येक व्यक्ति का जमान पिटने दो अनुच्छेदों में निर्दिष्ट कोई अपराध किया हो और उससे किसी अन्य व्यक्ति की न्याय की हो या घायल किया हो घायल करने के दण्ड एवं उक्त दण्ड की तुलना में प्राप्त गुस्तर दण्ड दिया जायगा।

अनु० 197—यदि किसी एक कर्मचारी या विवाचक (मध्यस्थ) ने अपने कर्तव्य के संबंध में उत्काच (धूम) किया हो मांगा हो या लेने की प्रतिज्ञा की हो तो उसे अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा यदि याचना के बाद स्वीकार किया हो तो उसे पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

उस दशा में जबकि किसी व्यक्ति ने लाक-कर्मचारी या विवाचक होने के अभिप्राय से अपन कर्तव्य के संबंध में याचना की स्वीकृति पर उत्काच किया हो या उमरा माग की हो तो उस जब वह लाक-कर्मचारी या विवाचक होता है अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 197-(2)—उस दशा में जब कि किसी लाक-कर्मचारी या विवाचक ने अपन कर्तव्य के संबंध में किसी तीसरे पक्ष को, प्रार्थना की स्वीकृति पर पूरा देने के लिए प्रेरित किया हो मांग किया हो या प्रतिज्ञा की हो तो उस अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 197-(3)—उस दशा में जब कि कोई लाक-कर्मचारी या विवाचक पिछले दो अनुच्छेदों में निर्दिष्ट अपराधों का करने के बाद कोई अनुचित कार्य करता है या कोई उचित कार्य छोड़ देता (नहीं करता) है, उस कम से कम एक वर्ष का मामित कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यही नियम उस दशा में भी लागू होगा जब कि किसी एक-कर्मचारी या विवाचक ने अपन कर्तव्य-न्याय में किया अनुचित कार्य के लिए जान या उचित कार्य के छोड़ देने के संबंध में धूम किया हो मांगा हो या न्याय की प्रतिज्ञा की हो अथवा किसी तीसरे पक्ष को देने के लिए प्रेरित किया हो मांग की हो या प्रतिज्ञा की हो।

उम दंगा में जहाँ कि कोई व्यक्ति लात कमचारी या विवाचक रहा हो और जिसने अपन कायदा में प्रायना का म्वाहृति पर किसी अनुचित काम के करने या उचित काम के न करने के मन्त्र में घूम किया हो मीमा हो या लेने की प्रतिना की हो तो उम अधिन स अधिन तीन बष तर का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 197 (4) —अभियुक्त द्वारा या परिस्थितिया के ज्ञान रखने वाले किसी तीमर पन द्वारा लिया गया घूम जलन कर लिया जायगा, उम दंगा में जहाँ कि घूम का पूरा या कोई भाग जलन न हो गव तो उमर बराबर की अनिरिक्त मुद्रा बमूठ कर ली जायगी ।

अनु० 198 प्रत्येक व्यक्ति का जिसन अनु० 197 स 197 (3) तर क अनुच्छेद में निर्दिष्ट घूम किसी गलत-कमचारी या विवाचक का दिया हो निवेदन किया हो या दना रवाचार किया हो अधिन स अधिन तीन बष तर का कठोरश्रमकारावास या 5 000 बन तर का अयदण्ड दिया जायगा ।

यदि पिठन परिष्ठन क अपराधा का काद अभियुक्त अपना प्रपाप्पान कर दिया हो तो उसका दण्ड हल्ला या क्षमा कर दिया जायगा ।

अध्याय 26

मानव-वध के अपराध

“सत्सुजिन नो सुमि”

अनु० 199 प्रत्येक व्यक्ति का जिसन किसी अप व्यक्ति का मार डाला हो प्राण-दण्ड या आजीवन या कम स कम तीन बष का कठोरश्रम कारावास दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 200—प्रत्येक व्यक्ति का जिसन अपन किसी पुरुष या अपन विवाहित जाड़े क पुरुष को मार डाला हो प्राण-दण्ड या आजीवन कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 201—प्रत्येक व्यक्ति का जिसन पिछे दो अनुच्छेद में निर्दिष्ट अपराधा में से किसी एक को करने के अभिप्राय से सैपारी की हो अधिन स अधिन दो बष तर का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा किन्तु परिस्थितियों के अनुसार उसका दण्ड क्षमा भी किया जा सकता है ।

अनु० 202—प्रत्येक व्यक्ति या जिसने किसी अन्य व्यक्ति या आत्म हानि करने के लिए प्रेरित किया है या अन्य व्यक्ति की प्राप्ति पर या उगरी ममता से उग्र मार डाला है या उग्रमें मारपीट पर्व्वार्द्ध हो छ माग से लेख मान वष तर या तटोरथमरागसग या रागसग या दण्ड दिया जायेगा ।

अनु० 203 अनु० 199 अनु० 200 तथा पिछले अनुच्छेद के अपराधों के प्रत्येक भी दण्डनीय होंगे ।

अध्याय 27

घायल करने का अपराध

“शोकाह नो त्सुमि”

अनु० 204 प्रत्येक व्यक्ति या जिसने अन्य किसी व्यक्ति को घायल कर दिया है अधिक से अधिक दण्ड वष तर या तटोरथमरागसग या 500 येन तर या अपदण्ड या तट्टे लघु अथदण्ड दिया जायेगा ।

अनु० 205— प्रत्येक व्यक्ति या, जिसने अन्य किसी व्यक्ति को घायल कर दिया है और उग्रमें उग्रमें किया कर दो हो, तम में वम दो वष या मौमित तटोरथमरागसग दण्ड दिया जायेगा ।

उग दगा में जयति यह अपराध अपराधों के संदीय पूर्वज के प्रति या विवाहित जाड़े के प्रति हुआ हो तो अपराधों की आज्ञाया या वम से तम मौन वष या तटोरथमरागसग दण्ड दिया जायेगा ।

अनु० 206— प्रत्येक व्यक्ति या जिसने पिछले दो अनुच्छेदों में निर्दिष्ट अपराधों के करने समय अपराधों या उत्पाति किया हो, अधिक से अधिक एत वष तर या तटोरथमरागसग या 50 येन तर या अपदण्ड या लघु अपदण्ड दिया जायेगा भवे हो उग्रमें किसी को घायल न किया हो ।

अनु० 207 यदि दो या अधिक व्यक्तियों ने किसी अन्य व्यक्ति पर वात्त-प्रमाण किया हो और ऐसा करने उन्होंने उग्र व्यक्ति को घायल कर दिया है ता उन्हें वम हो व्यवहार किया जायेगा, जैसा कि मरागसगसग के मवष में किया जाता है चाहे उग्रों सामुक्ति रूप में कार्य न किया हो, यदि चांटों की मागसगसगसग का निर्णय अगमय है अथवा यह जानना अगमय हो कि वगुत तट्टे किम व्यक्ति द्वारा पर्व्वार्द्ध गई ।

श्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा। यदि उम (गर्भपात) से वह मर जाय या घायल हो जाय तो उमका दण्ड तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास होगा।

अनु० 214—जिसी भी वैध दार्द औषधवाग्ग या दृगिष्ट का, जिसने जिसी स्त्री का गर्भपात उसकी प्रायता पर या उमकी सम्मति से कराया हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा। यदि दम (गर्भपात) से वह मर जाय या घायल हो जाय तो दण्ड छ मास से लेकर मान वष तक का कठोरश्रमकारावास होगा।

अनु० 215—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने किसी स्त्री का गर्भपात, बिना उसकी प्रायता पर या बिना सम्मति से कराया हो, छ मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

विच्छेद परिच्छेद में लिखित अपराध का प्रयत्न भी दण्डनीय होगा।

अनु० 216—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने विच्छेद अनुच्छेद में निर्दिष्ट अपराध किया हो और उसमें उसने किसी स्त्री की हत्या कर दी हो या चोट पहुँचाई हो तो उक्त दण्ड अब चाट पहुँचाने के दण्ड की तुलना करने पर जो मुक्तर दण्ड होगा, वही दिया जायगा।

अध्याय 30

अभित्याग के अपराध

“इकि नो त्सुमि”

अनु० 217—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने महायत्ना की अपेक्षा के समय, अन्य व्यक्ति का अभित्याग, वृद्धता, बाल्यवन, कुम्पता या रोग के कारण कर दिया हो, अधिक ग अधिक एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 218—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी वृद्ध, बालक, कुम्प या अन्य व्यक्ति का, जिसकी उमे रक्षा करनी चाहिए, अभित्याग कर दिया हो या उक्त व्यक्ति या जीवित रहने के लिये अपेक्षित गरक्षण प्रदान करने में अगम्य रहा हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अभिप्राय के अपराध

यदि यह अपराध आरोपी के विरुद्ध बनीय पूर्वज्ञ या उसके विवाहित जाते में से किसी के प्रति किया गया हो तो अपराधी का छ मास में लेकर मान वषं तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 219—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले दो अनुच्छेदों में निर्दिष्ट में से किसी अपराध का करने किसी व्यक्ति का मार हाथा हा या घाट पहुँचाया है, उसका दण्ड एक घाट पहुँचाने के अपराध की तुलना में जा गुनतर दण्ड होगा, दिया जाएगा।

अध्याय 31

(अवैध) बन्दीकरण एवं परिगोध के अपराध

“तद्गो आयोयि कम्किन् नो लुमि”

अनु० 220—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने किसी अन्य व्यक्ति का अवैध रूप से बन्दी कर लिया है या परिगोध कर लिया है, तीन मास में लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा। यदि यह अपराध जहागी के किसी बनीय पूर्वज्ञ या उसके विवाहित जाते में से किसी के प्रति किया गया हो तो अपराधी का छ मास में लेकर मान वषं तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 221—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट अपराध का करने में किसी व्यक्ति का मार हाथा हा या घाट पहुँचाया है, ता उसका अपराध एक घाट पहुँचाने के अपराध की तुलना में जा गुनतर दण्ड होगा, बही दिया जाएगा।

अध्याय 32

अभिप्राय के अपराध

“क्योहकु नो लुमि”

अनु० 222—प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने अन्य व्यक्ति को, उसके जीवन, शरीर, स्वतन्त्रता, स्थान या संपत्ति को हानि पहुँचाने की धमकी दी हो, अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 500 येन तक का जर्बदण्ड दिया जाएगा।

हानि पहुँचाया हो, तीन वर्ष तक का बढोत्थमद्वारावास या सामान्य कारावास अथवा 1,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा ।

किसी भी मृत-व्यक्ति की ख्याति को हानि पहुँचाने वाला व्यक्ति का तब दण्डित नहीं किया जाएगा जब तक कि उक्त हानि असत्य रूप से न की गई हो ।

अनु० 230-(2)—जब पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 के कार्य को, जनहित एवं जनता के लाभ सबंधन के एकमात्र उद्देश्य से संबद्ध तथ्यों के अभियोजन में किया गया समझा जाएगा तो उक्त अपराध दण्डनीय नहीं होगा, यदि तथ्यों की छान-बीन में उक्त कार्य की सत्यता निश्चित हो जाए ।

पिछले परिच्छेद में निर्दिष्ट उपबन्ध के विनियोग में, किसी अपराध-कार्य से संबद्ध तथ्यों का, जो कार्य कि उस व्यक्ति द्वारा संपादित हो जा उस विषय में अभियोजित न किया गया हो, मार्गजनिक हित में संबद्ध तथ्यों के रूप में समझा जाएगा ।

जब पिछले अनुच्छेद के परि० 1 का कार्य, किसी लोक-सम्वर्धनीय या किसी निर्वाचकीय लोक-कार्यालय के उम्मीदवार के विषय में संबद्ध तथ्यों के अभियोजन में किया गया हो तो उक्त कार्य दण्डनीय नहीं होगा, यदि छानबीन होने पर उक्त कार्य की सत्यता निश्चित हो चुकी हो ।

अनु० 231—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी व्यक्ति का बिना तथ्यों के अभियोजन के ही मार्गजनिक रूप से अपमानित किया हो, दण्डित निरोध या लघु अर्थदण्ड दिया जाएगा ।

अनु० 232—इस अध्याय के सभी अपराधों पर कार्यवाही परिवार पर ही की जाएगी ।

यदि परिवार का करने वाला सम्राट् (Emperor) सम्राज्ञी (Empress) विधवा महा सम्राज्ञी (Grand Empress Dowager) या विधवा सम्राज्ञी (Empress Dowager) या सम्राज्ञीय उत्तराधिकारी (Imperial Heir) हो तो परिवार प्रधानमन्त्री को उसी तरफ में करना होगा; और यदि परिवार-कर्ता कोई विदेशी अधिराज (Sovereign) या राष्ट्रपति (President) हो तो उसका प्रतिनिधि इसे उसकी तरफ में करेगा ।

अनु० 238—प्रत्येक चार, जिसने कोई संपत्ति चुराकर, उस चुराई हुई संपत्ति की पुनः प्राप्ति को रोकने, बन्दीकरण से बचने या अपराध के बिन्दु को लुप्त करने के लिए बल-प्रयोग किया है या घमकी दी है, लूट का अपराधी होगा।

अनु० 239—प्रत्येक व्यक्ति जिसने अन्य व्यक्ति की संपत्ति का उन बेहोमी (मूर्छा) में बुरा चुग लिया है, लूट का अपराधी होगा।

अनु० 240—यदि किसी लुटेरे ने किसी व्यक्ति का घायल किया हो तो उसे आजीवन या कम से कम सात वर्ष का बठारथमकारावास का दण्ड दिया जाएगा, यदि उसने किसी की हत्या कर डाली है तो उसे प्राण-दण्ड या आजीवन बठारथमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 241—यदि किसी लुटेरे ने किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया हो तो उसे आजीवन या कम से कम सात वर्ष का बठारथमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 242—इस अध्याय के अपराधों से संबंध व्यवस्थाओं (उपबन्धों) के विनियाम में वह संपत्ति या किसी लोक-कार्यालय के आदेशानुसार किसी व्यक्ति के अधिकार में हो या उसकी देखभाल में हो, उसी व्यक्ति की मानी जाएगी चाहे उस पर भल ही दूगरे का स्वामित्व हो।

अनु० 243—अनुच्छेद 235, 236 तथा 238 से 241 तक के अनुच्छेदों के अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अनु० 244—अनुच्छेद 235 के अपराध का या उसके प्रयत्न का दण्ड, जो कि अपराधी द्वारा अपने वंशीय गुरु-सबन्धी, विवाहित जाड़े, या उसी घर में मार रहने वाले किसी सबन्धी के विरुद्ध किया गया है, क्षमा कर दिया जाएगा; किन्तु यदि अपराध अन्य सबन्धियों के विरुद्ध किया गया हो तो उसकी कार्यवाही परिवार पर ही की जाएगी।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था, उन संयुक्त अपराधियों के संबंध में लागू नहीं होगी, जो सबन्धी न हों।

अनु० 245—इस अध्याय के अपराधों से संबंध की प्रत्येक में विजली को संपत्ति माना जाएगा।

अध्याय 37

धोखेबाजी (Fraud) और भयादोहन (Blackmail; दम से ऐंठने) के अपराध

‘ममि ओयोत्रि क्योऋत्सु नो त्सुमि’

अनु० 246 दूसरे व्यक्ति का धारा देनेवाला और उस धारा में उसकी मर्ति न बनवाने प्रत्येक व्यक्ति का दम का नर का बंशरधम-कारावास का दण्ड दिया जाएगा ।

यही व्यवस्था उस व्यक्ति के मरने में भी लागू होगी जिसने पिछले परिच्छेद के अन्तर्गत कोई अवैध आर्थिक लाभ लिया है या लाने के लिए प्रेरित किया है ।

अनु० 247—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध व्यवसाय का प्रयत्न करने में असफलता का अनुभव किया हो या अपने स्वामी की हानि करने के अभिप्राय में असफल व्यवसायिक कार्रवाई की हो या उसने अपने स्वामी का आर्थिक हानि का हानि कर तक का बंशरधम-कारावास या 100 घंटे तक का अथवा दण्ड दिया जाएगा ।

अनु० 248—प्रत्येक व्यक्ति का जिसने किसी अन्य व्यक्ति का अपराधिक बुद्धि या किसी व्यक्ति के निराले मस्तिष्क का अनुचित लाभ उठाने हुए उसका मर्ति न लिया है या अवैध आर्थिक लाभ लिया है या किसी तीसरे पक्ष में धमकाया है । दम का नर का बंशरधम-कारावास का दण्ड दिया जाएगा ।

अनु० 249 प्रत्येक व्यक्ति का जिसने किसी व्यक्ति का आनन्द करने उस अपनी मर्ति देने का प्रयत्न किया है दम का नर का बंशरधम-कारावास का दण्ड दिया जाएगा ।

यही नियम उस व्यक्ति के संबंध में भी लागू होगा जिसने पिछले परिच्छेद के अन्तर्गत किसी से स्वयं अवैध आर्थिक लाभ लिया है या किसी तीसरे पक्ष का हानि के लिए उत्साह दिया है ।

अनु० 250—इस अध्याय के अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे ।

अनु० 251—अनुच्छेद 242 244 तथा 245 की व्यवस्थाएँ पर्याप्त परिचय के साथ इस अध्याय के अपराधों के संबंध में भी लागू होंगी ।

अध्याय 38

छलपूर्ण विनियोजन के अपराध

“ओर्यो नो त्सुमि”

अनु० 252—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने पास में रखी हुई दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु का, अपने प्रयोग में विनियुक्त कर (लगा) लिया हो, पाँच वर्ष तक का बठोरथमनारावास का दण्ड दिया जाएगा।

यही व्यवस्था उस व्यक्ति के संबंध में भी लागू होगी जिसने अपनी उस वस्तु का विनियुक्त कर लिया हो, जिसको अधिकार में रखने के लिए उसे किसी लाव-कार्यालय द्वारा आदेश मिला हो।

अनु० 253 प्रत्येक व्यक्ति को जिसने अपने प्रयोग के लिए अपने व्यवसाय (व्यापार) के सिलसिले में, अधिकार में रखी हुई किसी दूसरे की वस्तु का विनियुक्त कर लिया हो, इस वर्ष तक का बठोरथमनारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 254—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने अपने प्रयोग के लिए, किसी छोई हुई वस्तु, हवा या पानी द्वारा स्वयं एखित कोई वस्तु या संपत्ति जिसका कोई स्वामी न हो, विनियुक्त कर लिया हो, एक वर्ष तक का बठोरथमनारावास या 100 येन तक का अथवा कोई लघु अर्थदण्ड दिया जाएगा।

अनु० 255—अनु० 244 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, इस अध्याय के अपराधों के संबंध में भी लागू होगी।

अध्याय 39

चोरी के मालों से संबद्ध अपराध

“ओयुत्सु नि कन-सुरु त्सुमि”

अनु० 256—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने (जानबूझकर) चोरी का माल ग्रहण किया हो, तीन वर्ष तक का बठोरथमनारावास का दण्ड दिया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने चोरी के मालों का (जानबूझकर) परिवहन किया हो, उन्हें अपने पास रखने के लिए जमा किया हो, गरीदा हो या इनके निर्वर्तन (disposal) में दलाल का काम किया हो दस वर्ष तक का बठोर-थमनारावास तथा 1,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा।

अनु० 257—पिछे अनुच्छेद के अपराध का दण्ड क्षमा कर दिया जाएगा, यदि वह अपराध दसोंय स्कन-मन्त्रिया, विवाहित जाड़े या गाय रहनेवाड़े मन्त्रिया नया दम्पति के बीच हागा ।

पिछे परिच्छेद की व्यवस्था उम मन्त्र-अपराधी के मरण में लागू नहीं होगी, जा मन्त्रो न हो ।

अध्याय 40

बिनाश (Destruction) एवं छिपाने (Concealment) के अपराध

“किंकि ओयोनि इन्तोऊ नो तुमि”

अनु० 258 प्रत्येक व्यक्ति का जिनन किसी गार-नारपात्र्य के उपयोग में आने वाला किसी प्रत्येक (dean material) का निनष्ट कर दिया हा, तीन मास में गार गान वष मर का कटारधम-नारावाग का दण्ड दिया जाएगा ।

अनु० 259 प्रत्येक व्यक्ति का जिनन अन्य व्यक्ति के अधिकारा या दायित्वा न मरुद प्रत्येक (document) का नष्ट कर दिया हा, पाँच वर्ष तक का कटारधम-नारावाग का दण्ड दिया जाएगा ।

अनु० 260 प्रत्येक व्यक्ति का जिनन अन्य व्यक्ति क भवन या जग्याने का हानि पहुँचाई हा या नष्ट कर दिया हा पाँच वर्ष तक का कटारधम-नारावाग का दण्ड दिया जाएगा । यदि ऐसा करने में उमने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी हा या घायल कर दिया हा तो उम उमन अपराध एवं घायल करने क अपराध की तुलना में जा गुन्तर दण्ड हागा वही दिया जाएगा ।

अनु० 261 प्रत्येक व्यक्ति का जिनने पिछे तीन अनुच्छेदों में उल्लिखित वस्तुओं स चिन्न कोई वस्तु नुनसान कर दी हा निनष्ट कर दिया हा या अन्य किसी तरह से उम व्यथ (useless) कर दिया हा, तीन वर्ष तक का कटारधम-नारावाग या 500 येन तक का अथदण्ड या कोई लघु अर्थ-दण्ड दिया जाएगा ।

अनु० 262—पिछे तीन अनुच्छेदों क दण्ड उस व्यक्ति के मन्त्र में भी लागू हागे जिसने अपनी वस्तु का भी, जा कुर्ची में हो जिसक वास्तविक

अधिकारी का निश्चय न हो, या भाड़े (पट्टे) पर दी गई हो, नुकसान किया हो, विवश्ट किया हो या दूसरे ढंग से अनुपयोगी बना दिया हो ।

अनु० 263—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अन्य व्यक्ति के पय को छिपा लिया हो छ मास तक का कठारथमकारावास या सामान्य कारावास या 50 येन तर का अर्थदण्ड या कोई लघु अर्थदण्ड दिया जाएगा ।

अनु० 264 अनुच्छेद 259, 261 तथा पिछले अनुच्छेद के अपराधों का अभियोजन केवल परिवार पर ही किया जाएगा ।

— —

अनु० 4—यदि किसी उच्चतर न्यायालय में लम्बित विविध न्यायालया के वास्तविक अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आने वाले विविध सबद्ध अभियागा के साथ कोई ऐसा अभियोग हो जिसका उच्चतर न्यायालय अन्या के साथ सामूहिक रूप से निणय देना आवश्यक समझ तो वह उस एक व्यवस्था (ruling) द्वारा किसी अधिकार-क्षेत्र संपन्न निम्न न्यायालय में अन्तर्गत कर सकता है।

अनु० 5—जब किसी उच्चतर न्यायालय एक निम्न न्यायालय में अनेक सबद्ध अभियाग (cases) विविध रूप से लम्बित हों उच्चतर न्यायालय वास्तविक अधिकार क्षेत्र का बिना विचार किए हुए ही एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, निम्न न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले अभियाग पर भी सामूहिक रूप से निणय दे सकता है।

जब किसी उच्च न्यायालय के विशेष अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आने वाले अभियोग किसी उच्च न्यायालय में लम्बित हों और उल्लिखित अभियागों से सबद्ध अभियोग किसी अवर न्यायालय में लम्बित हों तो उच्च न्यायालय, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा अवर न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आने वाले अभियागों पर भी सामूहिक रूप से निणय दे सकता है।

अनु० 6—जब विविध न्यायालयों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अन्दर आने वाले अनेक अभियोग (cases) परस्पर सम्बद्ध हों तो वह न्यायालय जिसके अधिकार-क्षेत्र में एक भी अभियाग आता हो अन्य अभियोगों पर भी, सामूहिक रूप से अपना अधिकार-क्षेत्र प्रयुक्त कर सकता है। तथापि, वह न्यायालय उन अभियागों पर अपना अधिकार-क्षेत्र प्रयुक्त नहीं कर सकता, जो अन्य विधियाँ की व्यवस्थाओं (Provisions) के अनुसार किसी विशेष न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं।

अनु० 7—यदि किसी एक न्यायालय में लम्बित, विविध न्यायालयों के प्रादेशिक अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आने वाले अनेक परस्पर सबद्ध अभियागों के साथ कोई ऐसा अभियाग हो जिसका वह न्यायालय अन्या के साथ, सामूहिक रूप से निणय देना आवश्यक समझता हो तो वह एक व्यवस्था (ruling) द्वारा उसी अन्य न्यायालय में अन्तर्गत कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह अभियाग आता हो।

अनु० 8—जब वास्तविक अधिकार-क्षेत्र के विषय में अनुम्न विविध न्यायालयों में अनेक परस्पर सबद्ध अभियाग अनेकानेक लम्बित हों तो वह

न्यायालय किसी लात-समाहर्ता (Public Prosecutor) या अभियुक्त के समावेदन (motion) पर, किसी व्यवस्था (ruling) द्वारा, यह निर्णय दे सकता है कि वे किसी न्यायालय में एत्र कर दिए जाएँ।

यदि विच्छेद परिच्छेद की स्थिति में विविध न्यायालयों की व्यवस्थाएँ (rulings) एवमन न हों तो उक्त सभी न्यायालयों का अधिकार-क्षेत्र में रहने वाला अन्य आसन्न उच्चतर न्यायालय, किसी लात-समाहर्ता या अभियुक्त की प्रार्थना पर, एक व्यवस्था (ruling) के आधार पर यह निर्णय दे सकता है कि उक्त सभी अभियोग किसी एक न्यायालय में एत्र कर दिए जाएँ।

अनु० 9—दा या अधिक अभियोग निम्नलिखित दशाओं में परस्पर सख्त हात है,

- (1) जहाँ कि एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक अपराध किए गए हों;
- (2) जब कि अनेक व्यक्ति सामूहिक रूप में कोई एक अपराध किए हों या अलग-अलग अपराध किए हों।
- (3) जहाँ दुर्भाग्य में काय करने-वाले अनेक में से हर व्यक्ति पृथक्-पृथक् अपराध करता है।

अपराधी का आशय देने, मादय व बिलप्ट करने, शपथ लेकर मिथ्या-मादय देने मिथ्या बिसौद-मादय या मिथ्या-व्याख्या के अपराध तथा असद रूप से प्राप्त वस्तुओं से सबूत अपराधी तथा, प्रधान अथवा अन्य द्वारा किए गए अपराध का सामूहिक रूप से किया गया माना जाएगा।

अनु० 10 जब एक ही अभियोग वास्तविक अधिकार क्षेत्र की दृष्टि से भिन्न विविध न्यायालयों में लम्बित हो तो इसका निर्णय किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

उच्चतर न्यायालय किसी लात-समाहर्ता या अभियुक्त के समावेदन (motion) पर एक व्यवस्था (ruling) द्वारा उक्त अभियोग को किसी अधिकार-क्षेत्र-संपन्न न्यायालय को निर्णय के लिए उद्युक्त कर सकता है।

अनु० 11—जब एक ही अभियोग समान वास्तविक अधिकार-क्षेत्र वाले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हो तो उक्त अभियोग का निर्णय उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जहाँ लात-कार्यवाही सर्वप्रथम की गई हो।

ऐसे सभी न्यायालयों को अपने अधिकार-क्षेत्र से प्रभावित करने वाला अन्य आसन्न उच्चतर न्यायालय, किसी लात-समाहर्ता या अभियुक्त के समावेदन

(motion) पर एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, अन्य न्यायालय को उस अभियोग के निणय के लिए उद्युक्त कर सकता है, जहाँ लाव-कार्यवाही बाद में की गई हो।

अनु० 12—तथ्या के प्रवटीकरण की आवश्यकता के अनुसार कोई न्यायालय अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आनेवाले जिले के बाहर भी अपने कार्य कर सकता है।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ (provisions) राजादिष्ट न्यायाधीशों के समक्ष में, यथाचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगी।

अनु० 13—न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र में न जाने के कारण कार्यवाहियाँ प्रभाव दून्य नहीं होंगी।

अनु० 14—अविलम्बिता (urgency) की दशा में, कोई भी न्यायालय अधिकार-क्षेत्र मरुत न होते हुए भी, तथ्या के प्रवटीकरण के लिए आवश्यक उपाय प्रमाण में ला सकता है।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ (provisions) राजादिष्ट न्यायाधीशों के समक्ष में यथाचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगी।

अनु० 15 निम्नलिखित दशाओं में कोई लाव-समाहर्ता, अधिकार-क्षेत्र-मरुत न्यायालय के निश्चय में मरुद सभी प्रथम न्यायालयों को अपने अधिकार-क्षेत्र से प्रभावित करने वाले किसी आमत्र उच्चतर न्यायालय को समावेदन प्रस्तुत कर सकता है

- (1) जय कि क्षमताशील न्यायालय की क्षमता का निर्धारण जिला-विषयक सीमाओं के स्पष्ट निदिष्ट न होने के कारण न हो सके;
- (2) जय कि उस अभियोग का अपने अधिकार-क्षेत्र में रखने वाला अन्य कोई न्यायालय न हो, जिसके विषय में किसी न्यायालय को अधिकार-क्षेत्र न रहित घोषित करने वाला कोई निर्णय अन्ततः बन्धनकारी न हो गया हो।

अनु० 16—जय कि विधानन अधिकार क्षेत्र मरुत कोई न्यायालय न हो, अथवा ऐसे न्यायालय का निश्चय अमरुत हो गया हो, तो महासमाहर्ता (Prosecutor General) अधिकार-क्षेत्र मरुत न्यायालय के नामनिर्देशन करने के लिए, उच्चतम न्यायालय का प्रार्थना (समावेदन) प्रस्तुत करेगा।

- (1) यदि वह स्वयं अपवृत्त पक्ष हो,
- (2) यदि वह अभियुक्त या अपवृत्त-पक्ष का सवधी हो या रह चुका हो,
- (3) यदि वह अभियुक्त या अपवृत्त पक्ष का वैध प्रतिनिधि, सरसक्ता या पर्यवेक्षक या पालक (क्युरेटर) हो,
- (4) यदि उसने उस अभियोग में साक्षी या विशेषज्ञ साक्षी के रूप में काम किया हो,
- (5) यदि उस अभियोग में उसने अभियुक्त के प्रतिनिधि, परामर्शदाता या सहायक के रूप में काम किया हो,
- (6) यदि उसने उस अभियोग में लोक-समाहर्ता या न्यायिक-पुलिस (आरसी) अधिकारी का कार्य किया हो,
- (7) यदि उसने, अनु० 266 प्रभाग 2 में उल्लिखित व्यवस्था (ruling) में, क्षिप्र आदेश (Summary order) में, निचले न्यायालय के निर्णय में, अनु० 398 से 400, 412 या 413 के अनुसार अन्तरिम या प्रति-प्रेषित अभियोग के प्राथमिक निर्णय में, या उन छानबीन में, जो ऐसे अभियोगों के आधारभूत हो, भाग लिया हो। परन्तु यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी यदि उसने एक अधिप्राप्त (requisitioned) न्यायाधीश के रूप में भाग लिया हो।

अनु० 21—उस दशा में, जब कि किसी न्यायाधीश को उसके कृत्यों से अपवर्जित करना हो, या यह भय हो कि वह पक्षपातपूर्ण निर्णय देगा तो उसके विषय में कोई लोक-समाहर्ता या अभियुक्त आपत्ति कर सकता है।

प्रतिवाद परामर्शदाता (Defense Counsel), अभियुक्त के लाभार्थ आपत्ति के लिए प्रावेदन (motion) कर सकता है, किन्तु अभियुक्त के स्पष्टतया व्यक्त अभिप्राय के विरुद्ध नहीं।

अनु० 22—अभियोग में किसी अभियाचना (demand) या विवरण (statement) के सपन्न हो जाने पर किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि उसने पक्षपातपूर्ण निर्णय देने का भय है। परन्तु, यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी यदि वह पक्ष आपत्ति के किसी आधार की जानकारी से अनभिज्ञ रहा हो, या ऐसा आधार (उन अभियाचना या विवरण के) वाद में हुआ हो।

अनु० 23—जब किसी न्यायाधीश के विरुद्ध, या किसी महयोगी (collegiate) न्यायालय का सदस्य हो, आपत्ति की गई हो तो वह न्यायालय, जिसका कि वह न्यायाधीश है, उस पर एक व्यवस्था (ruling) लागू करेगा। यदि ऐसी दशा में उक्त न्यायालय जिला-न्यायालय हो, तो व्यवस्था (ruling) किसी सहयोगी न्यायालय द्वारा लागू की जायगी।

जब किसी जिला-न्यायालय के या परिवार-न्यायालय (Family Court) के एकमात्र किसी न्यायाधीश के विरुद्ध आपत्ति की गई हो तो व्यवस्था (ruling) उस न्यायालय के सहयोगी न्यायालय द्वारा लागू की जायगी जिससे सबद्ध वह न्यायाधीश है, और जब कि किसी क्षिप्र-न्यायालय (Summary Court) के न्यायाधीश के विरुद्ध की गई हो तो किसी क्षमताशील जिला-न्यायालय के सहयोगी न्यायालय द्वारा लागू की जायगी। तथापि उक्त रूप में आपत्ति किया गया न्यायाधीश, यदि आपत्ति के प्रावेदन (motion) का साकार पाना है ना व्यवस्था (ruling) की गई हो समझी जाएगी।

इस प्रकार आपत्ति किया गया न्यायाधीश, पिछले दो परिच्छेदों में निर्दिष्ट व्यवस्था (ruling) में कोई भाग नहीं लेगा।

जब किसी आपत्ति किए गए न्यायाधीश के प्रत्याहरण (withdrawal) के फलस्वरूप कोई न्यायालय ऐसी व्यवस्था (ruling) चालू करने में असमर्थ हो तो व्यवस्था (ruling) अन्य क्षमता उच्चतर न्यायालय द्वारा दी जायगी।

अनु० 24—किसी आपत्ति का प्रावेदन या कि स्पष्टतः कार्यवाही में केवल बिलम्ब लाने के अभिप्राय से किया गया हो, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा खारिज कर दिया जायगा। ऐसी दशा में पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 3 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। यही नियम उस दशा में भी लागू होगा जब कि अनु० 22 के उपबन्ध या न्यायालय के नियमों द्वारा निर्धारित कार्यवाही के उत्तराधिकार के मध्य में आपत्ति के लिए किया गया प्रावेदन खारिज करना हो।

पिछले परिच्छेद की दशा में, कोई राजादिष्ट (Commissioned) न्यायाधीश किसी जिला-न्यायालय का एकमात्र न्यायाधीश, किसी परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय (Summary Court) का कोई न्यायाधीश, जिसके विरुद्ध आपत्ति की गई हो, आपत्ति के प्रावेदन को खारिज करते हुए कोई निर्णय दे सकता है।

अनु० 25 - किसी व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध, जिसके द्वारा किसी आपत्ति का प्रावेदन खारिज किया गया हो एक आमन फीकीसु अपील की जा सकती है।

अनु० 26 अनु० 20, प्रभाग 7 के उपबन्धों का छोड़कर, इस अध्याय के उपबन्ध न्यायालय-लिपिका के मकम में, यथाचिन् परिवर्तन के साथ, लागू होंगे।

व्यवस्था (ruling) उसी न्यायालय द्वारा दी जायगी जिससे सबद्ध वह लिपिक हागा। तथापि अनु० 24 परिच्छेद 1 में उल्लिखित स्थिति में आपत्ति के प्रावेदन का खारिज करने के लिए नियम उस राजादिष्ट न्यायाधीश द्वारा दिया जाएगा जिससे वह न्यायालय-लिपिक सबद्ध है।

अध्याय 3

वाद-करण सामर्थ्य

अनु० 27 जब अभियुक्त या सदस्य व्यक्ति कोई न्यायिक व्यक्ति हो तो प्रक्रिया अधिनियमों के संवध में उसका अभिवेदन किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा।

उस दशा में भी जब कि किसी न्यायिक व्यक्ति का अभिवेदन दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया हो, प्रक्रिया अधिनियमों के संवध में उसका अभिवेदन प्रत्येक द्वारा पृथक् रूप से होगा।

अनु० 28—यदि, जहाँ ऐसे अपराध का अभियोग हो जिसमें दण्ड-महिता के अनु० 39 से 41 तक के उपबन्ध न लागू हों, अभियुक्त या सदस्य मानसिक शक्ति से रहित हो तो प्रक्रिया अधिनियमों के संवध में उसका अभिवेदन किसी वैध प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा (जब कि दो व्यक्ति हों जिनमें से प्रत्येक पक्ष प्रभाव जमाता हो। यही व्यवस्था इसके आगे भी लागू होगी)।

अनु० 29—पिछले दो अनुच्छेदों के उपबन्धों के अनुसार जब अभियुक्त के अभिवेदन के लिए कोई व्यक्ति न हो तो किसी लोक-समाहर्ता या पदेन लोक-समाहर्ता के निवेदन पर न्यायालय द्वारा एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया जायगा।

यही नियम उस दशा में भी लागू होगा जब कि पिछले दो अनुच्छेदों के उपबन्धों के अनुसार सदस्य के अभिवेदन के लिये कोई व्यक्ति न हो और

लोक-समाहर्ता न्यायिक-आस्था (Police) अधिकारी या उसमें दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति द्वारा उक्त निवेदन किया गया हो ।

विवाद प्रतिनिधि अपने कार्यों का तब तक करेगा जब तक कि सश्रित या अभियुक्त के प्रतिनिधि के रूप में कार्यवाही के कार्य का करने के लिए अन्य कोई व्यक्ति न जा जाय ।

अध्याय 1

परामर्शदाता द्वारा प्रतिवाद तथा संबंधियों द्वारा सहायता

अनु० 30 अभियुक्त या सश्रित किसी मामले प्रतिवाद परामर्शदाता (Defense Counsel) का चुन सकता है ।

अभियुक्त या सश्रित का वैध प्रतिनिधि पाट्र (Tutor) विवाहित जाति बनाय सकता भाद या बन्त स्वतंत्र रूप से उमर लिए प्रतिवाद परामर्शदाता चुन सकता है ।

अनु० 31 परामर्शदाता का चुनाव अधिकारताया (Adversely) में से होगा ।

सिप्र-न्यायालय (Summary Court) परिवार-न्यायालय या जिला न्यायालय में प्रतिवाद-परामर्शदाता का चुनाव अधिकारताया से भिन्न व्यक्तियों में से न्यायालय की अनुमति से किया जा सकता है । तथापि यह नियम सिप्र-न्यायालय में बचत उन स्थानों में लागू होगा जिनमें अधिकारताया में से चुना गया एक अन्य प्रतिवाद-परामर्शदाता हो ।

अनु० 32 राज-कार्यवाही (Public Action) के लिए जान के पूर्व मर्यादित प्रतिवाद-परामर्शदाता का चुनाव प्रथम न्यायालय में भी प्रभावी रहेगा ।

जब कार्यवाही के लिए जान के पश्चात् किया गया प्रतिवाद-परामर्शदाता का चुनाव विचारण (trial) के प्रथम दृष्टान्त के स्थित किया जायगा ।

अनु० 33—उक्त दशा में जब कि अभियुक्त के लिए अनेक प्रतिवाद परामर्शदाता हों तो न्यायालय के तत्त्वसाक्षुसक एक मुख्य-प्रतिवाद परामर्शदाता की नियुक्ति का जाएगा ।

अनु० 34—मुख्य परामर्शदाता के कार्यों (Functions) एवं सामर्थ्य (powers) को जैसा कि पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित है, न्यायालय के नियमों द्वारा विहित किया जाएगा ।

अनु० 35—जैसा कि न्यायालय के नियमों द्वारा विहित है, न्यायालय अभियुक्त या सदिग्ध व्यक्ति के प्रतिवाद-परामर्शदाताओं की सूची नियत कर सकता है । तथापि, जहाँ तक अभियुक्त के प्रतिवाद-परामर्शदाता का संबंध है, यह नियम केवल विशेष परिस्थितियों में ही लागू होगा ।

अनु० 36—जब अभियुक्त, निवृत्तता या अन्य कारणवश अपने प्रतिवाद-परामर्शदाता का चुनने में असमर्थ हो, तो उसकी प्रार्थना पर, न्यायालय उसके लिए प्रतिवाद-परामर्शदाता की व्यवस्था करेगा । तथापि, यह व्यवस्था उन दशा में लागू नहीं होगी जब कि अभियुक्त स भिन किसी व्यक्ति द्वारा उसके लिए प्रतिवाद-परामर्शदाता चुन लिया गया हो ।

अनु० 47—यदि अभियुक्त, प्रतिवाद-परामर्शदाता द्वारा न अभिवेदित किया गया हो तो निम्नांकित दशाओं में, न्यायालय पदेन (ex-officio) उसके लिए परामर्शदाता की व्यवस्था करेगा

- (1) जब अभियुक्त अल्प-वयस्क हो,
- (2) जब अभियुक्त सत्तर (70) वर्ष से कम आयु का न हो,
- (3) जब अभियुक्त बहरा या गुंगा हो,
- (4) जब अभियुक्त अपरिपक्व या दुर्बल-मनस्क हो,
- (5) जब अन्य कारणवश ऐसा आवश्यक समझा जाए ।

अनु० 38—किसी न्यायालय या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा, इन विधि के उपबन्धों के अनुसार नियत किए जाने वाले प्रतिवाद-परामर्शदाता की नियुक्ति अधिवक्ताओं में से होगी ।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था के अनुसार नियुक्त किया गया प्रतिवाद-परामर्शदाता यात्रा-ध्यय, दैनिक भत्ता, आवास-भत्ता तथा शुल्क (fees) को माँग करने का अधिकारी होगा ।

अनु० 39—किसी भी प्रकार के शारीरिक निरोध में रखा गया अभियुक्त या सदिग्ध (व्यक्ति), किसी कार्यालयीय रणवाले की उपस्थिति के बिना, अपने प्रतिवाद-परामर्शदाता या किसी अन्य व्यक्ति से भी, जो उसका प्रतिवाद-

परामर्शदाता हा, उस व्यक्ति की प्रायः पर जिसे प्रतिवाद-परामर्शदाता को चुनने का अधिकार हो भाषान् कर सकता है तथा कोई प्रलेख या अन्य वस्तु ल या दे सकता है (उस दशा में जब कि किसी अभियुक्त से भिन्न कोई व्यक्ति प्रतिवाद-परामर्शदाता चुना जाने वाला हो तो यह नियम तभी लगेगा जब अनु० 31 के परिच्छेद 2 में निर्दिष्ट अनुमति के लो मई हा) ।

निम्न परिच्छेद में उल्लिखित साक्षान्कार या वस्तु क आशान-प्रदान के मन्त्र में विधि या जप्यादेश (जिनमें न्यायालय के नियम भी सम्मिलित हैं । यही नियम इसके आगे भी लागू हागा) द्वारा ऐसे उपाय विहित किए जा सकते हैं, जो अभियुक्त या सदिय को माग निकटने साक्ष के विनाश या परिवर्तन करने या उन वस्तुओं के, आशान-प्रदान करने का प्रतिवाद करें, जो (वस्तुएं) अभियुक्त या सदिय को सन्धक् अभियुक्ता का राय करनी हा ।

साक्ष-ममाहर्ता, साक्ष-ममाहर्ता-कार्यालय का सचिव तथा न्यायिक पुलिस कमिश्नरी (जिनमें न्यायिक पुलिस अधिकारी एवं सिपाही दाता हो सम्मिलित हैं । यही नियम इसके आगे भी लागू हागा) जब छात्रवीन के लिए ऐसा आवश्यक हा, परिच्छेद 1 में उल्लिखित साक्षान्कार तथा वस्तुओं के आशान-प्रदान के लिए, साक्ष-कार्यवाही के पहले ही कोई विधि, स्थाप एवं समय निर्धारित कर दें, परन्तु ऐसा निर्धारण, सदिय (व्यक्ति) का प्रतिवाद के लिए अपने अधिकारों के प्रयोग करन समय, अनुचित रूप से अवरोध में न रने ।

अनु० 40—साक्ष-कार्यवाही की मस्थिति के बाद, प्रतिवाद-परामर्शदाता किसी न्यायालय में अभियुक्त से मन्त्र प्रलेख एवं साक्ष के लेखा का निरीक्षण या उनकी प्रतिलिपि कर सकता है । तथापि साक्ष के लेखा को प्रतिलिपि करने के लिए उसे पीठासीन न्यायाधीश से अनुमति अवश्य लेनी हागी ।

अनु० 41—केवल उस दशा में जब कि यह इस विधि में विशेषरूप से विहित हा, प्रतिवाद-परामर्शदाता कार्यवाही की क्रिया का अपने नाम में ले सकता है ।

अनु० 42—अभियुक्त का वंच प्रतिनिधि, पालक (Curator), विवाहित आंठा, वरीय मन्त्र, भाई या बहन किसी भी समय सहायक (होसेनिन) हो सकते हैं ।

उस व्यक्ति का, जो अभियुक्त के सहायक के रूप में काम करना चाहता हो, विचारण के प्रत्येक दृष्टान्त के लिये न्यायालय में सूचना देनी चाहिए ।

काई भी सहायक अभियुक्त की कार्यवाही की उन सभी प्रियाजा का वहाँ तक कर सकता है जहां तक कि वे अभियुक्त के व्यक्ति अभिप्राय ने विरुद्ध न हो। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा जब कि इस विधि में यह अन्य प्रकार से विहित हो।

अध्याय 5

निर्णय

अनु० 43—इस विधि में अन्य प्रकार से विहित दशा का छोड़कर, काई भी न्याय-निर्णय (हंकेस्तु) मौखिक कार्यवाही के आधार पर दिया जायगा।

काई व्यवस्था (रेल्ड रूलिंग) या आदेश (मेइरेड, order) आवश्यक-रूप से मौखिक कार्यवाही पर जायत नहीं होगा।

विभी व्यवस्था (ruling) या आदेश के निर्माण में न्यायालय, आवश्यकतानुसार तथ्या की छानबीन (Examination) कर सकता है।

पिछले परिच्छेद में लिखित छानबीन किसी सबद्ध सहयोगी न्यायालय (Collegiate Court) के सदस्य का मौख दी जायगी अथवा जिन-न्यायालय परिवार न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय का काई न्यायाधीश इसके लिए अभिप्रायित किया जा सकता है।

अनु० 44—विभी भी निर्णय के साथ उसका कारण संलग्न रहेगा।

उस दशा में जब कि काई ऐसी व्यवस्था (ruling) या आदेश हो, जिसके विरुद्ध किसी अपील की अनुमति नहीं है ता उसके कारण का जलन किया जा सकता है। तथापि, यह उस व्यवस्था (ruling) के मन्थ में लागू नहीं होगा जिसके विरुद्ध, अनु० 428, परि० 2 के अनुसार, काई आपत्ति की जा सके।

अनु० 45—न्याय निर्णय में भिन्न काई विनिश्चय (decision) विभी सहायक न्यायाधीश द्वारा ही दिया जा सकता है।

अनु० 46—अभियुक्त या अनियाग में सबद्ध काई भी व्यक्ति, अपने मन्थ पर, निर्णय के प्रोग्र के अदा या तथाचार (protocol) की, जिसमें निर्णय लिखित है, प्रतिलिपि या उसके विभी अंश की प्राप्ति के लिये मांग कर सकता है।

अध्याय 6

प्रलेख (Documents) तथा वितरण (Service)

अनु० 47—निम्नी अभियोग स मबद्ध बाइ भी प्रन्त्र लाक विचारण (Public trial) के प्रारम्भ क पहल प्रकाशित नहो किया जायगा । तथापि, यह उम दशा में लागू नहो हागा जब ठाक-हिन या अउर किसी कारणवश इसे (प्रकाशित करना) आवश्यक समझा जाय ।

अनु० 48—लाक विचारण का बाइ नयाचार (Pilot i) लाक विचारण को नियिया पर हान बाओ बायबाहिया क अनुमान तैयार किया जायगा ।

लाक विचारण क नयाचार में उगको नियिया पर घन्नि विचारण स मबद्ध प्रमुख विषय रहेंग जैसा कि न्यायालय क नियमा द्वारा बिहित हा ।

जब विचारण का नयाचार एर अच्छ कम स विचारण का प्रत्येक निधि के ठाक बाइ या कम स कम निषय का पापना क समय या पहल ही पूरा हो जाना चाहिये । तथापि यह लाक विचारण के उस नयाचार के सत्र स लागू नहो हागा जिनमें कि निषय घोषित हा गया हा ।

अनु० 49 यदि अभियुक्त क पाग बाई प्रतिवाद-परामशदाता न हा ता वह जैसा कि न्यायालय के नियमा द्वारा बिहित हो लाक विचारण के नयाचार का निराकरण कर सकता है तथा यदि अभियुक्त अघा हो और स्वयं न पड सके ता वह नयाचार का अग्रन लिए जाय स पडवान के लिए मांग कर सकता है ।

अनु० 50—उस दशा में जब कि लाक विचारण का नयाचार दूसरे विचारण की निधि क पहल अच्छ कम स पूरा न हुआ हो ता बाइ पायालय लिपि क लाक-ममाहता अभियुक्त या प्रतिवाद-परामशदाता को प्रायना पर अनिम विचारण की निधि पर सागिया द्वारा दिए गए प्रमाण को हदरेला दूसरे विचारण की निधि पर या उसक पहल हो सूचित कर दे । एसी दशा में यदि प्रायना करन बाग लाक-समहर्ता अभियुक्त या प्रतिवाद-परामशदाता साक्षिया द्वारा दिए गए प्रमाण की रूपरेखा को मयायना पर आपति करें तो वह आपति भी नयाचार में समाविष्ट की जायगी ।

उस दशा में जब कि अभियुक्त या उसक परामशदाता की अनुपस्थिति में तैयार किया गया किसी लोक विचारण का नयाचार, दूसरे विचारण को

तिथि के पहले अच्छे क्रम में सज्जित न हो तो न्यायालय-लिपिक दूसरे विचारण की तिथि पर या पहले ही, उपस्थित होने वाले अभियुक्त या उसके परामर्शदाता को अंतिम विचारण की तिथि पर घटित प्रमुख घटनाओं का सूचित करेगा।

अनु० 51 लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या परामर्शदाता किसी लोक-विचारण के नयाचार की यथार्थता पर आपत्ति कर सकता है। यदि उक्त आपत्ति की गई हो तो उसका विवरण नयाचार में समाविष्ट किया जायगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित आपत्ति प्रत्येक व्यवहार (Instance) के लोक-विचारण की अंतिम तिथि के बाद चौदह दिन के अंदर ही की जा सकेगी तथापि, जहाँ तक लोक-विचारण के नयाचार का संबंध है जिसमें कि निर्णय धापित हो, ऐसी आपत्ति नयाचार की समाप्ति के बाद चौदह दिन के अंदर ही की जा सकती है।

अनु० 52—लोक-विचारण की निम्न की कार्यवाहियाँ या लोक-विचारण के नयाचार में लिखित रहती हैं, उन्हीं नयाचार द्वारा ही प्रमाणित की जा सकती हैं।

अनु० 53—कोई व्यक्ति किसी विचारण के अभिलेखों (records) का निरीक्षण आपराधिक अभियोग की समाप्ति पर ही कर सकता है। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा, जब कि निरीक्षण से विचारण के अभिलेखों के परिरक्षण, अथवा न्यायालय या लोक-समाहर्ता के कार्यालय के कार्य-व्यापार में बाधा पहुँचती हो।

उस विचारण के किसी अभिलेख का, जिसका मुनता सामान्य जनता के लिए निषिद्ध हो, अथवा किसी अभिलेख का, जिसका निरीक्षण सामान्य जनता के लिये अनुचित होने के कारण प्रतिषिद्ध हो, पिछले परिच्छेद के उपबन्धों के प्रतिकूल, निरीक्षण तब तक नहीं किया जायगा, जब तक कि वे (निरीक्षण करने वाले) उस अभियोग में सबद पक्ष (Parties) न हों, या उनके पास निरीक्षण के लिये समुचित कारण न हो तथा विचारण के अभिलेखों के अभिरक्षक (Custodian) से अनुमति न ले चुके हों।

जापान के संविधान के अनु० 82 परि० 2 के उपबन्धों द्वारा विहित अभियोगों में अभिलेखों का निरीक्षण निषिद्ध नहीं होगा।

विचारण के अभिलेखों के परिरक्षण तथा उनके निरीक्षण के परिषदों से सबद विषय अन्य विधि द्वारा विहित किये जायेंगे।

अनु० 54—न्यायालय के नियमों द्वारा अन्य प्रकार से विहित दशा को छोड़कर, दीवानी प्रक्रिया से सबद विधि या अध्यादेश के विधान (प्रकाशन द्वारा विवरण (Service) से सबद उपबन्धों का छोड़कर) प्रलेखों के विवरण (तामोलों) के सबन्ध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे।

अध्याय 7

अवधियाँ

(Periods)

अनु० 55—अवधियों के परिकलन (Calculation) में, जिनका परिकलन घण्टों में हो वह तुरन्त शुरू होंगे, जब कि जिनका दिनों, मासों अथवा वर्षों में करना हो पहला दिन उसमें सम्मिलित नहीं किया जायगा। तथापि, भोगाधिकार (Pre-scription) की अवधि का पहला दिन, उसके घण्टों की सख्या का विचार बिना, एक दिन के रूप में गिन लिया जायगा।

मासों एवं वर्षों का परिकलन कैलेंडर के अनुसार होगा।

यदि किसी अवधि का अन्तिम दिन रविवार, पहली, दूसरी, तीसरी जनवरी, 29 वें, 30 वें या 31 वें दिसम्बर, या उस दिन, जिसे सामान्य छुट्टी उद्दिष्ट किया गया हो, पड़ना हो तो उसे परिकलन में सम्मिलित नहीं किया जायगा। तथापि, यह भोगाधिकार की अवधि के सबब में लागू नहीं होगा।

अनु० 56—न्यायालय के नियमानुसार, कोई भी वैधानिक अवधि, कार्यवाही की प्रियात्रा को करने वाले व्यक्ति के अभिवास, निवास या कार्यालय, तथा न्यायालय या लाक-समाहर्ता के कार्यालय के बीच की दूरी के तथा परिवहन एवं संचार की सुविधाओं के अनुसार, बढ़ाई जा सकती है।

पिछले परिच्छेद के उपबन्ध उस अवधि के सबब में लागू नहीं होंगे जिसके अन्दर ही किसी घोषित निर्णय के विरुद्ध अपील की जाए।

अध्याय 8

अभियुक्त के आह्वान, प्रस्तुति और निरोध

अनु० 57—कोई न्यायालय किसी अभियुक्त को, समुचित अग्रिम समय देने हुए, जैसा कि न्यायालय के नियमों द्वारा विहित हो, आहूत (summon) कर सकता है।

अनु० 58—न्यायालय किसी अभियुक्त को निम्नांकित दशाओं में प्रस्तुत (produce) करा सकता है

- (1) यदि उसका कोई नियत निवास न हो ,
- (2) यदि समुचित कारण के बिना वह आह्वाना का अनुपालन न करे या उससे ऐसी आशंका हो कि वह पालन नहीं करेगा ।

अनु० 59 प्रस्तुत किया गया अभियुक्त न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के समय से चौबीस घण्टे के अंदर छाड़ दिया जायगा । तथापि यह उस दशा में लागू नहीं होगा जब कि उक्त समय के अंदर ही कोई भिरोय का अधिपत्र (Warrant) बायान्वित किया जा चुका हो ।

अनु० 60 न्यायालय अभियुक्त का निराध में रख सकता है यदि उस यह पुष्ट करने के समुचित आधार प्राप्त हो जायें कि उसने अपराध किया है और अभियोग यदि निम्नलिखित में से किसी प्रभाग (item) के अन्तर्गत आता है।

- (1) जब कि अभियुक्त का कोई नियत निवास न हो ,
- (2) जब कि अभियुक्त से इस विषय की आशंका के पर्याप्त प्रमाण हो कि वह साक्ष्य विनष्ट कर देगा ,
- (3) जब कि अभियुक्त ने पलायन किया हो या उसके पलायन करने की आशंका के पर्याप्त प्रमाण मिलें ।

निराध की अवधि लाव-कार्यवाही के संस्थित किए जाने के दिन से, दो मारा से अधिक नहीं होगी । उस दशा में, जब कि निराध का जारी करने की विशेष आवश्यकता हो तो प्रत्येक मास की अंतिम तिथि का निराध की अवधि, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा उसने नवीकरण के स्पष्ट कारणों के विवरण के साथ, नवीकृत की जाएगी । तथापि अनु० 89 प्रभाग 1 तथा 3 से 5 के अन्तर्गत आने वाली दशाओं का छोड़कर, निराध की अवधि का नवीकरण केवल एक बार होगा ।

उस अभियोग के मजरा में जिसमें 500 येन से अधिक अर्थ दण्ड, निराध या लघु-अर्थदण्ड न हो, इस अनुच्छेद का पहला परिच्छेद केवल उसी दशा में लागू होगा जब कि अभियुक्त का कोई नियत निवास न हो ।

अनु० 61—न्यायालय द्वारा अभियुक्त का उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना देने तथा उसके विषय में अभियुक्त के विवरण सुनने के पहले उसे निराश्रय में नहीं रखा जा सकता। तथापि यह उन अनियोगों के मन्त्र्य में लागू नहीं होगा जिनमें कि अभियुक्त ने पलायन किया है।

अनु० 62 अभियुक्त का आह्वान (Summons) उसकी प्रस्तुति या निराश्रय, आह्वान का प्रादेश (writ) अथवा प्रस्तुति या निराश्रय का अधिपत्र जारी करके निष्पादित किया जाएगा।

अनु० 63 आह्वान के प्रादेश में, अभियुक्त का नाम और उसका निवास अपराध का नाम, दिनांक, उपस्थित होने का समय तथा स्थान, साथ ही ऐसा विवरण जिसमें यह उल्लेख होगा कि वह यदि बिना समुचित कारण के उपस्थित नहीं होगा तो उसके विरुद्ध प्रस्तुति का अधिपत्र जारी किया जाएगा तथा इसके साथ अन्य विषय भी जा कि न्यायालय के नियमा द्वारा विहित है और उक्त प्रादेश जारी करने वाले पीठासीन अथवा राजादिष्ट न्यायाधीश का नाम तथा उसकी मुद्रा (मुहर) रहणी।

अनु० 64 प्रस्तुति अथवा निराश्रय के अधिपत्र में अभियुक्त का नाम एवं निवास अपराध का नाम, लोक-कार्यवाही के प्रमाण तथा स्थान, जहाँ उसे पाना है। या कारागार जहाँ उसे निरुद्ध करना है, प्रभावी अवधि तथा यह विवरण कि उक्त अधिपत्र के बीच जाने के पश्चात् अधिपत्र जारी नहीं किया जाएगा और जारी करने वाले न्यायालय का लौटा दिया जाएगा, जारी होने के तिथि, साथ ही और भी विषय जो न्यायालय के नियमा द्वारा विहित हों तथा अधिपत्र जारी करने वाले पीठासीन अथवा राजादिष्ट न्यायाधीश के नाम एवं मुद्रा (मुहर) रहेंगे।

उस दशा में जब कि अभियुक्त का नाम अनिश्चित हो तो उसकी मुद्रा-कृति, शरीर गठन एवं अन्य विशेष चिह्नों के विवरण द्वारा उसकी पहचान की जायगी।

उस दशा में जब कि अभियुक्त का निवास अनिश्चित हो तो उसे कहलवाया नहीं जायगा।

अनु० 65—आह्वानों के प्रादेश सामील (विनिरित) किये जायेंगे। यदि अभियुक्त कोई प्रलेख इस विवरण के साथ दाखिल करता है कि वह सुनवाई के लिये नियत की गई तिथि पर उपसजान होगा, या यदि न्यायालय,

मुनबाई की तिथि पर उपसजात अभियुक्त को, मुनबाई की दूसरी तिथि पर उपसजात होने के लिये आदेश देता है तो उसका प्रभाव आह्वानों के प्रादेश की तामीली के समान ही होगा। उस दशा में जब कि उसकी उपसजाति (appearance) का आदेश जवानों हुआ हो तो यह तथ्य नयाचार में उद्घिष्ट किया जायगा।

न्यायालय के समीप किसी कारागार में निरुद्ध कोई अभियुक्त कारागार के कर्मचारियों को सूचना देकर आह्वान किया जा सकता है। ऐसी दशा में, आह्वानों के प्रादेश की तामीली मान ली जाएगी यदि अभियुक्त को कारागार के कर्मचारियों से सूचना मिल चुकी हो।

अनु० 66—कोई न्यायालय अभियुक्त को उपसजात करने के लिये, तत्काल जहाँ वह रहता हो वहाँ के जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अधियाचना (माँग) कर सकता है।

इस प्रकार अधियाचित न्यायाधीश स्वयं किसी अन्य जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश की माँग कर सकता है, जा कि उक्त अधियाचना स्वीकृत करने के लिये प्राधिकृत हो।

यदि अधियाचित न्यायाधीश को स्वयं अधियाचना के अदर आने वाले अभियोग का अधिकार न हो तो वह उक्त अधियाचना की अन्य किसी जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के न्यायाधीश के यहाँ अन्तरित कर सकता है जो उक्त अधियाचना का स्वीकृत करने के लिये प्राधिकृत हो।

यह न्यायाधीश जिसने उक्त अधियाचना प्राप्त की हो या जिसके यहाँ अधियाचना अन्तरित की गई हो, प्रस्तुति का अधिपत्र जारी कर सकता है।

अनु० 64 का उपवन्ध पिछले परिच्छेद में लिखित प्रस्तुति के अधिपत्र के सद्य में, यथाचित परिवर्तन के साथ, लागू होगा। ऐसी दशा में, अधिपत्र के अन्तर्गत यह विवरण रहेगा कि वह अधियाचना के अन्तर्गत जारी किया गया है।

अनु० 67—पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट दशा में अधियाचना के अदर प्रस्तुति का अधिपत्र जारी करने वाले न्यायाधीश को अभियुक्त को लाए जाने के समय से चौतीस घण्टे के अदर यह निश्चय कर लेना होगा कि अभियुक्त की पहचान में कोई गलती तो नहीं हुई है।

यदि अभियुक्त की पहचान में कोई गलती न हो तो उसे तत्काल नामाद्घिष्ट न्यायालय का सोप दिया जाएगा। ऐसी दशा में, न्यायाधीश, जिसने

अधिपक्षता के अन्तर्गत प्रस्तुति का अधिपत्र जारी किया हो, समय की अवधि निर्धारित करेगा जिसके अंदर कि अभियुक्त को नामोद्दिष्ट न्यायालय के समक्ष लाया जायगा।

पिछले परिच्छेद की दशा में, अनु० 59 में उल्लिखित अवधि का परिवर्तन उस समय से किया जायगा जब कि अभियुक्त नामोद्दिष्ट न्यायालय के समक्ष लाया गया हो।

अनु० 68—न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर, अभियुक्त को किसी नामोद्दिष्ट स्थान पर उपसजात होने या साथ चलने के लिये आदेश दे सकता है। यदि अभियुक्त बिना समुचित कारण के उक्त आदेश के अनुपालन में असमर्थ रहे तो उसे उक्त स्थान पर उपसजात कराया जा सकता है। ऐसी दशा में अनु० 59 में निर्धारित अवधि का परिवर्तन उस समय से किया जायगा जब कि अभियुक्त उक्त स्थान पर उपसजात किया गया हो।

अनु० 69—अविलम्बिता की दशा में, कोई भी पीठासीन न्यायाधीश, अनु० 57 से 62, अनु० 63, 66 तथा पिछले अनुच्छेद में विहित उपाय स्वयं कर सकता है या अपने सहयोगी न्यायालय के किसी सदस्य से ऐसा करा सकता है।

अनु० 70—प्रस्तुति या निरोध को अधिपत्र को, लोक-समाहर्ता के निर्देशन में, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा निष्पादित किया जायगा। तथापि, अविलम्बिता की दशा में उसके निष्पादन का निर्देश किसी पीठासीन न्यायाधीश, राजादिष्ट न्यायाधीश अथवा जिला-न्यायालय या क्षेत्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा दिया जा सकता है।

कारागार में रहने हुए अभियुक्त के विरुद्ध जारी किया गया निरोध का अधिपत्र, लोक-समाहर्ता के निर्देशन में कारागार के कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किया जायगा।

अनु० 71—लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या कोई न्यायिक पुलिस कर्मचारी, आवश्यकता पड़ने पर, अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर भी प्रस्तुति के अधिपत्र को निष्पादित कर सकता है, अथवा लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी द्वारा वही निष्पादित करा सकता है।

अनु० 72—जब अभियुक्त का वर्तमान स्थान अज्ञात हो तो कोई पीछाशील न्यायाधीश (उच्च लोक-समाहता के कार्यालय के) किसी अधीक्षक समाहर्ता को, छानबीन करने तथा प्रस्तुति का अधिपत्र निष्पादित करने के लिये समादिष्ट कर सकता है।

उच्च लोक-समाहर्ता के कार्यालय का अधीक्षक समाहर्ता जिस उक्त समादेश मिला हो, अपने अधिवक्त्र क्षेत्र के अंदर किसी लाव-समाहर्ता को छानबीन और प्रस्तुति के अधिपत्र के निष्पादन की कार्यवाही का पालन करने के लिये प्रेरित करेगा।

अनु० 73—प्रस्तुति के अधिपत्र का निष्पादित करने में यह (अधिपत्र) उस अभियुक्त का दिखा दिया जायगा जिसे यथाशीघ्र सीधे न्यायालय के समक्ष या अन्य किसी नामादिष्ट स्थान पर लाया जाएगा। अनु० 66 परि० 4 में उल्लिखित प्रस्तुति के अधिपत्र की दशा में अभियुक्त, अधिपत्र जारी करने वाले न्यायाधीश के समक्ष लाया जाएगा।

निराध के अधिपत्र के निष्पादित करने में यह (अधिपत्र) उस अभियुक्त को, जिसे कि यथाशीघ्र सीधे नामादिष्ट कारागार में पहुँचा दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा।

अविलम्बिता की स्थिति में, प्रस्तुति या निराध का कोई अधिपत्र न रहने पर भी, पिछले दश परिच्छेदों पर बिना विचार किए, लाव-कार्यवाही के प्रमुख तथ्यों का और यह कि अधिपत्र जारी किया गया है, सूचित करने के पश्चात् अधिपत्र निष्पादित किया जा सकता है। तथापि, यह अधिपत्र यथासंभव शीघ्र ही उसे दिखा दिया जायगा।

अनु० 74—उस दशा में जब कि अभियुक्त, जिसके विरुद्ध प्रस्तुति या निराध का कोई अधिपत्र निष्पादित किया जा चुका हो, रक्षी (guard) की देखभाल में भेजा जाने वाला हो तो उसे, आवश्यकतानुसार, निवटस्थ कारागार में, अनन्तिमरूप से निरुद्ध किया जा सकता है।

अनु० 75—उस दशा में जब कि अभियुक्त, जिसके विरुद्ध प्रस्तुति का अधिपत्र निष्पादित किया जा चुका हो, लाया गया हो, यदि आवश्यक हो तो उसे कारागार में निरुद्ध किया जा सकता है।

अनु० 76—उस दशा में जब कि अभियुक्त प्रस्तुत किया गया हो, उसे तुरन्त लाव-कार्यवाही का सार सूचित किया जायगा और अपने प्रतिवाद

परामर्शदाता को भी चुनने के लिए उसे सूचित किया जाएगा तथा उस दसा में उसके लिए न्यायालय द्वारा परामर्शदाता के अधिन्यास (assignment) के विषय में भी उसे सूचित किया जाएगा जब कि वह, अपनी निर्धनता या अन्य कारणों से स्वयं परामर्शदाता प्राप्त करने में असमर्थ हो। तथापि, यदि अभियुक्त के पास पहले से ही परामर्शदाता हो तो उसे लोन-वार्पवाही के सार को ही सूचित करना पर्याप्त होगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित उपायों को करने के लिए किसी भी सहयोगी न्यायालय के सदस्य या न्यायालय के लिपिब को प्रेरित किया जा सकता है।

उस दसा में जब कि अनु० 66 परि० 4 के अनुसार प्रस्तुति का अधिपत्र जारी किया गया हो तो पहले परिच्छेद में उल्लिखित उपाय, अधिपत्र जारी करने वाले न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त किए जायेंगे। तथापि, न्यायालय का लिपिब भी ऐसा करने के लिये प्रेरित किया जा सकता है।

अनु० 77—केवल उस दसा को छोड़कर जब कि विरोध प्रस्तुति या बन्दीकरण के बाद हो अभियुक्त को निरुद्ध करने के लिए उसे यह तथ्य बताना दिया जाएगा कि वह अपना प्रतिवाद परामर्शदाता चुन ले और यदि वह अपनी निर्धनता या अन्य कारणों से स्वयं परामर्शदाता पाने में असमर्थ हो तो न्यायालय द्वारा उसके लिए परामर्शदाता के अधिन्यास (assignment) का अधिपत्र भी सूचित किया जाएगा। तथापि, यह उस दसा में लागू नहीं होगा यदि अभियुक्त के पास पहले से ही परामर्शदाता हो।

अनु० 61 के उपबन्ध की दसा में, अभियुक्त को निरुद्ध होने के ठीक बाद पिछले परिच्छेद में विहित तथ्यों के साथ लोन-वार्पवाही का सार भी सूचित किया जाएगा। तथापि, यदि अभियुक्त के पास पहले से ही प्रतिवाद-परामर्शदाता हो तो केवल लोन-वार्पवाही के सार से ही उसे सूचित कर देना पर्याप्त होगा।

पिछले अनुच्छेद के परि० 2 के उपबन्ध, पिछले दो परिच्छेदों में उल्लिखित उपायों के साथ में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे।

अनु० 78—प्रस्तुत किया गया या निरुद्ध अभियुक्त अपने प्रतिवाद-परामर्शदाता के चुनाव के लिए किसी अधिवक्ता या विधिज्ञ-संघ (Bar Association) को नामोद्घिष्ट करते हुए न्यायालय, बारामार के प्रमुख

या उसके स्थानापन्न का प्रार्थनापत्र दे सकता है। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा यदि अभियुक्त के पास पहले से ही परामर्शदाता हो।

न्यायालय या कारागार का प्रमुख अथवा उसका स्थानापन्न, जो उक्त प्रार्थनापत्र प्राप्त करे, तुरन्त इस तथ्य की सूचना अभियुक्त के अधिवक्ता अथवा विधिज्ञ-सघ को देगा। उस दशा में जब कि अभियुक्त ने प्रार्थनापत्र में दा या अधिवक्ता अधिवक्ताओं या विधिज्ञ सघों को नामोद्दिष्ट किया हो तो उनमें से किसी एक का सूचना देना पर्याप्त होगा।

अनु० 79 यदि अभियुक्त का निरद्व किया गया हो तो इस तथ्य की सूचना उसके परामर्शदाता का तत्काल दी जाएगी। यदि उसके पास कोई परामर्शदाता न हो तो उसके वैध प्रतिनिधि पालक (Curator), विवाहित जोड़े वशीय सबधी भाई या बहन में से किसी एक व्यक्ति को यह सूचना दी जाएगी जिसे उसने नामोद्दिष्ट किया हो।

अनु० 80—निरोध में रखा गया अभियुक्त, जहाँ तक विधि एक अध्यादेश अनुज्ञा है, अनु० 39 परि० 1 में अनिर्दिष्ट व्यक्तियों से साक्षात् कर सकता है, उन्हें प्रलेख या अन्य कोई वस्तु दे या उनसे ले सकता है। यही नियम प्रस्तुति के अधिपत्र पर कारागार में निरद्व किए गए अभियुक्त के सबध में भी लागू होगा।

अनु० 81—यदि इस आज्ञा का पर्याप्त दृढ आधार मिले कि निरोध के अन्तर्गत रहता हुआ अभियुक्त भाग सकता है या साक्ष्य नष्ट कर सकता है तो लोक-समाहर्ता या पदेन लोक-समाहर्ता के निवेदन पर, न्यायालय उसे अनु० 39 परि० 1 में उल्लिखित से भिन्न व्यक्तियों से साक्षात् करने से निषिद्ध कर सकता है, उक्त व्यक्तियों से जो प्रलेख या वस्तु वह ले या उन्हें दे उसकी जाँच कर सकता है अथवा उनका देना या लेना निषिद्ध कर सकता है अथवा उनका अभिग्रहण कर सकता है। तथापि, उसे साक्ष्य पदार्थ लेने से निषिद्ध नहीं किया जाएगा और न तो उसका अभिग्रहण ही किया जा सकेगा।

अनु० 82—निरोध के अन्तर्गत आया हुआ अभियुक्त अपने निरोध का हेतु बतलाने (सूचित करने) के लिये न्यायालय से निवेदन कर सकता है।

निरोध में आए हुए अभियुक्त का प्रतिवाद-परामर्शदाता, वैध प्रतिनिधि, पालक, विवाहित जोड़ा, वशीय सबधी, भाई या बहन अथवा अन्य कोई अभिरक्षि रखने वाला व्यक्ति पिछले परिच्छेद में निर्दिष्ट निवेदन कर सकता है।

पिछले दो परिच्छेदों में निर्दिष्ट निवेदन कार्यकर नहीं होगा यदि अभियुक्त को जमानती निष्पत्ति अथवा निरोध के निष्पादन का निलम्बन किया जा चुका हो या जब निराध विखण्डित कर दिया गया हो अथवा जब निराध का अधिपत्र प्रभावशून्य हो चुका हो।

अनु० 83 सूचना (Indication) की कार्यवाही खुल न्यायालय में की जाएगी।

न्यायालय न्यायाधीशों एवं न्यायालय के लिपिका के सामने लाया जाएगा।

यदि अभियुक्त तथा उसके प्रतिवाद-परामशदाता उपमजान न हों तो न्यायालय नहीं खोला जाएगा। तथापि यह अभियुक्त की उपमजान (appearance) से सबूत उस दशा में लागू नहीं होगा जब कि अभियुक्त बीमारा जैम अनिवायं कारणवश उपमजान ज्ञान में असमर्थ हो और जहाँ अभियुक्त का आर स कोई आपत्ति न हो और न तो अभियुक्त के परामशदाता की उपमजान में सबूत दशा में ही (लागू होगा) जहाँ कि अभियुक्त की ओर स कोई आपत्ति न हो।

अनु० 84 न्यायालय में पीठामीन न्यायाधीश निराध के कारणों की अधिसूचना देगा।

अभियुक्त उसका प्रतिवाद-परामशदाता और अन्य व्यक्ति जिन्होंने निवेदन किया हो अपनी समिति दे सकते हैं। यही नियम लाव-समाहर्ता के सबूत में भी लागू होगा।

अनु० 85—सूचना (Indication) की कार्यवाही किसी सहायी (Collateral) न्यायालय के सदस्य द्वारा निष्पादित की जाएगी।

अनु० 86—उस दशा में जब कि एक ही निराध के सबूत में अनु० 82 में उल्लिखित दो या अधिक निवेदन हो तो सूचना की कार्यवाही पहले निवेदन की तरह ही की जाएगी। एक व्यवस्था (ruling) द्वारा सूचना की कार्यवाही पूरी हो जाने पर अन्य निवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा।

अनु० 87—निराध के आधार (grounds) अथवा उसकी आवश्यकता न रह जाने पर, लोक-समाहर्ता निराध में रखे गए अभियुक्त उसके प्रतिवाद-परामशदाता वैध प्रतिनिधि पालक, विवाहित जोड़ा वंशीय सबंधी भाई या बहन या पड़ने किसी के निवेदन पर न्यायालय, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, निराध को विखण्डित कर देगा।

अनु० 82 परि० 3 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन के सबंध में लागू होंगे ।

अनु० 88—निरोध में रखा गया अभियुक्त, उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता, वैध प्रतिनिधि, पालक, विवाहित जोड़ा, वसीयत सचिव, माई या बहन उसकी जमानती निर्मुक्ति (release on bail) के लिए निवेदन कर सकता है ।

अनु० 82 परि० 3 के उपबन्ध पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन के सबंध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे ।

अनु० 89—जब जमानती निर्मुक्ति का निवेदन किया गया हो तो वह निम्नांकित दशाओं को छोड़कर स्वीकृत किया जाएगा

- (1) जब कि अभियुक्त पर प्राण-दण्ड या असीमित काल के लिए कठोर श्रम-कारावास या कारावास का दण्ड पाने का अपराध आरोपित हो,
- (2) जब कि अभियुक्त पहले प्राणदण्ड या असीमित काल के लिए अथवा दस वर्षों से अधिक अवधि के कठोरश्रम-कारावास या कारावास दण्ड के अपराध से अभिरक्षित हो,
- (3) जब कि अभियुक्त ने स्वभावतः (habitually) तीन वर्षों या उससे अधिक अवधि वाले कठोरश्रम-कारावास, या कारावास के दण्ड का अपराध किया हो,
- (4) जब इस आशङ्का का दृढ़ एवं तर्कसंगत आधार हो कि अभियुक्त राक्षस चिन्तित कर सकता है,
- (5) जब कि अभियुक्त का नाम और निवास अज्ञात हो ।

अनु० 90—कोई न्यायालय, यदि उचित समझे, जमानती निर्मुक्ति (release on bail) की अनुमति पदेन (ex-officio) दे सकता है ।

अनु० 91—जब निरोध के अधिपत्र पर, असमृद्धित दीर्घ अवधि के लिए निरोध निष्पादित हो चुका हो तो न्यायालय, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, अनु० 88 में उल्लिखित ध्येय के निवेदन पर या पदेन, निरोध को विग्रहित कर सकता है अथवा जमानती निर्मुक्ति स्वीकृत कर सकता है ।

अनु० 82 परि० 3 के उपबन्ध पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन के सबंध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे ।

अनु० 92—न्यायालय जमानती निर्मुक्ति की अनुज्ञा करने अथवा उसके लिए किए गए निवेदन को अस्वीकृत करने के पहले ही किसी लोच-समाहर्ता की समिति मुनेगा।

अनु० 93—जमानती निर्मुक्ति स्वीकृत हो जाने पर न्यायालय द्वारा जमानत का द्रव्य निश्चित किया जाएगा।

जमानत के द्रव्य की राशि, अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित (insure) करने के लिए अपराध के स्वरूप एवं परिस्थितियों, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य का भार, उसके चरित्र तथा जमानत देने की उसकी आर्थिक समर्थता का विचार करते हुए जितनी पर्याप्त एवं समुचित होगी, निश्चित की जाएगी।

जब जमानती निर्मुक्ति स्वीकृत हो गई हो, अभियुक्त के निवास पर निर्वन्धन (restriction) लगाया जा सकता है, अथवा अन्य कोई शर्तें जिन्हें उचित समझा जाय लगाई जा सकती हैं।

अनु० 94 जमानती निर्मुक्ति प्रदान करने वाली व्यवस्था (ruling) जमानत की राशि के जमा हो जाने के पहले निष्पादित नहीं की जाएगी।

न्यायालय जमानत की मांग करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को जमानत की राशि जमा करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है।

न्यायालय, अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, जिसे बिना वह उचित समझे, जमानत की राशि के बदले में स्थानापन्न करने के लिए पराक्राम्य जमानत (negotiable securities) या लिखित प्रतिभुति (written undertaking) प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकता है।

अनु० 95—न्यायालय, यदि उचित समझे तो एक व्यवस्था (ruling) द्वारा निरोध के अदर रखे गए अभियुक्त को उसके सबन्धी, किसी सरसक सत्त्वा या इसी तरह की अन्य सत्त्वा के प्रभार से सौंपकर अथवा उसके निवास पर निर्वन्धन लगाकर निरोध के निष्पादन का निलम्बित कर सकता है।

अनु० 96—यदि अभियुक्त भग गया हो या उसके भग जाने अथवा साक्ष्य विनष्ट करने के सदेह का तकसगत आधार हो, समन करने पर बिना सम्पुक्ति कारण के उपसज्जत होने में असमर्थ रहा हो या उसके विकास पर लगाए गए निर्वन्धन अथवा न्यायालय द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों का अतिलपन

किया हो तो न्यायालय, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, उसकी जमानती निर्मुक्ति अथवा निराध-निष्पादन के निलम्बन को विवर्णित कर सकता है।

जमानती निर्मुक्ति के विवर्णित हो जाने की दशा में, न्यायालय एक व्यवस्था (ruling) द्वारा जमानती धन-राशि के पूरे या किसी अंश को जप्त कर सकता है।

जब कि जमानत पर निर्मुक्त कोई व्यक्ति, जिसे दण्ड दिया जा चुका हो और निर्णय के अंतिम रूप से दायनकारी हो जाने पर निष्पादन के लिए न्यायालय के समक्ष बुलाए जाने पर बिना समुचित कारण के उपमजान होने में अममय रहा हो, या भग गया हो तो न्यायालय, किसी लांघ-ममाहर्ता के प्रावेदन (motion) पर एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, जमानती धन-राशि के पूरे या किसी अंश का जप्त कर सकता है।

अनु० 97—उस दशा में जब कि निराध को नवीकृत या विवर्णित करना हो अथवा जमानती निर्मुक्ति या निराध के निष्पादन का निलम्बन कार्यान्वित या विवर्णित करना हो, उस अभियोग के सचय में जिसकी अपील की अवधि बीती न हो और जिसकी अपील तत्काल सस्यित न की गई हो तो उसने लिए आवश्यक व्यवस्था (ruling) मूल (original) न्यायालय द्वारा जारी की जाएगी।

उस अभियोग के सचय में जिसकी अपील लम्बित हो और कार्यवाहियों के अभिलेख अपील न्यायालय में न पहुँचे हो, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था (ruling) जारी करने वाले न्यायालय का निर्धारण न्यायालय के नियमों द्वारा किया जाएगा।

पिछले दो परिच्छेदों के उपबन्ध, यथाचित परिवर्तन के साथ, उस दशा में भी लागू होंगे जहाँ कि निरोध के हेतु की मूचना देनी हो।

अनु० 98—जब कि जमानती निर्मुक्ति या निर्णय-निष्पादन का निलम्बन किसी व्यवस्था (ruling) द्वारा विवर्णित करना हो, या निन्द्यता की अवधि समाप्त होती हो तो अभियुक्त को, किसी लांघ-ममाहर्ता के निर्देशन में, लांघ-ममाहर्ता-कार्यालय के किसी मजिब, न्यायिक पुलिस कर्मचारी या बागातर अधिकारी द्वारा, जा कि अभियुक्त को निराध के अधिपत्र की अथवा उस अधिनियम व्यवस्था की एक प्रति दिखलाया जिसमें जमानती निर्मुक्ति या निराध-निष्पादन का निन्द्यता विवर्णित कर दिया गया हो अथवा जिससे निन्द्यता की अवधि निर्धारित की गई हो, परिरोध में रक्त लिया जाएगा।

अध्याय 9

अभिग्रहण और तलाश

(Seizure and Search)

अनु० 99—यायाक्य आवश्यकतानुसार इस अवकाश अथ विधिया द्वारा जयथा विहित गजा का छाडर रिया भी वस्तु का अभिग्रहण कर सकता है जिसे वह समन कि वह वस्तु साम्य म उपयुक्त हा सकता ह अथवा जा राज्यमाकरण क योग्य ह

यायाक्य अभिग्रहण म गी जान वाली वस्तुना का नामादित कर सकता ह और उसक स्वामा अधिकता या अभिरणक का उस वस्तु प्रस्तुत करन क लिए आग द सकता ह ।

अनु० 100—यायाक्य अभियुक्त द्वारा या उसक पाम भन गए तार स मरद कागजा या डाक-नामग्रा का जा किसी सरकारा कायाक्य या रिता अथ सचार-बाय करन वाग व्यक्ति क अभिरणण या अधिकार म हा अभिग्रहण कर सकता ह अथवा उह प्रस्तुत करा सकता ह ।

पिछर परिच्छ म उल्लिखित म भिन्न डाक-नामग्रा या तार स मरद कागजा का जा किसी सरकारा कायाक्य या सचार-बाय करन वाग अथ किसी व्यक्ति क अभिरणण या अधिकार म हा अभिग्रहण किया जा सकता ह या उन् प्रस्तुत कराया जा सकता ह केवड उसा दता म जद कि प्रस्तुत अभिधान स उनका सवय जनान वाला परिस्थितिया हा ।

जद पिछर दो परिच्छ म उपरजा क अलगन वाड कारवाड कायाक्य की गई हा ता इस तथ्य की सूचना भजन वाडे (sender) या पान वाडे (addressee) का दी जाएगी । तथापि यह तब गम नही जागा जब कि उक्त अधिसूचना स कायवाही म दराबट या जान की आगका हा ।

अनु० 101—व वस्तुएँ जा अभियुक्त या अथ किसी व्यक्ति द्वारा गिरा दा गई हा अथवा जा उनके स्वामा अधिकता या अभिरणक द्वारा स्वच्छपा प्रस्तुत की गई हा प्रतियारित (retained) की जा सकता ह

अनु० 102—यायाक्य आवश्यकतानुसार अभियुक्त क गरीर सपनि निवास या जय किसी स्थान की तलाश क सकता ह ।

अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति के शरीर, संपत्ति, निवास या अन्य किसी स्थान की तलाशी तभी की जा सकती है जब कि परिस्थितियों से यह विद्वान हो जाय कि वहाँ पर अभिग्रहण के योग्य वस्तुएँ हैं।

अनु० 103—यदि कोई व्यक्ति, जो किसी कार्यालय से संबद्ध कोई लोक-वर्मचारी हो या रह चुका हो, अपने अभिरक्षण या अधिकार में रखी हुई वस्तुओं के संबंध में, यह घोषणा करे कि उक्त वस्तुएँ किसी कार्यालयीय रहस्य से संबद्ध हैं तो ऐसी वस्तुओं का अभिग्रहण किसी समर्थ पर्यवेक्षी कार्यालय की समिति में ही किया जा सकता है। तथापि, उन दशाओं की छोड़कर, जिनमें कि अनुपालन राज्य के प्रधान हितों के प्रतिरूप हो, वह कार्यालय उक्त समिति देना अस्वीकृत नहीं कर सकता।

अनु० 104—यदि पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित घोषणा निम्नलिखित व्यक्तिप्रा द्वारा की गई हो तो अभिग्रहण, प्रभाग 1 में उल्लिखित व्यक्ति के संबंध में सदन की मर्माति के बिना, तथा प्रभाग 2 में उल्लिखित व्यक्ति के संबंध में मन्त्रिपरिषद् की समिति के बिना, नहीं किया जा सकता :

- (1) वह व्यक्ति जो प्रतिनिधि सदन या सभासद-सदन का सदस्य हो या रह चुका हो,
- (2) वह व्यक्ति जो प्रधान मंत्री या राज्य-मंत्री हो या रह चुका हो।

पिछले परिच्छेद की दशा में प्रतिनिधि-सदन, सभासद-सदन या मन्त्रि-परिषद्, केवल उस दशा की छोड़कर, जब कि अनुपालन राज्य के प्रधान हितों के प्रतिरूप हो, समिति देना अस्वीकृत नहीं कर सकते।

अनु० 105—कोई व्यक्ति जो डाक्टर, दन्तचिकित्सक, दार्ष्ट, उपचारिका अधिकृत, एक्स्व अभिवर्ती (patent agent) लेख्य-प्रमाणक या धार्मिक कार्यकर्ता हो या रह चुका हो, किसी प्रादेश (mandate) के फलस्वरूप जो उसे अपनी व्यवसायिक दिशा में मिला है और जिसका संबंध अन्य व्यक्तियों के रहस्यों से हो, अपने अधिकार या अभिरक्षण में रखी हुई वस्तुओं के अभिग्रहण की अस्वीकृत कर सकता है। मन्त्रि यह उस दशा में लागू नहीं होगा यदि मुख्य (मुख्य) ने उक्त अभिग्रहण की समिति दे दी हो, या अभिग्रहण की अस्वीकृति को केवल अधिकार के दुरुपयोग के अनिश्चित और कुछ न समझा जाए जिसका उद्देश्य अभियुक्त का हित मात्र हो, जब कि वह मुख्य (मुख्य) न हो, अथवा कोई विशेष परिस्थितियाँ हो जिनका निरूपण न्यायालय के नियमों द्वारा किया जाएगा।

अनु० 106 अभिग्रहण या तलाशी का अधिपत्र उम्मीदगारों में जारी किया जाएगा जब कि अभिग्रहण या तलाशी मुझे न्यायालय से अग्रसर करनी हो।

अनु० 107—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र में अभियुक्त और अपराध का नाम वस्तुएँ जिनका अभिग्रहण करना हो अथवा स्थान व्यक्ति या वस्तु जिनकी तलाशी उम्मीद है। प्रमाणावधि तथा यह विवरण कि उक्त अधिपत्र के दान जान पर अधिपत्र का निष्पादन किसी तरह नहीं किया जाएगा और उस जारी करने वाले न्यायालय को जहाँ किया जाएगा साथही अथ मध्य या जो न्यायालय नियमा द्वारा विहित है और पीठमौल न्यायालय का नाम एवं उसका मुख्यालय रहनी।

अनु० 6+ के परिच्छेद 2 के उपर्युक्त यथाचिन्तन के साथ पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अभिग्रहण एवं तलाशी के मध्य में समूह है।

अनु० 108—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र का निष्पादन लार्ड समाहता के निर्देशन में राज-समाहता-न्यायालय के किसी सचिव अथवा न्यायिक पुलिस कमचारी द्वारा किया जाएगा। तथापि उन देशों में जहाँ न्यायालय अभियुक्त के हिता की रक्षा आवश्यक समझता पीठमौल न्यायालय उक्त अधिपत्र के न्यायालय निमित्त या न्यायिक पुलिस कमचारी द्वारा निष्पादित किए जाने का निर्देश दे सकता है।

अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन में न्यायालय उसका निष्पादन करने वाले व्यक्ति का एक अनुदेश (instructions) लिखित रूप में दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अनुदेश, किसी सहपाठी (Collegiate) न्यायालय के सदस्य द्वारा दिया जा सकता है।

अनुच्छेद 71 के उपर्युक्त अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन के मध्य में यथाचिन्तन परवर्तन के साथ समूह है।

अनु० 109—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन में राज-समाहता-न्यायालय का सचिव अथवा न्यायालय निमित्त आवश्यकतानुसार, न्यायिक पुलिस कमचारी से सहायता की मांग कर सकता है।

अनु० 110—अभिग्रहण या तलाशी का अधिपत्र उस व्यक्ति को दिखाया जाएगा जिसके विरुद्ध यह कार्रवाई की गई हो।

अनु० 111—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन में ताते हटाए जा सकते हैं, मुहरें खाली जा सकती हैं या अन्य कोई आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। यही नियम गुले न्यायालय में कार्यान्वित, अभिग्रहण या तलाशी के सवन्ध में लागू होगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कार्रवाई अभिगृहीत वस्तुओं के सवन्ध में भी की जा सकती है।

अनु० 112—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन पर्यन्त किसी भी व्यक्ति का प्रवेश करने अथवा बिना अनुज्ञा के वह स्थान छाड़ने के लिए निषिद्ध किया जा सकता है।

वह व्यक्ति जो पिछले परिच्छेद के निषेध का अनुपालन न करे उसे निष्पादन की समाप्ति तक वापस जाने (पीछे हट जाने) अथवा कठपर में रखे जाने का आक्षेप किया जा सकता है।

अनु० 113—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादित किए जाने के समय लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद परामर्शदाता उपस्थित रह सकते हैं। तथापि, यह उस अभियुक्त के सवन्ध में लागू नहीं होगा जो शारीरिक अवरोध में रखा गया हो।

अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र को निष्पादित करने वाला व्यक्ति उन व्यक्तियों का, जो कि पिछले परिच्छेद के उपसन्धानानुसार उपस्थित रह सकते हैं, निष्पादन की तिथि, समय एवं स्थान के बारे में अग्रिम सूचना देगा। तथापि यह उस दशा में लागू नहीं होगा जबकि निष्पादन पर उपस्थित रहने का अधिकारी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अपने उपस्थित न रहने की इच्छा अग्रिम रूप में स्पष्टतः व्यक्त करे और न तो उस दशा में ही, जहाँ कि अविलम्बिता अपेक्षित हो।

अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन में, न्यायालय आवश्यकतानुसार अभियुक्त को उपस्थित रहने को प्रेरित कर सकता है।

अनु० 114—उस दशा में, जबकि अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र का निष्पादन किसी लोक-कार्यालय में करना हो तो उक्त कार्यालय के अध्यक्ष अथवा उसके स्थानापन्न व्यक्ति को इस तथ्य की अधिसूचना दी जाएगी और इस कार्रवाई के कार्यान्वित करते समय उसे उपस्थित रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

पिछले परिच्छेद के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित दगाब्रा का टाडकर अब कोई अभिग्रहण या तलाशी का अधिपत्र किसी व्यक्ति के निवास परमर भवन या व्यक्ति या द्वारा रहित जलयान में निष्पादित करना हा ना अधि मास्ता (occupant) या धारक (holder) अथवा उनसे स्थान पर काम करने वाले व्यक्तियों का उपस्थित हान के लिए प्रेरित किया जाएगा। यदि उस व्यक्ति ने मिल ना कोई पनामा या स्थानांतरण लाक-बन्दा के किसी कमबारा का उपस्थित रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

अनु० 115—यदि किसी स्त्री के ग़रार का तलाशी का निष्पादन करना हा तो एक अन्य व्यक्ति स्त्री का उपस्थित रहना आवश्यक होगा किन्तु अतिरिक्त कोई दगाब्रा में यह लागू नही होगा।

अनु० 116—मूख्य के पूर्व एवं मूख्य के बाद किसी व्यक्ति के निवास परमर भवन या व्यक्ति या द्वारा रहित जलयान में तलाशी या अभिग्रहण के अधिपत्र के निष्पादन के अभिप्राय से तब तक प्रवृत्त नही किया जाएगा जब तक कि अधिपत्र में यह विवरण न हा कि तलाशी निष्पादन रात्रि में भी होगा।

उस दगा में जबकि तलाशी या अभिग्रहण के किसी अधिपत्र का निष्पादन मूख्य के पूर्व प्रारम्भ किया गया हा ना वह कारबाही मूख्य के बाद तक भा जारी रहा ना सवना है।

अनु० 117—पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 में विहित विवरण का अनुपालन अनिवार्य या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन के सवत्र में निम्नांकित स्थानों में आवश्यक नही है —

- (1) वे स्थान जहाँ स्वभावतः कुछ सला राता हो लात्रा निकाली जाता हा अथवा जहाँ नविक आचारा के प्रतिकूल काम हान हा
- (2) पान्यगाला (Inns) भात्रालय या अन्य स्थान जहाँ ला रात का भा पहुँच सकते हा किन्तु कवन उद्देश्य में जबकि वे उन सामान्य के लिए खुल रहन हा।

अनु० 118—उस दगा में जबकि अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र का निष्पादन निम्नलिखित हा आवश्यकतानुसार उससे संबंध स्थान बन्द किया जा सकता है अथवा इसके लिए कोई भी (rule) तब तक के लिए निर्दुक्त किया जा सकता है जब तक कि निष्पादन पूर्ण न हो तब तक।

अनु० 119—जब कोई तलाशी की गई हो और साक्ष्य के किसी अथवा अभिग्रहण योग्य वस्तुओं का पता न लगा हो तो उस व्यक्ति की माँग पर, जिसकी तलाशी हुई हो, इस तथ्य का प्रमाण-पत्र उसे दिया जाएगा।

अनु० 120—अभिग्रहण के सदर्थ में, ली गई संपत्ति की एक वस्तु-सूची (inventory) बनाई जाएगी और संपत्ति के स्वामी अधिकर्ता या अभिरक्षक का अथवा उसकी अनुपस्थिति में उस व्यक्ति को, जो उसका अभिवेदन करता हो दे दी जाएगी।

अनु० 121 अभिगृहीत वस्तुओं के सवन्ध में, जिनका परिवहन सुविधा-पूर्वक न किया जा सके या जिन्हें सुविधापूर्वक अभिरक्षा (custody) में न रखा जा सके, या तो एक रक्षो (guard) रखा जा सकता है या उसका स्वामी या अन्य कोई व्यक्ति उसका अभिरक्षक बनने के लिए नियत किया जा सकता है यदि वह इससे सहमत हो।

अभिगृहीत वस्तुओं को यदि उनसे खतरा पैदा होने की आशका हो, विनष्ट किया अथवा दूर फेंका जा सकता है।

वह व्यक्ति, जिसने अभिग्रहण का अधिपत्र निष्पादित किया हो, पिछले दो परिच्छेदों में उल्लिखित कारवाइयाँ को भी कार्यान्वित कर सकता है, जबतक कि किसी न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेश न दिए जायें।

अनु० 122—यदि इस बात की आशका हो कि अभिगृहीत वस्तुएँ, जो राज्यसात्करण के योग्य हो, खो जाएँगी, विनष्ट या क्षत हो जाएँगी अथवा उन्हें सुविधापूर्वक अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता तो वे न्यायालय द्वारा बेची जा सकती हैं और वागम (Proceeds) अभिरक्षा में रखा जा सकता है।

अनु० 123—अभिगृहीत वस्तुएँ, जिनका प्रतिधारण अनावश्यक हो, बाद की समाप्ति की बिना प्रतीक्षा किए, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, प्रत्यावर्तित की जा सकती हैं।

अभिग्रहण के अन्तर्गत रखी वस्तुओं का, उन्हें प्रस्तुत करने वाले स्वामी, अधिकर्ता, अभिरक्षक या पार्टी का माँग करने पर, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, अस्थायीरूप से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

लाभ-समाहर्ता और अभियुक्त, या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की समिति, पिछले दो परिच्छेदों में उल्लिखित व्यवस्थाओं (rulings) के कार्यान्वित किए जाने के पहले ही सुनी जाएगी।

अनु० 124—असद रूप से प्राप्त (ill-gotten) अभिगृहीत माल, जिनका प्रतिधारण आवश्यक हो लोक-समाहर्ता अभियुक्त अथवा उसने प्रतिवाद-परामर्शदाता की समिति सुनने के बाद एक व्यवस्था (ruling) द्वारा याद की गमाप्ति की बिना प्रतीक्षा किए हुए अपवृत्त पक्ष को प्रत्यावर्तित कर दिए जाएंगे, किन्तु केवल उसी दशा में जब कि उन्हें अपवृत्त पक्ष को प्रत्यावर्तित करने के स्पष्ट कारण हों।

विच्छेद १ परिच्छेद के उपबन्ध किसी बद्धरित (interested) व्यक्ति को, बीवानी प्रविष्टा द्वारा अपने अधिकार प्रदर्शन से नहीं रोक्नेगे।

अनु० 125 सहयोगी न्यायालय के किसी सदस्य को अभिग्रहण या तलाशी कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है अथवा जहाँ अभिग्रहण या तलाशी कार्यान्वित करनी हो उस स्थान पर, जिला-न्यायालय, परिवार न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सूचित करने के लिए अधिवाचित किया जा सकता है।

अधिवाचित न्यायाधीश जिला-न्यायालय परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को, जिसे उक्त अभिग्रहण के अन्तर्गत कार्य करने का अधिकार हो, अधिवाचित कर सकता है।

यदि अधिवाचित न्यायाधीश के पास स्वयं, अभिग्रहण के अन्तर्गत विषय पर कोई प्राधिकार न हो तो वह उस अधिवाचना को दूसरे जिला-न्यायालय, परिवार न्यायालय, अथवा क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, जो उक्त अधिवाचना स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत हो, अन्तर्हित कर सकता है।

जहाँ तक किसी राजादिष्ट न्यायाधीश या अधिवाचित न्यायाधीश द्वारा कार्यान्वित अभिग्रहण या तलाशी का सम्बन्ध है, किसी न्यायालय द्वारा कार्यान्वित अभिग्रहण या तलाशी से सबद्ध उपबन्ध, मघोचित परिस्थान के साथ, लागू होंगे। तथापि, अनुच्छेद 100 परिच्छेद 3 में उल्लिखित सूचना किसी न्यायालय द्वारा दी जाएगी।

अनु० 126—यदि निरोध या प्रस्तुति के अधिपत्र के निष्पादन के लिए आवश्यक हो तो लोक-समाहर्ता-न्यायालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी, अभियुक्त की तलाशी के लिए, किसी व्यक्ति के विचार, अथवा परिवार, भयन या व्यक्तिगत द्वारा रक्षित जलवायु में प्रवेश कर सकता है। उपर्युक्त दशा में तलाशी या अधिपत्र आवश्यक नहीं है।

अनु० 127—पिछले परिच्छेद के उपबन्धों के अनुसरण में, किसी न्यायिक पुलिस कर्मचारी या लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव द्वारा कार्यान्वित तलाशी के सबन्ध में, अनुच्छेद 111, 112, 114 तथा 118 के उपबन्ध, योजित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे। तथापि, अविलम्बिता की दशा में, अनुच्छेद 114 परिच्छेद 2 के उपबन्ध का अनुपालन आवश्यक नहीं होगा।

अध्याय 10

निरीक्षण द्वारा साक्ष्य

(Evidence by Inspection)

अनु० 128—तथ्या का पता लगाने के लिए यदि आवश्यक हो तो न्यायालय साक्ष्य का एक निरीक्षण (Inspection of Evidence) कार्यान्वित कर सकता है।

अनु० 129—निरीक्षण के सदर्थ में, शरीर की परीक्षा, शव का विच्छेदन, कब्र का उत्खनन (opening of grave), वस्तुओं का विनाश अथवा अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

अनु० 130—सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद, किसी व्यक्ति के निवास अथवा पत्थर, भवन या व्यक्तियों द्वारा रक्षित जलयानों में, निरीक्षण के लिए, उनके अधिभोक्ता (occupants) या पालक या उनके स्थान पर काम करने वाले व्यक्तियों की समति से ही प्रवेश किया जा सकता है। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा जब कि यह आशका हो कि निरीक्षण की वस्तु सूर्योदय के बाद न मिल सकेगी।

सूर्यास्त के पहले प्रारम्भ किया गया निरीक्षण, सूर्यास्त के बाद भी जारी रखा जा सकता है।

अनुच्छेद 117 में उल्लिखित स्थानों के सबन्ध में, पहले परिच्छेद में उल्लिखित निबन्धन का पालन आवश्यक नहीं।

अनु० 131—शरीर की परीक्षा में लिंग, स्वास्थ्य की दशा, एवं अन्य परिस्थितियों का विचार, अवश्य किया जाएगा और उस व्यक्ति (स्त्री या पुरुष) की स्वाति का क्षति न पहुँचे इसके लिए हर उपाय से, विशेषतः निरीक्षण के दृग के चयन में, अवश्य विचार किया जाएगा।

किसी स्त्री की शरीर-परीक्षा में, किसी डाक्टर या अन्य वैद्यक हकी को उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

अनु० 132—न्यायालय, अभियुक्त से भिन्न व्यक्तियों को शरीर-परीक्षा के लिए या तो न्यायालय में या अन्य नामोद्दिष्ट स्थान पर बुला सकता है।

अनु० 133—उस दशा में जबकि पिछले अनुच्छेद के अनुसार माहृत (summoned) व्यक्ति बिना उचित कारण के उपमजान (पेश) न हो तो न्यायालय एव व्यवस्था (ruling) द्वारा उस पर पाँच हजार पैन तक का अदायिज अयदण्ड (non-penal fine) लगा सकता है और साथ ही उसकी अनुपसज्जाति (non-appearance) से होने वाले व्यय का प्रतिवर दमे के लिए आदेश दे सकता है।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आसन (immediate) कोकोठु अपील की जा सकती है।

अनु० 134 उस दशा में जबकि अनुच्छेद 132 के अनुसार समन किया हुआ व्यक्ति, बिना उचित कारण के उपसज्जात न हो तो उसे पाँच हजार पैन तक का अयदण्ड अथवा निरोध से दण्डित किया जा सकता है।

पिछले परिच्छेद के अपराध करनेवाले व्यक्ति पर परिस्थितियों के अनुसार, अयदण्ड और निरोध दोनों ही दण्ड लगाए जा सकते हैं।

अनु० 135—प्रत्येक व्यक्ति को, जो अनुच्छेद 132 के अनुसार समन (आह्वान) का पालन न करे, फिर से समन किया जा सकता है अथवा प्रस्तुति के अधिन पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

अनु० 136—अनुच्छेद 62, 63 और 65, मयाचित परिवर्तन के साथ, अनुच्छेद 132 और पिछले अनुच्छेद के उपबन्धा के अन्तर्गत समनों के सबन्ध में लागू होंगे, जबकि अनुच्छेद 62, 64 66, 67 70 71 और अनुच्छेद 73 का परिच्छेद 1, पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित प्रस्तुति (production) के सबन्ध में लागू होंगे।

अनु० 137—उस दशा में जबकि अभियुक्त अथवा अभियुक्त से भिन्न कोई व्यक्ति बिना समुचित कारण के, शरीर की परीक्षा अस्वीकृत कर दे तो उसे एक व्यवस्था (ruling) द्वारा पाँच हजार पैन तक का अदायिज अयदण्ड (non-penal fine) लगाया जाएगा, और साथ ही उसे उक्त

अस्वीकरण से होनेवाले व्यय का प्रतिफल देने के लिए आदेश दिया जा सकता है ।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आसन्न (immediate) कोकोफु अपील की जा सकती है ।

अनु० 138—प्रत्येक व्यक्ति का, जो बिना समुचित कारण के, शरीर की परीक्षा को अस्वीकृत करे, अधिक से अधिक पाँच हजार येन तय का अर्थदण्ड या निरोध का दण्ड दिया जाएगा ।

प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अपराध किया हो, परिस्थितियाँ के अनुसार, अर्थदण्ड एवं निरोध दोनों ही दण्ड दिया जा सकता है ।

अनु० 139—उस दशा में जबकि न्यायालय, शरीर-परीक्षा अस्वीकृत करनेवाले व्यक्ति पर अदाण्डिक अर्थदण्ड या अन्य दण्ड लगाना प्रभावशून्य समझे तो वह उसकी अस्वीकृति (refusal) का बिना विचार किए हुए उसकी शरीर की परीक्षा करा सकता है ।

अनु० 140—अनुच्छेद 137 के अन्तर्गत अदाण्डिक अर्थदण्ड लगाने अथवा पिछले अनुच्छेद के अन्तर्गत शरीर-परीक्षा के निष्पादन के पूर्व ही, न्यायालय किसी लोच-समाहर्ता की समिति सुनेगा और उस व्यक्ति की आपत्तियों (objections) को निश्चित रूप से जानने के लिए उचित प्रयत्न भी करेगा, जिसकी परीक्षा करनी हो ।

अनु० 141—निरीक्षण में, आवश्यकतानुसार, किसी न्यायिक पुलिस कर्मचारी का सहायता के लिए प्रेरित किया जा सकता है ।

अनु० 142—अनुच्छेद 112 से 114, 118 और 125 के उपबन्ध, यथाचित परिवर्तन के साथ, निरीक्षण के सवन्ध में लागू होंगे ।

अध्याय 11

साक्षी की परीक्षा

(Examination of Witness)

अनु० 143—इस विधि में अन्यथा विहित दशा को छोड़कर, न्यायालय साक्षी के रूप में किसी भी व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है ।

अनु० 144 यदि कोई व्यक्ति, जो लोक-कर्मचारी हो या पहले रह चुका हो, उन तथ्यों के विषय में जानकारी रखता हो जिनके विषय में वह स्वयं, अथवा लोक-कार्यालय जिससे वह संबद्ध हो या पहले रह चुका हो। यह घोषित करे कि वे तथ्य कार्यालयीय दृष्टियों से सबन्ध रखते हैं, तो साक्षी के रूप में उसकी परीक्षा, किसी सदस्य पर्यवेक्षी कार्यालय (competent supervisory office) की समति के बिना नहीं की जा सकती। तथापि, उक्त कार्यालय, उन दस्तावेजों छोड़कर जिनमें अनुपालन राज्य के प्रधान हिता के प्रतिबल हो, उक्त समति देना अस्वीकृत नहीं कर सकता।

अनु० 145— यदि पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित घापणा निम्नलिखित व्यक्तिवा द्वारा की गई हो तो साक्षी के रूप में उनकी परीक्षा प्रभाग 1 में उल्लिखित व्यक्ति के सबन्ध में सदन की समति के बिना, और प्रभाग 2 में उल्लिखित व्यक्ति के सबन्ध में, मन्त्रिपरिषद् की समति के बिना, नहीं की जाएगी :

(1) वह व्यक्ति, जो प्रतिनिधि-सदन या सभासद-सदन का सदस्य हो या रह चुका हो,

(2) वह व्यक्ति, जो प्रधान-मन्त्री या राज्य-मन्त्री हो या रह चुका हो।

पिछले परिच्छेद की दशा में, प्रतिनिधि-सदन, सभासद-सदन या मन्त्रि-परिषद् केवल उस दशा को छोड़कर जबकि अनुपालन राज्य के प्रधान हिता के प्रतिबल हो, उक्त समति देना अस्वीकृत नहीं कर सकती।

अनु० 146— कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी प्रश्न का उत्तर देना अस्वीकृत कर सकता है जिसका लक्ष्य स्वयं अपने आपका अभिशस्त (incriminate) करना हो।

अनु० 147— साक्षी ऐसे किसी भी प्रश्न का उत्तर देना अस्वीकृत कर सकता है जिसका लक्ष्य निम्नांकित व्यक्तिवा का अभिशस्त करना हो

- (1) साक्षी का पति या पत्नी, तीसरी सबन्ध-बोटी (third degree of relationship) के अन्दर का रक्त-सबन्धी, अथवा दूसरी सबन्ध-बोटी के अन्तर्गत विवाह-सबन्ध का सबन्धी अथवा वह व्यक्ति जो साक्षी के उपर्युक्त सबन्धियों में से कोई सबन्धी रहा हो,
- (2) साक्षी का संरक्षक, संरक्षण का पर्यवेक्षक या पालक (curator),
- (3) वह व्यक्ति जिसका संरक्षक, संरक्षण का पर्यवेक्षक, अथवा पालक (curator) साक्षी स्वयं हो।

अनु० 148 यद्यपि साक्षी पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित सबन्धों में से सहापराधिया (co-offenders) या सहप्रतिवादियों (co-defendants) में किसी एक या अधिक द्वारा सबद्ध हो तथापि वह उन तथ्या के सबन्ध में उत्तर देना अस्वीकार नहीं करेगा जो सहापराधिया या सहप्रतिवादियों से सबन्ध रखते हैं।

अनु० 149— कोई व्यक्ति जो डॉक्टर दन्तचिकित्सक, दाई, उपचारिता, अधिवक्ता एक्स्व अभिवर्ता (Patent Agent), लेख्य प्रमाणक या घासिक कार्यकर्ता है या रह चुका है, उन तथ्या के सबन्ध में जिनकी जानकारी उसे किसी प्रादेश (mandate) के फलस्वरूप हुई हो जा उसे अपनी व्यावसायिक दृष्टि में मिला हो, और जिनका सबन्ध अन्य व्यक्तियों के रहस्यों से हो मौखिक साक्ष्य देना अस्वीकृत कर सकता है। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा यदि मुख्य (मुख्यकल) ने समझि दे दी है अथवा जगि मौखिक साक्ष्य की अस्वीकृति का केवल अधिकार के दुरूपयोग से अतिरिक्त और कुछ न समझा जाए जिसका उद्देश्य अभिगुन्य का हित मात्र है। जबकि वह मुख्य अपराधी न है। अथवा कोई विशेष परिस्थितियां हो जिनका निश्चय न्यायालय-नियमा द्वारा किया जाएगा।

अनु० 150— यदि कोई समन किया गया साक्षी बिना उचित कारण के उपसजात होने में असमर्थ रहे तो उसे, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा अधिक से अधिक पाँच हजार येन तब का अदाण्डिक अर्थदण्ड (non-penal fine) दिया जा सकता है और साथ ही उसे उसकी अनुपसजाति (non-appearance) से होने वाले व्ययों के प्रतिकर देने का आदेश दिया जा सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आसन्न (immediate) अपील की जा सकती है।

अनु० 151— यदि साक्षी ने रूप में समन किया गया कोई व्यक्ति, बिना उचित कारण के, उपसजात होने में असमर्थ रहे तो उसे पाँच हजार येन तब का अर्थदण्ड या निरोध का दण्ड दिया जाएगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित दशा में, परिस्थितियों के अनुसार, अर्थदण्ड और निरोध दोनों की दण्ड लगाए जा सकते हैं।

अनु० 152—ऐसे साक्षी का जा समन का अनुपालन न कर, फिर से समन दिया जा सकता है ।

अनु० 153—अनुच्छेद 62, 63 और 65 के उपरान्त, यथाचित परिघटन के साथ साक्षी के समन के सवन्ध में लागू होने ज़रूर अनुच्छेद 62, 64, 66, 67, 70, 71 और 73 परिच्छेद 1 के उपरान्त गयी की प्रस्तुति के सवन्ध में ।

अनु० 154 साक्षी का हम विधि में अथवा विहित दंड का छात्र, शपथ दिये जाएगा ।

अनु० 155— शपथ न गमन करने वाला साक्षी की परीक्षा बिना शपथ दिये जा ही जाएगी ।

यदि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कोई मांगी (बलती से) शपथ ल दिया हो तथापि यह उमरे प्रमाण का सत्य मान्य होने से नहीं रोकता ।

अनु० 156 साक्षी का अपन अनुमानों के विवरण देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है जिसे उमने अपने अनुमन तथा से निरास है ।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित विवरण प्रमाण के रूप में अपनी मान्यता नहीं पाएगा चाहे वह विशेषतः साक्ष्य (expert evidence) का रूप में धारण करे ।

अनु० 157 साक्षी का परीक्षा के समय छात्र-समाहर्ता अभियुक्त अथवा उमरा प्रतिवाद परामर्शदाता उपस्थित रह सकता है ।

पिछले परिच्छेद के अनुसार परीक्षा के समय उपस्थित रहने के अधिकारों व्यक्तिता का साक्षी की परीक्षा के स्थान एवं निर्दिष्ट का गृहना अधिकार में दा जाएगी । तथापि यह उस दंड में लागू नहीं होगा जे रि परीक्षा के समय उपस्थित रहने का अधिकारी व्यक्ति वहाँ उपस्थित न रहने का अपनी दृष्टि व्यापार्य के समन अधिकार में स्पष्टत व्यक्त करे ।

जेर पछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यक्ति साक्षी की परीक्षा के समय उपस्थित हा ना के निम्नो पोटागीन व्याख्यास कर अविसूचित करके साक्षी की परीक्षा कर सकते हैं ।

अनु० 158—छात्र-समाहर्ता एवं अभियुक्त या उसका प्रतिवाद परामर्श-दाता की समन सुनने के बाद, तथा साक्षी, उसकी आयु, व्यवसाय स्वास्थ्य, अन्य विशेष परिस्थितियों के महत्व एवं बाद के गृहना पर विचार करत हुए

यायाग्य यदि आवश्यक समझ तो साक्षी का परीक्षा के लिए यायालय से भिन्न किसी स्थान पर समन कर सकता है अथवा वह जहाँ हो वहाँ पराग कर सकता है ।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित दंगा के अंतर्गत यायालय लाक-समाहृता अभियुक्त और उसके प्रतिवाद परामर्शदाता को यायालय द्वारा साक्षात् पूछ जाम बाँटे प्रश्नों का जानने का अवसर अग्रिम रूप में दंगा ।

लाक-समाहृता अभियुक्त अथवा उसके प्रतिवाद परामर्शदाता पिछले परिच्छेद में उल्लिखित प्रश्नों में प्रमाण अपने प्रश्नों का जान सकते हैं और उन्हें साक्षात् पूछने के लिए यायाग्य से निवेदन कर सकते हैं ।

अनु० 159—पिछले अनुच्छेद द्वारा विहित साक्षी की परीक्षा के समय यदि लाक-समाहृता अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता उपस्थित न रहा हो तो यायाग्य लाक-समाहृता अभियुक्त अथवा उसके प्रतिवाद परामर्शदाता को साक्षी द्वारा प्रमाणित तथ्य जानने का अवसर दंगा ।

उस दंगा में जब कि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित साक्षी के प्रमाण में अभियुक्त का कोई अप्रमाणित एवं गम्भीर अलाभ है तो वह अथवा उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता यायाग्य से उन विषयों के संबंध में जिस वह अथवा उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता प्रतिवाद के लिए आवश्यक समझता है पुनः परीक्षा के लिए फिर से निवेदन कर सकते हैं ।

यायाग्य पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन को स्वीकार कर सकता है यदि वह उक्त निवेदन को युक्तियुक्त न समझे ।

अनु० 160—यदि कोई साक्षी गपथ गन अथवा बिना उचित कारण के प्रमाण बना अस्वीकृत करे तो उस एक व्यवस्था (ruling) के आधार पर पाँच हजार यन तक का अल्पव्यय (non penal fine) एवं साथ ही उक्त अस्वाकृति सहित यात्रा व्ययों के प्रतिफल देने का आदेश दिया जा सकता है ।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आसन्न (immediate) कोकोकु अपील का जा सकता है ।

अनु० 161—किसी व्यक्ति को गपथ गन अथवा बिना उचित कारण के प्रमाण बना अस्वीकृत करने पर पाँच हजार यन तक का अल्पव्यय या निराप का दण्ड दिया जाएगा ।

पिटच परिच्छेद में उल्लिखित दशा के अन्तर्गत परिस्थितियों के अनुसार, अर्बदण्ड एवं निरोध दाना ही दण्ड लगाए जा सकते हैं।

अनु० 162 न्यायालय एक व्यवस्था (ruling) के आधार पर, आवश्यकतानुसार साक्षी का किसी नामाद्विष्ट स्थान पर साथ जाने के लिए आदेश दे सकता है। साक्षी को यदि वह बिना किसी उचित कारण के साथ जाने के आदेश का अनुपालन न करे प्रस्तुत कराया जा सकता है।

अनु० 163 उस दशा में जब कि किसी साक्षी की परीक्षा न्यायालय के बाहर कम्पनी हो तो उक्त परीक्षा करने के लिए सहयोगी न्यायालय के किसी सदस्य का प्रेरित किया जा सकता है अथवा जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश का जहाँ वह साक्षी हो, वहाँ (परीक्षा) करने के लिए अधिवाचित किया जा सकता है।

अधिवाचित न्यायाधीश अपनी बारी में किसी अन्य जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अधिवाचित कर सकता है जिस उक्त अधिवाचना स्वीकृत करने का प्राधिकार हो।

यदि अधिवाचित न्यायाधीश को अधिवाचना के अन्तर्गत विषय पर स्वयं प्राधिकार न हो तो वह अधिवाचना का अन्य जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश के यहाँ अन्तरित कर सकता है जिस उक्त अधिवाचना स्वीकृत करने का प्राधिकार हो।

साक्षी की परीक्षा के सबन्ध में राजाद्विष्ट अथवा अधिवाचित न्यायाधीश पीठासीन न्यायाधीश के न्यायालय से सवट्ट कारवाइयाँ कर सकता है। तथापि अनुच्छेद 150 एवं 160 में उल्लिखित व्यवस्थाएँ (rulings) न्यायालय द्वारा ही की जा सकेंगी।

पिटच परिच्छेद को छोड़कर अनुच्छेद 158 परिच्छेद 2 और 3 तथा अनुच्छेद 159 द्वारा विहित सभी कार्यवाहियाँ (प्रधान) न्यायालय द्वारा कार्यान्वित की जाएँगी।

अनु० 164—साक्षी यात्रा-व्यय (travelling expenses), दैनिक भत्ता एवं निवास प्रभारों (lodging charges) की माँग कर सकता है। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा, यदि उसने बिना उचित कारण के शपथ लेने अथवा प्रमाणित करने से इन्कार किया हो।

अध्याय 12

विशेषज्ञ साक्ष्य (Expert Evidence)

अनु० 165—न्यायालय विद्वाना एव अनुभव वाले व्यक्तियों को विशेष साक्ष्य (expert evidence) देने के लिए आदेश दे सकता है।

अनु० 166—विशेषज्ञ माक्षी को मध्य दिलाया जायगा।

अनु० 167—यदि अभियुक्त की शारीरिक या मानसिक दशाओं के सम्बन्ध में विशेषज्ञ साक्ष्य की आवश्यकता हो, तो न्यायालय, आवश्यकतानुसार, अभियुक्त को किसी औपचारिक या अन्य उपयुक्त स्थान में, निश्चित अवधि तक परिच्छेद रख सकता है।

पिछले परिच्छेद के अनुसार अभियुक्त का परिच्छेद रखने के लिए परिरोध का एक प्रादेश (writ) जारी किया जाएगा।

इस विधि में अन्यथा विहित दण्ड का छाड़कर, निरोध-मार्गी उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, पहल परिच्छेद में उल्लिखित परिरोध के साथ में लागू होंगे। तथापि, यह जमानती निर्मुक्ति से सबद्ध उपबन्धों के मध्य में लागू नहीं होंगे।

अनु० 168—विशेषज्ञ साक्ष्य के लिए आवश्यकतानुसार, कार्ट विशेषज्ञ साक्षी, न्यायालय की अनुमति से, किसी व्यक्ति के निवास, परिमण, भवन या व्यक्तियों द्वारा रक्षित जलयानों में प्रवेश कर सकता है, शरीर की परीक्षा (जाँच) कर सकता है, शव का विच्छेदन कर सकता है, समाधि उखाड़ सकता है, अथवा वस्तुओं को तोड़ या विनष्ट कर सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अनुमति देने पर, न्यायालय अनुमति का एक अधिपत्र जारी करेगा जिसमें अभियुक्त का नाम, अपराध, स्थान जिसमें प्रवेश करना हो, शरीर, जिसकी परीक्षा करनी हो, शव जिसका विच्छेदन करना हो, समाधि जिसे उखाड़ना हो, वस्तुएँ जिन्हें विनष्ट करना हो, विशेषज्ञ साक्षी का नाम तथा न्यायालय के नियमों द्वारा विहित अन्य विषय लिखित रहेंगे।

न्यायालय किसी व्यक्ति (शरीर) की परीक्षा के लिए कुछ उपबन्धों को विहित कर सकता है जिन्हें वह न्यायालय युक्तिमग्न मगसे।

विशेषज्ञ माश्री अनुमति का अधिपत्र उम व्यक्ति का दिखाना त्रिम पर पत्र परिच्छेद में उल्लिखित कारवाई हुई है।

पिछले तीन परिच्छेदों के उपरान्त विशेषज्ञ माश्री द्वारा न्यायालय-क्षेत्र में की जाने वाली पत्र परिच्छेद में उल्लिखित कारवायों के संबंध में नहीं लागू होंगे।

अनुच्छेद 131, 137, 138 और 140 के उपरान्त यथाचित परिवर्तन के साथ, पत्र परिच्छेद की व्यवस्थाओं के अनुसार किसी विशेषज्ञ माश्री द्वारा की गई परीक्षा की परीक्षा के संबंध में लागू होंगे।

अनु० 169—न्यायालय, महापाली न्यायालय के किसी सदस्य का विशेषज्ञ माश्री होने के लिए आवश्यक कारवाई करने का प्रेरित कर सकता है। तथापि यह अनुच्छेद 167, परिच्छेद 1 में विहित कारवायों के संबंध में लागू नहीं होगा।

अनु० 170—विशेषज्ञ माश्री द्वारा की जाने वाली परीक्षा या जांच के समय लाइ-अपमाइनों या प्रतिवाद-अगमशदानों परम्पित रह सकते हैं। इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 157 परिच्छेद 2 के उपरान्त, यथाचित, परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

अनु० 171 प्रभुति में सबूत उपरान्त का छाडकर, पिछले अध्याय के उपरान्त, यथाचित परिवर्तन के साथ, विशेषज्ञ माश्री के संबंध में लागू होंगे।

अनु० 172—वह व्यक्ति, त्रिमका शरीर-परीक्षा, अनुच्छेद 168, परिच्छेद 1 के अनुसार किसी विशेषज्ञ माश्री द्वारा की जाने वाली है, यदि परीक्षा देने में इच्छा करे तो विशेषज्ञ माश्री परीक्षा के लिए किसी न्यायाधीश से निषेधन कर सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन पर, न्यायाधीश, आवश्यक परिवर्तन के साथ अध्याय 10 की व्यवस्थाओं के अनुसार, शरीर की परीक्षा कर सकता है।

अनु० 173—विशेषज्ञ माश्री अपने यात्रा-व्यय, दैनिक भत्ते एवं निवास खर्च के साथ ही साथ अपनी समिति एवं परिचय की प्रतिपूर्ति के शुल्क की मांग कर सकता है।

अनु० 174—उस दशा में जब कि किसी व्यक्ति की परीक्षा, उन भूत-कालीन तथ्यों के संघर्ष में की गई हो, जिन्हें वह अपने विशेष-ज्ञान के कारण जानता हो, तो इस अध्याय के उपबन्धों के बदले पिछले अध्याय के उपबन्ध ही कार्यकर होंगे।

अध्याय 13

अर्थ-निर्वाचन एवं अनुवाद

(Interpretation and Translation)

अनु० 175—उस दशा में जब कि किसी ऐसे व्यक्ति में विवरण लेना हो जा जापानी भाषा में प्रयोग न हो ता एक भाषान्तर करने वाले (ट्रिभाप) को अर्थ-निर्वाचन के लिए प्रेरित किया जाएगा।

अनु० 176—उस दशा में जब कि किसी बहिर या मूक में विवरण लेना हो ता किसी अर्थ-निर्वाचक का अर्थ लगाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

अनु० 177 वण, चिह्न या मन्त्रेन जा जापानी भाषा में न हो अनूदित कराए जा सकते हैं।

अनु० 178 पिछले अध्याय के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, अर्थ-निर्वाचन एवं अनुवाद के सम्बन्ध में लागू होंगे।

अध्याय 14

साक्ष्य का परिचक्षण

(Preservation of Evidence)

अनु० 179—अभिषुक्त, सदिग्ध अथवा उनका प्रतिवाद-प्रगमसंज्ञाना, जब ऐसे कारण हो जिनमें साक्ष्य का अधिक परिचक्षण न होने पर, साक्ष्य का उपयोग दुष्कर हो जाय, पठे लाह-विचारण के पूर्व ही, न्यायाधीश में अभि-ग्रहण, तथ्यांश, निरीक्षण द्वारा साक्ष्य, साक्षी की परीक्षा अथवा विशेषज्ञ साक्ष्य जैसी कार्रवाइयों के करने का निवेदन कर सकता है।

पिछले परिच्छेद में विहित निवेदन का प्राप्त करने वाले न्यायाधीश को यही अधिकार होगा जैसा किसी पोडमोन न्यायाधीश के न्यायाध्य को उसकी कार्रवाइयों के संघर्ष में होता है।

अनु० 180—वार्ड लाव समाप्तता तथा प्रतिवाद-परामर्शदाता, न्यायालय में पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 में उल्लिखित वारंवाइया से सबद्ध साक्ष्य के असा एवं प्रत्येका (documents) का निरीक्षण एवं उसकी प्रतिलिपि कर सकते हैं। तथापि, यदि प्रतिवाद-परामर्शदाता को साक्ष्य के असा की प्रतिलिपि करना हो तो उसे न्यायाधीश की अनुमति लनी होगी।

अभियुक्त या सदिश्य न्यायालय में न्यायाधीश की अनुमति से, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित प्रत्येका एवं साक्ष्य के असा से निरीक्षण कर सकते हैं। तथापि यह उम दशा में लागू नहीं होगा जब कि अभियुक्त या सदिश्य को कोई प्रतिवाद-परामर्शदाता सौंपा गया हो।

अध्याय 15

विचारण के परिचय

(Costs of Trial)

अनु० 181—दण्ड के उद्घोषित किए जाने पर, विचारण के परिचय का पूरा या वार्ड असा अभियुक्त से धाज (बमूठ) किया जाएगा।

वार्ड दण्ड उद्घोषित किए जाने पर भी, यह परिचय, जो ऐसे कारण से उत्पन्न हुआ हो, जिसे अभियुक्त पर आरोपित किया जा सके, अभियुक्त से बमूठ किया जाएगा।

उम दशा में जब कि बेवल लोग-समाप्तता ने ही अपील की हो और वह अनीक मरिज की गई या वापस ले ली गई हो तो अपील से सबद्ध परिचय अभियुक्त पर नहीं लगाए जाएंगे।

अनु० 182—सहापराधियों के विरुद्ध विचारण का परिचय, उन सहा-पराधियों पर इस तरह लगाया जाएगा जिस के समुक्त और पृथक् रूप से घटन करे।

अनु० 183—यदि, उम दशा में जबकि उस अभियोग में निर्दोषिता या विमुक्ति का वार्ड निर्णय दिया गया हो जिस पर लाव-वारंवाई प्रतिवाद, अभियोजन या निवेदन से हुई हो, प्रतिवादकर्ता, अभियोक्ता या निवेदक ने असद्भाव (in bad faith) या धार प्रमादवश कार्य किया हो तो विचारण का परिचय उसी पर लगाया जाएगा।

अनु० 184—कार्यवाही के पुनर्विचार की मांग या अपील के सबंध में, जो लाक-समाहर्ता में भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा वापस ले ली गई हो, अपील या कार्यवाही के पुनर्विचार में सबद्ध परिषद उक्त व्यक्ति पर लगाए जाएंगे।

अनु० 185—जबकि उक्त अभियोग में, जिसमें कि कार्यवाहियाँ निर्णय द्वारा समाप्त कर दी गई हों, विचारण का परिषद अभियुक्त पर लगाया जाने वाला हो तो उक्त परिषद के विषय में निर्णय पदेन (ex-officio) किया जाएगा। ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील केवल तभी की जा सकती है जब कि मुख्य विषयों (principal matters) के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा चुकी है।

अनु० 186—जबकि उक्त अभियोग में जिसमें कि कार्यवाहियाँ निर्णय द्वारा समाप्त कर दी गई हों, अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति पर विचारण के परिषद लगाए जाने वाले हैं तो इसके लिए एक पृथक् व्यवस्था (ruling) पदेन जारी की जाएगी। ऐसी व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आमत्र कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 187—जबकि उक्त अभियोग में विचारण का परिषद चार्ज करता हो, जिसमें कि कार्यवाहियों की समाप्ति (termination) निर्णय में भिन्न तरह की गई हो तो इसके लिए उक्त न्यायालय द्वारा, जिसमें कि अभियोग अंत में लम्बित हो, एक व्यवस्था (ruling) पदेन जारी की जाएगी। ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध आमतौर कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 188—यदि, किसी निर्णय में, विचारण के परिषद वहन किए जाने के लिए आदेश दिया गया हो, (किन्तु) परिषद की राशि निश्चित न की गई हो तो वह उक्त लाक-समाहर्ता द्वारा निश्चित की जाएगी जो इसके निष्पादन का निर्देश करने वाला हो।

दूसरा खण्ड

प्राथमिक व्यवहार (First Instance)

अध्याय 1

परिप्ररन (जॉच) एवं अनुसंधान (Inquiry and Investigation)

अनु० 189—राष्ट्रीय ग्रामीण पुलिस (National Rural Police) के सदस्य अथवा स्वायत्तशासी सत्ताओं (Autonomous Entities) के किसी पुलिस को, विधि द्वारा अथवा राष्ट्रीय लोक-सुरक्षा आयोग (National Public Safety Commission), अनुशासकीय लोक-सुरक्षा आयोग (Prefectural Public Safety Commission), नगर (City), पौर (Town) ग्राम्य (Village) लोक सुरक्षा आयोग के अथवा सबूत स्पेशल वार्ड लोक-सुरक्षा आयोग (Special Ward Public Safety Commission) के विनियमों (regulations) द्वारा प्राविष्टन होकर न्यायिक पुलिस कर्मचारी के रूप में अपना कर्तव्य करना होगा।

न्यायिक पुलिस कर्मचारी जब यह समझे कि कोई अपराध किया गया है तो उन्हें अपराधी और उगसे सबूत साक्ष्य का अनुसंधान करना होगा।

अनु० 190 - उन व्यक्तियों को, जिन्हें वन विभाग (forestry), रेलवे या अन्य विद्युत विषयों में न्यायिक पुलिस कर्मचारी के कृत्य करने हो, उनके कृत्यों के क्षेत्र का विधान अन्य विधि द्वारा किया जाएगा।

अनु० 191—लोक-समाहर्ता, यदि आवश्यक समझे, किसी अपराध का अनुसंधान स्वयं कर सकता है।

किसी लोक-समाहर्ता के अनुदेशानुसार, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव, किसी अपराध का अनुसंधान करेगा।

अनु० 192—आपराधिक अनुसंधान (Criminal Investigation) के विषय में, लोक-समाहर्ताओं एवं अनुशासकीय लोक-सुरक्षा आयोग (Prefectural Public Safety Commission), नगर (City), पौर

(Town) या ग्राम्य (Village) लोक-सुरक्षा आयोग (Public Safety Commission) स्पेशल वार्ड लोक-सुरक्षा आयोग (Special Ward Public Safety Commission) तथा न्यायिक पुलिस कर्मचारियों में पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय रहेगा।

अनु० 193 बार्ड लोक-समाहर्ता अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत, न्यायिक पुलिस कर्मचारियों का उनके अनुसंधान के विषय में आवश्यक सुझाव दे सकता है। उक्त सामान्य सुझाव अपराधिक अनुसंधान की मुख्य आवश्यकताओं के मानकों (Standards) के निर्धारण तक ही सीमित रहेंगे और जा (मानव) लोक-न्यायवादी के स्थापन एवं पुष्टीकरण के लिए आवश्यक होंगे।

लोक-समाहर्ता अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत, न्यायिक पुलिस कर्मचारियों को ऐसे सामान्य अनुदेश भी जारी कर सकता है जो उनका अनुसंधान में सहायता देने के लिए आवश्यक हों।

लोक-समाहर्ता, जबकि वह स्वयं किसी अपराध का अनुसंधान करता हो, आवश्यकतानुसार, न्यायिक पुलिस कर्मचारियों का अनुदेश दे सकता है और उन्हें अनुसंधान में महामता करने का प्रेरित कर सकता है।

पिछले तीन परिच्छेदों की दशाओं में, न्यायिक पुलिस कर्मचारियों को लोक-समाहर्ता के सुझावों एवं अनुदेशों का अनुसरण करना होगा।

अनु० 194—महा-समाहर्ता (Procurator General), उच्च लोक-समाहर्ता-कार्यालय का अधीक्षक-समाहर्ता (Superintending Procurator) या जिला-लोक-समाहर्ता-कार्यालय का प्रधान (Chief), उन दशाओं में जबकि न्यायिक पुलिस कर्मचारी, बिना उचित कारण के, लोक-समाहर्ता के सुझावों एवं अनुदेशों का अनुसरण न कर सके, यदि आवश्यक समर्थता उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई अथवा उनके हटाए जाने के संबंध में आरोप (Charges) फाइल कर सकता है, यदि वे ऐसे न्यायिक पुलिस कर्मचारी हों जो राष्ट्रीय ग्रामीण पुलिस (National Rural Police) के सदस्य या स्वायत्तशासी सत्ताओं (Autonomous Entities) के पुलिस हों तो, या तो राष्ट्रीय लोक-सुरक्षा आयोग, अनुशासकीय लोक-सुरक्षा आयोग, नगर, शहर या ग्रामीण लोक-सुरक्षा आयोग अथवा स्पेशल वार्ड लोक-सुरक्षा आयोग में या उस व्यक्ति के यहाँ, जिसे अनुशासनिक कार्रवाई

का अधिकार हो, आरोप फाइल कर सक्ता है, अथवा उन्हे हटाए जाने के लिए, यदि वे राष्ट्रीय ग्रामीण पुलिस कर्मचारियों या स्वायत्तशासी सत्ताओं के कर्मचारियों से भिन्न न्यायिक पुलिस कर्मचारी हों, कार्रवाई कर सकता है।

राष्ट्रीय लोक-सुरक्षा आयोग, अनुशासकीय लोक-सुरक्षा आयोग, नगर, पौर या ग्रामीण लोक-सुरक्षा या स्पेशल वार्ड लोक-सुरक्षा आयोग या वह व्यक्ति जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण पुलिस कर्मचारियों तथा स्वायत्तशासी सत्ताओं के पुलिस कर्मचारियों से भिन्न न्यायिक पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई देने या उन्हें हटाने का अधिकार हो, जब वे यह समझें कि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित आरोप साधारण हैं तो आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध, जैसा विधि द्वारा विहित हो, अनुशासनिक कार्रवाई करें या उन्हें हटा दें।

अनु० 195—लोक-समाहर्ता और लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव, आवश्यकता पड़ने पर, अनुसंधान के लिए अपने अधिकार-क्षेत्र के बाहर भी अपने कर्तव्य कर सकता है।

अनु० 196—लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव, न्यायिक पुलिस कर्मचारी, प्रतिवाद-परामर्शदाता और अन्य व्यक्तियों को जिनके कर्तव्य आपराधिक अनुसंधान से संबद्ध हैं, सदिग्ध (suspicious) या अन्य व्यक्तियों की क्षमता का दृष्टि न पहुँचाने और आपराधिक अनुसंधान के प्रशासन में हस्तक्षेप न करने के प्रति सावधान रहना आवश्यक है।

अनु० 197—अनुसंधान के संबंध में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक जांच की जा सकती है। तथापि, अनिवार्य कार्रवाइयाँ, उन दशाओं को छोड़कर जिनमें उनके लिए इस विधि में विशेष उपबन्ध हो, प्रवर्तित नहीं की जाएंगी।

सार्वजनिक कार्यालयों या सार्वजनिक या वैयक्तिक सत्ताओं से अनुसंधान से संबद्ध आवश्यक विषयों का विवरण देने के लिए माँग की जा सकती है।

अनु० 198—लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव एवं न्यायिक पुलिस कर्मचारी किसी सदिग्ध को, यदि आपराधिक अनुसंधान के अनुसरण में आवश्यक हो, अपने कार्यालय में उपसजात होने के लिए आदेश दे सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं। तथापि, सदिग्ध, उस दशा को छोड़कर जबकि वह दण्डीकरण या निरोध में हो, उपसजात होने से इस्करा कर सकता है, अथवा उपसजात होने के बाद किसी समय वापस जा सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित पृच्छा (questioning) की दशा में, सदिग्ध को अग्रिम रूप से अधिसूचित किया जाएगा कि वह किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार कर सकता है।

सदिग्ध (suspect) का वक्तव्य एवं नयाचार (Protocol) में लिया जाएगा।

सदिग्ध अपने सत्यापन (verification) के लिए पिछले परिच्छेद में उल्लिखित नयाचार का निरीक्षण करेगा अथवा वह उसके सामने पढ़ा जाएगा और यदि वह उसमें कुछ बढ़ाने, घटाने या बदलने का प्रस्ताव करे तो उसके टिप्पण नयाचार में दर्ज किए जायेंगे।

यदि सदिग्ध, यह सवागता है कि नयाचार की अन्तर्वस्तुएँ ठीक हैं तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने एवं सील करने के लिए कहा जा सकेगा। तथापि, उस दशा में लागू नहीं होगा जबकि सदिग्ध ऐसा करने से इन्कार करे।

अनु० 199—अपराध सदिग्ध द्वारा ही किया गया है इस दावा का कोई युक्तियुक्त पर्याप्त कारण रहने पर कोई लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी किसी न्यायाधीश द्वारा अग्रिम जारी किए गए बन्दीकरण के अधिपत्र पर उसे बन्दी कर सकता है। तथापि, पाँच हजार येन तन के अर्बदण्ड, निरोध या छोटे अर्बदण्ड द्वारा दण्डनीय अपराध के मन्त्र में उक्त बन्दीकरण केवल उन्ही दशा में हो सकेगा जबकि सदिग्ध का कोई निश्चित निवास न हो या यह पिछले परिच्छेद के उपबन्धों के अनुसार बुलाए जाने के बावजूद बिना समुचित कारण के उपसजान होने में असफल रहे।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित बन्दीकरण का अधिपत्र, किसी लोक-समाहर्ता या न्यायिक पुलिस अधिकारी के निवेदन पर जारी किया जाएगा।

पहले परिच्छेद में उल्लिखित अधिपत्र की माँग करते हुए, लोक-समाहर्ता या न्यायिक पुलिस कर्मचारी उस सदिग्ध के विरुद्ध उसी अपराध के लिए पहले किए गए सभी निवेदनों या अधिपत्रों के निर्गमों (issuance) को, जो कोई हो, न्यायालय को सूचित करेगा।

अनु० 200 बन्दीकरण के अधिपत्र में सदिग्ध का नाम एवं निवास, अपराध का नाम, सदिग्ध-अपराध के प्रमुख तथ्य, लोक-कार्यालय या अन्य स्थान जहाँ उसे लाना हो, प्रभावी (effective) अवधि और यह विवरण

कि इस अवधि के बीत जाने पर बन्दीकरण नहीं किया जा सकता और यह कि अधिपत्र जारी करनेवाले न्यायालय को वापस कर दिया जाएगा जारी होने की तिथि और अन्य विषय जो न्यायालय नियमा द्वारा विहित हों तथा अधिपत्र जारी करनेवाले न्यायाधीश का नाम एवं उसकी मुहर रहेगी।

अनुच्छेद 64 के परिच्छेद 2 और 3 के उपबन्ध यथोचित परिवर्तन के साथ, बन्दीकरण के अधिपत्र के साथ में लागू होंगे।

अनु० 201 जब किसी बन्दीकरण के अधिपत्र पर सदिग्ध का बन्दी किया जाता है तो अधिपत्र उसे दियाया जाएगा।

अनुच्छेद 73, परिच्छेद 3 के उपबन्ध यथाचिन् परिवर्तन के साथ उस दशा में भी लागू होंगे जहाँ सदिग्ध बन्दीकरण के अधिपत्र पर बन्दी किया जायगा।

अनु० 202 जब लोक-समाहर्ता-न्यायालय का सचिव या न्यायिक पुलिस सिपाही न बन्दीकरण के अधिपत्र पर किसी सदिग्ध का बन्दी किया जाता है तो पहला (=लोक-समाहर्ता-न्यायालय का सचिव) उस (सदिग्ध को) लोक-समाहर्ता एवं दूसरा (=न्यायिक पुलिस सिपाही) उसे न्यायिक पुलिस अधिकारी के समक्ष अधिवन्द्य प्रस्तुत करेगा।

अनु० 203—जब किसी न्यायिक पुलिस अधिकारी ने बन्दीकरण के अधिपत्र पर किसी सदिग्ध का बन्दी किया हो या बन्दीकरण के अधिपत्र पर बन्दी किए गए सदिग्ध को प्राप्त किया हो तो वह उसे अपराध के प्रमाण समझेगा, तथा वह प्रतिवाद-परामशदाता चुनने का अधिकारी है इस तथ्य को अधिवन्द्य सूचित करेगा और तब, उस स्पष्टीकरण देने का अवसर देते हुए वह उक्त सदिग्ध का जब कि उसे निरुद्ध करने की आवश्यकता न समझे अविलम्ब निर्मुक्त करेगा अथवा साक्ष्य एवं प्रलेखों के साथ सदिग्ध का, उसके अवरोध में लाए जाने के अड्डतालीस (48) घण्टे के अन्दर यदि उसे निरुद्ध करना आवश्यक समझे, किसी लोक-समाहर्ता के यहाँ अन्तरित करने की कार्रवाई कर सकेगा है।

पिछले परिच्छेद की दशा में, सदिग्ध से यह पूछा जाएगा कि उसके पास प्रतिवाद परामशदाता है या नहीं, यदि उसके पास हो तो उसे प्रतिवाद परामशदाता चुनने के अधिकार की सूचना देना आवश्यक नहीं है।

यदि सदस्य, पहले परिच्छेद में उल्लिखित कालावधि के अन्दर अन्तर्गत नहीं कर दिया जाता तो उसे अविलम्ब निर्मुक्त कर दिया जाएगा ।

अनु० 204—जब किसी लोक-सभाओं ने बन्दीकरण के अधिपत्र पर किसी सदस्य का बन्दी किया हुआ बन्दीकरण के अधिपत्र पर बन्दी किए गए सदस्य का प्राप्त किया हो (वैसे सदस्य का छाड़कर जा पिछले अनुच्छेद के अनुसार मर्मा गया हो) तो वह उस अपराध के प्रमुख तथ्या और वह परामर्शदाता चुनने का अधिकारी है—इस तथ्य को अविलम्ब सूचित करना और तब उस स्पष्टीकरण देने का अवसर देने हुए वह उस सदस्य का, जब कि उस निरुद्ध करने की आवश्यकता न समझे अविलम्ब निर्मुक्त कर देगा, अथवा उसके अवरोध में लाए जाने के अडनालीस (48) घण्टे के अन्दर, यदि उसे निरुद्ध करना आवश्यक समझे उस निरुद्ध करने के लिए किसी न्यायाधीश से निवेदन करेगा । तथापि, उस दशा में जब कि कालावधि के अन्दर कोई लोक-कारवाई संस्थित की जा चुकी हो तो निराध के लिए निवेदन आवश्यक नहीं ।

यदि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कालावधि के अन्दर निराध के लिए निवेदन अथवा लोक-कारवाई की संस्थिति न की गई हो तो सदस्य अविलम्ब छाड़ दिया जाएगा ।

पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 2 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, इस अनुच्छेद के परिच्छेद 1 की दशाओं के सबंध में लागू होंगे ।

अनु० 205—जब किसी लोक-सभाओं ने अनुच्छेद 203 के उपबन्धों के अनुसार सौंप गए किसी सदस्य का प्राप्त किया हो तो वह सदस्य का स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा और उसे निरुद्ध करने की आवश्यकता न समझने पर, अविलम्ब निर्मुक्त कर देगा अथवा सदस्य का निरुद्ध करने की आवश्यकता समझने पर, वह उस (सदस्य) के प्राप्त करने के चौबीस (24) घण्टे के अन्दर उसका निरुद्ध करने के लिए किसी न्यायाधीश से निवेदन करेगा ।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कालावधि, सदस्य को, अवरोध में लाए जाने के बाद, बहुततर (72) घण्टे से अधिक नहीं होगी ।

उस दशा में जब कि पिछले दो परिच्छेदों द्वारा विहित कालावधि के अन्दर कोई लोक-कारवाई संस्थित की जा चुकी हो तो लोक-सभाओं द्वारा निराध के लिए निवेदन करना आवश्यक नहीं ।

यदि निरोध के लिये निवेदन या लाक-कार्रवाई की सस्थिति, पहल और दूसरे परिच्छेद में उल्लिखित कालावधि व अन्दर न की जा सके तो सदिग्ध अविलम्ब निर्मुक्त कर दिया जायगा।

अनु० 206—उस दशा में जब कि अनिवार्य परिस्थितिया ने लाक-समहर्ता या न्यायिक पुलिस अधिकारी का पिछले तीन अनुच्छेदों में विहित कालावधि के अनुपादन करने से, राक दिया हाता लाक-समाहर्ता उनके आधार के सम्बन्धित प्रमाण देकर, सदिग्ध का निरुद्ध करने के लिये न्यायाधीश से निवेदन कर सकता है।

निवेदित न्यायाधीश, जैसा कि पिछले परिच्छेद में विहित है, निराध का अधिपत्र तब तक जारी नहीं करेगा जबतक कि उसे यह ज्ञान न हा जाय कि अनिवार्य परिस्थितिया के कारण उक्त विलम्ब हुआ है।

अनु० 207—पिछले तीन अनुच्छेदों में उल्लिखित निराध के लिये निवेदन प्राप्त करने वाले न्यायाधीश का वही अधिकार होगा जा कि किसी न्यायालय या पीठासीन न्यायाधीश का उसकी कार्यवाही के सबध में होता है। तथापि यह जमानती निमुक्त के सबध में लागू नहीं होगा।

पिछल परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन पाने पर न्यायाधीश तुरन्त निराध का अधिपत्र जारी करेगा। तथापि जब उस ज्ञात हो जाय कि निरोध का कोई आधार नहीं है अथवा पिछल अनुच्छेद के परिच्छेद 2 के उपबन्धों के अनुसार निरोध का अधिपत्र जारी नहीं किया जा सकता तो वह निराध का अधिपत्र बिना जारी किये ही सदिग्ध का निर्मुक्त करने के लिये अविलम्ब आदेश देगा।

अनु० 208—उस अभियोग बाद के सबन्ध में जिसमें कि सदिग्ध का पिछले अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार निरुद्ध किया गया हो, जब निरोध के निवेदन किये जाने के दस दिन के अन्दर कोई लाक-कार्रवाई सस्थित न की गई हो तो लोक-समाहर्ता सदिग्ध का अविलम्ब निर्मुक्त कर देगा।

कोई न्यायाधीश, अनिवार्य परिस्थितिया के रहने पर लाक-समाहर्ता के निवेदन पर, पिछल परिच्छेद में विहित अवधि को बढ़ा सकता है। ऐसे अवधि के बढ़ाव या बढ़ावों का योग, किसी भी रूप में, दस दिन से लम्बा (अधिक) नहीं होगा।

अनु० 209—अनुच्छेद 74, 75 और 78 के उपबन्ध, यथावित परिवर्तन के साथ बन्दीकरण के अधिपत्र के अन्तर्गत किये गए बन्दीकरण के बन्ध में लागू होंगे।

अनु० 210—जब प्राण-दण्ड, असीमित बाल के लिये या कम से कम तीन वर्ष या उससे अधिक की चरम अवधि के बढोत्थम कारावास, या कारावास द्वारा दण्डनीय अपराध के संपादन की आज्ञा का पर्याप्त आधार है और यदि, उक्त साथ ही किसी न्यायाधीश ने अनिवार्य अविलम्बिता के कारण बन्दीकरण का अधिपत्र पढ़ते न लिया जा सके, तो लाक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी, उसके हनुआ के विवरण (Statement of reasons) पर सदिग्ध का पकड़ सकते हैं। ऐसी दशाओं में, न्यायाधीश से बन्दीकरण का अधिपत्र प्राप्त करने के उपाय अविलम्ब किये जायेंगे। यदि बन्दीकरण का अधिपत्र जारी न किया गया हो तो सदिग्ध अविलम्ब निमुक्त कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 200 के उपबन्ध, यथावित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित बन्दीकरण के अधिपत्र के साथ में लागू होंगे।

अनु० 211—उक्त दशा में जब कि कोई सदिग्ध, पिछले अनुच्छेद की व्यवस्थाओं के अनुसार बन्दी किया गया हो, अनुच्छेद 199 की व्यवस्थाओं के अनुसार बन्दी किये गए सदिग्ध से संबंध व्यवस्थाएँ, यथावित परिवर्तन के साथ, लागू होंगी।

अनु० 212—यह व्यक्ति जो कोई अपराध कर रहा हो या जिसने तुरन्त किया है कुख्यात अपराधी (flagrant) कहा जाएगा।

यदि निम्नान्वित में से किसी प्रमाण के अन्तर्गत आनेवाला कोई व्यक्ति, उन परिस्थितियों के अन्तर्गत है जो स्पष्टतः यह सूचित करें कि अपराध तुरन्त ही का किया गया है तो उसे कुख्यात अपराधी (flagrant) समझा जाएगा।

- (1) वह व्यक्ति, जिसका पीछा बहुत शोर-गुल के साथ किया गया हो,
- (2) वह व्यक्ति, जो असद रूप से प्राप्त (ill-gotten) माल, हथियार या अन्य वस्तुओं को, जिसका प्रमाण प्रत्यक्षतः अपराध में हुआ हो, ले जा रहा हो,

(3) वह व्यक्ति जिसके शरीर या वस्त्रों पर अपराध के द्योतक पड़ते हुए चिह्न हों,

(4) वह व्यक्ति, जो ललकारने पर भागने का प्रयत्न करे।

अनु० 213—बाई भी व्यक्ति कुख्यात अपराधी (flagrant) को बिना अधिपत्र के ही बन्दी कर सकता है।

अनु० 214—जब लोक-समाहर्ता लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी से भिन्न किसी व्यक्ति ने कुख्यात अपराधी (flagrant) को बन्दी किया हो तो वह अपराधी को अविलम्ब किसी जिला या स्थानीय लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लोक-समाहर्ता या न्यायिक पुलिस कर्मचारी का सौंप देगा।

अनु० 215 जब किसी न्यायिक पुलिस सिपाही ने किसी कुख्यात अपराधी को मुपुदगी पाई हो तो वह उसे तत्काल न्यायिक पुलिस अधिकारी को सौंप देगा।

अपराधों को मुपुदगी पानेवाला न्यायिक पुलिस सिपाही, बन्दी करनेवाले व्यक्ति का नाम और निवास तथा बन्दी करने का कारण निश्चित करेगा। आवश्यकानुसार, वह बन्दी करनेवाले व्यक्ति को तत्संबद्ध सरकारी कार्यालय या लोक-कार्यालय तक अपने साथ ले जा सकता है।

अनु० 216—अनुच्छेद 199 के अनुसार बन्दी किए गए सदिग्ध से संबंध उपबन्ध बन्दी किए गए कुख्यात अपराधी (flagrant) के संबंध में यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

अनु० 217—पाँच सौ येन तक के अयदण्ड, निरोध या छोटे अयदण्ड द्वारा दण्डनीय कुख्यात अपराध (flagrant offence) के संबंध में अनुच्छेद 213 से 216 तक के उपबन्ध केवल उसी दशा में लागू होंगे जबकि अपराधी का नाम या निवास अज्ञात हो या अपराधी के निकल भागने की आशंका हो।

अनु० 218—लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी किसी न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए अधिपत्र पर, अपराध के अनुसंधान की आवश्यकता के अनुसार, अभिग्रहण, तलाशी एवं साक्ष्य का निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसी दशा में, शरीर की जाँच के लिए कार्यान्वित अधिपत्र पर ही शरीर की जाँच की जाएगी।

उस दशा में जबकि कोई सदस्य शारीरिक अवरोध में हो, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अधिपत्र के बिना भी उसका अंगुली-छाप (finger-prints) या पद-चिह्न लिया जा सकता है, उसकी ऊँचाई या भार मापा जा सकता है या उसके चित्र लिए जा सकते हैं, किन्तु वह (स्त्री या पुरुष) विवश (नग्न) नहीं किया जा सकता।

पहले परिच्छेद में उल्लिखित अधिपत्र, लाव-समाहर्ता, लाव-समाहर्ता कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी की माँग पर ही जारी किए जा सकेगा।

लाव-समाहर्ता, लाव-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी, शरीर की जाँच के लिए अधिपत्र का निवेदन करत समय, शरीर लिए एवं शारीरिक अवस्थाओं और अन्य विषयों की जाँच की आवश्यकता का कारण अवश्य दिखलाएगा, जो न्यायालय-नियमों द्वारा विहित है।

कोई न्यायाधीश शरीर की जाँच के लिए कुछ प्रतिबन्ध लगा सकता है जिसे वह युक्ति-युक्त समझे।

अनु० 219—पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित अधिपत्र में, सदस्य या अभियुक्त का नाम एवं अवरोध का नाम, अभिगृहीत की जानेवाली वस्तुएँ, स्थान, शरीर या वस्तुएँ जिनकी तलाशी लेनी है, स्थान और वस्तुएँ जिनका निरीक्षण करना हो, व्यक्ति जिसकी जाँच करनी हो, शरीर की जाँच में मबद्ध प्रतिबन्ध, प्रभावी (effective) अवधि, यह विवरण कि अभिगृहण, तलाशी या साक्ष्य का निरीक्षण उक्त अवधि के बीच जाने पर किसी भी तरह नहीं किया जाएगा और अधिपत्र न्यायालय को वापस कर दिया जाएगा, तथा जारी किए जाने की तिथि के साथ ही साथ न्यायालय-नियमों द्वारा विहित अन्य विषय, जो अधिपत्र जारी करने वाले न्यायाधीश का नाम एवं उसके मुद्राय रहेंगे।

अनुच्छेद 64 परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ, यथांशित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अधिपत्र के सम्बन्ध में लागू होंगी।

अनु० 220—उन दशाओं में जहाँ कि लाव-समाहर्ता, लाव-समाहर्ता कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस वरमंचारी अनुच्छेद 199 के अनुसार किसी सदस्य की बन्दी (गिरफ्तार) करता है या जहाँ वह किसी क्रूरान् अपराधी (flagrant offender) का बन्दी करता है, वहाँ वह आवश्यकतानुसार,

निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है। यही नियम, आवश्यकतानुसार, अनुच्छेद 210 के अनुसार बदो किए गए मदिग्य के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

- (1) किसी व्यक्ति के निवास या परिसर, भवन या व्यक्तिगत द्वारा नक्षित जन्मना में प्रवेश करना तथा मदिग्य का दूँटना,
- (2) बदोक्षण के स्थान का अभिग्रहण, निरोक्षण या उसका तलाशी करना।

पिछले परिच्छेद के उत्तर भाग (latter part) में उल्लिखित दशा में, यदि रन्दोक्षण का अधिपत्र न पाया जा सके तो अभिगृहीत वस्तुओं का अविरम्भ रोटा दिया जाएगा।

पहले परिच्छेद में उल्लिखित कार्रवाई के लिए अधिपत्र की आवश्यकता नहीं।

परिच्छेद 1 के प्रभाग 2 एवं पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ, यथाचित परिवर्तन के साथ उस दशा में लागू होंगी जहाँ कि लाक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी प्रस्तुति या निराध का अधिपत्र निष्पादित करे। परिच्छेद 1 के प्रभाग 1 की व्यवस्थाएँ भी यथाचित परिवर्तन के साथ उस दशा में लागू होंगी जहाँ कि मदिग्य के विरुद्ध जारी किया गया प्रस्तुति या निराध का अधिपत्र निष्पादित किया जाय।

अनु० 221—लाक-समाहर्ता लाक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी उन वस्तुओं का, जो मदिग्य या अन्य व्यक्तिगत द्वारा छीन दी गई हैं या उनका जा उनसे स्वामी, अधिकता या अभिरक्षक द्वारा स्वतः प्रप्तुन की गई है, रख सकता है।

अनु० 222 अनुच्छेद 99, 100, 102 से 105, 110 से 112, 114, 115 और 118 से 124 तक की व्यवस्थाएँ यथाचित परिवर्तन के साथ, अनुच्छेद 218, 220 और 221 के अनुसार किसी लाक-समाहर्ता, लाक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा कार्यान्वित अभिग्रहण या तलाशी के सम्बन्ध में लागू होंगी। अनुच्छेद 110, 112, 114, 118, 129, 131 और 137 से 140 तक की व्यवस्थाएँ यथाचित परिवर्तन के साथ, अनुच्छेद 218 या 220 की व्यवस्थाओं के अनुसार किसी लाक-समाहर्ता, लाक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा कार्या-

न्यून साक्ष्य के निरीक्षण के सम्बन्ध में लागू होगी। तथापि, बार्ड न्यायिक सिपाही (Judicial constable), अनुच्छेद 122 से 124 तक के अनुच्छेदों में विहित कार्रवाई कार्यान्वित नहीं कर सकता।

अनुच्छेद 220 की व्यवस्थाओं के अनुसार सदिग्ध की तलाशी की दशा में, अनुच्छेद 114 परिच्छेद 2 की व्यवस्थाओं का अनुपालन अविविधता की स्थिति में, आवश्यक नहीं।

अनुच्छेद 116 और 117 की व्यवस्थाएँ पर्याप्त परिवर्तन के साथ, लोक-समाहर्ता लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस बर्मचारी द्वारा अनुच्छेद 218 की व्यवस्थाओं के अनुसार कार्यान्वित अभिग्रहण या तलाशी के सम्बन्ध में लागू होगी।

कोई लोक-समाहर्ता लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस बर्मचारी सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद, अनुच्छेद 218 की व्यवस्थाओं के अनुसार निरीक्षण द्वारा साक्ष्य लेने के अभिप्राय में किसी व्यक्ति के निवास, परिसर भवन या व्यक्तियों द्वारा रक्षित जलपान में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि अधिनियम में यह विवरण न हो कि इस रात्रि में भी कार्यान्वित किया जा सकता है। तथापि, यह अनुच्छेद 117 में उल्लिखित स्थला के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा।

उस दशा में जब कि निरीक्षण द्वारा साक्ष्य लेना सूर्यास्त के पश्चात् शुरू हो गया हो तो कार्रवाई सूर्यास्त के बाद भी जारी रखी जा सकती है।

उस दशा में जब कि कोई लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस बर्मचारी, अनुच्छेद 218 की व्यवस्थाओं के अनुसार अभिग्रहण, तलाशी या साक्ष्य का निरीक्षण करे, आवश्यकतानुसार सदिग्ध का उपस्थित कराया जा सकता है।

उस दशा में जब कि कोई व्यक्ति गरीब की जाँच कराना अस्वीकार करे, उस पर अदालत अथवा न्यायाधीश (non-penal fine) लगाया जायगा अथवा उसे, पहले परिच्छेद की व्यवस्थाओं के अनुसार उसके अस्वीकरण से जाने वाले परिणामों के प्रतिफल के लिए आदेश दिया जायगा, ऐसी कार्रवाइयों के लिए निवेदन न्यायालय में किया जायगा।

अनु० 223—लोकसमाहर्ता, लोकसमाहर्ता-कार्यालय के सचिव, एवं न्यायिक पुलिस बर्मचारी सदिग्ध के अनिश्चित अन्य किसी व्यक्ति को अपने कार्यालयों

में उपसजात होने के लिए जादय दे सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं या उसे, यदि आपगधिक अनुसंधान में आवश्यक है, एक विशेषज्ञ (expert) के रूप में अपनी सम्मति देने या अर्थनिर्वाचक (Interpreter) या भाषान्तरकार (translator) के रूप में कार्य करने का निवेदन कर सकते हैं।

अनुच्छेद 198 परिच्छेद 1 एवं उसी के तौमरे से पाँचवें परिच्छेद तक के उपबन्ध, यथाविन्न परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद द्वारा विहित दशा में लागू होंगे।

अनु० 224—उन दशाओं में जहाँ कि पिछले अनुच्छेद परिच्छेद 1 के अनुसार किसी विशेषज्ञ साक्ष्य के लिये निवेदन किया गया हो और अनुच्छेद 167 परिच्छेद 1 द्वारा विहित उपाय आवश्यक हो ता लाकममार्तर्ता, लाय-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी, उल्लिखित उपायों के लिये न्यायाधीश से निवेदन करेगा।

यदि वह पिछले परिच्छेदों में उल्लिखित निवेदन की तरफसमन समझे ता न्यायाधीश उन्हीं उपायों का कार्यान्वित करेगा जा अनुच्छेद 167 की दशा में हान है।

अनु० 225—वह व्यक्ति, जिससे अनुच्छेद 223 परिच्छेद 1 के अनुसार विशेषज्ञ सम्मति देने के लिये निवेदन किया गया है, न्यायाधीश की अनुमति से, अनुच्छेद 168 परिच्छेद 1 द्वारा विहित उपायों का कार्यान्वित कर सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अनुमति, लाय-समाहर्ता, लाक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी द्वारा माँगी जायगी।

जब न्यायाधीश पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अनुमति की माँग को तर्कसमन समझे ता वह इसे, एक अनुमति का अधिपत्र जारी करके, प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 168 के परिच्छेद 2 में 4 एवं 6 की व्यवस्थाएँ, यथावित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अनुमति के अधिपत्र के सबन्ध में लागू होंगी।

अनु० 226—जब कोई व्यक्ति, जो अपराध के अनुसंधान के लिये आवश्यक जानकारी प्रत्यक्ष रखता हो किन्तु उपसजात होने या अनुच्छेद 223 के परिच्छेद 1 के अनुसार परीक्षा में उक्त जानकारी को स्वतः प्रकट करना

अस्वीकार करे ता लाक-समाहर्ता किसी न्यायाधीश से बाद के लोब विचारण के लिये निश्चित पहली तिथि के पहले ही एर साक्षी के रूप में उससे पूछ-ताछ करने का निवेदन कर सकता है ।

अनु० 227—जब यह विश्वास करने के कारण हो कि उस व्यक्ति पर, जिसने लाक-समाहर्ता, लाक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कमिश्नरी द्वारा अनुच्छेद 223 परिच्छेद 1 के अनुसार परीक्षा (examination) के अवसर पर स्वच्छता भूषणा दी, लाक-विचारण के अवसर पर प्रमाण (testimony) में उक्त वक्तव्य (statement) वापस लेने या बदलने के लिये दवाव डाला जा सकता है और जब उक्त प्रमाण अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिये आवश्यक भासित होता लाक-समाहर्ता बाद के लाक-विचारण के लिये निश्चित पहली तिथि के पहले ही किसी न्यायाधीश को एक साक्षी के रूप में उस व्यक्ति से पूछताछ करने का निवेदन कर सकता है ।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन करते समय लाक-समाहर्ता को उक्त पूछताछ (interrogation) की आवश्यकता के कारणों का प्रवर्तित प्रमाण और अभियुक्त के अपराध का सिद्ध करने के लिये उसकी नितान्त आवश्यकता का प्रमाण देना होगा ।

अनु० 228 पिछले दो अनुच्छेदों द्वारा विहित निवेदन जिस न्यायाधीश के यहाँ किया जायगा उसे वही प्राधिकार होगा जा किसी न्यायालय या पीठसभ न्यायाधीश को साक्षियों की परीक्षा (examination) के सम्बन्ध में होता है ।

न्यायाधीश यदि समझे कि यह अपराधिव अनुसंधान के अनुगमन में बाधक नहीं होगा ता वह अभियुक्त, सदिग्ध या उमके प्रतिवाद-नरामशंकाता का, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित परीक्षा के अवसर पर, उपस्थित होने का प्रेरित कर सकता है ।

अनु० 229—अप्राकृतिक मृत्यु (unnatural death) से मरे हुए या जिसके विषय में अप्राकृतिक मृत्यु से मरने का संदेह हो उम व्यक्ति की शरीर (शव) मिलने पर जिग या स्थानीय लाक-समाहर्ता-कार्यालय का लाक-समाहर्ता, जिगके अधिार-क्षेत्र में वह स्थान हो जहाँ शव पाया गया हो, अन्वीक्षण (inquest, शव की जाँच) करेगा ।

लोन-ममाहर्ता, लोन-ममाहर्ता-वर्षाण्डय के सविब या न्यायिक पुलिस अधिकारी से पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कार्रवाई करा सकता है ।

अनु० 230— किसी अपराध के परिणामस्वरूप अपहृत (क्षत injured) व्यक्ति परिवार कर सकता है ।

अनु० 231—अपहृत पक्ष (injured party) का वैध प्रतिनिधि अपना स्वतंत्र परिवार कर सकता है ।

अपहृत-पक्ष की मृत्यु पर उमरा पति या पत्नी उमरे वसीय सम्पत्तियों में से कोई अथवा भाई या बहन परिवार कर सकते हैं किन्तु अपहृत पक्ष के साध आशय (intention) के विरुद्ध नहीं ।

अनु० 232—जहाँ अपहृत-पक्ष का वैध प्रतिनिधि मदिग्र, मदिग्र का पति या उमरी पत्नी, (apouse), मरघ की तीसरी कोटि के अंदर का रत्न-समयी या मदिग्र का तीसरी कोटि के अंदर आने वाला बन्धुना का मवधी हो तो अपहृत-पक्ष का मवधी स्वतंत्र परिवार कर सकता है ।

अनु० 233—किसी मृत-व्यक्ति की मानहानि के अपराध के सबध में उमर सम्पत्ती या वसत परिवार कर सकते हैं ।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाओं वहाँ भी निवर्तन करेंगी जहाँ मानहानि के अपराध के सम्बन्ध में अपहृत-पक्ष जिना परिवार किये ही मर गया हो । तथापि, अपहृत-पक्ष के अभिव्यक्त आशय के विरुद्ध कोई परिवार नहीं किया जायगा ।

अनु० 234 —यदि परिवार पर अभियोजनीय किसी अपराध के सम्बन्ध में परिवार करने वाला कोई व्यक्ति न हो तो किसी बद्धहित (interested) व्यक्ति के प्रार्थनापर, लोन-ममाहर्ता किसी व्यक्ति की नामोदित कर सकता है आ परिवार कर सके ।

अनु० 235—परिवार पर अभियोजनीय किसी अपराध के सबध में, अपराधों की जानकारी होने की क्रिय से छ मस वीत जाने के बाद कोई परिवार नहीं किया जायगा । तथापि यह दण्ड संहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 232 परिच्छेद 2 के अनुसार किसी विदेशी शक्ति (foreign power) के प्रतिनिधि द्वारा किये जाने वाले परिवार या दण्ड-संहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 230 या 231 में उल्लिखित जापान का भेजे गए किसी विदेशी मिशन (Foreign mission) के विरुद्ध अपराध के सम्बन्ध में उक्त मिशन द्वारा किये जाने वाले परिवार के सबध में लागू नहीं होगा ।

दण्ड-महतिता (Penal Code) के अनुच्छेद 229 का व्यवस्था (Proviso) में अवधिनि बाध का परिवाद नव तब मान्य (valid) नही होगा जब तक कि विवाद का प्रभावहान या गृह धापित करने यात्र नियम के अट्ट (irrevocable) हान का निधि स छ माम के अन्दर न किया जाय ।

अनु० 236—जहाँ परिवाद करने के दो या अधिक अधिकारों व्यक्ति हो वहा उनमें से एक द्वारा परिवाद की अवधि के अनुपातन का प्रममयना दूसरा के प्रति प्रवर्तित नही होगी ।

अनु० 237—लाक-कायवाहा के सम्बन्धन किये जाने के पत्र किमा भी समय परिवाद वापस लिया जा सकता है ।

अपन परिवाद वापस उन बाट व्यक्ति का अन्य परिवाद करने में बाधित किया जायगा ।

निष्ठ दा परिच्छेदा का व्यवस्था, यथाचित परिवर्तन के माध मांग (demand) पर लिये जाने बाट अभियाग में का गद मांग के मन्द में गगू हागा ।

अनु० 238—परिवाद (Complaint) पर अभियाजनाय अलगध में एक या उसम अधिक सह-अपरगधिया (Co-offenders) के विरुद्ध किया गया परिवाद या उसका प्रवाहण (withdrawal) दूसरे सह-अपरगधिया के सम्बन्ध में भा बाधक हागा ।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था, यथाचित परिवर्तन के माध मांग (demand) या अभियाजन (accusation) पर लिये जाने बाट अभियाग के मन्द में किये गये अभियाजन या मांग या उसका प्रवाहण (withdrawal) के सम्बन्ध में गगू हागी ।

अनु० 239—काट व्यक्ति जिम यह विश्वास है कि पार्टी अलगध किया गया है अभियाजन कर सकता है ।

अब काट सरकार या गक-समचारों अपने कार्यों के सम्पादन में यह विश्वास कर कि पार्टी अलगध किया गया है ना उन अभियाजन अवश्य करना हागा ।

अनु० 240—परिवाद प्रतिपत्रा (proxy) द्वारा किया जा सकता है । यहाँ नियम परिवाद के प्रवाहण (withdrawal) के सम्बन्ध में ना गगू हागा ।

अनु० 241—परिवाद या अभियाजन लिखित या मौखिक रूप में किसी गक-समाहता या न्यायिक पुष्टि अधिकारी के यहाँ किया जायगा ।

किसी मौखिक परिवाद या अभियोजन के ले लेने पर लाक-समाहर्ता या न्यायिक पुलिस अधिकारी एक नयाचार (Protocol) तैयार करेगा।

अनु० 242—किसी परिवाद या अभियोजन के ले लेने पर न्यायिक पुलिस अधिकारी प्रलेख (documents) एवं उससे संबद्ध साक्ष्य का अन लाक-समाहर्ता का तुरन्त अग्रपिन (forward) करेगा।

अनु० 243—पिछले दो अनुच्छेदों की व्यवस्थाएँ यथाचित परिवर्तन के साथ, परिवाद या अभियोजन के प्रत्याहरण (withdrawal) के सम्बन्ध में भी लागू होंगी।

अनु० 244 दण्ड-संहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 232 परिच्छेद 2 की व्यवस्थाओं के अनुसार किसी विदेशी शक्ति (foreign power) के प्रतिनिधि द्वारा किया जाने वाला परिवाद या उसका प्रत्याहरण (withdrawal) इस विधि (law) के अनुच्छेद 241 तथा पिछले अनुच्छेदों की व्यवस्थाओं के विचार विषे बिना परगण्ट मंत्री के यहाँ किया जा सकता है। यही नियम दण्ड-संहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 230 या 231 में उल्लिखित जापान का भेजे गए किसी विदेशी मिशन (mission) के विरुद्ध अपराध के लिये उन मिशन द्वारा किये जाने वाले परिवाद या उसके प्रत्याहरण (withdrawal) के सम्बन्ध में लागू-होगा।

अनु० 245—अनुच्छेद 241 एवं 242 की व्यवस्थाएँ, यथाचित परिवर्तन के साथ, आत्म प्रत्यान्याय (self-denunciation) के सम्बन्ध में लागू होंगी।

अनु० 246—इस विधि में अन्यथा विहित दशा का छोड़कर, जब किसी न्यायिक पुलिस अधिकारी ने किसी अपराध का अनुसन्धान किया हो तो वह उस अभियोग को, प्रलेख एवं साक्ष्य के अन्तर्गत के साथ लाक-समाहर्ता के यहाँ भेज देगा। तथापि, यह उस अभियोग के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा जो लाक-समाहर्ता द्वारा विशेष रूप से नामोद्दिष्ट किया गया हो।

अध्याय 2

लोक-कार्यवाही

(Public Action)

अनु० 247—लोक-कार्यवाही लोकसमाहर्ता द्वारा सक्षिप्त की जायगी।

अनु० 248—यदि अपराधी के चरित्र, आयु एवं स्थिति, अपराध की

गुन्ता परिस्थिति जिनमें अपराध किया गया है, और अपराध-सम्पादन के बाद की दशाओं पर विचार करने के बाद, अभियोजन (Prosecution) अनावश्यक समझा जाय ता रास-कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

अनु० 249—रास-समाप्ति द्वारा नामादृष्ट, अभियुक्त से भिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध रास-कार्यवाही कार्यरत नहीं होगी।

अनु० 250—भाषाविवार (Prescription) निम्नलिखित अवस्था के तीन ताने पर पूरा होगा

- (1) प्राण-दण्ड पाने योग्य अपराध के लिये, पन्द्रह वर्ष,
- (2) अनिश्चित अवधि काट कठोरश्रम-कारावास या सामान्य कारावास दण्ड पाने योग्य अपराधों के लिये, दस वर्ष
- (3) कम से कम दस वर्ष की कम अवधि (maximum term) के कठोरश्रम-कारावास या सामान्य कारावास दण्ड पाने योग्य अपराधों के लिये सात वर्ष
- (4) अधिक से अधिक दस वर्ष की शरम अवधि के कठोरश्रम-कारावास या सामान्य कारावास दण्ड पाने योग्य अपराधों के लिये, पाँच वर्ष,
- (5) पाँच वर्ष से कम की शरम अवधि के कठोरश्रम-कारावास या सामान्य कारावास के दण्ड या अर्धदण्ड पाने योग्य अपराधों के लिये, तीन वर्ष,
- (6) निरोध या छोटे अर्धदण्ड पाने योग्य अपराधों के लिए, एक वर्ष।

अनु० 251—जहाँ तक दो या अधिक प्रधान दण्डों (principal penalties) में से एक अथवा दो या अधिक प्रधान दण्डों के एक साथ आरोपण (Concurrent imposition) द्वारा दण्डनीय अपराधों का सन्ध है, पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ (उनमें से) गुन्तम दण्ड (heaviest penalty) के सम्बन्ध में लागू होंगी।

अनु० 252—जहाँ दण्ड मन्त्रिणा (Penal Code) के अनुसार दण्ड मन्त्रिणा या कम करना है ता अनुच्छेद 250 की व्यवस्थाएँ, इस तरह न बढ़ाए गए या कम न किए गए दण्ड के सम्बन्ध में ही लागू होंगी।

अनु० 253—भाषाविवार (prescription) उक्त समय से आरम्भ हो जायगा जसके अपराधिक कृत्य समाप्त हुए हैं।

दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप में (cojointly) किए गए अपराध के सम्बन्ध में भोगाधिकार की अवधि सभी सह-अपराधियों (co-offenders) के लिए उसी समय से आरम्भ हो जायगी जबकि अंतिम कृत्य (final act) समाप्त हुआ।

अनु० 254—अभियोग के विरुद्ध लोक-कार्यवाही के सन्धित हो जाने पर भोगाधिकार रद्द जाएगा और उस समय आरम्भ हो जावेगा जब क्षेत्राधिकारिक अक्षमता (jurisdictional incompetency) अधिसूचित करने वाला या लोक-कार्यवाही को खारिज (रद्द) करने वाला कोई निणय अंतिम रूप में बन्धनकारी (finally binding) हो गया हो। तथापि, यह उन अभियोगों में नहीं लागू होगा जिनमें लोक-कार्यवाही की संस्थिति (institution of public action), अनुच्छेद 271 के परिच्छेद 2 के अनुसार अपनी मान्यता (validity) ला चकी हो।

सह-अपराधियों (co offenders) में से एक के विरुद्ध सन्धित लोक-कार्यवाही द्वारा किया गया भोगाधिकार रद्द विराम (cessation) अन्य सह-अपराधियों के विरुद्ध भी प्रभावी होगा तथा रद्द हुआ भोगाधिकार अभियोग के निर्णय के अन्ततः बन्धनकारी (finally binding) हो जाने पर फिर पुनः हो जायगा।

अनु० 255—उस अवधि में भोगाधिकार चालू नहीं रहेगा जिसमें कि अपराधी जापान के बाहर रहे या वह अपने को इस तरह छिपा ले कि उस अभ्यारोपण (indictment) की एक प्रति तामील करना असंभव हो जाय।

जापान से अपराधी की अनुपस्थिति या उसका छिप जाना, जिससे कि उसे अभ्यारोपण (indictment) की प्रति तामील करना असंभव हो गया हो, सिद्ध करने के लिए आवश्यक विषय न्यायालय के नियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

अनु० 256—लोक-कार्यवाही की संस्थिति न्यायालय को एक लिखित अभ्यारोपण (written indictment) फाइल करने के द्वारा की जायगी।

लिखित अभ्यारोपण में निम्नलिखित विषय रहेंगे —

- (1) अभियुक्त (accused) का नाम तथा अन्य विषय, जो अभियुक्त को निर्दिष्ट करने में आवश्यक हो,
- (2) आरोपित अपराध के घटक तथ्य,
- (3) आरोप,

आरापित अपराध के घटक तथ्यों का स्पष्ट विवरण निर्दिष्ट गणका (counts) के रूप में दिया जाएगा जिसमें अपराध के समय, घटना-स्थल तथा उसके टग का जानकारी के अनुसार, अवश्य वर्णन किया जाएगा।

आरापा का वर्णन उन विधियाँ एवं अध्यादेशों के लागू होने वाले अनुच्छेदों की गणना द्वारा किया जाएगा जिनका अभियुक्त ने उल्लंघन किया है। तथापि उक्त अनुच्छेदों की गणना सबकी गलतियाँ (errors), लाक-कार्यवाही की सम्मति की मान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगी, यदि उनके द्वारा अभियुक्त के प्रतिपाद में कोई सारवाणु प्रतिरूल प्रभाव उत्पन्न करने की आशा न हो।

अनेक गणका (counts) और लागू होने वाले अनुच्छेद वैकल्पिक (alternative) या यौगिक (conjunctive) रूप में उल्लिखित किए जा सकते हैं।

काई भी साक्ष्य-विषयक लक्ष या अन्य वस्तु का न्यायाधीश का पूर्वनिर्णय (Prejudication) करने में साधन हो सके, लिखित अभ्यारापण में न ता अनुबद्ध की जायगी और न निर्दिष्ट की जायगी।

अनु० 257—लाक-कार्यवाही प्राथमिक न्यायालय (first instance) से निणय दिए जाने से पहले वापस ली जा सकती है।

अनु० 258—यदि लाक-समाहर्ता यह समझे कि प्रस्तुत अभियोग उसके निजी लाक-समाहर्ता-कार्यालय से सबद्ध न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आता तो वह उक्त अभियोग को प्रलेपों एवं साक्ष्य के अंश के सहित, क्षमता-शील न्यायालय से सबद्ध किसी लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लाक-समाहर्ता के पास भेज देगा।

अनु० 259—जब किसी लोक-समाहर्ता ने लोक-कार्यवाही न सम्स्थित करने के लिए कोई कार्रवाई किया हो तो वह सदिय के निवेदन करने पर उसे उक्त तथ्य की सूचना अविलम्ब देगा।

अनु० 260—यदि किसी अभियोग के सप्रथ में जिसमें परिवाद (complaint), अभियोजन (accusation) या माँग (demand) की गई हो, लाक-कार्यवाही सम्स्थित की गई हो अथवा इसके सम्स्थित न किए जाने की कार्रवाई की गई हो तो उक्त तथ्य की सूचना लाक-समाहर्ता द्वारा परिवादो (complainant) अभियाक्ता (accuser) या माँग करने वाले व्यक्ति को तत्काल दी जाएगी। यही नियम उस दशा में भी लागू होगा जहाँ लोक-

कारवाई वापस ले ली गई है अथवा अभियोग दूसरे लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लोक-समाहर्ता के यहाँ भेज दिया गया हो।

अनु० 261—यदि किसी अभियोग में सम्बन्ध में जिसमें परिवार अभियोजन या माँग की गई हो लोक-कायवाही सम्बन्धित न करने का कारवाई की गई है तो परिवारों अभियोजन या माँग करने वाले व्यक्ति के निवेदन पर लोक-समाहर्ता उन्हें उनके कारवाई के कारण की सूचना तुरन्त देगा।

अनु० 262 यदि किसी अभियोग में जिसके सम्बन्ध में दण्डसंहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 193 से 196 तक में अनुच्छेद में उल्लिखित अपराधों में से कोई अभियोजन या परिवार दिया गया हो और परिवारों या अभियोजन लोक-समाहर्ता द्वारा लोक-कायवाही सम्बन्धित न करने का कारवाई में अमन्य हो तो वह अभियोग को किसी न्यायालय में विचारणाय (for trial) सौंपने के लिए उस जिला-न्यायालय में प्राथनापत्र भर सकता है जिसके क्षमता में उनके लोक-समाहर्ता-कार्यालय जाना हो। जिसमें सेबद्ध वह लोक-समाहर्ता हो।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित प्राथनापत्र लोक-कायवाही सम्बन्धित न करने के लिए कारवाई करने वाले लोक-समाहर्ता के यहाँ उल्लिखित प्राथनापत्र के रूप में अनुच्छेद 260 में उल्लिखित सूचना के प्राप्त करने के सात दिनों के अन्दर दिया जाएगा।

अनु० 263 पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 में उल्लिखित प्राथनापत्र अनुच्छेद 262 की व्यवस्था (ruling) कार्यान्वित की जान के पक्ष वापस लिया जा सकता है।

पिछले परिच्छेद में विहित वापसी (recall) करने वाला व्यक्ति उसी अभियोग के सम्बन्ध में पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 में उल्लिखित प्राथनापत्र को फिर से नहीं दे सकता।

अनु० 264—अनुच्छेद 262 के परिच्छेद 1 में उल्लिखित प्राथनापत्र का यदि साधारण समझ तो लोक-समाहर्ता लोक-कायवाही सम्बन्धित करेगा।

अनु० 265—अनुच्छेद 262 के परिच्छेद 1 में उल्लिखित प्राथनापत्र पर किसी सहयोगी न्यायालय द्वारा विचारण एवं निष्पत्ति किया जायगा।

न्यायालय यदि आवश्यक समझ तो सहयोगी न्यायालय के किसी सदस्य को तथ्य के अनुसन्धान के लिए प्रेषित कर सकता है या जिला-न्यायालय या

क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश का ऐसा करने के लिए अधिवाचित कर सकता है। ऐसी दशा में राजादिष्ट (commissioned) न्यायाधीश या अधिवाचित (requisitioned) न्यायाधीश का वही प्राधिकार होगा जो किसी न्यायालय के न्यायाधीश या पीठासीन (presiding) न्यायाधीश का होता है।

अनु० 266—अनुच्छेद 262 परिच्छेद 1 में उल्लिखित प्रार्थनापत्र पाने, पर, न्यायालय निम्नांकित वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्था (ruling) जारी करेगा

(1) विधि अथवा अध्यादेश द्वारा निश्चित किये गए प्रपत्र (form) या रूप से प्रतिकूल रूप में दिया गया, या प्रार्थनापत्र देने के अधिकार के समाप्त हो जाने के बाद दिया गया, या आधारहीन प्रार्थनापत्र स्वीकृत कर दिया जायगा,

(2) यदि प्रार्थनापत्र सुदृढ़ (well-founded) हो तो अभियोग क्षमता-शील जिला-न्यायालय में विचारण के लिये सुपुर्द कर दिया जायगा।

अनु० 267—जब पिछले अनुच्छेद के प्रभाग 2 में उल्लिखित व्यवस्था (ruling) जारी की जा चुकी हो तो अभियोग पर लोक-न्यायवाही मस्तिष्क समझी जायगी।

अनु० 268—जब कोई अभियोग अनुच्छेद 266 प्रभाग 2 की व्यवस्थाओं के अनुसार किसी न्यायालय में सुपुर्द किया गया हो तो वह (न्यायालय) अधिवक्ताओं (advocates) में से किसी एक या नामोद्दिष्ट करेगा जो लोक-न्यायवाही का समर्थन (sustain) करेगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित नामोद्दिष्ट अधिवक्ता, उस अभियोग के निर्णय के अन्तिम रूप में बाध्यकारी (finally binding) होने तक लोक-न्यायवाही के समर्थन के लिये, लोक-समाहर्ता के कार्य करेगा। तथापि, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अधिवक्ता किसी लोक-समाहर्ता को, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिवों या न्यायिक पुलिस कर्मचारियों को आपराधिक अनुसंधान के लिये निर्देशित करने की आज्ञा देगा।

पिछले परिच्छेद के अनुसार लोक-समाहर्ता के कार्य करने वाले अधिवक्ता की विधियाँ एवं अध्यादेशों के अनुसार लोक-सेवा (public service) में लगे हुए कर्मचारियों के रूप में समझा जायगा।

न्यायालय, पहले परिच्छेद के अनुसार नामोद्दिष्ट अधिवक्ता के नामोद्देश (designation) को किसी समय निरस्त कर सकता है यदि वह (न्यायालय) समझे कि वह अपने कार्य करने में योग्य नहीं है अथवा कोई दूसरी विशेष परिस्थितियाँ हों।

पहले परिच्छेद के अनुसार नामोद्दिष्ट अधिवक्ता की मन्त्रि-परिषद् के आदेशों द्वारा निश्चय मत्ते दिये जायेंगे।

अनु० 269—अब कोई न्यायालय, अनुच्छेद 262 के परिच्छेद 1 में उल्लिखित प्रायोजनापत्र का खारिज कर या प्रायोजनापत्र वापस ले लिया जाय तो न्यायालय, एक व्यवस्था (ruling) के आधार पर प्रायोजनापत्र देने वाले व्यक्ति को प्रायोजनापत्र सबूतों कार्यवाही से हटाने वाले परिणाम के पूरे अथवा किसी अंश के प्रतिनिर (compensation) देने का आदेश दे सकता है। उक्त व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आपत्त (immediate) कोकोकु अर्पित की जा सकती है।

अनु० 270—लोक-कार्यवाही के सन्स्थित किये जाने के बाद, लोक-समाहर्ता उस अभियोग से सबद्ध साक्ष्य के अलावा एक प्रलेखा का निरीक्षण एक उनकी प्रतिलिपि कर सकता है।

अध्याय 3

लोक-विचारण (Public Trial)

अनुभाग 1 लोक-विचारण की तैयारी तथा उसकी प्रक्रिया।
(Preparation for Public Trial and Process of Public Trial)

अनु० 271—लोक-कार्यवाही सन्स्थित की जाने पर, न्यायालय अभियुक्त को अन्वयारोपण (indictment) की एक प्रति अविलम्ब सामील करेगा।

यदि लोक-कार्यवाही सन्स्थित की जाने के दो मास के अन्दर अन्वयारोपण की प्रतिलिपि अभियुक्त को सामील न की जा सके तो लोक-कार्यवाही की सन्स्थिति की मान्यता निष्क्रियता (retroactively) समाप्त हो जायगी।

अनु० 272—लोक-कार्यवाही के सन्स्थित हो जाने पर न्यायालय अभियुक्त को अधिसूचित करेगा कि वह (अपने स्वयं से) अपना प्रतिवाद-परामर्शदाता चुन सकता है, अथवा यदि वह निर्धनता या अन्य कारणों से प्रतिवाद-परामर्श-

दाता न चुन सके ता वह अपने लिये परामर्शदाता नियुक्त करने के लिये न्यायालय में निवेदन कर सकता है। तथापि, यह तब लागू नहीं होगा यदि अभियुक्त के पाम पहले से ही प्रतिवाद-परामर्शदाता हो।

अनु० 273—पीठासीन न्यायाधीश लोक-विचारण (public trial) की तिथि निश्चित करेगा।

लोक-विचारण की तिथि पर अभियुक्त को समन किया जायगा।

डाकूमहर्ता प्रतिवाद-परामर्शदाता एवं सहायक (assistant) का लोक-विचारण की तिथि की सूचना दी जायगी।

अनु० 274—यदि अभियुक्त का न्यायालय के उपान्त (precincts) में मिलने पर न्यायालय द्वारा लोक-विचारण की निश्चित तिथि की सूचना दी जाय ता उसे समन का प्रादेश (writ of summons) तामील किया गया समझा जायगा।

अनु० 275—लोक-विचारण के लिये निश्चित पहली तिथि तथा अभियुक्त का समन का प्रादेश की तामिली में न्यायालय-नियमों द्वारा विहित समुचित अवकाश (reasonable interval) रहेगा।

अनु० 276—न्यायालय पदेन अथवा लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर, लोक-विचारण के लिये नियत तिथि का बदल सकता है।

जैसा कि न्यायालय-नियमों द्वारा विहित हों, न्यायालय लोक-विचारण की नियत तिथि के बदलने के पहले ही लोकसमाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की राय सुनेगा। तथापि, अविलम्बिता (urgency) की स्थिति में यह लागू नहीं होगा।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था (proviso) द्वारा विहित दस्ताजों में न्यायालय लोकसमाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता को नई तिथि (new date) पर लोक-विचारण के आरम्भ (commencement) के समय मापित करने का अवसर देगा।

अनु० 277—यदि किसी न्यायालय ने अपने प्राधिकार (authority) के दुरुपयोग के फलस्वरूप लोक-विचारण की तिथि बदल दिया हो तो उस अभियोग से संबंध व्यक्ति, उच्चतम न्यायालय के नियमों (rules) अथवा

अनुच्छेद (instructions) के अनुसार अन्तर्गत प्रशासनिक निषेधण काय बाहिया (judicial administrative control proceedings) में उपचार का निबन्धन कर सकते हैं।

अनु० 278 यदि लोक विचारण के लिए समन किया गया कोई व्यक्ति बीमारी या अन्य कारणों से नियत तिथि पर उपसजान न हो सके तो वह 'यायाग्य नियमा' के अनुसार चिकित्सा प्रमाणपत्र (medical certificate) या अन्य साक्ष्य-सामग्री (evidential materials) का 'यायालय' में प्रस्तुत करेगा।

अनु० 279—लाक-गमाहर्ता अभियुक्त या उसके प्रतिवाक्य-परामर्शदाता के निषेधण पर या अपने कोई 'यायाग्य' अन्य 'गार-बायवाणी' या सत्यापन का बाह्य व साक्ष्य-सामग्री या व्यक्तिगत हो 'गार विचारण' के लिए आवश्यक विषयों का विवरण देने के लिए आदेश दे सकता है।

अनु० 280 'गार-बायवाणी' के सत्यता हान के बावजूद और लोक विचारण की प्रक्रिया निर्धार के पक्ष की निरास करने की कारवाइया का बायभार 'यायाधीन' द्वारा दिया जायगा।

अनु० 204 या 205 द्वारा विहित कारवाइया की समाप्ति के पूर्व ही अनुच्छेद 199 या 210 की व्यवस्थाओं के अनुसार बंदी नियमों के बिना मर्ग्य या कुर्यान अरराया (flaunt offender) के विरुद्ध लोक रायवाणी सत्यता की जा चेका हो और जिस निरोध के अधिपत्र द्वारा निरासित किया गया हो 'यायाग्य' अभियुक्त का उस पर आरोपित अपराधों का सूचना अधिपत्र दंगा और उस पर उसका विवरण (statement) मुनगा और यदि 'यायाग्य' निरोध का अधिपत्र जारी न कर तो उस तुरन्त विमर्क करने का आदेश अवश्य दंगा।

चिठ 20 परिच्छेदों में उक्तिवित्त 'यायाधीन' का वही अधिकार होगा जो किसी 'यायाग्य' या पीनसोम 'यायाधीन' (presiding judge) को कारवाइया के समर्थन में हाना है।

अनु० 281—अनुच्छेद 158 द्वारा विहित किसी उपबन्ध (condition) पर विचार करने और लाक-गमाहर्ता अभियुक्त या उसके प्रतिवाक्य-परामर्शदाता की राय मुनन के बावजूद 'यायाग्य' यदि आवश्यक समझ तो लोक विचारण के लिए निषेधण तिथि से बिना किसी निषेधण पर साक्ष्यों की परीक्षा कर सकता है।

अनु० 282 सुनवाई (hearing) किसी न्यायालय-वृक्ष में लोक-विचारण की तिथि पर की जाएगी।

न्यायालय न्यायाधीश (या न्यायाधीशों) और न्यायालय लिपिकों की सम्मेलित (assembled) उपस्थिति तथा लोचसमाहर्ता की उपस्थिति में सोला जाएगा।

अनु० 283 यदि अभियुक्त कोई न्यायिक व्यक्ति (judicial person) हो तो वह सदैव प्रतिपक्षी (proxa) द्वारा उपमज्जात हो सकता है।

अनु० 284—यदि अम्मारोपित अपराध (offence charged) का दण्ड पाँच हजार येन से अधिक न हो या कोई छोटा अवदण्ड हो तो अभियुक्त को उपमज्जात नहीं होना पड़ेगा। तथापि वह प्रतिपक्षी (proxa) द्वारा उपमज्जात हो सकता है।

अनु० 285—यदि अम्मारोपित अपराध का दण्ड निराश्रित (detention) हो तो लोक-विचारण की तिथि पर निर्णय दिए जाने समय अभियुक्त को अवश्य उपस्थित रहना पड़ेगा। लोक-विचारण की अन्य किसी भी अवस्था में, जब कि न्यायालय यह समझे कि उसकी उपस्थिति उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, उसे अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दे सकता है।

जहाँ अम्मारोपित अपराध (offence charged) का दण्ड अधिक से अधिक तीन वर्षों की चरम अवधि का कठोरश्रम-वारावास या सामान्य वारावास हो अथवा पाँच हजार येन से अधिक का अवदण्ड हो, वहाँ अभियुक्त का लोक-विचारण की तिथि पर अनुच्छेद 291 में वर्णित कार्यवाहियों के अवसर पर तथा निर्णय दिए जाने के समय अवश्य उपस्थित रहना होगा। लोक-विचारण की अन्य अवस्था में, पिछले परिच्छेद का अन्तिम भाग (last part) लागू होगा।

अनु० 286—पिछले तीन अनुच्छेदों द्वारा अन्यथा विहित दशाओं के अतिरिक्त, अभियुक्त के उपस्थित न रहने पर लोक-विचारण नहीं किया जाएगा।

अनु० 287 लोक-विचारण के न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को तब तक किसी तरह के शारीरिक अवरोध में नहीं रखा जाएगा जब तक कि वह कोई हिसक प्रयोग या निन्दित भावने का प्रयत्न नहीं करता।

तथापि, शारीरिक अवरोध (physical restraint) में न ररे जाने की स्थिति में भी अभियुक्त पर जागधी (guards) रगे जा सकते हैं।

अनु० 288—पीठासीन न्यायाधीश को अनुज्ञा के अतिरिक्त अभियुक्त न्यायालय से नहीं हट सरेगा ।

पीठासीन न्यायाधीश अभियुक्त का न्यायालय में ठहरने एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए (to maintain an order) उचित उपाय कर सकता है ।

अनु० 289 यदि अम्बाराणिज अलग्ग का दण्ड प्राण-दण्ड अनिवारित काठ का या चीर काप का अरिष चम्म श्रमधि का बटारधम-नारायात का सामान्य तागजाल हा ता काउ डिचारण बिना प्रतिवाद-परामसदाता के नहीं किया जायगा ।

जहाँ प्रतिवाद-परामसदाता उपसज्जत हो या उा अभियोगों में तत्र तत्र प्रतिवाद परामसदाता हुआ ही उ मया हा जिनमें काउ डिचारण प्रतिवाद-परामसदाता की उपस्थिति के बिना न किया जा सके ता पीठासीन न्यायाधीश पदेन (ex officio) अभियुक्त के ठिके प्रतिवाद-परामसदाता अवश्य नियुक्त करेगा ।

अनु० 290 यदि अनुच्छेद 37 के किसी प्रभाग (section) के अन्तगत दस (आम ग मिली में प्रतिवाद परामसदाता उपसज्जत नहीं हाता तो न्यायालय, पदेन (ex officio) प्रतिवाद-परामसदाता नियुक्ति कर सकेता है ।

अनु० 291 लाउ विदारण के आरम्भ करते समय लाउ-समाहर्ता द्वारा अम्बारापण (indictment) जाउ से पढ़ा जाएगा ।

अम्बारापण पढ़ जाउ के बाद पीठासीन न्यायाधीश अभियुक्त का अवश्य अधिसूचित करेगा कि वह सदैव खुलाप रह सकेता है और किसी भी प्रदा का उत्तर देन ग दुनहार कर सकेता है तथा न्यायालय नियमा द्वारा विहित अन्य विषयों का भी सूचित करेगा जे अभियुक्त के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और अभियुक्त एवं उसी प्रतिवाद परामसदाता की अभियोग के सम्बन्ध में जरा विवरण देन का जवसर अवश्य देगा ।

अनु० 292—विछर अनुच्छेद द्वारा विहित कायवाही की समाप्ति के बाद सादय की परीक्षा (examination of evidence) आरम्भ की जायगी ।

अनु० 293 सादय की परीक्षा समाप्त होने पर, लाउ-समाहर्ता तथ्य के विषय में एवं विधि के विनियाम (application of law) के सम्बन्ध में अपनी समझ देगा ।

अभियुक्त एवं उसी प्रतिवाद-परामसदाता भी अपनी समझ देंगे ।

अनु० 294—राम विचारण के लिए नियत तिथि पर सुनवाई (hearing), पीठासीन न्यायाधीश की अध्यक्षता में की जाएगी।

अनु० 295 पीठासीन न्यायाधीश (अभियुक्त या छाद्दकर मामलों एवं दूसरा के विषय में) पूछे गए किसी भी प्रश्न अथवा विचारण से सख्त व्यक्ति या द्वारा दिए गए किसी विवरण (statement) का विवरणित कर सकता है यदि वे अनावश्यक रूप से दुहराए गए हों वाद-प्रत्येक से असंबद्ध हों। अथवा किसी भी तरह वास्तविक न हों। वहीं नव जहाँ तक कि यह (विवरणित) उन व्यक्तियों के मुख्य अपराधों का ज्ञान न पहुँचाए।

यही नियम उम दंगा में भी लागू होगा जहाँ विचारण से सख्त व्यक्तियों द्वारा अभियुक्त में प्रश्न किया जाय।

अनु० 296 रामसमाहर्ता साक्ष्य की परीक्षा करने के बाद यथावत् विवरणित वह क्या प्रमाणित करने की प्रक्रिया रखता है। तथापि, वह अग्रार्थ मामलों पर आधारित अथवा साक्ष्य के रूप में न देने योग्य विषयों पर आधारित कोई ऐसा विवरण नहीं देगा जो न्यायालय में पक्षपात (prejudice) करने में सक्षम हो अथवा कोई प्रतिस्पर्धी प्रभाव (prejudicial effect) उत्पन्न कराने वाला हो।

अनु० 297—जहाँ तक साक्ष्य की परीक्षा की प्रक्रिया (process) का सम्बन्ध है न्यायालय लाव-समाहर्ता और अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-प्रामाण्य-दाता का समानि सुनने के बाद, उमका क्षेत्र, प्रश्न एवं प्रणाली निर्धारित करेगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कार्यवाही का कार्यान्वित करने के लिए न्यायालय अपने किसी भी मह्यार्थ सदस्य का प्रेरित कर सकता है।

न्यायालय, किसी भी समय जब वह उचित समझे, लाव-समाहर्ता और अभियुक्त अथवा उमके प्रतिवाद-प्रामाण्य-दाता की समानि एवं मुद्दा सुनने के बाद, पहले परिच्छेद के अनुसार पूर्व निर्धारित साक्ष्य की परीक्षा के क्षेत्र, प्रश्न एवं प्रणाली में बदल सकता है।

अनु० 298—रामसमाहर्ता, अभियुक्त और उसके प्रतिवाद-प्रामाण्य-दाता साक्ष्य की परीक्षा के लिए निवेदन कर सकते हैं।

न्यायालय, यदि आवश्यक समझे, साक्ष्य की परीक्षा पदन (ex-officio) कर सकता है।

अनु० 299 किसी माफ़ी, विरोध साक्षी, अर्थनिर्वाचक या अनुवादक की परीक्षा का निवेदन करने के पक्ष, लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता अपने विरोधी पक्ष (opponent party) का अधिम रूप में उस व्यक्ति का नाम एवं पता जानने का अवसर देगा। जब कोई दस्तावेज़ (documentary) या वास्तविक साक्ष्य (real evidence) परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाय तो इसके निरीक्षण के लिए विरोधी पक्ष का अधिम रूप में अवसर अवसर दिया जाएगा। तथापि, यह उस दस्ता में शामिल नहीं होगा यदि विरोधी पक्ष आपत्ति न करे।

साक्ष्य की परीक्षा की व्यवस्था (ruling) पदेन (ex-officio) जारी करने के पक्ष, न्यायालय लोक-समाहर्ता और अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की समति अवसर मुनेगा।

अनु० 300—लोक-समाहर्ता उन प्रश्नों की परीक्षा का निवेदन अवसर करेगा जिसका साक्ष्य के रूप में प्रयोग, अनुच्छेद 321 परिच्छेद 1, प्रभाग 2 के अधिम भाग की व्यवस्थाओं के अनुसार हो सकता है।

अनु० 301—जहाँ अभियुक्त का वक्तव्य (statement), जिसे अनुच्छेद 322 और अनुच्छेद 324 के परिच्छेद 2 की व्यवस्थाओं के अनुसार साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त किया जा सके, अपराधीन अपराध की स्वीकृति (confession) हो तो उसकी परीक्षा का निवेदन (request) तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपराध के घटक तथ्यों का प्रमाणित करने वाले अन्य साक्ष्यों की परीक्षा न हो जाय।

अनु० 302—जहाँ अनुच्छेद 321 से 323 तक या 326 की व्यवस्थाओं के अनुसार साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रत्येक अनुसंधान के अभिलेखों (investigation records) के ही अलावा लोक-समाहर्ता उन्हें अन्य फाइलों से जहाँ तक हो सके अध्ययन करने हुए उनकी परीक्षा का निवेदन करेगा।

अनु० 303—न्यायालय, लोक-विचारण की निधि पर, उन सभी प्रलेखों की परीक्षा (जब) करेगा जिनमें साक्षियों या अन्य व्यक्तियों की परीक्षा (examination), अभिग्रहण और तलाशी एवं साक्ष्य के निरीक्षण के परिणाम (result) तथा लोक-विचारण की तैयारी के मदर्म में प्रलेखीय या वास्तविक साक्ष्य के रूप में अभिगृहीत सभी वस्तुएँ होंगी।

अनु० 304—साक्षियों विशेषज्ञ-साक्षियों, अर्थनिर्वाचका या अनुवादकों की परीक्षा (examination) सर्वप्रथम किसी पीठासीन न्यायाधीश या सह-न्यायाधीश (associate judge) द्वारा की जाएगी।

कार-समाहता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता पीठासीन न्यायाधीश का अधिमूर्चित करके पिछड़े परिच्छेद में उल्लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद साक्षियां, विशेषज्ञ-साक्षियां, अर्थनिर्वाचका या अनुवादकों की परीक्षा कर सकत हैं। उस दशा में जहाँ कि साक्षियां विशेषज्ञ-साक्षियों, अर्थनिर्वाचका या अनुवादकों की परीक्षा कार-समाहता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर आरम्भ की गई हों, वही निवेदन करने वाला व्यक्ति ही उनकी परीक्षा करने वाला पहला व्यक्ति होगा।

न्यायालय यदि उचित समझे तो कार-समाहता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की समिति मुनने के बाद, पिछले दो परिच्छेदों में उल्लिखित परीक्षा का क्रम (order) बदल सकता है।

अनु० 305—कार-समाहता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता द्वारा किए गए निवेदन पर की जाने वाली लेख्य-साक्ष्यों की परीक्षा के समय में पीठासीन न्यायाधीश निवेदन करने वाले व्यक्ति का उन्हें जार से पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तथापि, पीठासीन न्यायाधीश उन लेख्य-साक्ष्यों की स्वयं जार से पढ़ सकता है अथवा सह-न्यायाधीश या न्यायालय-लिपिक से ऐसा करा सकता है।

उस दशा में जबकि न्यायालय लेख्य-साक्ष्यों की परीक्षा पदेन (ex-officio) करे तो पीठासीन न्यायाधीश उन लेख्यों का स्वयं जार से पढ़ेगा या सह-न्यायाधीश अथवा न्यायालय-लिपिक से ऐसा कराएगा।

अनु० 306—कार-समाहता, अभियुक्त या उसके परामर्शदाता द्वारा किए गए निवेदन पर की जाने वाली वास्तविक साक्ष्यों (real evidences) की परीक्षा के समय में, पीठासीन न्यायाधीश, निवेदन करने वाले व्यक्ति को उन्हें दिखाने के लिए प्रेरित करेगा। तथापि, पीठासीन न्यायाधीश स्वयं उन्हें दिखाने में सक्षम है अथवा किसी सह-न्यायाधीश या न्यायालय-लिपिक से ऐसा करा सकता है।

उस दशा में जबकि न्यायालय वास्तविक साक्ष्यों की परीक्षा, पदेन करे तो पीठासीन न्यायाधीश स्वयं उन्हें विचारण (trial) से संबंधित व्यक्तियों

की दिशाएँ अथवा किसी सह-न्यायाधीश या न्यायालय-टिपिक में ऐसा कराएगा।

अनु० 307—अन्य वास्तविक साक्ष्यों में, जिनका सार (purport) प्रमाण का काम दे, प्रमाण (documents) की परीक्षा दोनों ही अनुच्छेद 305 एवं पिछड़े अनुच्छेद के अनुसार की जाएगी।

अनु० 308—न्यायालय, लोक-समाहर्ता एवं अभियुक्त अथवा उमरे प्रतिवाद-परामर्शदाता का साक्ष्य के प्रमाणन मूल्य (probative value) पर जायति करने के लिए आसन्न उचित दस्तावेज प्रदान करेगा।

अनु० 309—लोक-समाहर्ता अभियुक्त या उमरा प्रतिवाद-परामर्शदाता साक्ष्य की परीक्षा के सम्बन्ध में आपत्तियाँ (objections) नहीं कर सकते हैं।

लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उमरे प्रतिवाद-परामर्शदाता, पिछड़े परिच्छेद द्वारा रिक्ति आपत्तियाँ व अतिरिक्त, पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कार्यन्वित किसी भी शरंकाई पर आपत्ति कर सकते हैं।

न्यायालय पिछड़ या परिच्छेदों के अन्तर्गत की गई आपत्तियों पर एक ध्येयवा (ruling) जारी करेगा।

अनु० 310—लोक-विषय या वास्तविक साक्ष्य, परीक्षा समाप्त हो जाने पर न्यायालय के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत किए जाएंगे। तथापि, जहाँ तक किसी प्रमाण का संबंध है, न्यायालय की अनुमति से मूल के बदले में उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत की जा सकती है।

अनु० 311—विचारण के काम में अभियुक्त मरैब धुपचाप रह सकता है या किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर सकता है।

जहाँ अभियुक्त स्वेच्छया अपना वक्तव्य (statement) दे तो पीठासीन न्यायाधीश किसी समय आवश्यक विषय (matters) पर प्रश्न कर सकता है।

सह-न्यायाधीश (associate judge), लोक-समाहर्ता, प्रतिवाद-परामर्शदाता, सह-प्रतिवादी (co-defendant) या उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता भी, पीठासीन न्यायाधीश को अधिमूर्चित कर, पिछड़े परिच्छेद में उल्लिखित दशांश में अभियुक्त से प्रश्न कर सकते हैं।

अनु० 312 लोक-समाहर्ता के निवेदन पर न्यायालय उसे गणक (count) या अभ्यारापण में उद्धृत दण्डित उपबन्धों (penal provisions) को जोड़ने, वापस लेने या बदलने की अनुमति उस अवस्था तक देगा जहाँ तक कि उसमें अभ्यारापित अपराध (offence charged) की अंत्यता (identity) में हेर-फेर न हो।

न्यायालय जहाँ विचारण की प्रगति के अनुसार उचित समझे, किसी लोक-समाहर्ता को दण्डित उपबन्धों या गणक को जोड़ने या बदलने का आदेश दे सकता है।

जहाँ दण्डित उपबन्ध या गणक जोड़े गए वापस लिए गए या बदले गए हों वहाँ न्यायालय अभियुक्त को जोड़े गए, वापस लिए गए या बदले गए अशो की अविलम्ब अधिसूचना देगा।

जहाँ न्यायालय को यह विश्वास हो कि अभ्यारापण के दण्डित उपबन्धों या गणक में जोड़ या परिवर्तन के अभियुक्त के प्रतिवाद पर सार्वजनिक प्रतिकूल प्रभाव (substantial prejudice) पड़ेगा तो वह अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा लोक-विचारण की प्रक्रिया को उनसे समय तक के लिए रोक देगा जितने में अभियुक्त अपने पर्याप्त प्रतिवाद के लिए तैयार हो सके।

अनु० 313—न्यायालय जब उचित समझे, लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर या एक्से-ऑफिसो (ex-officio) एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, मौखिक कार्यवाहियों को अलग या सम्मिलित कर सकता है अथवा समाप्त की गई मौखिक कार्यवाहियों को फिर से आरम्भ कर सकता है।

जहाँ अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक हो, न्यायालय एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, न्यायालय-निर्णयों के अनुसार मौखिक कार्यवाहियों को पृथक् कर सकता है।

अनु० 314—यदि अभियुक्त विवृतचित्तता की अवस्था (state of unsound mind) में हो तो लोक-विचारण की प्रक्रिया, लोक-समाहर्ता और परामर्शदाता की समझ मुनने के बाद, उस अवस्था के मान्य (continuance) में, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, रोक दी जाएगी। तथापि, उस दशा में जब कि निर्दोषता, विमुक्ति, दण्ड-क्षमा या लोक-कार्यवाही के

परितार (dismissal) के निर्णय देने के स्पष्ट कारण हो तो ऐसा निर्णय अभियुक्त की उममजानि की रित प्रतीक्षा रित ही मुक्त दिया जाएगा ।

यदि अभियुक्त बीमारी के कारण उममजात होने में अग्रमर्ष हो तो छोट-विचारण की प्रतीक्षा, ओरममातना और प्रतारद-परामर्शना की मम्मति मुनने के बाद, एर स्पष्टता (ruling) द्वारा ममत के रित रार दी जाएगी जमत उमम उममजान हुना ममत न हो जाय । नयारि, पर उम दगा में लागू नही होगा जहाँ अनुच्छेद 284 और 285 के अनमर बार्द प्रति-परी (proxy) उममजान करारा गया हो ।

जहाँ रिती अरराय के पटर तम्यों की मना या अनार की प्रमातिन करने के रित अन्वयम्यर बार्द मारी बीमारी के कारण मार रितारण की रिति पर उममजान न हो मरता हा ना न्यायालय मार-विचारण की प्रतीक्षा का तमत के रित अवम्य रार दगा जमत रित उमम उममजान हुना ममत न हो जाय, केवल उम दगा का छाटर रर रित न्यायालय उमरी परीक्षा मार-विचारण की रिति म अन्य रितिंयां पर कम्मा उतिन मममे ।

रिछने तीन परिच्छेद व अनुमर रितारण रोरने के पत्रे न्यायालय रिती रितरिना रितेपम (medical expert) की मम्मति मुनेगा ।

अनु० 315—जहाँ मार विचारण के मारम के बाद ही एर (या अनेर) न्यायापीम बदल दिया (दिन) गया (गए) हो (हा) ना उमरी कायंवाही मवीरुन की जाएगी । नयारि, यह उम दगा में लागू नही हुंगा जर रित केवल मार निर्णय (judgment) मार का उद्घोषित रित जाना ही मीप रर हा ।

अनु० 316—रिती रित-न्यायालय के अनेरे एर न्यायापीम द्वारा मी प्रमातिन कायंवाही प्रमाद-मुन्य नही हुगी काहे प्रमुन अभिमांण ऐसा मने ही हो रिते रिती महीमापी-न्यायालय (collegiate court) में ही विचारण जाना रीर हा ।

अनुमाग 2 साक्ष्य (Evidence)

अनु० 317—नयों (facts) का पना मादड के ओमर पर न्याया जाएगा ।

अनु० 318 -साक्ष्य का प्रमाणक मूल्य (probative value) न्याया-
धीनता व स्वतंत्र विवेक (discretion) पर छोड़ दिया जाएगा ।

अनु० 319- बाध्यता, यन्त्रणा या घमभी द्वारा अथवा लम्बे पन्दीकरण
या निराश के बाद की गई मस्वीकृति (confession) अथवा जिसके
स्वच्छया न किए जाने का गदह हा ऐसी मस्वीकृति का साक्ष्य में नहीं
माना जाएगा ।

उम दशा में अभियुक्त का अभिशस्त (convicted) नहीं किया जाएगा
जहाँ उमकी निजी मस्वीकृति ही चाहे वह खुले न्यायालय में की गई हा या
नहीं उमक विरुद्ध एक मात्र प्रमाण हा ।

पिछर दा परिच्छेदा में उल्लिखित मस्वीकृति में अभियुक्त की कोई भी
स्वीकृति जा सजती है जा उम अम्भारापित अपराध का दायी अभिस्वीकृत
करे ।

अनु० 320 अनुच्छेद 321 स 328 तक के अनुच्छेदा द्वारा अन्यथा
विहित दशा के अतिरिक्त न ना किसी व्यक्ति द्वारा लाक-विचारण की तिथि
पर मौखिक रूप में दिए गए वक्तव्य के बदले किसी प्रलख का साक्ष्यरूप में
प्रयोग किया जाएगा और न अन्य व्यक्ति द्वारा लाक-विचारण की तिथि से
भिन्न अन्य निविया पर दिए गए किसी वक्तव्य का मौखिक विवरण ही साक्ष्य
रूप में प्रयुक्त होगा ।

अनु० 321—अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति द्वारा दिया गया लिखित वक्तव्य
(written statement) या प्रलेख (document), जिसमें उमका
वक्तव्य हा और उसी के द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील किया गया हो, केवल
निम्नांकित प्रमाणा में से किसी के अन्तर्गत होने पर ही साक्ष्य रूप में प्रयुक्त
हा मरेगा

(1) जहाँ तक उस प्रलेख का मवध है, जिसमें किसी व्यक्ति का न्याया-
धीन के समक्ष दिया गया वक्तव्य हा, जहाँ कि वह लाक विचारण की तैयारी
या लाक-विचारण की तिथि पर, मृत्यु, मानसिक स्थिति की विवृति
(unsoundness), लापता होने (missing), या जापान के बाहर रहने
के कारण उपसजात न हो या प्रमाणित न करे अथवा वह शरीर से इतना असमर्थ
हा कि प्रमाणित न कर सके या जहाँ वह उल्लिखित तिथि पर उपसजात होकर
अपने पहले के वक्तव्य से किसी रूप में भिन्न प्रमाण दिया हो,

(2) जहाँ तक 'म प्रश्न' का संबंध है जिसमें निम्न व्यक्ति का लोक समझना व समझ लिया गया वक्तव्य है। जहाँ व लोक विचारण का तयारा या लोक विचारण का विधि पर मुख्य मानसिक स्थिति का विह्वल (unsoundness) गाना हान (misleading) या जापान व बाहर रहने व कारण उपमजान न हो सकें या प्रमाणित न कर सकें अथवा ग़रार में इतना असमर्थ हो कि प्रमाणित न कर सकें अथवा जहाँ व ग़ल्लिबिब विधि पर उपमजान ग़रार भ्रम पड़ने व वक्तव्य व विच्छेद या 'म' तत्त्वों भिन्न प्रमाण लिया हो। न्यायि अतिम दंगा में यह बचने वहा लागू होगा जहाँ विधि पर परिस्थितियाँ न जिनके कारण न्यायस्थ का यह पना ला सकें कि पड़ने व वक्तव्य ग़ल्लिबिब विधि पर पूछनाछ (interrogation) व मध्य में लिए गए प्रमाण में अतिरिक्त विमर्शनाय है।

(3) जहाँ तक पिछले प्रमाण (items) में विहित स मित स्थिति वक्तव्य का संबंध है जहाँ कि वक्तव्य इन कारणों व्यक्ति लोक विचारण का तयारा या लोक विचारण का विधि पर मुख्य मानसिक स्थिति का विह्वल (unsoundness) गाना हान (misleading) या जापान व बाहर रहने व कारण उपमजान न हो सकें या प्रमाणित न कर सकें अथवा ग़रार में इतना असमर्थ हो कि प्रमाणित न कर सकें और उससे पिछले वक्तव्य अभ्यारणित अथवा व अवस्था प्रमाण है। न्यायि यह उठा दंगा में लागू होगा जहाँ कि विधि पर परिस्थितियाँ रहा हो जिनमें वक्तव्य लिए गए और जो विधि प्रयोजना (special credibility) उत्पन्न करे।

काइ लिखित अभिलेख (record) जिसमें अभिवृत्त स साथ निम्न व्यक्ति द्वारा लोक विचारण का तयारा या लोक विचारण का विधि पर लिए गए वक्तव्य व अथवा वह लिखित अभिलेख जिसमें न्यायालय या निम्न जायायाग द्वारा किए गए निरीक्षण (inspection) व परिणाम (result) का बान हो पिछले परिच्छेद का बिना विचार किए हो। मध्यस्थ व प्रयुक्त किया जा सकता है।

काइ लिखित अभिलेख जिसमें लोकसमाहवा लोकसमाहवा न्यायालय व सचिव या जायिक पुलिस नमबारी द्वारा किए गए निरीक्षण के परिणाम का बचन हो इस अवस्था के पिछले परिच्छेद का बिना विचार किए हो साक्ष्य में प्रयुक्त किया जा सकता है यदि इसे तयार करने वाला

व्यक्ति लोक-विचारण की तिथि पर साक्षी के रूप में उपसजात हो और तब तक बचने पर प्रत्येक का सत्याकन करे।

पिछला परिच्छेद यथोचित परिवर्तन के साथ, उम प्रलेख (document) के मन्त्र में लागू होगा जिसे किसी विशेषज्ञ साक्षी (expert witness) ने तैयार किया है और जिसमें उसके निष्कर्षों (conclusions) एवं प्रक्रिया (process) का वर्णन है जिसके अन्तर्गत उसने अपनी समिति दी है।

अनु० 322—अभियुक्त द्वारा दिया गया कोई लिखित वक्तव्य (written statement) या प्रलेख जिसमें उसका वक्तव्य है और उसके द्वारा हस्ताक्षर एवं माल किया गया हो, उसके विरुद्ध साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त हो सकता है यदि वक्तव्य में अभियुक्त द्वारा की गई उस तथ्य की स्वीकृति (admission) है जो उसके हित (interest) के विरुद्ध है अथवा यदि वक्तव्य असाधारण परिस्थितियों (unusual circumstances) में दिया गया है जिनसे विशेष प्रत्येयता (special credibility) पैदा हो गई है। तथापि, जहाँ लिखित वक्तव्य या प्रलेख में अभियुक्त द्वारा अपने हित के विरुद्ध तथ्य की स्वीकृति (admission) की गई हो और यह सदा है कि स्वीकृति स्वेच्छया नहीं की गई है तो वह, एवं साथ ही साथ अनुच्छेद 319 द्वारा विहित दशाओं में, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जायगा, चाहे स्वीकृति (admission) किसी अपराध की सस्वीकृति (confession) भले न हो।

कोई लिखित अभिलेख, जिसमें अभियुक्त द्वारा पहले, लोक-विचारण की तैयारी या लोक-विचारण की तिथि पर, दिए गए वक्तव्य हो, तभी तक साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त हो सकता है जब तक कि वह स्वेच्छया दिया गया प्रतीत हो।

अनु० 323—पिछले दो अनुच्छेदों में विहित से भिन्न प्रलेख (documents) केवल तभी साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं यदि वे निम्नांकित में से कोई हो :

- (1) किसी के कुटुम्ब रजिस्टर (family register) की एक प्रति या विलेख (notarial deed) की प्रति अथवा उन तथ्यों की प्रमाणित करने वाले ऐसे ही अन्य लोक-लेख्य (public documents) जिन्हें प्रमाणित करने का कर्तव्य (duty) या प्राधिकार (authority) किसी लोक-कर्मचारी (जिनमें विदेशी सरकार के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) को हो,

- (2) बाई लेखा-पुस्तक (account book), जल-यात्रा अभिलेख (voyage log) एवं अन्य प्रलेख या व्यापार को नियमित परिधि में तैयार किए गए हों,
- (3) पिछले दो प्रभागों द्वारा विहित से भिन्न प्रलेख या अपने अनगुन वक्तव्यों के दृढ़ कथन (assertions) के प्रति विशेष प्रत्येयता में (special credibilty) प्रदान करने वाली परिस्थितियों तैयार किये गए हों।

अनु० 324—जहाँ तक अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति द्वारा लोक-विचारण की नैशानों की निधि या उस लोक-विचारण की निधि पर दिए गए मौखिक वक्तव्यों का सम्बन्ध है, जिनमें अभियुक्त के विचारण के पहले के वक्तव्य (pre-trial statements) का अनुच्छेद 322 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होगी।

जहाँ तक अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति द्वारा उल्लिखित निधि पर दिए गए मौखिक वक्तव्यों का संबंध है जिनमें अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति द्वारा दिए गए, विचारण के पूर्व के वक्तव्य (pre trial statements) हों, अनुच्छेद 321, परिच्छेद 1 प्रभाग 3 की व्यवस्थाएँ यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होगी।

अनु० 325—पिछले चार अनुच्छेदों के अनुसार साक्ष्य-रूप में प्राप्त वक्तव्य या प्रलेख न्यायालय द्वारा तब तक साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि उसे अनुसंधान के बाद यह विश्वास न हो जाय कि किसी व्यक्ति के वक्तव्य या प्रलेख में वर्णित वक्तव्य, जो अन्य व्यक्ति द्वारा लोक-विचारण की तैयारी की निधि या लोक-विचारण की निधि पर दिये गए मौखिक वक्तव्य में निहित हो, स्वच्छता (voluntarily) दिया गया था।

अनु० 326—अनुच्छेद 321 से 325 तक के अनुच्छेदों के अतिरिक्त भी कोई प्रलेख या वक्तव्य केवल तभी साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त हो सकता है जब कि लोक-न्यायाधीश और अभियुक्त उसके लिए सम्मति (consent) दें और न्यायालय उन परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जिनमें उक्त प्रलेख या वक्तव्य लिया गया था, इसे उचित समझे।

उन अभियोगों में जहाँ अभियुक्त की अनुपस्थिति (non-attendance) में भी साक्ष्य की परीक्षा (examination of evidences) कार्यान्वित की जा सकती है और अभियुक्त उपसजान न हो तो पिछले परिच्छेद में

उल्लिखित सम्मति उसने दे दी ऐसा मान लिया जायगा । तथापि, वह उस दशा में लागू नहीं होगा जहां उनसे बढ़ते में उसका प्रतिपक्ष या परामर्शदाना उपसजात हो ।

अनु० 327—लाभ-समाहर्ता और अभियुक्त या उससे प्रतिवाद परामर्श-दाना के महत्त्व होने पर निम्नो प्रत्यक्ष के अन्तर्विषया के सम्बन्ध में लिखित अनुबन्ध (written stipulations) या निम्नो प्रमाण का सातान, जो यदि माफी न्यायालय में उदमज्ञान होने वाला होता तो दिया जाना मौलिक प्रत्यक्ष (original document) को जाँच के बिना ही या लाभ-विचारण में साक्षी से बिना पूछनाछ दिए ही साक्षर-रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है । तथापि अनुबन्ध के प्रमाणन मूल्य (probative value) पर निम्नो भी समय आपत्ति (objection) की जा सकती है ।

अनु० 328 किसी प्रत्यक्ष या मौखिक वक्तव्य (oral statement) का जिस अनुच्छेद 321 से 324 तक के अनुच्छेदों द्वारा साक्षर-रूप में प्रयुक्त किया जा सके, उस वक्तव्य की प्रत्येयता (credibility) निर्धारण करने की प्रणाली (method) के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है जो लाभ-विचारण की तैयारी की नियि या लाभ-विचारण की नियि पर अभियुक्त, साक्षी या अन्य ध्यक्षिया (जिन्होंने अपने वक्तव्य (statements) न्यायालय के बाहर दिए हैं) द्वारा दिए गए हैं ।

अध्याय 3

लोक-विचारण का विनिश्चय (Decision in Public Trial)

अनु० 329—किसी अभियुक्त के विरुद्ध लम्बित (pending) अभियोग (case) की दशा में, जो न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र (jurisdiction) में न जाता हो, अक्षमता (incompetency) की उद्घोषणा एक निर्णय (judgment) द्वारा की जायगी । तथापि, अनुच्छेद 266, प्रभाग 2 के अन्तर्गत किसी जिला-न्यायालय में विचारण के लिए सौंपे गए अभियोग के समय में न्यायालय अक्षमता की उद्घोषणा नहीं करेगा ।

अनु० 330—यदि कोई अभियोग, जिससे लिए लाभ-न्यायवाही उससे विशेष क्षेत्राधिकार में आने के कारण निम्नो उच्च न्यायालय में सत्विता की गई हो,

किसी निम्न न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में आता हो तो पिछ्छ अनुच्छेद की व्यवस्था का बिना विचार किए एक व्यवस्था द्वारा उस क्षमताशील (competent) न्यायालय में अन्तरित कर दिया जायगा।

अनु० 331—अभियुक्त के प्राथम्य-पत्र देन की दंगा के अतिरिक्त न्यायालय प्रादेशिक क्षमताधिकार (territorial jurisdiction) के सबष में अक्षमता की उदघोषणा नहीं करेगा।

अभियुक्त के विरुद्ध सम्बन्धित अभियोग (charge) के समक्ष में साक्ष्य का परोषा प्रारम्भ की जान के बाद किसी भी अक्षमता की अभ्युक्ति (plea of incompetency) का स्वीकार नहीं हो जायगी।

अनु० 332—कोई निम्न-न्यायालय एक व्यवस्था द्वारा किसी अभियोग की अधिकार-क्षेत्र-सम्पन्न उच्च-न्यायालय में अन्तरित कर दगा यदि वह अभियोग का उच्च-न्यायालय में विचारित कराना उचित समझे।

अनु० 333 जहाँ अभियुक्त के विरुद्ध सम्बन्धित अभियोग के समक्ष में अपराध का प्रमाण सिद्ध हो वहाँ अनुच्छेद 334 की दंगा की छाछर एक नियम द्वारा दण की उदघोषणा का जायगी।

एसे दण्ड के साथ ही साथ नियम द्वारा दण्ड निषादक के निरन्धन (suspension) की उदघोषणा की जायगी।

अनु० 334—जहाँ अभियुक्त के विरुद्ध सम्बन्धित अभियोग के सबष में दण्ड क्षमा किया जानवाला हो तो नियम द्वारा इस तथ्य की उदघोषणा की जायगी।

अनु० 335—अभियुक्त का अपराधी उदघोषित करन में अपराध के घटक तथ्या साक्ष्य की सूची (inventory) तथा विधियाँ एक अध्यादेश की प्रयुक्ति (application) का निर्देश दिया जायगा।

जहाँ अपराध के सघटन (formation of offence) का बाधित करन वाले वैधानिक आधार (legal ground) के सबष में कोई अपराध लगाया गया हो अथवा उन तथ्या के सबष में लगाया गया हो जिनके कारण दण्ड बढ़ाया (aggravated) या घटाया (commuted) जा सके तो उस पर भी विनिश्चय (decision) का निर्देश दिया जायगा।

अनु० 336—यदि अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग में किसी अपराध का सघटन न हो अथवा यदि अपराध में प्रमाण का अभाव हो तो अभियुक्त की

निणय (judgement) द्वारा निर्दोष' (not guilty) उदघाषित किया जायगा।

अनु० 337—विमुक्ति (acquittal) की उदघाषणा निणय द्वारा निम्नावित दशाओं में की जायगी।

- (1) जहाँ बाइ अन्त वाध्यकारी निणय (finally binding judgment) पहुँची दिया जा चुका हो
- (2) जहाँ अपराध-संपादन के बाद ही प्रवर्तित (लागू) किया गए विधि या अध्यादेश द्वारा दण्ड परिहृत (abolished) कर दिया गया हो
- (3) जहाँ बाइ सामान्य राजक्षमा (general amnesty) घोषित की गई हो
- (4) जहाँ बाइ भागाधिकार (Prescription) पूरा किया गया हो।

अनु० 338—निम्नावित दशाओं में निणय द्वारा लाव-कायवाही निरस्त (dismiss) कर दी जायगी

- (1) जहाँ अभियुक्त पर न्यायालय का अधिकार क्षय लागू न हो
- (2) जहाँ बाइ लाव-कायवाही अनुच्छेद 340 के उत्प्रेषण में संस्थित की गई हो
- (3) जहाँ उमा अभियाग पर, जिस पर बाई लाव-कायवाही की गई थी दूसरी लाव-कायवाही उमा न्यायालय में लाइ गई हो
- (4) जहाँ लाव-कायवाही संस्थित करने की प्रक्रिया (procedure) उमम सबद्ध व्यवस्थाओं के विरोध में होने के कारण प्रभावहीन (void) हो।

अनु० 339—निम्नलिखित दशाओं में एक व्यवस्था द्वारा लाव-कायवाही निरस्त कर दी जायगी

- (1) जहाँ अभ्यासायण (indictment) के सभी गणक (counts) सह सही नहीं हैं बाइ विशेष अपराध का वर्णन नहीं करें,
- (2) जहाँ यह (लाव-कायवाही) वापस ली गई हो,
- (3) जहाँ अभियुक्त मर गया हो या न्यायिक व्यक्ति (juridical person) होने के कारण (अभियुक्त रूप में) नहीं हो,

(1) जहाँ अनुच्छेद 10 या 11 की व्यवस्थाओं द्वारा न्यायनियम (adjunction) बाधित हो ।

निम्न परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था के विरुद्ध आशुन कोकोकु अपील की जा सकती है ।

अनु० 340 जहाँ वापसी (withdrawal) के बलवत्कृत लोच-बाधवाहक या निरस्त करने वाली व्यवस्था अन्तर्गत बाधवाहक (fully binding) को जाय तो उस अपराध के क्रिय केवल उसी दशा में नई लोच-बाधवाहक सन्धित की जा सकती है जब कि यह किसी नयाविकृत (newly discovered) साख्यान साक्ष्य (material evidence) पर आपृत हो ।

अनु० 341—उस दशा में जब कि कोई अभियुक्त बयान (statement) इन या इनकार करने बिना अनुमति के न्यायालय से निवृत्त (retire) हो जाय या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा सान्ति स्थापन के लिये न्यायालय से निवृत्त हान व लिये आदेश पावे या उत्तरदायक बिना गुने ही निर्णय दिया जा सकता है ।

अनु० 342—सार विचारण-न्यायालय (public trial court) में निणय उद्घाटन (pronouncement) अवस्था करायी जायगी ।

अनु० 343—बारायास या किसी गुहार दण्ड दिये जाने के समय जमानत या निराध निष्पादन का निश्चयन (suspension) प्रभावहीन हो जायगा । ऐसी दशा में अनुच्छेद 98 की व्यवस्थाएँ यथावित परिवर्तन व साथ केवल सभी लागू होंगी जब कि जमानत या निराध निष्पादन व निश्चयन की कोई नई व्यवस्था न जारी की गई हो ।

अनु० 344—अनुच्छेद 89 की व्यवस्थाएँ बारायास या गुहार दण्ड दिये जाने व बाद नहीं लागू होंगी ।

अनु० 345—निर्दोषिता (not guilty) विमुक्ति दण्ड-दशा दण्ड निष्पादन के निश्चयन लोच-बाधवाहक व निरस्त असमता (incompetency) या अपदण्ड या छोटे अपदण्ड का निणय दिये जाने के समय निरोध का अधिपत्र (warrant of detention) प्रभावहीन हो जायगा ।

अनु० 346—यदि अभिग्रहीत (seized) वस्तुओं के संवध में राज्य-सात्वरण (confiscation) की उद्घापणा न की गई हो तो अभिग्रहण (seizure) से उक्त वस्तुओं की छूट की उद्घापणा की गई समझी जायगी।

अनु० 347—यदि अभिग्रहण के अन्तर्गत रखे गए अन्यायाजित (illegotten) माला के संवध में, अपकृत-पक्ष (injured party) का पुनः लौटा देने के स्पष्ट हेतु (clear reason) हो तो उक्त माला का अपकृत-पक्ष को प्रत्यावर्तित करने (restoration) का एक उद्घापण किया जायगा।

वह अभियाग भी जिसमें अपकृत-पक्ष अन्यायाजित माल के विचार के लिये ली गई किसी वस्तु का पुनः लौटाने की मांग करे, पिछले परिच्छेद द्वारा ही नियन्त्रित होगा।

जहाँ अन्तिम रूप से प्रत्यावर्तित (provisionally restored) माला के संवध में, कोई विराधी उद्घापण न किया गया हो, वहाँ प्रत्यावर्तन का उद्घापण किया गया समझा जायगा।

पिछले तीन परिच्छेदों के अतिरिक्त कोई भी बद्धिहित (interested) व्यक्ति दीवानी प्रक्रिया (civil procedure) के अनुसार अपने अधिकारों का दृढ़-प्रतिपादन (assertion) कर सकता है।

अनु० 348—यदि कोई न्यायालय अभियुक्त पर अर्पणदण्ड, छोटे अर्पणदण्ड या अनिश्चित वसूली (additional collection) का उद्घापण करे तो न्यायालय वस्तुतः या पदम लावसमाहर्ता के निवेदन पर, उक्त उद्घापित धनराशि की अन्तिम अदायगी (provisional payment) का आदेश दे सकता है, यदि वह समझे कि निष्पादन के विलम्बित होने की दशा में जब तक निर्णय अन्ततः बाध्यकारी न हो जाय तब तक निर्णय को निष्पादित करना असंभव या अत्यन्त कठिन होगा।

अन्तिम अदायगी के विनिश्चय (decision) का उद्घापण न्यायाधीश द्वारा दण्ड के उद्घापण के साथ ही साथ किया जायगा।

अन्तिम अदायगी के आदेश करने वाले विनिश्चय को अविलम्ब निष्पादित किया जा सकता है।

अनु० 349—उस दशा में, जब कि दण्ड-निष्पादन को निलम्बित करने वाला उद्घापण विरुद्धित किया जाने वाला (to be rescinded) हो, लावसमाहर्ता जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय से,

जिसके अभियार-क्षेत्र में सिद्धनाप व्यक्ति (convicted person) रहता हो या रह चुका हो, उक्त विच्छेदन (rescission) की माँग करेगा ।

जब पिछले परिच्छेद में उल्लिखित माँग की जा चुकी हो न्यायालय अभियुक्त या उसके प्रतिपरी (proxy) की सम्मति सुनने के बाद एक व्यवस्था जारी करेगा । उक्त व्यवस्था के विरुद्ध याचन कोकोहु अपील की जा सकती है ।

अनु० 350—उस दशा में जब कि दण्ड-संहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 52 के अनुसार किसी दण्ड का निर्धारण किया जाने वाला हो तो लोक-समाहर्ता उस न्यायालय से दण्ड निर्धारित करने की माँग करेगा जिसने उस अभियोग पर दण्ड निर्धारित करने का अन्तिम निर्णय दिया हो । इस दशा में, पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ यथाचित परिवर्तन के साथ लागू होंगी ।

— — —

तीसरा खण्ड-अपील

अध्याय 1

सामान्य उपबन्ध

(General Provisions)

अनु० 351—अपील (जोसो) किसी लायममाहर्ता या अभियुक्त द्वारा की जा सकती है।

जब अनुच्छेद 266 के प्रभाग 2 के अनुसार किसी न्यायालय में विचारण के लिये मौफा गया कोई अभियोग दूसरे अभियोग के साथ सामूहिक रूप में विचारित किया गया है और निणय दिया गया है तो अनुच्छेद 268 के परिच्छेद 2 के अनुसार लायसमाहर्ता के कार्यों का करने वाला अधिवक्ता (advocate) एव दूसरे अभियोग में लगा हुआ लाय-समाहर्ता जमदा स्वन्ध रूप में उन निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है।

अनु० 352—अभियुक्त या लायसमाहर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध कोई व्यवस्था (ruling) जारी की गई हो, कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 353—अभियुक्त का वंश प्रतिनिधि (legal representative) या पालक (curator) अभियुक्त की ओर से अपील कर सकता है।

अनु० 354—जहाँ निराश का कारण निर्देशन किया गया है, निर्देशन (indication) का निवेदन करने वाला व्यक्ति भी, अभियुक्त की ओर से निरोध (detention) के विरुद्ध अपील कर सकता है। यही नियम अपील को निरस्त करने वाली व्यवस्था के मवध में भी लागू होगा।

अनु० 355—मूल न्यायालय (original instance) का प्रतिपक्षी (proxy) या परामर्शदाता अभियुक्त की ओर से अपील कर सकता है।

अनु० 356—पिछले तीन अनुच्छेदों में उल्लिखित अपील अभियुक्त के स्पष्टत व्यक्त किए गए आशय (intention) के विरुद्ध नहीं की जायगी।

अनु० 357—निर्णय के किसी अंश के विरुद्ध अपील की जा सकती है।

वह अपील जा निर्णय के किसी अंश मात्र तक ही सीमित न हो, पूरे निर्णय पर की गई समझी जायगी।

अनु० 358—अपील करने की अवधि निर्णय विज्ञापित करने के दिन से आरम्भ हो जायगी।

अनु० 359—लोक-समाहर्ता अभियुक्त या अनुच्छेद 352 में उल्लिखित व्यक्ति अपील वापस ले सकते हैं।

अनु० 360 अनुच्छेद 353 या 354 में उल्लिखित व्यक्ति अभियुक्त की सम्मति (consent) से अपील वापस ले सकते हैं।

अनु० 361—वह व्यक्ति जिसने कोई अपील वापस ले ली हो, उसी अभियोग के सम्बन्ध में दूसरी अपील नहीं कर सकता। यही उस अभियुक्त के सम्बन्ध में लागू होगा जिसने अपील का वापस लेने की ममति (consent) दी है।

अनु० 362—जब अनुच्छेद 351 से 355 तक के अनुच्छेदों के अन्तर्गत (by virtue of) अपील करने का अधिकारी व्यक्ति, ऐसे कारण से जो स्वयं उस पर या उसके प्रतिनिधि पर आरोपित न किया जा सके, अपील करने की अवधि के अन्दर अपील करने से रोक दिया गया हो तो वह अपील करने के अपने अधिकार की पुनर्प्राप्ति (recovery) के लिए मूल न्यायालय (original court) में प्रार्थनापत्र दे सकता है।

अनु० 363—अपील करने के अधिकार की पुनर्प्राप्ति (recovery of right) की माँग लिखित रूप में उस अवधि के अन्दर की जायगी, जो अपील करने की अवधि के बराबर होगी जिसका आरम्भ उस दिन होगा जिस दिन अपील रोकने वाला कारण समाप्त हुआ।

अपील करने के अधिकार की पुनर्प्राप्ति की माँग करने वाला व्यक्ति उक्त माँग के साथ ही साथ अपील के लिये एक प्रार्थनापत्र दगा।

अनु० 364—अपील करने के अधिकार की पुनर्प्राप्ति की माँग के सम्बन्ध में की गई व्यवस्था के विरुद्ध आसन्न कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 365—जब अपील करने के अधिकार की पुनर्प्राप्ति की माँग की गई हो तो मूल न्यायालय निर्णय के निष्पादन की रोकने वाली कोई व्यवस्था

तब तक के लिये जारी कर सकता है जब तक कि पिछले अनुच्छेद में विहित व्यवस्था जारी न कर दी जाय। इस दशा में, अभियुक्त के विरुद्ध निरोध का अधिपत्र जारी किया जा सकता है।

अनु० 366— यदि कारागार में रहने हुए अभियुक्त द्वारा अपील के लिये लिखित प्रार्थनापत्र मुख्य काराधिकारी (Chief Prison Officer) या उसके सहायक के पास, अपील की अवधि के अंदर दे दिया जाय तो ऐसी अपील विहित अवधि में की गई ममझी जायगी।

यदि अभियुक्त लिखित प्रार्थनापत्र स्वयं तैयार करने में असमर्थ हो तो मुख्य काराधिकारी या उसका सहायक उसके लिये प्रार्थनापत्र लिख देगा अथवा अपने अधीन किसी कर्मचारी से ऐसा करा देगा।

अनु० 367 पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, उन अभियागा में लागू होंगी जहाँ कारागार में रहता हुआ अभियुक्त अपील वापस या अपील करने के अपने अधिकार की पुनः प्राप्ति की माँग करे।

अनु० 368 उस दशा में जब कि केवल लाक-समाहर्ता द्वारा सस्थित अपील स्थापित की या वापस ली गई हो, राज्य (State) अभियोग के तत्कालीन अभियुक्त को उस न्यायालय में जिसमें अपील की गई हो अपील के कारण किये गए व्ययों (expenses) का प्रतिफल (compensation) देगा।

अनु० 369—प्रतिफल की राशि में केवल यात्रा-व्यय (travelling expenses), दैनिक भत्ते, और आवास खर्च (lodging charges), जिन्हें तत्कालीन अभियुक्त एवं तत्कालीन प्रतिवाद-परामर्शदाता (then Defense Counsel) ने लोक-विचारण की तैयारी या लोक विचारण की तिथि पर उपसजात होने के लिये दिया हो, और पारिश्रमिक (remuneration) रहेगा जिसे अभियुक्त ने परामर्शदाता का दिया हो, तथा जहाँ तक अनुदान (grant) की जाने वाली राशि का संबंध है आपराधिक प्रक्रिया के परिव्ययों (Costs of Criminal Procedure) से संबंध विधि (Law) के परामर्शदाता एवं साक्षी से संबंध व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, तत्कालीन अभियुक्त एवं तत्कालीन परामर्शदाता के संबंध में लागू होंगी।

अनु० 370—प्रतिर तराखीन अभियुक्त या उमने प्रतिपत्री (proxy) की प्रार्थना पर, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जितने उस अभियुक्त पर अपना अपील कीय क्षेत्राधिकार (appellate jurisdiction) प्रयुक्त किया है, एन व्यवस्था द्वारा स्वीकृत (allowed) किया जायगा।

विच्छेद परिच्छेद में उल्लिखित प्रार्थना (request), अपील स्वीकृत करने वाले निर्णय व अधिमूर्चन किये जाने या अपील के वापस लिये जाने के बाद दो मास व अदर की जायगी।

उच्च न्यायालय द्वारा पहलू परिच्छेद के चल पर जारी की गई व्यवस्था पर अनुच्छेद 428 के परिच्छेद 2 के अनुसार आपत्ति (objection) की जा सकती है। आसन्न कोसोके अपील स समय व्यवस्थाएँ भी, यथोचित परिवर्तन के साथ, उल्लिखित आपत्ति व समय में लागू होंगी।

अनु० 371 इस संहिता (Code) में अन्यथा कितना दत्त की छाड़कर, न्यायालय के नियम प्रतिर सत्रकी प्रार्थना प्रतिर की अदायगी एवं प्रतिर से सबद अन्य कार्यवाही का अधिस्त करने।

अध्याय 2

कोसो अपील

(Koso Appeal)

अनु० 372—जिसी जिला-न्यायालय परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय द्वारा प्रथम न्यायालय (first instance) में दिए गए निर्णय के विरुद्ध कोसो अपील की जा सकती है।

अनु० 373—कोसो अपील के लिए निर्धारित अवधि सोदह दिन होगी।

अनु० 374—कोसो अपील प्रथम न्यायालय (Court of first instance) में कोसो अपील के लिए लिखित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने हुए की जायगी।

अनु० 375—जहाँ यह स्पष्ट हो कि कोसो अपील, कोसो अपील करने के अधिनार की समाप्ति के बाद की गई है, प्रथम न्यायालय उसे एन व्यवस्था के आधार पर स्वीकृत कर देगा। ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध आसन्न (immediate) कोसोके अपील की जा सकती है।

अनु० 376—अपीलवर्ता (appellant) कोसो अपील के हेतुओं का विवरण अपीलार्थ न्यायालय को, न्यायालय-नियमों द्वारा विहित अवधि के अंदर, अवश्य प्रस्तुत करेगा।

जैसा कि न्यायालय-नियमों या इस संहिता (Code) में अपेक्षित है कोसो अपील के हेतुओं के विवरण के साथ परामर्शदाता या लोकसमाहर्ता का प्रमाणपत्र या प्रकल्पित प्रमाण (presumptive proof) अवश्य सलमन किया जायगा।

अनु० 377—जहाँ निम्नांकित में से किसी आधार पर कोसो अपील की जाय परामर्शदाता या लोकसमाहर्ता के प्रमाणपत्र के साथ अपील के हेतुओं का विवरण इस आशय से सलमन किया जायगा कि (यदि अवसर दिया जाय) ऐसे आधारों की सत्ता या पर्याप्त प्रमाण दिया जा सकता है

- (1) जब कि मूल-न्यायालय का सघटन विधि द्वारा विहित रूप में न किया गया हो,
- (2) जब कि किसी न्यायाधीश ने जिसे कुछ वैधानिक कारणों (legal reason) से निर्णय में भाग नहीं लेना चाहिए था किन्तु उतने निर्णय देने में सम्मिलित भाग लिया हो,
- (3) जब कि छूटे लाव-विचारण से संबद्ध व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया गया हो।

अनु० 378—जहाँ कोसो अपील निम्नांकित में से किसी आधार पर की जाय, अपील के हेतुओं के विवरण (statement) में, अभिव्यक्त आधार (ground alleged) की प्रत्येक (credible) बनाने के लिए उन विषयों का समुचित उद्धरण रहेगा जो विषय उक्त अभिलेख में आने हों जिनमें पहले की कार्यवाही एवं मूल न्यायालय द्वारा लिख गए भाष्य के अन्तर्विषयों (contents) का विवरण हो

- (1) जब कि न्यायालय अपने को अवैध रूप में (illegally) क्षमताशाली (competent) या अक्षम (incompetent) समझ ले,
- (2) जब कि लोक-कार्यवाही अवैध रूप में स्वीकृत या खारिज की गई हो,

(3) जब कि अभ्यारोपण (indictment) में आए हुए किसी गणक (count) के संबंध में निणय न दिया गया हो अथवा उस गणक के संबंध में दिया गया हो जो अभ्यारोपण में न हो।

(4) जब कि निणय सन्तुष्ट न किया गया हो या हेतु विराध में रहे हो।

अनु० 379—जहाँ बीसो अपील पिछले दो अनुच्छेदों द्वारा विहित से मिलित इस आधार पर की जाय कि नायवाणी में किसी विधि या अध्यादेश का उल्लंघन किया गया है और यह कि वह उल्लंघन निणय में महत्वपूर्ण (material) स्थान रखता है तो अपील के हेतुओं के विवरण में अभिव्यक्त आधार का प्रत्यय (credible) बनान के लिए उन विषयों का समुचित उद्धरण रहेगा जो उस अभिप्रेत में आते हैं जिसमें की गई कायवाणी एवं मूत्र प्रमाणों द्वारा लिए गए साक्ष्य के अन्तर्विषय (contents) का वर्णन हो।

अनु० 380—जहाँ बीसो अपील मूत्र प्रमाणों द्वारा विधि या अध्यादेश के निर्माण (construction) अथवा निवचन (interpretation) या प्रयुक्ति (application) में की गई गलती (mistake) के आधार पर की जाय और वह मूत्र निणय में महत्वपूर्ण रती हो तो अपील के हेतुओं के विवरण में उक्त मूत्र एवं निणय में उसकी महत्वपूर्णता का विवरण निर्देश किया जायगा।

अनु० 381—जहाँ बीसो अपील इस आधार पर की जाय कि दण्ड का निर्धारण अनुचित एवं अयोग्यपूर्ण ढंग से किया गया है तो अपील के हेतुओं के विवरण में अभिव्यक्त आधार का प्रत्यय बनान के लिए उन विषयों का समुचित उद्धरण रहेगा जो उस अभिलेख (record) में आते हैं जिसमें की गई कायवाणी एवं मूत्र प्रमाणों द्वारा लिए गए साक्ष्य के अन्तर्विषयों का वर्णन हो।

अनु० 382—जहाँ बीसो अपील तथ्यों के अनुसंधान में त्रुटि (error) एवं निणय में उसकी स्पष्ट महत्वपूर्णता (obvious materiality) के आधार पर की जाय तो अपील के हेतुओं के विवरण में अभिव्यक्त आधार को प्रत्यय बनान के लिए उन विषयों का समुचित उद्धरण रहेगा जो उस अभिलेख में आते हैं जिसमें की गई कायवाणी एवं मूत्र प्रमाणों द्वारा लिए गए साक्ष्य के अन्तर्विषयों का वर्णन हो।

अनु० 383—जहाँ कोसो अपील निम्नांकित में से किसी आधार पर की जाय ता अपील के हेतुओं के विवरण का आधार के प्रकल्पित प्रमाण के माध्यम से सत्यता किया जायगा

- (1) जब कि कायबाही के पुनर्विचार (reopening of procedure) का समयन करने वाला कोई तथ्य मिलता है (संश्लेषित),
- (2) जब कि अबर न्यायालय में निणय दिये जाने के ठीक बाद, दण्ड का परिहार या परिवर्तन कर दिया गया है या सामान्य राजशमा (general amnesty) की घोषणा की गई है।

अनु० 384—कोसो अपील अनु० 377 से 383 तक के अनुच्छेदों द्वारा विहित अपील के आधारों में से किसी एक के दृढ़करण (ascertaining) द्वारा की जा सकती है।

अनु० 385—जहाँ यह स्पष्ट है कि कोसो अपील का प्रार्थनापत्र विधि या अध्यादेश द्वारा विहित प्रपत्र (form) के अनुसार नहीं बनाया गया है अथवा अपील करने के अधिकार की समाप्ति के दाव दिया गया है ता कोसो अपील का न्यायालय उस एक व्यवस्था द्वारा खारिज कर देगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था के विरुद्ध अनुच्छेद 428 परिच्छेद 2 के अनुसार आपत्ति (objection) की जा सकती है, ऐसी दशा में, आसन्न कोसो अपील की व्यवस्थाएँ भी यथोचित परिवर्तन के माध्यम से लागू होंगी।

अनु० 386—कोसो अपील का न्यायालय कोसो अपील का एक व्यवस्था द्वारा खारिज (dismiss) कर सकता है

- (1) जब कि कोसो अपील के हेतुओं का विवरण अनुच्छेद 376 परिच्छेद 1 में विहित अवधि के अन्दर न प्रस्तुत किया जाय,
- (2) जब कि कोसो अपील के हेतुओं का विवरण इस संहिता (Code) एवं न्यायालय के नियमों द्वारा निर्दिष्ट किए गए प्रपत्र (form) के अनुसार न है, अथवा जब इसके साथ, इस संहिता (Code) अथवा न्यायालय-नियमों द्वारा विहित आवश्यक प्रकल्पित प्रमाण या प्रमाणपत्र (certificate) न है।

अनु० 393—पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित अनुसंधान (investigation) के लिए आवश्यकता समझने पर कोसो अपील का न्यायालय लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर या घटेन तथ्यों की जाँच कर सकता है। तथापि, उन साक्ष्यों के संचय में जिनके विषय में यह प्रदर्शित करने वाला प्रकल्पित प्रमाण (presumptive proof) प्रस्तुत किया जाय कि प्रथम न्यायालय में मौखिक कार्यवाहियाँ के पर्यवसान (conclusion) के पहले उन्हें जाँच के लिए नहीं दिया जा सका तो न्यायालय उक्त साक्ष्यों की जाँच केवल उसी दशा में करेगा जबकि वे दण्ड के अनुचित निर्धारण (improper determination) अथवा निर्णय के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों के अनुसंधान में की गई भ्रष्टियाँ के प्रमाण के लिए आवश्यक हैं।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित जाँच (examination) सहायी-न्यायालय के किसी सदस्य द्वारा कार्यान्वित कराई जा सकती है, अथवा इसे करने के लिए जिला-न्यायालय, पञ्चिका-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय का कोई न्यायाधीश अधियाचित किया जा सकता है। ऐसी दशा में, राजादिष्ट न्यायाधीश या अधियाचित न्यायाधीश के वही अधिकार होंगे जो किसी न्यायालय या पीठासीन न्यायाधीश के रहते हैं।

अनु० 394—पाई साक्ष्य जो प्रथम न्यायालय में साक्ष्य-रूप में स्वीकृत या प्रयुक्त किया गया हो, कोसो अपील के न्यायालय में भी साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

अनु० 395—जब कोसो अपील का कोई प्रारम्भ-पत्र विधि या अध्यादेश द्वारा विहित प्रपत्र के अनुसार न दिया गया हो या कोसो अपील करने के अधिकार की समाप्ति के बाद दिया गया हो तो कोसो अपील का न्यायालय निर्णय द्वारा इसे खारिज कर देगा।

अनु० 396—जहाँ अनुच्छेद 377 से 383 तक के अनुच्छेदों में विहित कोसो अपील के आधारों (grounds) में से कोई न हो तो इसे एक निर्णय द्वारा खारिज कर दिया जायगा।

अनु० 397—जहाँ अनुच्छेद 377 से 383 तक के अनुच्छेदों में विहित कोसो अपील के आधारों में से कोई हो तो एक निर्णय द्वारा मूल निर्णय (original judgment) खण्डित कर दिया जायगा।

अनु० 398—जबकि मूल निणय का इस आधार पर खण्डित करना हो कि मूल न्यायालय (original court) ने अपन को अवैध रूप से अक्षम (incompetent) घोषित किया अथवा लाक-बायवाही का अवैध रूप से खारिज कर दिया तो वह अभियोग एक निणय द्वारा पुन मूल न्यायालय को वापस भेज दिया जायगा ।

अनु० 399—यदि मूल निणय का इस आधार पर खण्डित करना हो कि न्यायालय ने अवैधरूप से अपन का प्रमत्ताक्षम (competent) समझ लिया था वह अभियोग एक निणय के द्वारा बिना समयासी के प्रथम न्यायालय में अन्तर्गत कर दिया जायगा । तथापि उस अभियोग पर यदि कोसो अपाल के न्यायालय का प्रथम न्यायालय का अधिकार-पत्र प्राप्त हो तो वह उस अभियोग पर प्रथम न्यायालय के रूप में प्रचार (try) करेगा ।

अनु० 400—जब कि मूल निणय को पिछड़ा या अनुच्छेदों में उल्लिखित आधारों में भिन्न बिना आधार पर खण्डित करना हो तो वह अभियोग या तो मूल न्यायालय का पुन वापस कर दिया जायगा या एक निणय द्वारा मूल न्यायालय का हा काटि के अथ किसी न्यायालय में अन्तर्गत कर दिया जायगा । तथापि यदि न्यायालय यह समझ कि वह मूल न्यायालय या अपील-न्यायालय द्वारा परागित (transmitted) एक प्रस्तुत अभिलेखा (record) एक माहत्या के आधार पर अविलम्ब निणय दे सकता है तो वह उस अभियोग पर निणय दे सकता है ।

अनु० 401—उस दशा में जब कि मूल निणय (original judgment) का अभियुक्त के लाभ के लिए खण्डित किया जाय तो एस निणय का उस सहाभियुक्त (co accused) के लिए भी खण्डित किया जायगा जिसने कोसो अपाल किया हो यदि खण्डित करने का आधार (ground) उस सहाभियुक्त के सबब में भी समान हो ।

अनु० 402—उस अभियोग में जिसमें अभियुक्त द्वारा या उसके नाम के लिए कोसो अपील की गई हो तो मूल निणय द्वारा आरोपित दण्ड से गुरुतर दण्ड को घापणा नहीं की जायगी ।

अनु० 403—उस दण्ड में जब कि कोई मूल न्यायालय लाक-बायवाही को खारिज करने वाली किसी व्यवस्था को जारी करने में अवैध रूप से असमर्थ रहे तो लाक-बायवाही एक व्यवस्था द्वारा खारिज की जायगी ।

जहाँ तक पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था का संबंध है अनुच्छेद 385 परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ, यथाचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगी।

अनु० 404—इस संहिता (Code) में अन्यथा विहित दशा का छोड़कर, दूसरे खण्ड (Book II) में प्रतिपादित लान-विचारण (public trial) से संबंध व्यवस्थाएँ, यथाचित परिवर्तन के साथ, कोसो अपील के विचारण के संबंध में लागू होंगी।

अध्याय 3

जोकोकु अपील (Jokoku Appeal)

अनु० 405—जोकोकु अपील प्रथम या द्वितीय न्यायालय (first or second instance) में किसी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध निम्नांकित दशाओं में की जा सकती है

- (1) इस आधार पर कि सविधान का उल्लंघन हुआ है अथवा सविधान के निर्माण, अर्थनिश्चय या विनियम (प्रयुक्ति) में त्रुटि (error) हुई है,
- (2) इस आधार पर कि उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व स्थापित न्यायिक दृष्टान्तों (judicial precedents) में असंगत कोई निर्णय किया गया है,
- (3) उन अभियोगों में, जिनके लिए उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायिक दृष्टान्त (judicial precedent) न हो, इस आधार पर कि पूर्ववर्ती उच्चतम न्यायालय (दइ शिन इन) द्वारा अथवा जोकोकु अपील न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा अथवा इस संहिता (Code) के प्रवर्तन (enforcement) के बाद कोसो अपील न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व स्थापित न्यायिक दृष्टान्तों (judicial precedents) में असंगत (in-compatible) निर्णय किया गया है।

अनु० 406—जोकोकु अपील के न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय, न्यायालय नियमों के अनुसार, बिन्ही भी वैसे अभियोगों को, उनके मूल-

निर्णय व अन्ततः बाध्यकारी (finally binding) हान के पक्ष ही ले सजता है जिन्हें वह समझ कि उनमें विधि या अध्यादेश के निर्माण-संबंधी महत्वपूर्ण समस्या अन्तर्हित है चाहे व वैसे अभियोग न हो जिनकी जोरोंपु अपील पिछले अनुच्छेद के अंतर्गत की जा सके।

अनु० 407—जोकोकु अपील व हेनुआ व विवरण में न्यायालय नियमा के अनुसार अपील के आधार (ground) का निर्देश विनियम रूप में रहेगा।

अनु० 408—जहाँ जोकोकु अपील के न्यायालय का जोकोकु अपील व हेनुआ के विवरण एवं अन्य प्रलेख (documents) की जाँच करने के बाद, यह पता लग जाय कि अपील निर्विवाद (unassailable) नहीं है तो वह एक निर्णय द्वारा मौखिक वापदाहिवा का दिना आयोजन किये ही अपील का सार्वजनिक कर सकता है।

अनु० 409—जोकोकु अपील के न्यायालय के लिए लाव विचारण की दिधि पर अभिवृत्त का समन करना आवश्यक नहीं है।

अनु० 410—यदि जोकोकु अपील के न्यायालय का यह ज्ञान हो जाय कि अनुच्छेद 405 के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विहित सज्जित करने (quashing) के आधार में सबाई है तो वह मूत्र निर्णय का एक निर्णय द्वारा सज्जित कर देगा। तथापि यह लागू नहीं होगा यदि आधार की सत्ता निर्णय को एतदम प्रभावित न करे।

पिछले परिच्छेद उग दगा में लागू नही होगा जहाँ यद्यपि जहाँ तब अनुच्छेद 405 के प्रमाण 2 और 3 की प्रयुक्ति (application) का सबब है मत्र निर्णय को सज्जित करने के कुछ आधार मिलते हैं। तथापि जोकोकु अपील का न्यायालय मूत्र निर्णय का सज्जित करने के बदले प्रस्तुत याचिका दृष्टान्त (judicial precedent) का भय करना या बदला अधिन उचित समझता हो।

अनु० 411—चाहे अनुच्छेद 405 के किसी भी प्रमाण में विहित कोई भी आधार न हो यदि जोकोकु अपील का न्यायालय निम्नांकित कारणों से मूत्र निर्णय को सज्जित न करना न्यायतः असंगत समझे तो वह एक निर्णय द्वारा उसे सज्जित कर सकता है।

(1) जब कि विधि या अध्यादेश के निर्माण (construction) अथवा निबचन (interpretation) या प्रयुक्ति (application) में

कोई मूल (mistake) रह गई हो जो निर्णय में महत्वपूर्ण (material) हो।

- (2) जब कि दण्ड निनान्त अन्यायपूर्ण एवं अनुचित रूप से लगाया गया हो,
- (3) जब कि तथ्या के अनुसंधान में कोई घोर त्रुटि (gross error) हो जा निर्णय में महत्वपूर्ण हो,
- (4) जब कि कार्यवाही के पुनर्विचार (संश्लेष) का समर्थन करने वाला वाद हेतु हो,
- (5) जब कि मूल निर्णय दिए जाने के बाद, दण्ड का परिहार (abolition) या परिवर्तन कर दिया गया हो, या सामान्य राज-क्षमा (general amnesty) की घोषणा की गई हो।

अनु० 412 जब मूल-निर्णय का इस आधार पर खण्डित करना हो कि न्यायालय ने अवैध रूप में अपने का क्षमताक्षेत्र (competent) मान लिया था तो वह अभियोग एक निर्णय द्वारा, क्षमताक्षेत्री कोसो अपील न्यायालय या क्षमताक्षेत्री प्रथम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जायगा।

अनु० 413—जब कि मूल-निर्णय को, पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित आधारों में भिन्न आधार पर खण्डित करना हो तो वह अभियोग एक निर्णय द्वारा, या तो मूल-न्यायालय (original court) या प्रथम-न्यायालय में वापस भेज दिया जायगा या इन्हीं न्यायालयों के तुल्य कोर्ट के किसी अन्य न्यायालय में अन्तर्हित कर दिया जायगा। तथापि, यदि जोकोकु अपील का न्यायालय समझे कि वह, मूल-न्यायालय या प्रथम-न्यायालय द्वारा जांच किए गए एक पूर्व प्रस्तुत साक्ष्यों तथा अभिलेखों के आधार पर, अविवक्षित निर्णय दे सकता है तो वह उस अभियोग पर निर्णय दे सकता है।

अनु० 414 इस संहिता में अन्यथा विहित दंडों को छोड़कर, पिछले अध्याय को व्यवस्थाओं यथोचित परिवर्तन के साथ, जोकोकु न्यायालय के विचारण के मंत्र में लागू होगी।

अनु० 415—अपने निर्णय के अन्तर्विषयों (contents) में त्रुटि पाने पर जोकोकु अपील का न्यायालय लोक-समाहर्ता या अभियुक्त या उसके परामर्शदाता के निवेदन पर, अन्य निर्णय द्वारा उसका मशौघन कर सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन, निर्णय के उद्घाटन के दिन के बाद दस दिन के अन्दर किया जायगा ।

जोकोकु अपील का न्यायालय, यदि उचित समझे इस अनुच्छेद के प्रथम परिच्छेद में उल्लिखित व्यक्तियों के निवेदन पर पिछले परिच्छेद द्वारा निर्धारित अवधि का बढ़ा सकता है ।

अनु० 416—औचित्य कारणवाही बिना किये ही सशायन के लिये निर्णय दिया जा सकता है ।

अनु० 417—जोकोकु अपील का न्यायालय, उस दशा में जब कि वह सशायन (amendment) के लिये निर्णय न दे एक व्यवस्था द्वारा, निवेदन को अविश्वस्य अस्वीकृत कर देगा ।

अनुच्छेद 415 के परिच्छेद 1 के चल पर सशायन के निर्णय के विरुद्ध फिर कोई निवेदन प्रस्तुत नहीं किया जायगा ।

अनु० 418—जोकोकु अपील के न्यायालय का निर्णय, अनु० 415 में उल्लिखित अवधि को समाप्ति पर अथवा जहाँ इसी अनुच्छेद के परिच्छेद 1 के अनुसार कोई निवेदन किया गया हो उस दशा में सशायन के लिये निर्णय दिये जान या निवेदन अस्वीकृत करने वाली व्यवस्था के निर्णय दिये जान पर अन्ततः बाध्यकारी हो जायगा ।

अध्याय 4

कोकोकु अपील

(Kokoku Appeal)

अनु० 419—उन अभियोगों का छाहकर, जिनमें यह विशेषतः विहित है कि एक आसन्न (immediate) कोकोकु अपील की जा सकती है, किसी न्यायालय द्वारा जारी की गई व्यवस्था के विरुद्ध, इस सहिता (Code) में अन्यथा विहित दशा को छाहकर कोकोकु अपील की जा सकती है ।

अनु० 420—किसी न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र या सार्यवाहियों से सबद्ध, निर्णय से पहले की गई व्यवस्था के विरुद्ध केवल उन अभियोगों को छोड़

कर, जिनमें यह विशेषतः विहित है कि आसन्न कोकोकु अपील की जा सकती है, वहाँ कोकोकु अपील नहीं की जायगी।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ निराध, जमानती निर्मुक्ति, अभिगृहीत वस्तुआ के अभिग्रहण या प्रत्यावर्तन (restoration) सबकी व्यवस्था या विशेषज्ञ साक्ष्य (expert evidence) के लिये आवश्यक परिचायनवर्षी व्यवस्था के संवध में लागू नहीं होगी।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाआ के रहत हुए भी, किसी निराध के विरुद्ध, इस आधार पर कि अपराध का सबूत नहीं है, वहाँ कोकोकु अपील नहीं की जायगी।

अनु० 421—आसन्न (immediate) कोकोकु अपील का छाडकर, कोकोकु अपील किसी भी समय की जा सकती है तथापि वह उम दशा में लागू नहीं होगा जब कि मूल-व्यवस्था का निरसित (cancelled) नगने में कोई वास्तविक लाभ न हो।

अनु० 422—आसन्न कोकोकु अपील के लिए विहित अवधि तीन दिन की होगी।

अनु० 423—कोकोकु अपील मूल-न्यायालय (original court) का एक लिखित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए की जायगी।

मूल-न्यायालय, यह जान लेने पर कि कोकोकु अपील सुदृढ आधार (well-founded) पर है, व्यवस्था की घुटि (error) का टीका कर देगा। उस दशा में जब कि वह कोकोकु अपील के पूरे या किसी अंश का निराधार (groundless) पावे, लिखित प्रार्थनापत्र को, उसमें मलग्न लिखित समलिया (written opinions) के साथ, कोकोकु अपील के न्यायालय में, प्रार्थना-पत्र पाने के दिन के बाद तीन दिन के अन्दर, भेज देगा।

अनु० 424—आसन्न कोकोकु अपील को छाडकर, (सामान्य) कोकोकु अपील में निर्णय के निष्पादन को निलम्बित करने का प्रभाव (effect) नहीं होगा। तथापि, मूल न्यायालय, एक व्यवस्था द्वारा, निष्पादन को तब तक के लिये निलम्बित कर सकता है जब तक कि कोकोकु अपील पर याय-निर्णय न दे दिया जाय।

कोकोकु अपील का न्यायालय, एक व्यवस्था द्वारा, निर्णय को निलम्बित कर सकता है।

अनु० 425—आमन्त बौद्धिक अपील के लिए विहित अवधि में, एवं जब वास्तु अपील की जा चुकी हो, निर्णय का निष्पादन निलम्बित कर दिया जाएगा ।

अनु० 426—बौद्धिक अपील का निम्नलिखित करने वाली व्यवस्थाया (provisions) के प्रतिकूल रूप में की गई बौद्धिक अपील अथवा यदि कोई बौद्धिक अपील निगूणार (groundless) हो तो वह एक व्यवस्था द्वारा खारिज कर दी जायगी ।

यदि बौद्धिक अपील मुद्रित आधार पर हो तो मूलव्यवस्था (original ruling), एक व्यवस्था (ruling) द्वारा निर्गमित कर दी जायगी, और आवश्यकतानुसार, फिर से नया निर्णय दिया जायगा ।

अनु० 427—बौद्धिक अपील के व्यापारिक के विरुद्ध, फिर वार्ड बौद्धिक अपील नहीं की जायगी ।

अनु० 428—किसी उच्च न्यायालय की व्यवस्था के विरुद्ध वार्ड बौद्धिक अपील नहीं की जायगी ।

उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई व्यवस्था पर, जिसके विरुद्ध विशेष व्यवस्थाया (special provisions) द्वारा आमन्त बौद्धिक अपील विहित हो अथवा जिसके विरुद्ध अनुच्छेद 419 एवं 420 के अन्तर्गत बौद्धिक अपील की जा सके, उच्च न्यायालय में आपत्ति (objection) की जा सकती है ।

बौद्धिक अपील में सबद्ध व्यवस्थाएँ यथाचित परिवर्तन के साथ, निम्नलिखित पत्रिका में उल्लिखित आपत्ति के अवध में लागू होंगी । आमन्त बौद्धिक अपील से सबद्ध व्यवस्थाएँ (provisions), यथाचित परिवर्तन के साथ उन व्यवस्था (ruling) की आपत्ति के अवध में लागू होंगी जिसके विरुद्ध आमन्त (immediate) बौद्धिक अपील विशेष व्यवस्थाया (special provisions) द्वारा विहित हो ।

अनु० 429—निम्नलिखित निर्णयों में से किसी पर अमरुष्ट वार्ड व्यक्ति, निर्णय के विच्छेदन (rescission) या परिवर्तन (alteration) के लिये, यदि निर्णय निम्न-न्यायालय द्वारा दिया गया हो तो जिला-न्यायालय में, जिसके अधिकारक्षेत्र में वह अभिवाग हो, अथवा यदि उच्चतर न्यायालय के किसी

न्यायाधीश द्वारा दिया गया हो तो उस न्यायालय में, जिसका वह न्यायाधीश हो, निवेदन (request) कर सकता है —

- (1) आपत्ति के प्रस्ताव (motion) को स्वीकार करने वाला निर्णय (decision),
- (2) निरोध, जमानती निर्मुक्ति, अभिग्रहण या अभिगृहीत वस्तुओं (seized articles) के प्रत्यावर्तन (restoration) में सबद्ध निर्णय,
- (3) विशेषज्ञ साक्ष्य (expert evidence) के लिये परित्राध (confinement) का आदेश करने वाला निर्णय,
- (4) अदाण्डित अर्थदण्ड (non-penal fine) लगाने वाला या किसी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, अर्थनिर्वाचक या अनुवादक के व्ययों (expenses) के प्रतिफल (compensation) का आदेश करने वाला निर्णय,
- (5) अदाण्डित अर्थदण्ड लगाने वाला या किसी व्यक्ति के व्यय के प्रतिफल का आदेश करने वाला निर्णय, जिसके शरीर की जांच होने वाली हो,

अनुच्छेद 420 परि० 3 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद में विहित निवेदन के सबध में लागू होगी।

पहले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन प्राप्त करने वाला जिला-न्यायालय या परिवार-न्यायालय किसी सहयोगी-न्यायालय (collegiate court) द्वारा एक व्यवस्था बनवाएगा।

पछले परिच्छेद के प्रभाग 4 या 5 में उल्लिखित निर्यात के विच्छेदन (rescission) या परिवर्तन (alteration) के लिये निवेदन उक्त निर्णय दिये जाने के दिन के तीन दिन के अन्दर, किया जायगा।

पिछले परिच्छेद के निवेदन के लिये विहित अवधि में एक उक्त निवेदन दिये जाने पर, निर्णय का निष्पादन निलम्बित रखा जायगा।

अनु० 430—प्रत्येक व्यक्ति, जिसे अनुच्छेद 39, परिच्छेद 3 में उल्लिखित कारंवाइयो अथवा अभिग्रहण या अभिगृहीत वस्तुओं के प्रत्यावर्तन (restoration) से सबद्ध कारंवाइयो पर, जो किसी लोक-समाहर्ता या लोकममाहर्ता-

कोकोतु के मन्त्रि द्वारा चारा का गद हा बाद आपति (objection) हो उक्त न्यायालय या मन्त्रि के लोकमाला-न्यायालय में सबद न्यायालय में उन कारवाइया के विमर्शन (cancellation) या परिवर्तन (alteration) के लिये निवेदन कर सकता है।

प्रत्येक व्यक्ति जिस पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कारवाइया पर जा किमा न्यायिक पुनर्निर्माण-कारवाइया द्वारा चारा का गद हा बाद आपति हा उन कारवाइया के विमर्शन या परिवर्तन के लिये उस निगम-न्यायालय या निगम-न्यायालय में निवेदन कर सकता है जिसके अधिकार-क्षेत्र में वह स्थान आता है जहाँ पर उक्त न्यायिक पुनर्निर्माण कारवाइया आय करता है।

प्रशासनिक कारवाइया (administrative litigation) से सबद किनि एवं अध्यादेश का व्यवस्थाए पिछले दो परिच्छेदों में उल्लिखित निवेदन के मन्त्र में लागू नहीं होगा।

अनु० 431—पिछले दो अनुच्छेदों में उल्लिखित निवेदन किनि अप में किमा समन्ताना न्यायालय (competent court) में किये जायेंगे।

अनु० 432—अनुच्छेद 421 426 और 427 की व्यवस्थाएँ (provisions) यथाचिन्त परिवर्तन के साथ उन दंगा में लागू होगा जहाँ अनुच्छेद 429 और 430 में उल्लिखित निवेदन किये गए हैं।

अनु० 433—उस व्यवस्था या आदेश (order) के विरुद्ध जिस पर हम सहिता में बाद आपति किनि नग है अनुच्छेद 405 में किनि किमा हु के लिये के आधार (ground) पर उच्चतम न्यायालय में कोकोतु अपील का जा सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कोकोतु अपील के लिये किनि अवधि पाँच दिन का होगा।

अनु० 434—अनुच्छेद 423 424 और 426 का व्यवस्थाएँ (provisions), यथाचिन्त परिवर्तन के साथ हम सहिता में अध्यादेश किनि दंगा का छाडकर पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 में उल्लिखित कोकोतु अपील के मन्त्र में लागू होगा।

चौथा खण्ड

कार्यवाही का पुनर्विचार

(Reopening of Procedure)

अनु० 435—निम्नांकित दस्तावेजों में कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन उस व्यक्ति के हित के लिए किया जा सकता है जिसके विरुद्ध "दोषिता" ("guilty") का बार्ड निर्णय अन्ततः बाध्यकारी हो चुका हो।

- (1) जब कि लेख्यसाक्ष्य (documentary evidence) या साक्ष्य के जमा, जिन पर मूल-निर्णय आधारित था, अन्य अन्ततः बाध्यकारी निर्णय द्वारा जाली (forged) या परिवर्तित (altered) सिद्ध हो चुके हों,
- (2) जब कि बार्ड मौखिक साक्ष्य (testimony), विशेष-मामति (expert opinion), अर्थ-निर्देशन या अनुवाद, जिन पर कि मूल निर्णय आधारित था, अन्य अन्ततः बाध्यकारी निर्णय द्वारा गलती (false) सिद्ध हो चुका हो,
- (3) जब कि किसी दोषी (guilty) घोषित व्यक्ति के विरुद्ध किए गए मिथ्या अभियोग (false accusation) का अपराध अन्य अन्ततः बाध्यकारी निर्णय द्वारा प्रमाणित किया जा चुका हो, तथापि यह केवल उन्हीं दस्तावेजों में लागू होगा जहाँ "दोषिता" का निर्णय उक्त मिथ्या अभियोग के ही कारण दिया गया हो,
- (4) जब कि विनिश्चय (decision), जिन पर कि मूल-निर्णय आधारित था, एक अन्ततः बाध्यकारी विनिश्चय द्वारा परिवर्तित कर दिया गया हो,
- (5) जब कि किसी अभियोग में, जिसमें किसी एकत्र अधिकार (patent right), उपयोगिता-आदर्श अधिकार (utility model right) अभिव्यक्ति अधिकार (design right), या व्यापार-टाप अधिकार (trade-mark right) के अतिक्रमण (infringing) के

आधार पर 'दायिता का निणय दिया जा चुका है। उक्त अधिकारी का प्रभावहीन करता हुआ एक्स्क्वायज़र (Patent Officer) का वाइ विनिशिय (division) अन्तर्गत बाध्यकारी है। चूँकि हा अथवा निम्न न्यायालय द्वारा ऐसा ही (उक्त अधिकारी का प्रभावहीन करने वाला) निणय दिया गया है।

(6) तब कि ऐसा स्पष्ट साक्ष्य (clear evidence) नवाविष्कृत (newly discovered) हो कि किसी दायी घोषित व्यक्ति के संबंध में 'निर्दोषता' ('not guilty') या विमुक्ति (acquittal) का निणय दिया जाय अथवा किसी दायित (condemned) व्यक्ति के संबंध में दण्ड क्षमा (remission) का निणय दिया जाय अथवा मूल निणय द्वारा प्रतिपादित अपराध न होना (lighter) अपराध मान लिया जाय।

(7) जब कि किसी अन्तर्गत बाध्यकारी निणय द्वारा यह प्रमाणित हो जाय कि मूल निणय में भाग लेने वाले न्यायाधीश या मूल निणय के आधारभूत दस्तावेजों के निर्माण में भाग लेने वाले न्यायाधीश या मूल निणय के आधारभूत साक्ष्य प्रलेख (extrajudicial document) या कथन (statements) को तैयार करने वाले लोक-समाहता लोक-समाहता कार्यलय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा कार्यालयीय कार्यों (official functions) के संबंध में किए गए अवगत रहे हैं। तथापि यह केवल वहीं लागू होगा जहाँ उस देश में तब कि उक्त न्यायाधीश लोक-समाहता लोक-समाहता कार्यलय के सचिव अथवा न्यायिक पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध मूल निणय दिए जाने के पूर्व ही कोई लोक-समाहता (public action) की गई हो मूल निणय देने वाला न्यायालय उक्त तथ्य से अनभिज्ञ रहा हो।

अनु० 436—निम्नांकित दशाओं में किसी अन्तर्गत बाध्यकारी निणय के विरुद्ध जिसके द्वारा किसी अपील या जोकोकु अपील सारित्र की गई है। उस व्यक्ति के हित के लिए जिसने प्रति निणय दिया गया हो कार्यवाही के पुनर्विचार के लिए निवेद किया जा सकता है।

- (1) यदि पिछले अनुच्छेद के प्रभाग 1 या 2 में उल्लिखित हेतु (causes) मिलने हों,
- (2) यदि पिछले अनुच्छेद के प्रभाग 7 में उल्लिखित हेतु उस न्यायाधीश के मस्य में मिलने हों जिसने मूल-निर्णय या मूल-निर्णय में माध्य के रूप में अंगीकृत लेख्य-माध्य (documentary evidence) की तैयारी (preparation) में भाग लिया हो।

किसी अभियोग पर, जिसमें प्रथम न्यायालय में, अन्ततः बाध्यकारी निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन किया गया था, कार्यवाही के पुनर्विचार का निर्णय दिए जाने के बाद, जोरों-जोरों को खारिज करने वाले निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन नहीं किया जाएगा।

किसी अभियोग पर जिसमें प्रथम या द्वितीय न्यायालय में किसी अन्ततः बाध्यकारी निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन किया गया था कार्यवाही के पुनर्विचार का निर्णय दिए जाने के बाद, जोरों-जोरों को खारिज करने वाले निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन नहीं किया जाएगा।

अनु० 437—जब किसी अभियोग में ऐसा अन्ततः बाध्यकारी निर्णय पाना असंभव हो जिसमें, पिछले दो अनुच्छेदों के अनुसार, किसी अन्ततः बाध्यकारी निर्णय द्वारा प्रमाणित किए गए किसी अपराध का कोई तथ्य (fact, कार्यवाही के पुनर्विचार का हेतु बनाया जाय तो उक्त तथ्य का प्रमाणित करने पर कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन किया जा सकता है। तथापि, यह उस अभियोग के सम्बन्ध में नहीं लागू होगा जिसमें ऐसा अन्ततः बाध्यकारी निर्णय, माध्य के अभाव (lack of evidence) के कारण न पाया जा सके।

अनु० 438—कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन मूल-निर्णय देने वाले न्यायाध्य के अधिकार-क्षेत्र (jurisdiction) में आएगा।

अनु० 439—निम्नांकित व्यक्ति कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन कर सकते हैं

- (1) (क्षमताहीन या अशक्त न सन) का-अमान्यता
 - (2) दापी घापित किया गया व्यक्ति
 - (3) दापी' घापित किए गए व्यक्ति व वेष प्रतिनिधि एवं पात्र ,
 - (4) 'दापी' घापित किए गए व्यक्ति के पति या पत्नी (heir)
- काय सनधा भाई या बहन यदि वह व्यक्ति मर गया है अथवा विधुन चिनता (unsound mind) का स्थिति में है ।

अनुच्छेद 435 प्रमाण 7 या अनुच्छेद 436 परिच्छेद 1 प्रमाण 2 में उल्लिखित हेतुओं व वर पर कायवाही व पुनर्विचार का निवेदन करने का अधिकार द्वारा किया जा सकता है यदि वह अपराध दापी घापित व्यक्ति द्वारा उतसाया गया (instigated) है ।

अनु० 440—जब का-अमान्यता से निम्न कोई व्यक्ति कायवाही व पुनर्विचार का निवेदन करे तो वह प्रतिवा-अरमगानता (defence counsel) चुन सकता है ।

विच्छेद परिच्छेद की व्यवस्था (provision) व अनुसार प्रतिवाद परामगानता का चुनाव तब तक मान्य (valid) रहेगा जब तक कायवाही व पुनर्विचार में कोई नियम न हो जाय ।

अनु० 441—कायवाही के पुनर्विचार का निवेदन दण्ड निष्पादन (execution of penalty) व पूर किए जाने के बाद भी अथवा जहाँ दण्ड निष्पादित न किया जान वाला हो किया जा सकता है ।

अनु० 442—कायवाही व पुनर्विचार का निवेदन दण्ड व निष्पादन का नहीं रोकेगा । तथापि किसी क्षमताहीन या अशक्त से संबद्ध लोक समाहर्ता-न्यायालय का का-अमान्यता दण्ड के निष्पादन को तब तक व लिए रोक सकता है जब तक कि कायवाही व पुनर्विचार के निवेदन व संबंध में कोई निणय (decision) न दिया जाय ।

अनु० 443—कायवाही के पुनर्विचार का निवेदन वापस लिया जा सकता है ।

वह व्यक्ति जिनका कायवाही के पुनर्विचार का निवेदन वापस लिया हो फिर उसी हेतु (same cause) पर कायवाही के पुनर्विचार का निवेदन नहीं कर सकेगा ।

अनु० ४४४—अनुच्छेद 366 की व्यवस्थाएँ, यद्योचित परिवर्तन के साथ, कार्यवाही के पुनर्विचार के निवेदन एवं प्रत्याहरण (withdrawal) के सबंध में लागू होंगी।

अनु० 445—कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन प्राप्त कर लेने पर, न्यायालय, आवश्यकतानुसार, उस निवेदन के हेतु से संबद्ध तथ्या का अनुसंधान चालू करने के लिए, सहायी-न्यायालय के किसी सदस्य को प्रेरित कर सकता है अथवा इस करने के लिए जिला-न्यायालय, कुटुम्ब-न्यायालय, या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश का अधियाचित कर सकता है। ऐसी दशा में, राजादिष्ट न्यायाधीश या अधियाचित न्यायाधीश का वही अधिकार होगा जो न्यायालय या पीठमोन न्यायाधीश का होता है।

अनु० 446—जब कार्यवाही के पुनर्विचार का बार्द निवेदन विधि या अध्यादेश के प्रपत्र (form) के विरुद्ध अथवा निवेदन करने के अधिकार की समाप्ति (termination) के वाद किया गया हो तो वह एक व्यवस्था के द्वारा मारिज कर दिया जायगा।

अनु० 447—जब कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन निराधार (without grounds) हो तो वह एक व्यवस्था द्वारा मारिज कर दिया जायगा।

विच्छेद परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था के जारी किये जाने के बाद, किसी भी व्यक्ति द्वारा उसी हेतु पर फिर से, कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन नहीं किया जा सकेगा।

अनु० 448—जब कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन सुदृढ़ आधार (well-founded) पर हो तो कार्यवाही के पुनर्विचार को आरम्भ करने के लिये एक व्यवस्था जारी की जायगी।

जब कार्यवाही के पुनर्विचार का आरम्भ करने के लिये कोई व्यवस्था जारी की जा चुकी हो तो दण्ड का निष्पादन, एक व्यवस्था द्वारा रोका जा सकता है।

अनु० 449 जब, किसी अपील मारिज करने वाले अन्ततः वाच्यकारी निर्णय के सबंध में तथा उल्लिखित निर्णय द्वारा अन्ततः वाच्यकारी हुए प्रथम न्यायालय के किसी निर्णय के सबंध में, कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन किये जाने पर प्रथम न्यायालय (court of first instance) ने कार्यवाही

व पुनर्विचार में बाइ निणय दे लिया हो ता जोसो अपा का यायाय एर व्यवस्था द्वारा कायवाही के पुनर्विचार का निवेदन मागि कर दगा ।

जर प्रथम या द्वितीय यायाय व निणय के विरुद्ध जोकोहु अपील खारिज करन वा अतल बाध्यकारी निणय व सत्रम म तथा उक्त निणय द्वारा अन्तत बाध्यकारी हुए प्रथम या द्वितीय यायाय के किसी निणय व सत्रम म कायवाही के पुनर्विचार का निवेदन किय जान पर प्रथम या द्वितीय यायाय न कायवाहा के पुनर्विचार में का निणय दे लिया हा ता जोकोहु अपील का यायाय एक व्यवस्था द्वारा कायवाही के पुनर्विचार का निवेदन खारिज कर दगा ।

अनु० 450 अनुच्छ० 446 447 परिच्छ० 1 अनुच्छ० 448 परिच्छ० 1 अपवा अनुच्छ० 449 परिच्छ० 1 म उल्लिखित व्यवस्था के विरुद्ध आसन जोकोहु अपील की जा सकती ह ।

अनु० 451—उस अभियाग म जिसके संबंध म कायवाही का पुनर्विचार आरम करन के लिए व्यवस्था अन्तत बाध्यकारी हा चुकी हा यायाय अनुच्छ० 449 की दगा को छोडकर अपनी थपी (grade) के अनुसार नय मरे से (year) विचारण करेगा ।

अनुच्छ० 314 के परिच्छ० 1 एवं अनुच्छ० 339 परिच्छ० 1 प्रभाग 3 के निवाय (body) की व्यवस्थाएँ (provisions) निम्नांकित दगाभा में पिछे परिच्छ० म उल्लिखित विचारण (trial) के संबंध में लागू नहीं हागी

- (1) जर रि कायवाही के पुनर्विचार का निवेदन किसी मृत-व्यक्ति (deceased) या विवृत चित्त (unsound mind) व्यक्ति की ओर से किया गया हो जिने ठीक होन की काई आगा न हो
- (2) जर रि दोषी घोषित व्यक्ति कायवाही के पुनर्विचार में बाइ निणय न्य जान के पूव हो मर गया हा या विवृत चित्तता की स्थिति म आ गया हो और उसे ठीक होन की आगा न हा ।

पिछे परिच्छ० की दगा म रिता अभियुक्त की उपसजति (appearance) के विचारण किया जा मस्ता ह । तथापि उसके प्रतिवा परामर्श

दाता (defense counsel) की अनुपस्थिति में विचारण नहीं किया जायगा ।

यदि पिछले परिच्छेद की दशा में कार्यवाही के पुनर्विचार के लिए निवेदन करने वाला व्यक्ति प्रतिवाद-परामर्शदाता नहीं चुनता तो उसके लिये पीठासीन न्यायाधीश पदेन (ex-officio) कोई परामर्शदाता निर्दिष्ट करेगा ।

अनु० 452—कार्यवाही के पुनर्विचार में, मूल-निर्णय में घोषित किये गए दण्ड से गुरुतर (heavier) दण्ड नहीं दिया जायगा ।

अनु० 453—यदि कार्यवाही के पुनर्विचार में ' निर्दोष ' की घोषणा की गई हो तो ऐसे निर्णय का सरकारी राजपत्र (Official Gazette) एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायगा ।

— —

पाँचवाँ खण्ड

अमाधारण अपील

(Extraordinary Appeal)

अनु० 454—जब, किसी निर्णय के अन्तर्गत वाध्यकारी होने के बाद यह ज्ञात हो गया हो कि अभियोग का विचारण (trial) या निर्णय विधि या अध्यादेश के उल्लंघन (violation) में हुआ है तो महा-समाहर्ता (Prosecutor General) उच्चतम न्यायालय में अमाधारण अपील कर सकता है।

अनु० 455—अमाधारण अपील करने में, उसके हेतुओं (reasons) का विवरण वाला एक लिखित प्रार्थनापत्र उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जायगा।

अनु० 456—लाफ़ समाहर्ता लाफ़ विचारण (public trial) की विधि पर लिखित प्रार्थनापत्र के आधार पर बहुत करेगा।

अनु० 457—अमाधारण अपील निराधार होने पर एक निर्णय द्वारा खारिज कर दी जायगी।

अनु० 458—यदि कोई अमाधारण अपील सुदृढ़ आधारों (well-founded) पर समझी जाय तो निम्नांकित वर्गों (categories) के अनुसार निर्णय दिया जायगा

(1) जब कि मूल निर्णय विधि या अध्यादेश के उल्लंघन (violation) में दिया गया हो तो उल्लंघन में आने वाले अंश को खण्डित कर दिया जायगा। तथापि यदि मूल निर्णय अभिप्रेत के लिये अहित-कारक (disadvantageous) रहा हो तो उसे खण्डित कर दिया जायगा और अभियोग पर फिर से (anew) निर्णय दिया जायगा,

(2) जब कोई कार्यवाही विधि या अध्यादेश के उल्लंघन में हो तो उल्लंघन में आने वाली कार्यवाही खण्डित कर दी जायगी।

अनु० 459— पिछले अनुच्छेद के प्रमाण 1 के प्रतिधन्य (provisio) के अन्तर्गत दिए गए निर्णय को छोड़कर, असाधारण अपील में निर्णय का प्रभाव (effect) अभिव्यक्त तब नहीं बढ़ेगा।

अनु० 460 न्यायालय केवल उन्हीं विषयों का अनुसंधान करेगा जो असाधारण अपील के लिखित प्रार्थनापत्र में उक्त रहेंगे।

न्यायालय मूल-न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र (jurisdiction), लोक-कार्यवाही की स्वीकृति (acceptance of public action) एवं अभियोग की प्रक्रिया से संबंधित तथ्यों की जांच कर सकता है। इस दशा में अनुच्छेद 393, परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ, यथाचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगी।

छठा खण्ड

क्षिप्र-प्रक्रिया

(Summary Procedure)

अनु० 461—क्षिप्र-प्रक्रिया, अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी मामले में, लोक-समाहर्ता की माँग पर एक क्षिप्र-आदेश (summary order) द्वारा लोक-विचारण के पूर्व ही पाँच हजार सेन तक का अर्पण या छोटा अर्पण दे सकता है। इन दशा में दण्ड-निष्पादन का निरन्धन, राज्य-मात्करण (confiscation) एवं अन्य महापक कार्रवाइयाँ (accessory-dispositions) की जा सकती हैं।

क्षिप्र-आदेश केवल उसी दशा में दिया जायगा जहाँ लोक-समाहर्ता द्वारा की गई क्षिप्र-आदेश की माँग की अधिमूचना जिस दिन मदिथ की दी गई हो उस दिन से सात दिन बीत चुके हो और मदिथ की आर में क्षिप्र-प्रक्रिया (summary procedure) पर कोई प्राप्ति (objection) न हो।

अनु० 462—क्षिप्र-आदेश की माँग लिखित रूप में लोक-कार्यवाही की मस्थिति (institution) के साथ ही साथ की जायगी।

अनु० 463—यदि, उस दशा में जर कि पिछले अनुच्छेद के अन्तर्गत माँग (demand) की गई हो, ऐसा समझा जाय कि अभियोग क्षिप्र-आदेश जारी किए जाने योग्य नहीं है अथवा ऐसा करना उचित नहीं है तो विचारण सामान्य व्यवस्थाओं (provisions) के अनुसार किया जायगा।

अनु० 464—क्षिप्र-आदेश में, अपराध का घटक तथ्य, प्रयुक्त विधि या अपराध, दण्ड (penalty) एवं की जाने वाली अन्य महापक कार्रवाइयाँ एवं यह वक्तव्य (statement) कि नियमित विचारण (regular trial) के लिए प्रायःना-पत्र, आदेश की अधिमूचना (notification) के दिन से सात दिन के अन्दर दिया जा सकता है, लिखे जायेंगे।

अनु० 465—वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई क्षिप्र-आदेश जारी किया गया हो, या लोक-समाहर्ता, उस (क्षिप्र आदेश) की अधिमूचना मिलने के सात दिन के अन्दर नियमित विचारण के लिए प्रायःना-पत्र दे सकता है।

नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र लिखित रूप में क्षिप्र-आदेश जारी करने वाले न्यायालय में दिया जायगा। नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर, न्यायालय इस तथ्य की अधिसूचना तुरन्त लोक-समाहर्ता या उस व्यक्ति को देगा जिसके विरुद्ध क्षिप्र-आदेश जारी किया गया हो।

अनु० 466—नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र प्रथम न्यायालय (first instance) में कोई निर्णय दिए जाने के पहले वापस लिया जा सकता है।

अनु० 467 अनुच्छेद 353, 355 से 357 एवं 359 से 365 तक की व्यवस्थाएँ प्रयोजित परिवर्तन के साथ, नियमित विचारण (regular trial) के प्रार्थना-पत्र एवं उसके प्रत्याहरण (withdrawal) के सम्बन्ध में लागू होंगी।

अनु० 468—यदि नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र विधियाँ एवं अध्यादेश के प्रपत्र (forms) के विरुद्ध दिया गया हो अथवा प्रार्थना-पत्र देने के अधिकार की समाप्ति (termination) के बाद दिया गया हो तो वह एक व्यवस्था द्वारा खारिज कर दिया जायगा। ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध आसन (immediate) कोकोकु अपील की जा सकती है।

यदि नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र विधि-मगत (legal) समझा जाय तो विचारण सामान्य व्यवस्थाओं के अनुसार चालू किया जायगा।

पिछले परिच्छेद की दशा में क्षिप्र-आदेश बाध्यकारी (binding) नहीं होगा।

अनु० 469—नियमित विचारण के प्रार्थना-पत्र पर कोई निर्णय दिए जाने पर क्षिप्र-आदेश प्रभाव मूल्य हो जायगा।

अनु० 470—क्षिप्र-आदेश के वे ही प्रभाव (effects) होंगे जो नियमित विचारण के प्रार्थना-पत्र देने की अवधि के बीत जाने अथवा प्रार्थनापत्र वापस लेने पर अंतिम निर्णय (irrevocable judgment) के होते हैं। यही उस दशा में भी लागू होगा जहाँ नियमित विचारण के प्रार्थनापत्र को खारिज करने वाला धिनिश्चय (decision) अटल (irrevocable) हो चुका हो।

सातवाँ खण्ड

विनिश्चय का निष्पादन

(Execution of Decision)

अनु० 471—इस संहिता में अन्यथा विहित दसा की छोड़कर, किसी विनिश्चय (decision) का निष्पादन उसके अन्तर्गत बाध्यकारी हो जाने पर किया जायगा।

अनु० 472—विनिश्चय का निष्पादन उस विनिश्चय देने वाले न्यायालय से सबद्ध लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लोक-समाहर्ता द्वारा निदेशित किया जायगा। तथापि, यह अनुच्छेद 70 परिच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 108, परिच्छेद 1 में उल्लिखित प्रतिबन्ध (proviso) की दसा में लागू नहीं होगा और न तो ऐसे अनियामों (uses) के सम्बन्ध में ही जिनमें इसका निदेशन किसी न्यायालय या न्यायाधीन द्वारा किया जाना आवश्यक हो।

उस दसा में, जब कि किसी अरील पर किए गए अथवा अरील की वापसी (withdrawal) पर किए गए विनिश्चय (decision) के परिणाम स्वरूप किसी अवर न्यायालय (inferior court) का कोई विनिश्चय निष्पादित करना हो या अरील के न्यायालय से सबद्ध लोक-समाहर्ता-कार्यालय का लोक-समाहर्ता उसके निष्पादन (execution) को निदेशित करेगा। तथापि, यदि अभियोग के अभिलेख (records) अवर न्यायालय या उस न्यायालय से सबद्ध लोक-समाहर्ता-कार्यालय में हो तो उस न्यायालय से सबद्ध लोक-समाहर्ता-कार्यालय या लोक-समाहर्ता विनिश्चय के निष्पादन को निदेशित करेगा।

अनु० 473—विनिश्चय के निष्पादन को लिखित रूप में निदेशित किया जायगा और इस केस के साथ विनिश्चय के प्रलेख (document of decision) अथवा नयाचार (protocol) की एक प्रति अथवा उसका उद्धरण (extract) जिसमें विनिश्चय अङ्कित हो सम्मन रहेगा। तथापि, निदेश (direction) भी, यदि वह दण्ड के निष्पादन का न हो, विनिश्चय के प्रलेख के मूल या प्रतिलिपि अथवा उद्धरण या नयाचार की प्रति या उसके उद्धरण पर मुद्राक (autograph) लगा कर दिया जा सकता है।

अनु० 474- उस दशा में जब कि अथदण्ड या छोट दण्ड अर्थ के अतिरिक्त दो या अधिक प्रधान दण्ड (principal penalties) हैं तो गुरुतम (दण्ड) को सबसे पहलू निष्पादित किया जायगा। तथापि लाक-समाहर्ता महा-लोक-समाहर्ता (Procurator General) की अनुमति से जब कि वह उच्चतम लोक-समाहर्ता कार्यालय का लोक-समाहर्ता है, अथवा (उच्च लोक-समाहर्ता-कार्यालय के) अधोक्षक समाहर्ता (Superintending Procurator) की अनुमति से जबकि वह उच्चतम लोक-समाहर्ता-कार्यालय से भिन्न किसी (कार्यालय) का लाक-समाहर्ता हो गुरुतर दण्ड के निष्पादन को राक (stay) एवं अन्य दण्ड का निष्पादित करा सकता है।

अनु० 475 प्राण दण्ड का निष्पादन अटार्नी जनरल (Attorney-General) के आदेश के अन्तर्गत किया जायगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित आदेश नियम व अन्तत वाध्यकारी होने के दिन से ॥ मास के अन्दर दिया जायगा। तथापि उन दशाभा में, जहाँ अपील करने के अधिकार की पुन प्राप्ति (recovery of right to Appeal) या वायवाही के पुनविचार का निवेदन (request) किया गया हो अथवा असाधारण अपील या राज-क्षमा (amnesty) की याचिका (petition) या प्राथना-पत्र (application) दिया जा चुका है तो उसकी प्रक्रिया (procedure) के पर्यवसान की अवधि एवं वह अवधि जब तक के लिए सह-प्रतिवादिया पर यदि काई है, घापित नियम अन्तत वाध्यकारी न हो जाय उक्त अवधि में परिवर्तित (calculated) नहीं की जायेंगी।

अनु० 476- अटार्नी जनरल (Attorney General) द्वारा प्राण-दण्ड के निष्पादन का आदेश दिए जाने की दशा में ऐसा निष्पादन पाँच दिन के अन्दर कार्यान्वित किया जायगा।

अनु० 477- प्राण-दण्ड लाक-समाहर्ता, लाक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव, एवं कारागार व सरक्षक (warden of prison) या उसका प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित किया जायगा।

कोई भी व्यक्ति लाक-समाहर्ता या कारागार के सरक्षक की अनुमति के बिना निष्पादन के स्थान (place of execution) में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

local public entities) को खोप देगा तथा किसी चिकित्सालय या अन्य अनुकूल स्थान (suitable place) में रखवा देगा ।

वह व्यक्ति, जिसने दण्ड का निष्पादन रोक दिया गया हो, एक कारागार में तब तक रखा जायगा जब तक कि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित बारंबार कार्यान्वित नहीं कर दी जाती, और इस प्रकार के निराप की अवधि दण्ड की अवधि में सम्मिलित की जायगी ।

अनु० 482—पठारथम-नारावास, नारावास अथवा निरोध का निष्पादन, निम्नांकित दसाओं में, दण्ड घापित करने वाल न्यायालय से सबड लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लोक-समाहर्ता अथवा जिला-लावसमाहर्ता-कार्यालय के, जिसके क्षेत्राधिकार में वह स्थान आता है जहाँ अपराधित व्यक्ति स्थित हो, निवेदन के अधीन, रोक दिया जायगा । तथापि, लोक-समाहर्ता को, यदि वह उच्चतम लोकसमाहर्ताकार्यालय का सदस्य है तो महा-लोकसमाहर्ता की अथवा यदि वह उच्चतम लोकसमाहर्ता-कार्यालय से अन्य का लाव-समाहर्ता हो तो (उच्च लोक-समाहर्ताकार्यालय के) अधीक्षक-समाहर्ता (Superintending Procurator) की अग्रिम अनुमति लेना आवश्यक होगा :

- (1) यदि अपराधित व्यक्ति के स्वास्थ्य में, दण्ड के निष्पादन के फल-स्वरूप गम्भीर ह्रास हो गया है अथवा यह भय हो कि वह जीवित नहीं बचेगा ,
- (2) यदि अपराधित व्यक्ति कम से कम सत्तर वर्ष की आयु का हो ;
- (3) यदि अपराधित महिला एक सौ पचास या इससे अधिक दिनों की गर्भिणी हो ,
- (4) यदि अपराधित महिला के बच्चा प्रसव करने के बाद साठ दिन न बीते हैं ,
- (5) यदि यह आशंका है कि दण्ड के निष्पादन से अप्रतिभायें अलाभ (irretrievable disadvantage) होगा ,
- (6) यदि अपराधित व्यक्ति के महाजनक (grand parents, पिता-मही-पितामह) या माता-पिता कम से कम सत्तर वर्ष की आयु के या विवलाग (crippled) अथवा असाध्य बीमार (seriously ill) हो, और उनकी देख-भाल करनेवाला अन्य कोई सबधी न हो,

(7) यदि अपराधित व्यक्ति के पुत्र (children) या पोत (grand children) संसमाहृता में हों और उनकी देखभाल करने वाला कोई सबधी न हो,

(8) यदि अन्य कोई गम्भीर कारण (serious cause) हो।

अनु० 483—विचारण के खर्चिया (Costs of trial) का वहन करने का आदेश करने वाले विनिश्चय का निष्पादन, अनुच्छेद 500 द्वारा विहित निवेदन (requisition) के लिए नियत अवधि तक मथका उम दसा में जब कि उक्त निवेदन किया जा चुका हो उस पर विनिश्चय के अन्तत बाध्यकारी हो जाने तक के लिये, रोक् दिया जायगा।

अनु० 484—यदि प्राण दण्ड, बठोरधम-कारावास या निरोध के दण्ड से अपराधित व्यक्ति परित्राण में न हो ता लोक-समाहृता उसी दण्ड के निष्पादन के लिये मुलायमा। यदि उक्त बुलावे (calling) के उत्तर में वह उपसमाहृता न हो ता एक सुपुदंगी का प्रादेश (writ of commitment) जारी किया जायगा।

अनु० 485—यदि प्राण दण्ड, बठोरधम-कारावास, कारावास या निरोध के दण्ड से अपराधित व्यक्ति निवृत्त भया हो अथवा उससे निकल अपने की भावना हो ता लोक-समाहृता सुरत एक सुपुदंगी का प्रादेश जारी करेगा अथवा किसी न्यायिक पुलिस अधिकारी को ऐसा करने का आदेश देगा।

अनु० 486—यदि प्राण दण्ड, बठोरधम-कारावास, कारावास या निरोध के दण्ड से अपराधित व्यक्ति का पता (whereabouts) अज्ञात हो तो लोक-समाहृता उच्च छात्र-समाहृता-न्यायालय के किसी अधीक्षक समाहृता (Superintending Procurator) से, उसे कारागार में सीपने का निवेदन करेगा।

इस प्रकार से निवेदित किया गया अधीक्षक समाहृता लोक-समाहृता को अपने जिले में सुपुदंगी का प्रादेश जारी करने का निदेशन देगा।

अनु० 487—सुपुदंगी के प्रादेश में, अपराधित व्यक्ति का नाम, निवास-स्थान एवं आयु, दण्ड का नाम एवं अवधि तथा सुपुदंगी के अन्य विषय लिखित रहेंगे, और इस पर लोक-समाहृता या न्यायिक पुलिस अधिकारी का नाम तथा मुद्रा (सील) रहेगा।

अनु० 488—सुपुदंगी के प्रादेश का वही प्रयोजन होगा जो प्रस्तुति के अधिपत्र (warrant of production) का होता है ।

अनु० 489—प्रस्तुति के अधिपत्र के निष्पादन से सबद्ध व्यवस्थाएँ, यथाचित परिवर्तन के साथ, सुपुदंगी के प्रादेश के निष्पादन के सबन्ध में लागू होंगी ।

अनु० 490—अर्बदण्ड लघु अर्बदण्ड, राज्यसात्करण, अतिरिक्त वसूली (additional collection) अदाण्डिव अर्बदण्ड (non-penal fine), जर्जी (sequestration), विचारण के परिष्वया, परिष्वया के प्रतिवर अथवा अन्तर्निम अदायगी (provisional payment) के आरोप करने वाले (imposing) विनिश्चय का निष्पादन, लाकममाहर्ता के आदेश द्वारा किया जायगा । ऐसे आदेश का वही प्रयोजन होगा जो बन्धन (obligation) के किसी निष्पादनीय हक (executable title) का हाना है ।

दीवानी प्रक्रिया से (civil procedure) से सबद्ध विधि एवं अध्यादेश की व्यवस्थाएँ, यथाचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद में निर्दिष्ट विनिश्चय (decisions) के निष्पादन के साथ में लागू होंगी । तथापि, विनिश्चय की तामीली (service of the decision) निष्पादन के पहले आवश्यक नहीं ।

अनु० 491—बरो (taxes) या अन्य लागों (imposts) अथवा सरकारी एकाधिकारों (monopolies) से सबद्ध विधि या अध्यादेश की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आरंभित राज्यसात्करण (confiscation) या अर्बदण्ड या अतिरिक्त वसूली (additional collection) का निष्पादन, निर्णय के अन्तत वाध्यकारी हो जाने के बाद, अभियुक्त के मर जाने की स्थिति में, उनराधिकार का संपत्ति पर किया जा सकता है ।

अनु० 492—यदि, उस दशा में जब कि कोई न्यायिक व्यक्ति (juridical person) अर्बदण्ड, राज्यसात्करण या अनिरिक्त वसूली से उपराधित किया गया हो और वह न्यायिक व्यक्ति निर्णय के अन्तत वाध्यकारी हो जाने के बाद, समामेलन (amalgamation) द्वारा समाप्त (extinguish) हो गया हो तो समामेलन के बाद जो न्यायिक व्यक्ति कार्य करता हो या जो समामेलन द्वारा बनाया गया हो उस पर दण्ड का निष्पादन किया जायगा ।

अनु० 493—यदि, उस दशा में जब कि प्रथम या द्वितीय न्यायालयों में

अनन्तिम अदायगी (provisional payment) के विनिश्चय किए गए हैं, प्रथम न्यायालय का विनिश्चय (decision) निष्पादित किया जा चुका है तो ऐमा निष्पादन द्वितीय चापराय के विनिश्चय के लिए धन की राशि के उस परिमाण तक समान जायगी जितना द्वितीय चापराय के विनिश्चय द्वारा जमा करने का आदेश दिया गया है।

पिछले परिच्छेद की दशा में जब प्रथम चापराय में आन्तिम अदायगी के विनिश्चय के निष्पादन द्वारा प्राप्त धनराशि का परिमाण उस विनिश्चय द्वारा द्वितीय चापराय में जमा की जाने के लिए आदिष्ट धनराशि के परिमाण से बड़ा जाय तो अधिक परिमाण का वापसी (reimbursed) कर दी जायगी।

अनु० 494—यदि अनन्तिम अदायगी के विनिश्चय के निष्पादन के बाद किसी अपराध में अपराध या अतिरिक्त समूची के विनिश्चय अन्तः प्राप्यकारी है गया है तो जमा किए गए परिमाण तक दण्ड निष्पादित समाना जायगा।

पिछले परिच्छेद की दशा में जब अनन्तिम अदायगी के विनिश्चय के निष्पादन द्वारा धनराशि का परिमाण अपराध में अपराध, या अतिरिक्त समूची के परिमाण से बड़ा जाय तो अधिक परिमाण की वापसी कर दी जायगी।

अनु० 495—अपील के लिए बिहिन अवधि में निरोध के दिना की तद्वत् अपील के प्राथनापत्र के द्वारा निरोध द्वारा लम्बित निषेध (detention pending judgment) के दिनों की तद्वत् का छाड़कर नियत दण्ड (regular penalty) के परिचयन में सम्मिलित की जायगी।

अपील के प्राथनापत्र के द्वारा निरोध द्वारा लम्बित निषेध के दिनों की मात्रा निम्नांकित दशाओं में नियत दण्ड के परिकलन (calculation) में सम्मिलित की जायगी

- (1) उस अभियोग में जिसमें अपील के लिए प्राथनापत्र लोक-समाहर्ता द्वारा दिया गया हो
- (2) उस अभियोग में जिसमें अपील के लिए प्राथनापत्र लोक-समाहर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया हो और अपीलीय क्षत्राधिकार सप्त न्यायालय (court of appellate jurisdiction) द्वारा मूत्र निषेध खण्डित कर दिया गया हो।

पिछले दो परिच्छेदों के अनुसार परिवर्तन के लिए, निरोध द्वारा लम्बित निर्णय का एक दिन, दण्डित अवधि (penal term) के एक दिन या बीस येन की राशि के बराबर गिना जायगा।

अपीलीय क्षेत्राधिकार-संपन्न न्यायालय द्वारा मूल-निर्णय तण्डित किए जाने के बाद कार्यान्विता निराध का, अपील के लम्बन (pendency) की अवधि में निराध के दिना की सख्या की तरह परिवर्तन में सम्मिलित किया जायगा।

अनु० 496—राज्यमात्वरण में लिए गए माला का लाक-समाहर्ता द्वारा बेच दिया जायगा।

अनु० 497—यदि, राज्यमात्वरण के निष्पादन के बाद तीन मास के अन्दर अधिकारी व्यक्ति द्वारा राज्यसात्कृत माला (confiscated goods) को लौटाने की माँग (demand) की जाय तो लाक-समाहर्ता, विनष्ट किए जाने अथवा दूर फेंके जाने वाले माला को छाड़कर, उन्हें वापस दे देगा।

यदि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित माँग (demand) राज्यमात्वरण में लिए गए माला के बेचे जाने के बाद की गई हो तो लाक-समाहर्ता लाक-विभय (public sale) में प्राप्त आगम (proceeds) को वापस दे देगा।

अनु० 498—उस दशा में जब कि कोई जाली (forged) या परिवर्तित (altered) वस्तु वापस दी गई हो तो उस वस्तु पर ही उसके जाली या परिवर्तित अंश का निर्देश किया जायगा।

उस दशा में जब कि कोई जाली या परिवर्तित वस्तु का अभिग्रहण न किया गया हो तो इसे प्रस्तुत कराया जायगा और पिछले परिच्छेद में निर्दिष्ट उपाय (measures) किए जायेंगे। तथापि, यदि वह वस्तु किसी लाक-कार्यालय की है तो उसके जाली या परिवर्तित अंश की सूचना उस कार्यालय को दी जायगी और उचित कार्रवाई कराई जायगी।

अनु० 499—उस दशा में जब कि अभिग्रहीत माल (goods under seizure), जिसे वापस करना हो ऐसे अधिकारी व्यक्ति का पता अज्ञात रहने या अन्य कारण से वापस न किया जा सके तो लाक-समाहर्ता इस तथ्य की सार्वजनिक सूचना (public notice) सरकारी राजपत्र (Official Gazette) में देगा।

पिछले तीन अनुच्छेदों में उल्लिखित प्रावदनों (motions) एवं उनके प्रत्याहरण (withdrawal) के संबंध में लागू होगी।

अनु० 504 अनुच्छेद 500 में 502 तक के अनुच्छेदों में उल्लिखित प्रावदनों (motions) के संबंध में जागे वो गई व्यवस्था विरुद्ध, आसन के (immediate) फोबोको अपील की जा सकती है।

अनु० 505—जिसी अथदण्ड या लघु अथदण्ड की पूरी अदायगी न कर सकने की दशा में जहाँ तक किसी निवृत्त-निवेदन (work-house) में निराप के निष्पादन का संबंध है, दण्ड के निष्पादन में सबूत व्यवस्थाएँ, यथाचित परिवर्तन के साथ लागू होंगी।

अनु० 506 अनुच्छेद 490, परिच्छेद 1 में निर्दिष्ट विनिश्चयों में किसी भी विनिश्चय के निष्पादन के खर्च (costs of execution) उस व्यक्ति में वसूल किए जायेंगे, जिस व्यक्ति पर उस निष्पादन का उद्ग्रहण किया गया हो और निष्पादन के साथ ही साथ दीवानी प्रक्रिया (civil procedure) में गण्य विधि एक अध्यादेश की व्यवस्थाओं के अनुसार, वसूल किया जायगा।

अनुपूरक उपबन्ध :

(Supplementary Provisions)

यह सहित जनवरी 1, 1949 से लागू होंगी।

— — —

शब्दावली

अक्षम	incompetent	अनुपूरक	supplemen-
अक्षुण्ण	inviolate		tary
अग्नि काण्ड	arson	अनुपूरक उपबन्ध	supplimen-
अटल निर्णय	irrevocable		tary pro-
	judgment		visions
अतिचार	trespass	अनुवाद	translation
अतिरिक्त	additional	अनुमन्थान	investiga-
अतिरिक्त दण्ड	additional		tion
	penalty	अनूहा-गमन	fornication
अदाण्डिक अर्थदंड	non-penal	अनेकापराध	Heigozai
	fine	अन्ततः बाध्य-	finally bind-
अधिकार	right	कारी	ing
अधिकार क्षेत्र	jurisdiction	अन्तर्विवेक	conscience
अधिकारी	officer	अन्तर्विषय	content
अधिनिषम	act	अपहृत पक्ष	injured party
अधिन्यास	assignment	अपराध	crime
अधिपत्र	warrant	अपराधित	condemned
अधिमोक्ता	occupant	अपराधी	criminal }
अधियाचित	requisitioned	अपवर्जन	exclusion }
अधिलघन	suppression	अपहरण	abduction
अधिवक्ता	advocate	अपीलीय क्षेत्रा-	appellate ju-
अधिवास्त	domicile	धिकार	risdiction
अधिवेशन	session	अप्रतिकार्य	irretrievable
अधिसेविना	servitude	अभिग्रहण	seizure
अध्यादेश	ordinance	अभित्याग	desertion
अध्याय	chapter	अभिनास	intimidation
अनुच्छेद	article	अभिधाचना	demand
अनुदेश	instruction	अभियुक्त	accused

अभियुक्ता	accuser	आयान	import
अभियोग	case	आयाग	Commission
अभियोजन	prosecution	आशय	intention
अभिरक्षक	custodian	आसन्न	immediate
अभिरक्षण	custody	उत्साहना	instigate
अभिलेख	record	उच्चतम न्याया-	Supreme
अभिज्ञास्त करना	incriminate	लय	Court
अभ्यारोपण	indictment	उच्चन्यायालय	High Court
अभ्युक्ति	plea	उपयोग	utilization
अर्थनिवचन	interpretation	उपसज्जानि	appearance
अर्हता	qualification	उपसहायक	accessory
अवधि	term	उपान्त	precincts
अवर न्यायालय	Inferior court	उल्लंघन	violation
अवरोध	restraint	क्रण पर	security
अदलीलता	obscenity	एकस्य अभिवर्ता	patent agent
अन्यत	incompatible	कटपूर्ण उपाय	fraudulent
असहिष्णुता	intolerance		stratagem
असाधारण अपील	extraordinary appeal	कब्रिस्तान	cemetery
असावधानी	negligence	कर	tax
अहितकारक	disadvantageous	कठोरश्रम-कारा-	Penal servi-
		वास	tude
आगम	proceeds	कर्मचारी	duty
आधार	ground	कर्मशाला	official
आपत्ति	objection	कारागार	work-house
आपराधिक अनु-	criminal in-	कारावास	prison
सधान	vestigation		imprison-
		कार्यवाही	ment
आपराधिक विधियां	criminal laws	कार्यवाही पर	proceeding
आप्लावन	inundation	पुनर्विनार	recopening
आय-व्यय	budget		of proce-
			dure

कायान्वय भ्रष्टाचार	official corruption	जनन सपह जनहित	referendum public welfare
कारवाइ	disposition		fare
कुख्यात	flagrant	अमानता निमुक्ति	release on bail
कुछो	attachment		
कुत्तानना	peerage	अन्नना	water main
कुतु	signal	अन्नदान	ve-el
क्षमादान	annuity	क्षान्नात्रा	forgery
मित्र आदेश	summary order	क्षण	forged counterfeit
मित्रव्यापार	summary procedure	क्षण मित्रता	coin
मित्रशक्ति	jurisdictional	क्षण शक्ति	gambling
मित्राधिकारिक	incompetency	क्षण	fact
अभिमता	quash	क्षण	search
अभिनव करना	reputation	क्षण	resignation
अभिन	counts	क्षण	spouse
अभिन	abortion	क्षण	penalty
गुलना	gravity	क्षण	extenuating
गुलपुड	civil war	क्षण	circumstances
गोबनायना	secrecy	क्षण	code of criminal procedure
घनाव	mitigation	क्षण	penal code
घायल करना	wounding	क्षण	oppression
घर शक्ति	gross error	क्षण	penal detention
घायना	pronouncement	क्षण	civil procedure
चरम	maximum	क्षण	diplomatic
चोर	injury	क्षण	bigamy
चोरी	theft	क्षण	
छुड़ा लना	rescue	क्षण	

पगड़ी	threat	परिवर्तन	calculation
पात्री	midwife	परिच्छेद	paragraph
नयाचार	protocol	परित्याग	renunciation
निकाल दिया गया	deleted	परिग्रह (जान)	inquiry
नियन्त्रण	control	परिरक्षण	preservation
नियम	regulation	परिरोध	confinement
निरीक्षण	inspection	परिवर्तन	commutation
निरोध	detention	परिवाद	complaint
निर्णय	judgement	परिवादो	complainant
निर्देशन	indication	परिष्कृत	costs
निर्दोष	not guilty	परिहार	abolition
निर्बन्धन	restriction	परीक्षा	examination
निर्वाचक	electors	पर्यवेक्षण	supervision
निर्वाह्य	sustainable	पलायन	escape
निलम्बन	suspension	पारपत्र	passport
निवास प्रभार	lodging charges	पालक	curator
निविदा	tender	पीठासीन न्यायाधीश	presiding judge
निष्पादन	execution	पीडा	torture
नुक्सान पहुँचाना	damage	पुन प्राप्ति	recovery
न्यायपालिका	judiciary	पुनरावृत्त अपराध	repeated crimes
न्यायाधीश	judge		
न्यायालय	court	पुनर्विलोकन	review
न्यायिक दृष्टान्त	judicial precedent	पूछताछ	interrogation
		प्रबलित प्रमाण	presumptive proof
न्यास	trust		
न्यूनतम	minimum	प्रस्थापन	promulgation
पडताल	entry	प्रणाल	sluice
पदनाम	designation	प्रतिभर	compensation
पदेन	ex-officio	प्रतिनिधि	representative
परामर्शदाता	counsel		

प्रतिनिधि-मदन	House of re presenta tive	प्राप्त प्रादक्षिण्य सत्राधि कार	writ territorial jurisdic tion
प्रतिपक्षी	proxy		tion
प्रतिपक्ष	proviso	प्राधिकरण	authorisation
प्रतिष्ठा	defense	बन्धन	arrest
प्रतिपक्ष परामर्श	defense cou nsel	दण्ड	riot
प्रतिपक्ष	rescript	बन्धन	rape
प्रतिपक्ष	report	बाधा	obstruct
प्रतिपक्ष	revocation	बाधना	obligation
प्रतिपक्ष	revoke	बाध	embankment
प्रतिपक्ष	guaranteed	भुगतान	payment
प्रतिपक्ष	restoration	भगवत्पितर	prescription
प्रतिपक्ष	withdrawal	मन्त्रि-मन्त्रिपर	cabinet
प्रतिपक्ष	credible	महत्त्वपूर्ण	material
प्रतिपक्ष	item	महाभियोग	public impe achment
प्रतिपक्ष	sovereignty	मानव व मौलिक	fundamental
प्रतिपक्ष	probative value	अधिकार	human rights
प्रतिपक्ष	attempt	मानवदण्ड	homicide
प्रतिपक्ष	document	मिथ्या अभियोग	false accusa tion
प्रतिपक्ष	enforcement		
प्रतिपक्ष	administra tion	मिथ्या गवाह	perjury
प्रतिपक्ष	resolution	मुख्य अपराधी	principal
प्रतिपक्ष	production	मुद्रा	seal
प्रतिपक्ष	death penalty	मूल न्यायालय	original court
प्रतिपक्ष	court of first instance	यात्रायात अवरोध	traffic obstru ction
प्रतिपक्ष	first instance	यात्रा-व्यय	travelling expenses

रक्षी	guard	लोक प्राधिकरण	public authority
राजप्रतिनिधि	regent		
राजप्रतिनिधि	regency	लोक विचारण	public trial
मण्डल		लोक विषय	public sale
राजवित्तीय वर्ष	fiscal year	लोक समाहर्ता	public procurator
राजस्व	revenue		
राजादिपट	commissioned	बमूली	collection
		बादवरण सामर्थ्य	litigation capacity
राज्य-मदन-विधि	imperial house law	वापसी	restoration
राज्य सभा	Diet	विवलाग	crippled
राज्यमात्वरण	confiscation	विगण्डन	rescission
राज्य मिहासन	imperial throne	विचारण	trial
		वितरण	service
राष्ट्रीय-ध्वज	National flag	वित्त	finance
लगाता	impose	विधान	law
लघु अर्थदण्ड	minor fine	विधायन अंग	law-making organ
लम्बित	pendency		
लम्बित	pending	विधि, विधान	law
लापता होना	missing	विधिज्ञ गण	bar association
लिखित अनुबन्ध	written stipulations	विधेय	bill
लूट	robbery	विध्वस्त करना	subvert
लेखा	record	विनिमय	exchange
लेखापरीक्षण	board of audit	विनियोग	application
मण्डल		(प्रयुक्ति)	
लेखा परीक्षण	audit	विनियोजन	appropriation
लेख्य प्रमाण	notary	विनिश्चय	decision
लोक अधिकारी	public officer	विवाजन	non-constitution
लोक बमंचारी	public official		
लोक कार्यालय	public office	विलेप	deed

विवरण (वक्तव्य)	statement	समाप्ति	extinction
विवाचक	arbitrator	समामेलन	amalgama- tion
विशेषज्ञ साक्ष्य	expert evi- dence	समावेदन	motion
विशेष प्रयेयता	special cre- dibility	सम्राट्	emperor
विशेषाधिकार	privilege	सरकारी राजपत्र	official gazette
बंध	legal	संगना	ring leader
व्यवसाय	business	सर्वोच्च विधि	supreme law
व्यवस्था	provision	महन्वायाधीश	associate judge
शोपण	exploitation		co defendant
पडयन्त्र	plot	सह-द्रविवादी	collegiate
संशय	suspect	सहपागी	complicity
संधिपत्र	treaty	सहापराधिता	accomplice
संगत	agreement	सहापराधी	constitution
समति	consent	साविधानिकता	ality
संविधान	constitution		witness
संशोधन	amendment	साक्षी	evidence
सश्रय देना	harbor	साक्ष्य	evidential
सस्वीकृति	confession	साक्ष्यसामग्री	material
सहिता	code		credit
सचिव	secretary	साल	provisional
सत्याकन	ratification	सामयिक निर्मुक्ति	release
सत्यापन	verification		general pro- visions
सभासद् सदन	House of councillors	सामान्य उपबन्ध	public auc- tion
समन (आह्वान)	summon	सार्वजनिक	Universal
समर्थ न्यायाधि- कारी	competent judicial officer	नीलामी	adult suffrage
मनाधि	grave	सार्वजनिक वयस्क मताधिकार	

सिद्धदाय	convicted	स्थानीय लाव	local public
सीमित	limited	सत्ता	entity
मुनवाई	hearing	स्थानीय स्वाम्यन	local self
मुपुदगी का प्रादेश	writ of com-	शासन	government
	mitment	स्वीकृति	approval
सूची	inventory	हरण	kidnapping
		हल्वा करना	mitigate

— — —

GLOSSARY

abduction	अपहरण	article	अनच्छेद
abolition	एगिहार	assignment	अभिन्नाम
abortion	गर्भपात	associate	सम्बन्धकारी
accessory	उपसहायक	judge	
accomplice	सहायक	attachment	कृषि
accuser	अभियोगी	attempt	प्रयत्न
accused	अभिप्रेत	audit	लघु परीक्षा
act	अविनियम	authorisation	प्राधिकरण
additional	अतिरिक्त	Bar Association	विधिज्ञ मण्डल
additional penalty	अतिरिक्त दण्ड	bigamy	द्विपत्नीय
administration	प्रशासन	bill	विधेयक
advocate	अभिप्रेत	board of audit	लेखापरीक्षक मण्डल
agreement	समन	budget	आयव्यय
amalgamation	समाश्लेषण	business	व्यवसाय
amendment	समाश्लेषण	cabinet	मन्त्रिमण्डल
amnesty	क्षमादान	calculation	परिवर्तन
appearance	उपस्थिति	case	अभियोग
appellate jurisdiction	अपीलीय क्षेत्राधिकार	cemetery	कब्रिस्तान
application	विनियोग(प्रयुक्ति)	chapter	अध्याय
appropriation	विनियोग	civil procedure	दीवानी प्रक्रिया
approval	स्वीकृति	civil war	गृह युद्ध
arbitrator	विवाचक	code	संहिता
arrest	बन्दीकरण	co-defendant	सह प्रतिवादी
arson	अग्निप्राण्ड	code of criminal procedure	दण्ड प्रक्रिया संहिता

collection	कमूली	counts	गणन
collegiate	सहायी	court of first instance	प्राथमिक न्याया-लय
commission	आयोग	credible	प्रत्येय
commissioned	राजादिष्ट	credit	मात्र
commutation	परिवर्तन	crime	अपराध
compensation	प्रतिवार	criminal	अपराधी
competent	समर्थ	criminal in-vestigation	अपराधिव अनु-गन्धान
judicial officer	न्यायाधि-कारी	criminal laws	आपराधिव विधियाँ
complainant	परिवादी	crippled	बिबलाग
complaint	परिवाद	custodian	अभिरक्षक
complicity	सहापराधिता	custody	अभिरक्षण
condemned	अपराधित	curator	पालक
confession	सस्वीकृति	damage	नुकसान पहुँचाना
confinement	परिरोध	death penalty	प्राणदण्ड
confiscation	राज्यमात्वरण	decision	विनिश्चय
conscience	अन्तर्विवेक	deed	दिलेख
consent	ममति	defense	प्रतिरक्षा
constitution	संविधान	defense	प्रतिवाद परामर्श-दाना
constitutionality	सांविधानिकता	counsel	
content	अन्तर्विषय	deleted	निवाले दिया गया
control	नियन्त्रण	demand	अभियाचना
convicted	मिट्ट दोष	desertion	अभित्याग
costs	परिच्यय	designation	पदनाम
court	न्यायालय	detention	निरोध
counsel	परामर्शदाता	diet	राज्य मन्त्रा
counterfeit	जाली सिक्का	diplomatic	दोयसम्बन्धी
com		disadvan- tagous	अहितकारक

disposition	कारवाइ	finally bind	अन्ततः बाध्यकारी
document	प्रत्यक्ष	ing	
domicile	अधिवास	finance	वित्त
duty	वन्ध	first instance	प्राथमिक व्यवहार
electors	निवाचक	final year	राजवित्तिय वर्ष
embankment	बाध	flagrant	बुद्ध्यान्
emperor	महाराज	forged	जाला
enforcement	प्रवर्तन	formation	बालमारा
entry	प्रवृत्ति	formation	अनर्थ-नामन
escape	पलायन	fraudulent	कपटपूर्ण उपाय
evidence	साक्ष्य	tristagem	
evidential material	साक्ष्य सामग्री	fundamental	मानव व मौलिक
examination	परीक्षा	human rights	अधिकार
exchange	विनिमय	gambling	जुआ खेलना
exclusion	अपवर्जन	general provisions	सामान्य उपबंध
execution	निष्पादन	gravity	समाप्ति
ex officio	पद	gross error	गलती
expert evidence	विशेषज्ञ साक्ष्य	ground	धार वृत्ति
exploitation	गादण	guaranteed	आगार
extenuating circumstances	कम घटान वाली परिस्थितियाँ	harbor	प्रमाण
extinction	समाप्ति	hearing	रक्षा
extraordinary appeal	असाधारण अपील	hanging	मध्य देना
fact	तथ्य	hanging	मुतबाई
false accusation	मिथ्या अभियोग	hanging	अनकाराद्य
		high court	उच्च न्यायालय
		homicide	मानववध
		house of	समास-सन्त
		councilors	

house of re presenta tives	प्रतिनिधि सदन	inventory	सूची
immediate	आसन्न	investigation	अनुसन्धान
imperial	राज्य-सम्बन्ध विधि	involute	अशुष्क
house law		irretrievable	अप्रतिवाद्य
imperial	राज्य सिंहासन	irrevocable	अटूट निणय
throne		judgement	
import	आयात	item	प्रभाग
impose	लगाना	judge	न्यायाधीश
imprison	बाराबान	judgement	निणय
ment		judicial pre cedent	न्यायिक दृष्टान्त
incompatible	असंगत	judiciary	न्यायपालिका
incompetent	अक्षम	jurisdiction	अधिकारक्षेत्र
incriminate	अभिज्ञास्त करना	jurisdic	क्षेत्राधिकारिक
indication	निर्देशन	ctional in	अक्षमता
indictment	अभ्यारापण	competen cy	
inferior court	अवर न्यायालय	kidnapping	हरण
injured party	अपहृत पक्ष	law	विधान
injury	चाट	law	विधि विधान
inquiry	परिग्रह (जांच)	law making	विधायक अंग
inspection	निरीक्षण	organ	
instigate	उत्साहना	legal	वैध
instruction	अनुदेश	limited	सामित
intention	आशय	litigation	वाह्यकरण सामयिक
interpreta tion	अर्थनिबचन	capacity	
interrogation	पूछनाछ	local public entity	स्थानाय गण सत्ता
intimidation	अभिज्ञास	local self	स्थानाय स्वायत्त
intolerance	अहिष्णुता	govern ment	शासन
inundation	आप्लावन		

lodging	निवास प्रमाण	ordinance	अव्यादेश
charges		original	मूल न्यायालय
material	महत्वपूर्ण	court	
maximum	चरम	Paragraph	परिच्छेद
midwife	घात्रा	passport	पारपत्र
minimum	न्यूनतम	patent agent	पेटन्ट अभिकर्ता
minor fine	लघु अदण्ड	payment	भुगतान
missing	गपना होना	peerage	कुलानता
mitigate	हल्का करना	penal code	दण्ड महिना
mitigation	घटाव	penal de	दाण्डिक विधान
motion	समावेदन	tention	
National flag	राष्ट्रीय ध्वज	penal servi	कठोरतम कारा
negligence	अमावधान	tude	वास
non consti	विधान	penalty	दण्ड
tution		pendency	लम्बन
non penal	अदाण्डिक अदण्ड	pending	लम्बित
fine		perjury	मिथ्या स्वीय
notary	गुरु प्रमाणक	plea	अभ्युक्ति
not guilty	निर्दोष	plot	पडपत्र
objection	आपत्ति	precincts	उपान्त
obligation	बाध्यता	prescription	भागवित्तर
obscenity	अश्लीलता	preservation	परिरक्षण
obstruct	बाधा डालना	presiding	प्रीडासीन
occupant	अधिभाक्ता	judge	न्यायाधीश
officer	अधिकारी	presumptive	प्रकल्पित प्रमाण
official	कर्मचारी	proof	
official cor	वार्यान्वीय	principal	मुख्य अपराधी
ruption	अपराध	prison	कारागार
official gazet	सरकारी राजपत्र	privilege	विशेषाधिकार
te		probative	प्रामाणिक मूल्य
oppression	दलन	value	

proceeding	कार्यवाही	quash	मण्डित करना
proceeds	आगम	rape	बलात्कार
production	प्रस्तुति	ratification	सत्यावन
promulgation	प्रख्यापन	record	लेखा
pronounce- ment	घोषणा	record	अभिलेख
prosecution	अभियोजन	recovery	पुनः प्राप्ति
protocol	मयाचार	referendum	जनमत संग्रह
proviso	प्रतिबन्ध	regency	राजप्रतिनिधि
provision	ध्ववस्था	regent	मण्डल
provisional	सामयिक निर्मुक्ति	regulation	राजप्रतिनिधि
release		release on bail	नियम
proxy	प्रतिपत्नी		जमानती निर्मुक्ति
public	सार्वजनिक	renunciation	परित्याग
auction	नीलामी	reopening	कार्यवाही पर
public au- thority	लोक प्राधिकरण	of proce- dure	पुनर्विचार
public im- peachment	महाभियोग	repeated crimes	पुनरावृत्त अपराध
public office	लोक कार्यालय	report	प्रतिवेदन
public officer	लोक अधिकारी	representa- tive	प्रतिनिधि
public official	लोक कर्मचारी	reputation	ख्याति
public pro- curator	लोक समाह्वान	requisitioned	अधियाचित
public sale	लोक विप्रय	rescission	विग्वण्डन
public trial	लोक विचारण	rescript	प्रतिविधान
public wel- fare	जनहित	rescue	छुड़ा लेना
qualification	अर्हता	resignation	त्याग पत्र
		resolution	प्रस्ताव
		restoration	वापसी
		restoration	प्रत्यावर्तन

restraint	अवरोध	summary	क्षिप्रप्रक्रिया
restriction	निर्बन्धन	procedure	
revenue	राजस्व	summon	ममन (आह्वान)
review	पुनर्विचार	supervision	परीक्षण
revocation	प्रतिमहरण	supplemen-	अनुपूरक
revoke	प्रतिमहण करना	tary	
right	अधिकार	supplemen	अनुपूरक उपरान्त
riot	बग़वा	tary provi-	
ring leader	सरगना	sions	
robbery	लूट	suppression	अधिकार
seal	मुद्रा	supreme	उच्चतम
search	तलाश	court	न्यायालय
secrecy	गोपनीयता	supreme law	सर्वोच्च विधि
secretary	सचिव	suspect	संदिग्ध
security	सुरक्षापत्र	suspension	निलम्बन
seizure	अभिग्रहण	statement	विवरण (बयान)
service	वितरण	sustainable	निर्वाह्य
servitude	अग्रिमविना	tax	कर
session	अधिवेशन	tender	निविदा
signal	केतु	term	अवधि
sluice	प्रणाल	territorial	प्रादेशिक क्षेत्र
sovereignty	प्रभुत्व	jurisdic	धिकार
special credi-	विशेष प्रत्येयता	tion	
blity		theft	चोरी
spouse	दंपति	threat	धमकी
subvert	विध्वस्त करना	torture	पीडा
summary	क्षिप्रन्यायालय	traffic obs-	यातायात अवरोध
court		truction	
summary	क्षिप्रआदेश	translation	अनुवाद
order		travelling	यात्राव्यय
		expenses	

treaty	मघिपत्र	violation	उल्लपन
warrant	अघिपत्र	water man	जलनली
trespass	अतिचार	withdrawal	प्रत्याहरण
trial	विचारण	witness	साक्षी
trust	न्यास	workhouse	बर्मशाला
Universal	सार्वजनिक वयस्क	wounding	घायल करना
adult	मताधिकार	writ	प्रादेश
suffrage		writ of com-	सुपुर्दगी का प्रादेश
utilization	उपयोग	mitment	
verification	सत्यापन	written sti-	लिखित अनुबन्ध
vessel	जलयान	pulations	
